



सत्यमेव जयते

गुजरात सरकार

गुजरात के राज्यपाल
श्री आचार्य देवव्रत
द्वारा
गुजरात विधानसभा में दिया गया
अभिभाषण

गांधीनगर
सोमवार, १६ फरवरी, २०२६

माननीय अध्यक्ष महोदय श्री तथा विधानसभा ना माननीय सदस्यश्रीओ, पंदरमी गुजरात विधानसभा ना आठमा सत्र ना मंगल प्रारम्भे आप सौनुं हृदयपूर्वक स्वागत करूं छुं।

विश्व को अहिंसा और सत्य का मार्ग दिखाने वाले महात्मा गांधीजी, देश को एकता के सूत्र में बांधने वाले सरदार वल्लभभाई पटेल, गुजरात के महान सपूत, ऋषितुल्य मूकसेवक पूज्यश्री रविशंकर महाराज, आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती, गुजरात की अस्मिता के ध्वजवाहक श्री इंदुलाल याज्ञिक की जन्मभूमि गुजरात राज्य की विधानसभा को संबोधित करने का शुभ अवसर मुझे प्राप्त हुआ, इसलिए मैं आनंद और गौरव का अनुभव कर रहा हूं। “विकसित गुजरात से विकसित भारत” मंत्र को सार्थक करने तथा गुजरात की जनता का सर्वसमावेशी, सर्वस्पर्शी, सर्वांगीण विकास सुनिश्चित करने के लिए इस विधानसभा सदन में अनेक ऐतिहासिक और नागरिकलक्ष्यी निर्णय लिए गए हैं।

देश ना कोई पण खूणा मां ‘केम छो’ नो उच्चार थाय छे. त्पारे प्रत्युत्तर मां ‘मजा मां’ सांभळवा मळे छे। गुजरात माटे नो आ आदरभाव, गुजरातनी प्रगतिशील विचारसरणी अने विकास ने राष्ट्रीय आंदोलन बनावनार वडाप्रधान श्री नरेंद्रभाई मोदी जी ना लोकप्रिय नेतृत्व नुं प्रतिबिम्ब छे.

गुजरात के लिए विकास की परिभाषा वह है जिसमें “सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय” की भावना हो। गुजरात की विकास यात्रा ऐसी है...

जहां युवाशक्ति के सपनों को मिलती है नयी उड़ान, जहां किसान के पसीने को मिलता है पूरा सम्मान, नारी शक्ति के गौरव का हम करते हैं जतन और गरीब कल्याण के लिए करते हैं चिंतन। एक ओर उद्योगों के लिए है प्रगति के द्वार तो दूसरी तरफ जन-जन के स्वास्थ्य की ली जाती है सम्पूर्ण दरकार... गुजरात की जनता ऐसे सर्वग्राही विकास की साक्षी रही है।

शाश्वत संस्कृति के धाम सोमनाथ मंदिर पर हुए आक्रमण को एक हजार वर्ष पूरे हुए हैं। सोमनाथ मंदिर मात्र एक शिवालय नहीं है बल्कि काल के कपाल पर अंकित हमारी अस्मिता और अस्तित्व की विजयगाथा है। इतिहास साक्षी है कि इस पवित्र धाम पर आक्रमण हुए, विनाश के प्रयास हुए...लेकिन आक्रमण के एक हजार वर्ष के बाद भी हमारी संस्कृति का ध्वज उतनी ही शान से फहरा रहा है। इसलिए, यह वर्ष कोई सामान्य वर्ष नहीं है, यह तो इतिहास के संघर्ष और स्वाभिमान में पलटने का ऐतिहासिक पर्व है। आज की मेरी युवा पीढ़ी...जो आने वाले कल का भारत है, उसकी रग-रग में राष्ट्रभक्ति और हमारी भव्य विरासत का गौरव धड़कता रहे, इसके लिए ही सोमनाथ स्वाभिमान पर्व का आयोजन किया गया। जनवरी की 09 से 15 तारीख तक भगवान सोमनाथ के चरणों में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्रभाई मोदीजी के प्रेरक सानिध्य में हम सभी ने साथ मिलकर संस्कृति की आराधना की है। यह उत्सव मात्र उत्सव ही नहीं है बल्कि राष्ट्र के गौरव को पुनः स्थापित करने का सुंदर अवसर है।

देश की एकता और अखंडता के शिल्पकार लौह पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल और भगवान बिरसा मुंडाजी की १५० वीं (एकसौ पचासवीं) जयंती मनाने का वर्ष ऐतिहासिक बन रहा है। यह राष्ट्रीय गौरव को उजागर करने का एक पावन पर्व है। यह वर्ष, राष्ट्रगान वंदे मातरम और सरदार साहब की राष्ट्रीय विचारधारा का समूचे विश्व में प्रचार-प्रसार का प्रेरणास्रोत बन रहा है। देश की एकता और अखंडता के शिल्पी लौहपुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल की जन्म जयंती के सुअवसर पर करमसद से केवड़िया युनिटी मार्च “सरदार एट एक सौ पचास” का आयोजन हुआ। करमसद की पावन ‘रज’ में से प्रगट हुई राष्ट्रभक्ति की ज्योति, यह ग्यारह दिन की पदयात्रा जब विश्व की सबसे विराट प्रतिमा ‘स्टेच्यु ऑफ युनिटी’ के चरणों में वंदन करने पहुंची, तब गुजरात के इतिहास में सबसे सुनहरा पृष्ठ शामिल हुआ। यह पदयात्रा कोई सामान्य यात्रा नहीं थी बल्कि भारतीयों के जन और मन को एकता के अदृश्य सूत्र में बांधने वाली एक अविस्मरणीय एकता यात्रा बन गई।

धरती आबा भगवान बिरसा मुंडाजी की एक सौ पचासवीं जन्म जयन्ती को यादगार बनाने और जनजातीय नायकों के शौर्य तथा अमूल्य योगदान को सम्मानित करने के लिए समग्र देश में 2025 का वर्ष जनजातीय गौरव वर्ष के तौर पर मनाकर भगवान बिरसा मुंडा को सही अर्थों में सम्मान दिया गया है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्रभाई मोदी जी की उपस्थिति में जनजातीय गौरव दिवस को राष्ट्रीय स्तर पर भव्य और दिव्य पर्व के स्वरूप में नर्मदा जिले के देडियापाडा में मनाया गया। यह वास्तव में गुजरात के लिए गौरव की बात है। भगवान बिरसा मुंडाजी और जनजातीय समाज के योगदान को लोगों तक पहुंचाने के लिए राज्य में 7 से 13 नवम्बर, 2025 के दौरान जनजातीय गौरव रथयात्रा का आयोजन किया गया। ‘सबका साथ सबका विकास’ मंत्र को चरितार्थ करने के लिए तथा विकास में कोई पीछे ना रह जाए- विकास से कोई वंचित ना रह जाए, इस भावना के साथ सरकार ने जनजातियों के उत्कर्ष का मार्ग बनाया है। जनजातीय समुदायों के लिए स्वास्थ्य सुविधा को ज्यादा सुनिश्चित करने के लिए प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से गुजरात ‘जीनोम सिकवन्सिंग प्रोजेक्ट’ शुरू करने वाला देश का प्रथम राज्य बना है। खास तौर पर, कमजोर आदिम समूहों को प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत आवास आवंटन में गुजरात ने देश में बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट के तौर पर पुरस्कार पाने का गौरव हासिल किया है।

अहमदाबाद में आयोजित अंतरराष्ट्रीय पतंग महोत्सव 2026 में देश के माननीय प्रधानमंत्री और जर्मनी के माननीय चांसलर की प्रेरक उपस्थिति ने राज्य के उत्सव को वैश्विक पहचान दी। इसमें पतंगबाजी के साथ ग्रैंड सिम्फनी, फ्लोटिंग आर्ट काइट म्यूजियम और पोल संस्कृति के प्रदर्शन द्वारा राज्य की भव्य विरासत प्रदर्शित की गई।

मेरी सरकार सरल, सहज, लेकिन ठोस और लोकाभिमुख प्रशासन अपनाने के लिए सतत प्रयासशील रही है। इसके तहत पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी की जन्मजयन्ती पर ‘सुशासन दिवस’ भव्य रूप से मनाया गया। राज्य के नागरिकों की इज ऑफ लीविंग बढ़ाने के लिए योजनाओं, सेवाओं और विकास कार्यों तथा शिकायत निवारण की कार्यवाही प्रभावी रूप से की जा रही है।

राज्य के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री भूपेन्द्रभाई पटेल के निर्देशन में विभिन्न विभागों की कार्यप्रणाली के महत्वपूर्ण पैरामीटर्स को सी.एम. डैशबोर्ड पर एक ही इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म पर लाया गया है। गुड गवर्नेंस की उज्ज्वल परम्परा को गतिपूर्वक आगे बढ़ाने हेतु सी.एम. डैशबोर्ड द्वारा गवर्नेंस परफॉर्मेंस इंडेक्स (GPI) तैयार किया गया है।

कॉमनवेल्थ गेम्स 100 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं तब, राज्य के तत्कालीन मुख्यमंत्री और वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्रभाई मोदी जी की 24 वर्षों की अथक मेहनत से खेलकूद क्षेत्र में जो इकोसिस्टम स्थापित हुआ है, उसके फलस्वरूप कॉमनवेल्थ गेम्स के नेतृत्व का अवसर हमें मिला है। यह हम सभी के लिए गौरवपूर्ण क्षण है। इस कॉमनवेल्थ गेम्स के माध्यम से विश्व का भारत में स्वागत करने और गुजरात को स्पोर्ट्स हब बनाने के लिए राज्य तैयार और प्रतिबद्ध है।

प्राकृतिक आपदा के समय मेरी सरकार हमेशा गुजरात की जनता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी रही है। राज्य में आई बाढ़ और बेमौसम वर्षा के कारण किसानों को हुए नुकसान की भरपाई कर के उन्हें फिर से मजबूत करने के हेतु मुख्यमंत्री ने संवेदनशील अभिगम अपनाते हुए ग्यारह हजार करोड़ रुपये से अधिक का सहायता पैकेज घोषित किया। यह ऐतिहासिक पैकेज मात्र एक सहायता ही नहीं है बल्कि धरतीपुत्रों के परिश्रम को सम्मान है और कृषि अर्थव्यवस्था को फिर से खड़ी करने का अभियान है। राज्य सरकार द्वारा घोषित राहत पैकेज मात्र एक नीतिगत कदम नहीं है बल्कि यह एक मानवीय संवेदना का प्रतिबिम्ब है। राज्य सरकार धरतीपुत्रों के साथ है। यह कदम किसानों के परिश्रम को परखने के साथ ही राज्य के कृषि आधारित अर्थतंत्र को खड़ा करने की दिशा में एक मजबूत कदम साबित होगा।

मुख्यमंत्री श्री भूपेन्द्रभाई पटेल के नेतृत्व में अत्याधुनिक गुजरात के विकास पथ पर एक ठोस कदम के तौर पर राज्य के चार झोन में "वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कांफ्रेंस" का आयोजन किया गया। महेसाणा और राजकोट में यह सम्मेलन सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। 'रीजनल एस्पिरेशन्स, ग्लोबल एम्बिशन्स' की थीम और 'हर घर स्वदेशी, घर-घर स्वदेशी' की भावना के साथ आयोजित यह सम्मेलन केवल एक कार्यक्रम नहीं, बल्कि 'आत्मनिर्भर गुजरात से आत्मनिर्भर भारत' के विजन को साकार करने का रणनीतिक मंच बन गया। वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कांफ्रेंस का यह नवाचार राज्य के उद्योगों को प्रधानमंत्री जी के विकसित भारत 2047 विजन को आत्मनिर्भर भारत और "वोकल फॉर लोकल" तथा "लोकल फॉर ग्लोबल" के लिए मार्गदर्शन प्रदान करने का महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म बनेगा।

राजस्व की जटिल और उलझपूरी प्रक्रिया को लोकाभिमुख और सरल और बनाने हेतु I-ORA (आई-ओरा) पोर्टल की पहल की गई। यह एक ऐसी पहल है, जिसके परिणाम स्वरूप भूमि रिकॉर्ड से संबंधित 35 से अधिक सेवाएं एंड टु एंड ऑनलाइन उपलब्ध हुई हैं। साथ ही नागरिकों को घर बैठे इंडेक्स-टु (INDEX-2) और भूमि संबंधित दस्तावेज पहुंचाने हेतु गरवी-टु (GARVI-2) जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म की सुविधा भी सराहनीय है।

गुजरात में देश का सबसे विशाल समुद्री तट है। मुख्यमंत्री श्री भूपेन्द्रभाई पटेल के नेतृत्व में 'समुद्र से समृद्धि' के विजन को साकार करने हेतु राज्य में बंदरगाहों के आधुनिक ढांचागत विकास का एक महत्वपूर्ण कदम सरकार ने उठाया है। इसके अंतर्गत गुजरात मेरिटाइम बोर्ड के साथ गुजरात पीपावाव पोर्ट लिमिटेड (APM टर्मिनल्स) द्वारा रुपये सत्रह हजार करोड़ के निवेश के समझौते (MoU) किए गए। इन समझौते से पीपावाव पोर्ट्स का विस्तार होगा। जिसके परिणाम स्वरूप गुजरात की भारत में 'मेरिटाइम गेटवे' के रूप में स्थापित पहचान और ज्यादा मजबूत होगी।

मेरी सरकार ने राज्य शासन में प्रशासनिक विकेंद्रीकरण का उद्देश्य रखा है। इस हेतु बनासकांठा में नया वाव-थराद जिला और नयी 17 तहसील बनाई गई। इस विकेंद्रीकरण से लोगों को जिला-तहसील स्तर के कार्यालयों के साथ काम में सुगमता रहेगी। नये तहसील मुख्यालय नजदीक होने से सामाजिक, आर्थिक, स्वास्थ्य और शैक्षणिक सुविधाओं में वृद्धि होगी तथा दूरदराज के गांवों से तहसील मुख्यालय आने-जाने में समय, शक्ति और धन की बचत होगी।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्रभाई मोदी जी की जन्मभूमि "अनंत अनादि वडनगर" के ऐतिहासिक शर्मिष्ठा तालाब परिसर में मुख्यमंत्री श्री भूपेन्द्रभाई पटेल की उपस्थिति में 11वां अंतरराष्ट्रीय योग दिवस "Yoga for One Earth One Health" और "स्वस्थ गुजरात, मोटापामुक्त गुजरात" थीम के साथ राज्य स्तरीय उत्सव आयोजित किया गया। इस अवसर पर दो हजार एक सौ इक्किस योग साधकों द्वारा एक साथ भुजंगासन का नया कीर्तिमान गिनिज बुक्स ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ।

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्रभाई मोदी जी द्वारा जिसे डेमोग्राफिक डिविडंड कहा गया है, ऐसी युवाशक्ति को लोगों की सेवा करने का अवसर देने हेतु पिछले वर्ष तीस हजार से अधिक उम्मीदवारों को मेरी सरकार द्वारा नियुक्तिपत्र प्रदान किए गए। जनसेवा का अवसर पाने वाली यह युवा पीढ़ी ईमानदारी और निष्ठा से सेवा देने तथा नवीन दृष्टिकोण के साथ निरंतर प्रगति की ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रतिबद्ध है।

इस प्रक्रिया को निरंतर और नियमित बनाए रखने हेतु राज्य सरकार ने मेनपावर प्लानिंग के लिए 10 वर्षीय भर्ती कैलेंडर तैयार किया है। इसके अंतर्गत वर्ष 2024 से 2033 के दौरान कुल दो लाख से अधिक पदों को चरणबद्ध रूप से भरने का आयोजन राज्य सरकार ने किया है।

सरकार ईमानदारी और निष्ठा से जनता की सेवा करने वाले सरकारी कर्मचारियों के प्रति संवेदनशील है। गुजरात में कार्यरत अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों तथा राज्य सरकार के अधिकारी-कर्मचारी, पेंशनरों एवं उनके परिवारजनों के स्वास्थ्य की चिंता करते हुए हुए मेरी सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। इस योजना के अंतर्गत 'गुजरात कर्मयोगी स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (G-कैटेगरी)' का शुभारंभ किया गया है। इस योजना के तहत सभी सरकारी अधिकारी-कर्मचारियों और उनके परिवारजनों को ₹10 लाख तक की कैशलेस चिकित्सीय उपचार सुविधा का लाभ मिलेगा तथा उनके स्वास्थ्य एवं कल्याण में वृद्धि होगी।

भारत के लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्रभाई मोदी जी द्वारा निर्मित गुजरात के विकास पथ पर मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्रभाई पटेल के नेतृत्व में मेरी सरकार नये आत्मविश्वास के साथ गुजरात को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध है। मेरी सरकार के मृदु और दृढ़ नेतृत्व में पारदर्शी और प्रगतिशील निर्णयों के द्वारा सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, स्वास्थ्य और ढांचागत संरचना जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में तीव्र गति से विकास हो रहा है।

कृषि एवं किसान कल्याण

प्राकृतिक खेती

- भूमि, पर्यावरण और मानवजाति के स्वास्थ्य के लिए प्राकृतिक कृषि एक वरदान है। प्राकृतिक कृषि को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्रभाई मोदी जी ने अपने हृदय के सबसे करीब माना है और इस देश का प्रत्येक किसान प्राकृतिक कृषि अपनाए, यह उनका सपना है। इस सपने को साकार करने के लिए गुजरात राज्य में प्राकृतिक कृषि का विस्तार हो, इस उद्देश्य से माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्रभाई पटेल के मार्गदर्शन में सरकार द्वारा सुनियोजित अभियान के रूप में कार्य किया जा रहा है।
- राज्य में प्राकृतिक कृषि का दायरा बढ़ाने के लिए गुजरात प्राकृतिक कृषि विकास बोर्ड और विश्व की प्रथम प्राकृतिक कृषि युनिवर्सिटी की स्थापना की गई है, इसमें प्राकृतिक कृषि संबंधी प्रशिक्षण, प्रेरणा प्रवास, संशोधन, कॉन्क्लेव, मेगा शिविर, परिसंवाद तथा प्रदर्शनियों का आयोजन किया जाता है।
- अब तक लगभग उन्नीस लाख किसानों को प्राकृतिक खेती का प्रशिक्षण दिया जा चुका है।
- चालू वर्ष में प्राकृतिक कृषि करने वाले एक लाख से अधिक किसानों को देशी गाय के भरण-पोषण व्यय हेतु अठ्ठावन करोड़ से ज्यादा रुपये की सहायता प्रदान की गई है।
- किसानों को प्राकृतिक कृषि की प्रत्यक्ष जानकारी उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से राज्य में अब तक किसानों के खेतों पर लगभग सात हजार एक सौ मॉडल फार्मों का निर्माण किया गया है।
- राज्य में अनुमानित आठ लाख से अधिक किसानों ने प्राकृतिक खेती अपनाई है।
- राज्य के डांग जिले को सम्पूर्ण रसायन-मुक्त कृषि जिला घोषित किया गया है। इसके अंतर्गत लगभग दस हजार किसानों को प्राकृतिक खेती के अंतर्गत शामिल कर पचीस करोड़ से अधिक की सहायता प्रदान की गई है।

- इस साल बाढ़ में पानी किसानों की आंख का आंसु बनकर बरसा है। इस अतिवृष्टि के अति कठिन समय में यह सरकार किसानों की साथी बनकर खड़ी रही है। मेरी सरकार ने बेमौसम वर्षा के कारण किसानों को सहायता प्रदान करने हेतु चालू वर्ष में बड़े पैमाने पर कृषि राहत पैकेज की घोषणा की है, जिसके अंतर्गत तैंतीस लाख से अधिक किसानों को नौ हजार छह सौ दस करोड़ रुपये की सहायता प्रभावित किसानों के बैंक खातों में जमा कराई गई है। नुकसान का आंकलन और भुगतान गुजरात के इतिहास में रिकॉर्ड समय में पूर्ण किया गया है। गुजरात के इतिहास में यह एक शानदार और पहला उदाहरण है कि इतने कम समय में इतनी बड़ी मदद सीधे किसानों के खातों में पहुंची है। इससे पता चलता है कि अगर इरादा मजबूत हो तो मुश्किलों से भी निपटा जा सकता है। जो मेरी सरकार की किसानों के प्रति संवेदनशीलता और प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
- वर्ष 2025-26 में राज्य में खरीफ सीजन के दौरान मूंगफली, मूंग, उड़द और सोयाबीन जैसी फसलों की अब तक आठ लाख बत्तीस हजार किसानों से तेरह हजार एक सौ करोड़ रुपये के मूल्य की अठारह लाख चौबीस हजार मीट्रिक टन से अधिक मात्रा की समर्थन मूल्य पर खरीद की गई है। भारत सरकार के सहयोग से समर्थन मूल्य पर मूंगफली, मूंग, उड़द और सोयाबीन जैसी फसलों की त्वरित खरीद तथा दूसरी ओर बेमौसम वर्षा से हुई क्षति की सहायता का भुगतान तथा दूसरी ओर बेमौसम वर्षा के कारण हुए नुकसान की सहायता का भुगतान, इन दोनों से “डबल इंजन” सरकार का दृष्टिकोण सार्थक होता है।
- प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत राज्य में अब तक पहली से इक्कीसवीं किस्त तक बाईस हजार करोड़ रुपये की सहायता उनहत्तर लाख से अधिक किसान परिवारों के बैंक खातों में सीधे जमा की गई है।
- चालू वर्ष 2025-26 में ट्रैक्टर तथा ट्रैक्टर-चालित कृषि उपकरणों और साधनों की खरीद हेतु अधिकतम लाभार्थियों को कवर करने के लिए एक हजार चार सौ करोड़ रुपये से अधिक राशि का बजटीय प्रावधान किया गया है। ट्रैक्टर खरीद पर सहायता बढ़ाकर वर्ष 2025-26 से एक लाख की गई है।
- राज्य स्तर पर सभी जिलों और तहसीलों में फसल स्थिति, मौसम-आधारित जोखिमों और रोग-कीटों की रियल-टाइम मॉनिटरिंग तथा किसानों को समय पर और उचित मार्गदर्शन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से “कृषि प्रगति” वेब पोर्टल और “कृषि प्रगति” मोबाइल ऐप विकसित किए गए हैं, जिनसे लाखों किसान सीधे जुड़े हुए हैं।

- किसानों को विभिन्न सहायता योजनाओं में “ऑनलाइन” आवेदन की सुविधा देने हेतु चालू वर्ष 2025-26 से नया आई-खेडूट पोर्टल-टु (I-KHEDUT PROTRAL-2) विकसित किया गया है।
- भारत सरकार की एग्रीस्टैक योजना के अंतर्गत गुजरात राज्य द्वारा फार्मर रजिस्ट्री के तहत अब तक उनसठ लाख से अधिक किसानों का पंजीकरण पूर्ण किया गया है तथा डिजिटल क्रॉप सर्वे का कार्य भी किया गया है। बेहतर कामकाज के लिए भारत सरकार द्वारा चार सौ तेरह करोड़ रुपये की प्रोत्साहन ग्रांट प्रदान की गई है।
- **बागवानी**
 - गुजरात की विशिष्ट पहचान और वैश्विक स्तर पर विशिष्ट स्थान रखने वाले बागवानी उत्पादों में “गिर की केसर आम”, “वलसाड़ी हाफुस आम”, “कच्छी खारेक” और “अमलसाड़ी चीकू” शामिल हैं।
 - बागवानी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन से वर्ष 2024-25 में फल फसलों में चार लाख चौवालीस हजार हेक्टेयर क्षेत्रफल तथा पचासी लाख से ज्यादा मीट्रिक टन उत्पादन, सब्जी फसलों में आठ लाख पचहत्तर हजार हेक्टेयर क्षेत्रफल तथा एक सौ पचासी लाख मीट्रिक टन उत्पादन तथा मसाला फसलों में आठ लाख अठारह हजार हेक्टेयर क्षेत्रफल एवं बारह लाख इक्यानवे हजार मीट्रिक टन उत्पादन हुआ है।
 - चालू वर्ष 2025-26 में एकीकृत बागवानी विकास की गतिविधियों हेतु तीन सौ इकतालीस करोड़ से ज्यादा रुपये की सहायता से लगभग एक लाख बहत्तर हजार बागवानों को विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत लाभान्वित किया गया है।
 - बागवानी विभाग द्वारा बागवानी फसलों के कटाई-उपरांत प्रबंधन के लिए राज्य में विभिन्न आधारभूत संरचनाएं विकसित की गई हैं, जिनमें 548 कोल्ड स्टोरेज, 2762 पैक हाउस, 83 रिपनिंग चेंबर, 413 सॉर्टिंग-ग्रेडिंग इकाइयां, 19 रीपर वैन तथा अन्य संरचनात्मक सुविधाएं शामिल हैं।
 - राज्य के किसानों को बागवानी फसलों के लिए अत्याधुनिक तकनीक उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राज्य में आठ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कार्यरत हैं। इसके अतिरिक्त राज्य में नौ नये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस निर्माणाधीन हैं। इन केंद्रों के माध्यम से अब तक लगभग एक लाख किसानों और युवाओं को कौशल्य-वर्धन का प्रशिक्षण प्रदान किया गया है।

पशुपालन

- गुजरात राज्य के आर्थिक और सामाजिक विकास में पशुपालन एवं डेयरी क्षेत्र का महत्वपूर्ण योगदान है।
- पशु-स्वास्थ्य के क्षेत्र में राज्य में जनवरी, 2026 तक साठ लाख से अधिक पशुओं का उपचार किया गया है तथा चार हजार से अधिक पशु-स्वास्थ्य मेलों का आयोजन किया गया है।
- राज्य के पशुपालकों को अपने पशुओं में सेक्स-सॉर्टेड सीमन के संवर्धन की उन्नत तकनीक का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु सरकारी संस्थानों में मात्र पचास रुपए शुल्क पर सेक्स-सॉर्टेड सीमन से कृत्रिम गर्भाधान की सुविधा सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई है और इस वर्ष जनवरी, 2026 तक दो लाख, चौहत्तर हजार (2.74 लाख) पशुओं में सेक्स-सॉर्टेड सीमन से कृत्रिम गर्भाधान किया गया है।
- कृत्रिम गर्भाधान कवरेज की दृष्टि से सौ लाख से अधिक प्रजनन पशुधन वाले राज्यों में गुजरात प्रथम स्थान पर है।
- जनवरी, 2026 तक पंद्रह हजार, तीन सौ पंद्रह फर्टिलिटी इम्प्रूवमेंट कैंप-यौन-स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन कर आठ लाख से अधिक पशुओं को उपचार प्रदान किया गया है।
- भारतीय संस्कृति गौ-गंगा-गीता और गायत्री की संस्कृति है। पब्लिक ट्रस्ट एक्ट के अंतर्गत पंजीकृत गौशालाओं-पांजरापोलों में रखे जाने वाले गाय एवं भैंस वर्ग के पशुओं के भरण-पोषण हेतु “मुख्यमंत्री गौमाता पोषण योजना” के अंतर्गत प्रति पशु प्रतिदिन तीस रुपए की दर से राज्य सरकार द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। वर्ष 2025-26 के दौरान कुल एक हजार, छह सौ से अधिक संस्थाओं के साठे चार लाख से अधिक पशुओं के लिए दो सौ इकतालिस करोड़ से ज्यादा सहायता राशि का भुगतान किया गया है।

मत्स्योद्योग

- राज्य का वर्ष 2025-26 (दिसंबर-2025 तक) का कुल अनुमानित मत्स्य उत्पादन सात लाख इक्यावन हजार मीट्रिक टन हुआ है, जिसकी कुल कीमत उन्नीस हजार करोड़ है।
- मत्स्य उतार केंद्रों के विकास के लिए लगभग एक हजार, सात सौ करोड़ करोड़ के विभिन्न कार्य प्रगति पर हैं।

- गुजरात मत्स्योद्योग (संशोधन) अधिनियम, 2025 के अंतर्गत गुजरात स्टेट फिशरीज़ हार्बर एन्ड एक्वाल्चर ओथोरिटी की स्थापना की गई है, जो अंतर्देशीय एक्वाल्चर के विकास तथा मत्स्य उतार केंद्रों के रखरखाव की जिम्मेदारी निभाएगी।
- झींगा फार्म संवर्धन क्षेत्र के लिए पंचानवे करोड़ का कम्प्रिन्सिव पैकेज चालू वर्ष में स्वीकृत किया गया है, जिसके तहत खारे पानी के मत्स्य उद्योग क्षेत्र में फार्म धारकों को विद्युत ड्यूटी पर पूर्ण छूट तथा विद्युत उपभोग की इकाइयों पर अनुदान दिया जा रहा है। जनवरी-2026 तक कुल साठ करोड़ का खर्च किया गया है।
- गुजरात के मछुआरे नई तकनीक का उपयोग कर मत्स्य, झींगा उत्पादन बढ़ाकर अपनी आय दोगुनी कर सकें, इसके लिए विकसित गुजरात फंड के अंतर्गत इंटेंसिव एक्वाल्चर फार्मिंग तथा मेरीकल्चर झोनेशन हेतु भारत सरकार की संस्थाओं को ₹12.50 करोड़ आवंटित किए गए हैं।
- प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत मछुआरा समूह दुर्घटना बीमा योजना के माध्यम से राज्य के एक लाख, दस हजार मछुआरों को बीमा कवच प्रदान किया गया है।

सहकारिता

- भारत सरकार द्वारा गठित सहकारिता मंत्रालय के माध्यम से 'सहकार से समृद्धि' के मंत्र को साकार करने तथा सहकारी संस्थाओं को आर्थिक रूप से अधिक सशक्त और पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा अनेक क्रांतिकारी पहलें लागू की गई हैं।
- राज्य की सहकारी संरचना में वित्तीय समावेश को गति देने के लिए मेरी सरकार ने ऐतिहासिक कदम उठाते हुए बारह हजार, पांच सौ अस्सी से अधिक माइक्रो एटीएम (Micro ATM) कार्यरत किए हैं, जिनके माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में अब तक तेरह हजार करोड़ से अधिक मूल्य के दो करोड़ से अधिक लेनदेन सफलतापूर्वक पूर्ण किए गए हैं। इस पहल के अंतर्गत उन्नीस लाख से अधिक पशुपालकों को प्रत्यक्ष बैंकिंग सेवाओं से जोड़ा गया है तथा राज्य के अधिकांश गांव बैंकिंग सुविधाओं का लाभ प्राप्त कर रहे हैं।
- बनास डेयरी द्वारा दामा में प्रतिदिन चालीस मीट्रिक टन गोबर का संग्रहण एवं वैज्ञानिक प्रसंस्करण कर बायो-सीएनजी का उत्पादन करने वाला संयंत्र स्थापित किया गया है, जिससे पशुपालकों को गोबर की बिक्री से प्रत्यक्ष एवं अतिरिक्त आय प्राप्त हो रही है तथा इस प्रसंस्करण के दौरान तैयार होने वाले उच्च गुणवत्ता वाले भूमि-जैविक खाद ("भूमि अमृत") के उपयोग से किसानों के कृषि खर्च में कमी आई है।

- सौ मीट्रिक टन क्षमता वाले एक संयंत्र द्वारा प्रतिदिन लगभग एक हजार आठ सौ किलोग्राम बायो-सीएनजी (Bio-CNG) तथा लगभग सौ मीट्रिक टन जैविक उर्वरक का उत्पादन किया जाता है, जिसे बनास डेयरी द्वारा “भूमि अमृत” ब्रांड नाम से बेचा जाता है। यह परियोजनाएं न केवल पशुपालकों की आय में वृद्धि कर रही हैं, बल्कि वार्षिक अनुमानित छह हजार, सात सौ पचास टन कार्बन उत्सर्जन में कमी लाकर पर्यावरण संरक्षण में भी आधारभूत भूमिका निभाएंगी।

जल

व्यवस्थापन

- एक समय में गुजरात को जल की कमी वाला क्षेत्र माना जाता था। मेरी सरकार के उत्तम जल व्यवस्थापन से आज गुजरात “पानीदार राज्य” बना है। वर्ष 2025-26 में दिसंबर-2025 तक छोटे और बड़े मिलाकर कुल 202 चेकडैमों के कार्य पूर्ण हो चुके हैं। इसके अतिरिक्त 186 छोटे और 204 बड़े चेकडैम प्रगति पर हैं, जो पूर्ण होने पर सात हजार, आठ सौ हेक्टेयर क्षेत्र को सिंचाई लाभ प्रदान करेंगे। दिसंबर-2025 तक राज्य में कुल एक लाख, सतासी हजार, सात सौ इक्यानवें चेकडैमों के माध्यम से लगभग 4.61 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सिंचाई लाभ प्राप्त हुआ है।
- मानसून के दौरान साबरमती नदी में धरोई बांध से डाउनस्ट्रीम बहने वाले पानी के संग्रह के लिए साबरमती नदी पर दो हजार करोड़ से अधिक की लागत से विभिन्न चौदह स्थानों पर सीरीज ऑफ बैराज बनाकर नदी को जीवंत रखने की योजना सरकार द्वारा बनाई गई है। इनमें से पांच बैराजों का कार्य पूर्ण हो चुका है, जिससे अहमदाबाद, गांधीनगर, मेहसाणा और साबरकांठा जिलों के पचास हजार हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से सिंचाई का लाभ मिलता है।
- इसके अतिरिक्त धरोई बांध को एक हजार उनसठ करोड़ की लागत से विश्व स्तरीय पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने का कार्य प्रगति पर है।
- सौनी योजना के अंतर्गत नर्मदा के बाढ़ के अतिरिक्त पानी से दिसंबर-2025 तक एक सौ पांच जलाशयों को जोड़ा गया है। इनमें से निम्नान्वे जलाशयों, दो सौ चौतीस गांव तालाबों और एक हजार, छह सौ सोलह चेकडैमों में एक लाख उनत्तीस हजार मिलियन घनफुट जल प्रदान किया गया है, जिससे लगभग दो लाख, तिरसठ हजार हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में सिंचाई सुविधा तथा अनेक शहरों में पेयजल सुविधा सुदृढ़ हुई है।

- कड़ाणा, पानम, करजण, उकाई जलाशय तथा नर्मदा नहर आधारित कुल ग्यारह उद्बहन सिंचाई योजनाओं के माध्यम से दाहोद, पंचमहाल, महिसागर, सूरत, भरूच और नर्मदा जिलों के सात सौ, उनहत्तर गांवों के लगभग बानवे हजार हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई का लाभ दिया जा रहा है।
- सुजलाम सुफलाम जल अभियान, “कैच द रेन 2.0” के अंतर्गत वर्ष 2025 के दौरान विभिन्न विभागों द्वारा चौदह हजार, पांच सौ कार्य किए गए हैं। इन कार्यों से जल भंडारण क्षमता में कुल बीस हजार, आठ सौ पंद्रह लाख घनफुट की वृद्धि हुई है तथा दस लाख से ज्यादा मानव-दिवस का रोजगार उत्पन्न हुआ है।

जलापूर्ति

- राज्य सरकार ने जल आपूर्ति योजनाओं के लिए भू-जल पर निर्भरता न रखते हुए उन्हें नदी, जलाशय, नहर, तालाब जैसी सरफेस स्रोत आधारित योजनाओं में परिवर्तित करने की एक उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है।
- जल आपूर्ति योजनाओं हेतु तीन हजार, दो सौ नब्बे किलोमीटर की बल्क पाइपलाइन का विशाल नेटवर्क स्थापित कर देश में पहली बार इतनी व्यापक राज्यव्यापी जल आपूर्ति ग्रिड के माध्यम से राज्य के पंद्रह हजार, आठ सौ दो गांवों और दो सौ इक्यावन शहरी क्षेत्रों को सरफेस स्रोत आधारित पेयजल सुविधा उपलब्ध कराने में राज्य सरकार सफल हुई है, जिससे गुजरात के पांच करोड़ से ज्यादा नागरिकों को पेयजल का लाभ मिल रहा है।
- मेरी सरकार द्वारा चालू वर्ष में चार सौ तैंतालिस करोड़ की बारह योजनाओं का लोकार्पण तथा साठ करोड़ की एक योजना का भूमिपूजन किया गया है।
- राज्य की जनता को उचित गुणवत्ता वाला तथा पर्याप्त मात्रा में जल वितरण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, साथ ही लीकेज, चोरी और अपव्यय पर नियंत्रण रखने हेतु स्मार्ट मीटरिंग तथा वॉटर ट्रीटमेंट प्लांटों में क्वालिटी एनालाइजर का उपयोग किया गया है, जिसकी गांधीनगर सेंट्रल मॉनिटरिंग स्टेशन द्वारा रियल-टाइम मॉनिटरिंग की जाती है।
- पानी की गुणवत्ता की उचित जांच के लिए राज्य में चालू वर्ष में नवीन तीन प्रयोगशालाएं प्रारंभ होने से कुल तिराशीं प्रयोगशालाएं कार्यरत हो गई हैं।

अन्न, नागरिक आपूर्ति एवं ग्राहक मामले

- प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत मेरी सरकार द्वारा पचहत्तर लाख परिवारों की तीन करोड़ अठारह लाख जनसंख्या को सुरक्षा प्रदान की जा रही है, जिसमें अंत्योदय परिवारों को मासिक परिवार प्रति पैंतीस किलोग्राम तथा प्राथमिकता वाले परिवारों को मासिक व्यक्ति प्रति पांच किलोग्राम अनाज का निःशुल्क वितरण किया जाता है।

- वन नेशन वन राशनकार्ड योजना के अंतर्गत राज्य के विभिन्न जिलों में पंजीकृत कार्डधारक राज्य में किसी भी उचित मूल्य की दुकान से “स्टेट पोर्टेबिलिटी” के तहत अनाज प्राप्त कर सकते हैं। इसके तहत राज्य में गत वर्ष की तुलना में चालू वर्ष में लगभग पांच लाख से अधिक अर्थात् कुल सैंतीस लाख, इक्यानवे हजार कार्डधारकों ने इस योजना का लाभ लिया है।
- वर्ष 2025-26 में जनवरी-2026 तक वर्ष 2024-25 की तुलना में दलहन वितरण योजना के अंतर्गत तुवर दाल एवं चने का कुल सत्रह हजार, एक सौ अड़तीस मीट्रिक टन अधिक वितरण किया गया है तथा नमक वितरण योजना के अंतर्गत डबल फोर्टीफाइड नमक का चार हजार, तीन सौ तीन मीट्रिक टन अधिक वितरण किया गया है और खाद्य तेल वितरण योजना के अंतर्गत सतहत्तर हजार से अधिक पाउच का वितरण किया गया है।
- “प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना” के अंतर्गत वर्ष 2025-26 के प्रथम चरण में गत वर्ष की तुलना में आठ लाख अधिक लाभार्थियों अर्थात् कुल अड़तीस लाख उनतालीस हजार लाभार्थियों को लाभ प्रदान किया गया है।
- जनविश्वास 2.0 पहल के अंतर्गत लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट के तहत छोटे व्यापारियों और उद्योगों को व्यवसाय करने में सुगमता बढ़ाने के उद्देश्य से अनावश्यक अनुमतियों एवं दंडात्मक प्रावधानों से राहत प्रदान की गई है।
- राज्य ग्राहक सुरक्षा हेल्पलाइन पर चालू वित्तीय वर्ष में दस हजार से अधिक उपभोक्ताओं को शिकायतों के संबंध में मार्गदर्शन प्रदान करने का कार्य किया गया है।

ऊर्जा एवं पेट्रो केमिकल्स

- यह ऊर्जावान गुजरात है। राज्य के नागरिकों के जीवन से अंधेरे को खत्म करने और उजाले बिखराने के लिए यह सरकार प्रतिबद्ध है। गुजरात राज्य में वर्ष 2002 से वर्ष 2025 के दौरान हुए उल्लेखनीय और ऐतिहासिक विकास में विद्युत क्षमता वृद्धि का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। राज्य की अधिकतम विद्युत मांग वर्ष 2002 में 7.7 गीगावॉट थी, जो वर्ष 2025 तक बढ़कर 26.4 गीगावॉट हो गई है, जो लगभग तीन गुना वृद्धि को दर्शाती है। यह गुजरात के तीव्र औद्योगिक विकास और आर्थिक प्रगति का प्रतिबिंब है।
- गुजरात में वर्ष 2002 में सब-स्टेशनों की संख्या सात सौ, छत्तीस थी, जो वर्ष 2025 में तीन गुना वृद्धि के साथ दो हजार, चार सौ चौहत्तर हो गई है। ट्रांसमिशन लाइनें 31 हजार किमी से बढ़कर 79 हजार किलोमीटर हो गई हैं तथा डिस्ट्रीब्यूशन लाइनें (HT + LT) तीन लाख इकसठ हजार किलोमीटर से बढ़कर

सवा दो गुना वृद्धि के साथ आठ लाख, छब्बीस हजार किलोमीटर हो गई है, जिससे ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में बिजली की पहुंच अधिक सुदृढ़ हुई है। ट्रांसफॉर्मर केंद्र दो लाख, अठाईस हजार से दस गुना वृद्धि के साथ इक्कीस लाख, पचीस हजार हो गए हैं।

- गुजरात स्टेट इलेक्ट्रिसिटी कॉरपोरेशन लिमिटेड (GSECL) को इंडिया इलेक्ट्रिसिटी पावरिंग इंडिया अवॉर्ड्स 2025 में “बेस्ट जनरेशन कंपनी ऑफ द ईयर – स्टेट जेनको” के प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।
- गुजरात राज्य को इंडियन विंड टर्बाइन मैनुफैक्चरर्स एसोसिएशन (IWTMA) द्वारा सर्वाधिक पवन ऊर्जा क्षमता स्थापित करने के लिए “विंड इंडिया अवॉर्ड 2025” के प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।
- राज्य की चारों सरकारी विद्युत वितरण कंपनियों UGVCL, MGVCL, DGVCL एवं PGVCL को भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा A+ रेटिंग के साथ देश की श्रेष्ठ चार कंपनियों में स्थान प्राप्त हुआ है।
- गुजरात का इतिहास सूर्य और प्रकृति पूजा का इतिहास है। इस पुरातन इतिहास को नूतन टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ते हुए गुजरात आज पूरे देश में 42.5 गीगावॉट स्थापित नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता के साथ प्रथम स्थान पर है। इसमें 14.8 गीगावॉट स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता तथा 25.5 गीगावॉट स्थापित सौर ऊर्जा क्षमता के साथ भी गुजरात देश में प्रथम स्थान पर है।
- गुजरात राज्य के कच्छ जिले में खावड़ा में सैंतीस गीगावॉट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता वाला विश्व का सबसे बड़ा रिन्युएबल एनर्जी पार्क विकसित किया जा रहा है, जिसमें वर्तमान में ग्यारह गीगावॉट से अधिक नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन क्षमता प्राप्त की जा चुकी है।
- रिन्युएबल एनर्जी प्रोजेक्ट रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रोजेक्ट कमिशनिंग तक के वन स्टॉप सॉल्युशन के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस पोर्टल “अक्षय ऊर्जा सेतु पोर्टल” प्रारंभ किया गया है।
- राज्य के किसानों को विश्वसनीय विद्युत आपूर्ति, उद्योगों को निरंतर ऊर्जा तथा आम नागरिकों को गुणवत्तापूर्ण सेवा उपलब्ध कराने के लिए विद्युत वितरण कंपनियों द्वारा बीस हजार, सात सौ किलोमीटर से अधिक MVCC केबल बिछाई गई है।

- तटीय क्षेत्रों एवं सीमा चौकी (बॉर्डर आउटपोस्ट) क्षेत्रों में सुरक्षा चिंताओं और अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए एलिवेटेड Elevated 11KV XLPE केबल नेटवर्क को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लागू किया गया है।
- भारत सरकार की RDSS योजना के अंतर्गत बिजली आपूर्ति क्षेत्र में नुकसान घटाने, विस्तरण नेटवर्क मजबूत करने और ग्राहकों को गुणवत्तापूर्ण, निरंतर बिजली आपूर्ति उपलब्ध करवाई जाती है। इस योजना के अंतर्गत राज्य में बिजली विस्तरण अंतर्दाचागत मजबूतीकरण और आधुनिकीकरण के लिए भारत सरकार द्वारा साठ फीसदी वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाई गई है। इसका मेरी सरकार ने महत्तम उपयोग करके दिसम्बर 2025 तक तीन हजार, सात सौ चौरासी करोड़ के कार्य पूर्ण किए गए हैं।
- मेरी सरकार द्वारा दिसंबर 2025 में तीन अत्यंत महत्वपूर्ण नई नीतियां (1) गुजरात इंटीग्रेटेड रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी 2025, (2) गुजरात पंप्ड स्टोरेज प्रोजेक्ट (PSP) पॉलिसी 2025 तथा (3) गुजरात ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी 2025 घोषित की गई हैं। जो दर्शाती है कि इस राज्य का विकास नीति संचालित विकास है।
- उक्त नीतियों के माध्यम से राज्य में 100 GW से अधिक नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता के विकास का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके अतिरिक्त ग्रीन हाइड्रोजन हेतु 30 GW इलेक्ट्रोलाइजर क्षमता को समर्थन देने के लिए 75 GW नवीकरणीय ऊर्जा का लक्ष्य रखा गया है, जिससे लगभग 5 MMTPA CO₂ उत्सर्जन में कमी लाने में महत्वपूर्ण योगदान मिलेगा। राज्य में वर्ष 2035 तक लगभग पचहत्तर हजार करोड़ के निवेश से 75 GWh पंप्ड स्टोरेज क्षमता विकसित करने का भी लक्ष्य रखा गया है, जो गुजरात को स्वच्छ ऊर्जा, ऊर्जा भंडारण एवं ग्रीन हाइड्रोजन के अग्रणी केंद्र के रूप में स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
- शीत ऋतु की कड़ाके की ठंड में किसानों को रात में खेतों में सिंचाई करने में होने वाली कठिनाइयों तथा जंगली पशु-पक्षियों के भय को दूर करने हेतु सरकार द्वारा दिन में बिजली उपलब्ध कराने के लिए किसान सूर्योदय योजना लागू की गई है। इस योजना के अंतर्गत राज्य के निम्नानबे फीसदी गांवों में किसानों को दिन में बिजली उपलब्ध कराई जा रही है।
- राज्य में पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत पांच लाख से अधिक रूफटॉप सोलर सिस्टम स्थापित कर गुजरात देश में प्रथम स्थान पर है।

- GSECL द्वारा भावनगर (पडवा) में सात सौ पचास किलोवॉट का राज्य का पहला फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट प्रारंभ किया गया है तथा लगभग दो हजार पांच सौ मेगावॉट से अधिक क्षमता के अन्य फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट्स योजना चरण में हैं।
- राज्य की गुजरात स्टेट पेट्रोनेट लिमिटेड (GSPL) द्वारा गैस परिवहन हेतु अक्टूबर 2025 तक कुल दो हजार, सात सौ पंचानबे किमी लंबा प्राकृतिक गैस ट्रांसमिशन पाइपलाइन नेटवर्क विकसित किया गया है।

उद्योग

- उद्योग और व्यापार गुजरातियों के रक्त में है। वाइब्रेंट गुजरात के सफल मॉडल को और अधिक विस्तार देने के उद्देश्य से आयोजित वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय परिषद (VGRC) 2025-26 में महेसाणा में कुल तीन लाख, पचीस हजार करोड़ के तथा राजकोट में पांच लाख, अठहत्तर हजार करोड़ के एम.ओ.यू. किए गए हैं।
- राज्य में टेक्सटाइल उद्योगों को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने हेतु विभिन्न टेक्सटाइल नीतियों के अंतर्गत आठ हजार से अधिक इकाइयों को एक हजार, आठ सौ करोड़ से अधिक की सहायता का भुगतान किया गया है तथा अनुमानित पैसठ हजार से अधिक रोजगार सृजित हुए हैं।
- राज्य में अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों को गति देने तथा राज्य के युवा उद्यमियों को उनके नवोन्मेषी विचारों के लिए प्रोत्साहन प्रदान करने के उद्देश्य से स्टार्ट-अप एवं इनोवेशन योजना के अंतर्गत अड़सठ करोड़ से अधिक की सहायता का भुगतान किया गया है। इस योजना के अंतर्गत वर्ष 2018, 2019, 2021, 2022 तथा वर्ष 2023-24 लगातार पांचवीं अवधि में नेशनल स्टार्ट-अप रैंकिंग फ्रेमवर्क के तहत पूरे देश में गुजरात को प्रथम स्थान पर “बेस्ट परफॉर्मर” के रूप में घोषित किया गया है।
- बड़े आकार के उद्योगों को सहायता योजना के अंतर्गत कुल दो सौ तेबीस इकाइयों को दिए गए पंजीकरण के माध्यम से कुल तिरेसठ हजार करोड़ से ज्यादा करोड़ से ज्यादा के प्रस्तावित पूंजी निवेश तथा अनुमानित इकहत्तर हजार, पांच सौ प्रत्यक्ष रोजगार एवं एक लाख, अठहत्तर हजार अनुमानित अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होंगे।
- राज्य ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एवं ईज ऑफ लिविंग को अपनाकर उन्हें और सशक्त बनाने हेतु विश्वास-आधारित शासन (ट्रस्ट बेज्ड गवर्नेंस) के दृष्टिकोण तथा रिड्यूसिंग कम्प्लायंस बर्डन अध्ययन के अंतर्गत मेरी सरकार द्वारा गुजरात जन

विश्वास (प्रावधानों में सुधार) अधिनियम, 2025 लागू किया है। इस अधिनियम के अंतर्गत ग्यारह राज्य अधिनियमों एवं नियमों की कुल पांच सौ सोलह धाराओं को अपराधमुक्त किया गया है। इन समान कानूनी सुधारों के अंतर्गत छोटी एवं तकनीकी त्रुटियों के लिए कारावास के प्रावधान को निरीक्षणात्मक दंड से प्रतिस्थापित किया गया है, जिससे उत्पादकों, दुकानदारों एवं औद्योगिक श्रमिकों को प्रत्यक्ष लाभ प्राप्त हुआ है तथा सरकार के प्रति विश्वास और अधिक सुदृढ़ हुआ है।

- एम.एस.एम.ई. (MSME) उद्योगों को सहायता प्रदान करने हेतु विभिन्न योजनाओं के लिए कुल एक हजार, पांच सौ पचास करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। आत्मनिर्भर गुजरात स्कीम फॉर असिस्टेंस टू एम.एस.एम.ई. योजना के अंतर्गत कुल बाईस हजार, सात सौ तीस क्लेम आवेदनों पर एक हजार, तीन सौ उन्नीस करोड़ की सहायता का भुगतान किया गया है, जिससे अनुमानित सताईस हजार, चार सौ सड़सठ करोड़ का पूंजी निवेश आया है तथा एक लाख से ज्यादा रोजगार का सृजन हुआ है।
- मार्केट डेवलपमेंट असिस्टेंस योजना के अंतर्गत प्रदर्शनों में भाग लेने वाली इकाइयों एवं आयोजकों को लाभ प्रदान किया जाता है। इस योजना के तहत कुल एक हजार से ज्यादा इकाइयों को एक हजार, आठ सौ चौरासी लाख से ज्यादा की सहायता का भुगतान किया गया है।
- गुजरात औद्योगिक विकास निगम (GIDC) द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 में लगभग तीन सौ बयालीस हेक्टेयर से अधिक भूमि नई औद्योगिक वसाहतों के लिए प्राप्त की गई है। वर्ष 1962 से दिसंबर-2025 के दौरान कुल छियालिस हजार, आठ सौ उन्नीस हेक्टेयर भूमि औद्योगिक विकास हेतु अधिग्रहित की गई है।
- गुजरात औद्योगिक विकास निगम द्वारा अब तक राज्य में दो सौ उनतालिस से अधिक औद्योगिक बस्तियों की स्थापना की गई है।
- वर्ष 2025 के दौरान चार सौ सैंतालिस औद्योगिक ईकाइयों के लिए दो सौ चौहत्तर हेक्टेयर भूमि पर आधारभूत संरचना सुविधाओं का विकास किया गया है।
- साणंद एक अंतरराष्ट्रीय इंडस्ट्रियल हब के तौर पर उभर रहा है। साणंद औद्योगिक क्षेत्र में Micron, Kaynes Technology, CG Power, Taiyo Nippon Sanso India, BASF जैसी विश्व-स्तरीय बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए आधारभूत संरचना विकसित की जा रही है।

- एक समय में जिसको खारा पट्टे की खारी जमीन के तौर पर जाना जाता था, वह धोलेरा आज विकास की नई उंचाइयों के साथ नई पहचान प्राप्त कर रहा है। धोलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजनल डेवलपमेंट अथॉरिटी क्षेत्र में भारत सरकार के “इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन” के अंतर्गत कुल पांच में से चार सेमीकंडक्टर परियोजनाएं गुजरात में स्थापित की जा रही हैं। इनमें देश की पहली सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन यूनिट धोलेरा में टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स द्वारा इकरानवे हजार करोड़ के निवेश से स्थापित की जा रही है।
- गुजरात रेल इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा बेडी पोर्ट से विंडमिल स्टेशन (2.57 किमी) तक रेलवे एवं गति-शक्ति टर्मिनल परियोजना पूर्ण कर कमीशनिंग की गई है। साथ ही पीएम गति-शक्ति परियोजना के अंतर्गत (मोरबी के निकट) रफालेश्वर में गति-शक्ति कार्गो टर्मिनल का कार्य भी पूर्ण किया गया है।
- भूस्तर विज्ञान एवं खनिज विभाग के माध्यम से चालू वर्ष 2025-26 के दौरान कुल दो हजार, सड़सठ करोड़ की राजस्व आय प्राप्त हुई है।
- सार्वजनिक नीलामी के माध्यम से प्रमुख खनिजों के कुल नौ ब्लॉकों तथा गौण खनिजों के कुल चार सौ सतावन ब्लॉकों में खनिज उत्पादन की प्रक्रिया प्रारंभ की गई है, जिससे आने वाले समय में राजस्व आय में वृद्धि का संकेत मिलता है।
- चालू वित्तीय वर्ष के दौरान गुजरात खनिज विकास निगम लिमिटेड द्वारा बीस हजार करोड़ के मार्केट कैप का लक्ष्य प्राप्त किया गया है।
- पिछले वित्तीय वर्ष में गुजरात खनिज विकास निगम के माध्यम से राज्य सरकार को दो सौ सैंतीस करोड़ की डिविडेंड आय प्राप्त हुई है।
- गरबा गुजरात की सांस्कृतिक पहचान है। यूनेस्को द्वारा गुजरात के गरबा को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत (Intangible Cultural Heritage) के रूप में घोषित किए जाने के उपलक्ष्य में गुजरात टूरिज्म द्वारा पहली बार प्री-नवरात्रि का आयोजन राज्य के बाहर उदयपुर, राजस्थान में तथा पोस्ट-नवरात्रि का आयोजन दिल्ली में किया गया था।
- राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर दिल्ली के बाहर पहली बार “भारत पर्व” का आयोजन स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, एकतानगर में एक से पंद्रह नवंबर 2025 के दौरान किया गया था। भारत पर्व में विभिन्न राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा भाग लेकर अपनी लोकसंस्कृति, खान-पान तथा हस्तकला का प्रदर्शन करते हुए “भारत की विविधता में एकता” का सजीव दर्शन कराया गया।

पर्यटन

- कृष्ण-रुक्मणी तीर्थधाम के समग्र विकास हेतु प्रथम चरण में सैंतालिस करोड़ निन्यानबे हजार के कार्य पूर्ण किए गए हैं।
- आद्यशक्ति धाम अंबाजी में आदि शक्ति राष्ट्रीय महिला तीरंदाजी प्रतियोगिता का आयोजन दिनांक आठ से दस अप्रैल 2025 के दौरान किया गया था। इस तीन दिवसीय प्रतियोगिता में देश के विभिन्न राज्यों से सात सौ से अधिक युवा महिला तीरंदाजों ने भाग लिया था। वर्ष 2026 में दिनांक इक्कीस से तेईस जनवरी के दौरान राष्ट्रीय महिला तीरंदाजी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है।
- एडवेंचर पर्यटन के विकास हेतु मई-जून 2025 में धरोई में आयोजित एडवेंचर फेस्ट तथा दिसंबर 2025 में मांडवी में आयोजित बीच फेस्टिवल के दौरान खेल गतिविधियों का सफल आयोजन किया गया है।
- मोकरसागर-पोरबंदर तथा धोळावीरा-कच्छ में दो सौ करोड़ के व्यय से वर्तमान में पर्यटन सुविधाओं के विकास का कार्य प्रगति पर है।
- गुजरात में पर्यटन क्षेत्र में हुए विकास के परिणामस्वरूप राज्य में आने वाले पर्यटकों की संख्या वर्ष 2024 में सोलह करोड़, सत्तर लाख थी, जो बढ़कर वर्ष 2025 में बाईस करोड़, अठाईस लाख हो गई है।
- अंबाजी तीर्थधाम में “अंबाजी कॉरिडोर” परियोजना के अंतर्गत एक हजार, छह सौ बत्तीस करोड़ के व्यय से दो चरणों में विभिन्न विकास कार्य प्रगति पर हैं।
- श्री माता का मढ़, जिला कच्छ में स्थित श्री आशापुरा माताजी मंदिर के दर्शन हेतु आने वाले श्रद्धालुओं को पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से बत्तीस करोड़, सत्तर लाख के व्यय से समग्र विकास कार्य किए गए हैं।
- हैदराबाद में आयोजित राष्ट्रीय स्तर की ‘विंग्स इंडिया-2026’ इवेंट में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री के करकमलों द्वारा गुजरात को “बेस्ट स्टेट फॉर प्रमोशन ऑफ एविएशन इकोसिस्टम” पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।
- मेरी सरकार द्वारा ‘वोकल फॉर लोकल’ तथा ‘हर घर स्वदेशी, घर-घर स्वदेशी’ के मंत्र को साकार करने हेतु स्वदेशी खादी के उत्पादन पर सहायता एवं बिक्री के लिए मेलों के माध्यम से प्रोत्साहन प्रदान किया जा रहा है। राज्य सरकार के विभिन्न प्रयासों के परिणामस्वरूप पिछले चार वर्षों में खादी का कुल विक्रय ₹367 करोड़ से बढ़कर छह सौ, तैयासी करोड़ हो गया है। इस प्रकार खादी की बिक्री में पिछले चार वर्षों में छियासी प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है।

कुटीर एवं ग्रामोद्योग

- श्री वाजपेयी बैंकेबल योजना के अंतर्गत ऋण सीमा आठ लाख से बढ़ाकर पचीस लाख तथा सहायता की अधिकतम सीमा 1.25 लाख से बढ़ाकर 3.75 लाख कर दी गई है। इस योजना के माध्यम से वर्ष 2025-26 में जनवरी-2026 तक कुल सैंतालिस हजार से अधिक लाभार्थियों को तीन सौ सड़सठ से अधिक रुपये का करोड़ का लाभ प्रदान किया गया है।
- गुजरात राज्य हस्तकला एवं हथकरघा निगम द्वारा वर्ष 2025-26 में जनवरी-2026 तक तीस करोड़ से ज्यादा की हथकरघा एवं हस्तकला वस्तुओं की रिकॉर्ड ब्रेक बिक्री की गई है।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण

- मेरी सरकार 'सर्वे सन्तु निरामय' के मंत्र को सही अर्थों में साकार कर रही है। उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवाएं जन-जन तक पहुंचाने के लिए यह सरकार प्रतिबद्ध है। दिसंबर 2025 तक ओ.पी.डी. एवं आई.पी.डी. के माध्यम से लगभग नौ करोड़, पचास लाख मामलों में स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की गई हैं। तेरह लाख से अधिक बड़ी एवं छोटी सर्जरी, छह करोड़, पचीस लाख से अधिक प्रयोगशाला परीक्षण तथा दो करोड़, छियानबे लाख से अधिक लोगों की गैर-संचारी रोगों के लिए स्क्रीनिंग की गई है। इसके अतिरिक्त लगभग नौ लाख, तिरसठ हजार गर्भवती महिलाओं एवं नौ लाख, इकतालिस हजार बच्चों का टीकाकरण किया गया है।
- किडनी एवं कैंसर रोगियों को विकेंद्रीकृत सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु दो सौ इक्यासी डायलिसिस केंद्र तथा पैंतीस डे-केयर कीमोथेरेपी केंद्र स्थापित किए गए हैं।
- दूरस्थ क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ बनाने के लिए दिसंबर 2025 तक बाईस टेलीमेडिसिन हब के माध्यम से एक करोड़, चौबीस लाख से अधिक परामर्श किए गए हैं।
- आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत दिसंबर 2025 तक दो करोड़, सत्तर लाख से अधिक लाभार्थियों को आयुष्मान कार्ड प्रदान किए गए हैं तथा तीन हजार दो सौ करोड़ से ज्यादा के दावों को स्वीकृति दी गई है।
- नमोश्री योजना के अंतर्गत मातृ मृत्यु दर एवं शिशु मृत्यु दर में कमी लाने के उद्देश्य से डीबीटी के माध्यम से पात्र सात लाख से अधिक महिलाओं को लगभग चार सौ पचास करोड़ की वित्तीय सहायता प्रदान की गई है।
- मल्टी-स्पेशियलिटी एवं सुपर-स्पेशियलिटी सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु गांधीनगर, अहमदाबाद-सोला, वडोदरा, सूरत, राजकोट, भावनगर एवं जामनगर स्थित सरकारी अस्पतालों की क्षमता एवं कार्यक्षमता में वृद्धि की जा रही है।

- डॉक्टरों की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। एम.बी.बी.एस. डॉक्टरों के पंचानवें प्रतिशत से अधिक पद भरे जा चुके हैं। एम.बी.बी.एस. एवं विशेषज्ञ डॉक्टरों की पर्याप्त उपलब्धता हेतु राज्य में स्नातक एवं स्नातकोत्तर सीटों की संख्या क्रमशः सात हजार, पांच सौ पचहत्तर एवं तीन हजार पांच सौ पैतालिस हो गई है।
- सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली में दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक दवाओं की सूची (Essential Drug List) में एक सौ पचास नई दवाओं को शामिल किया गया है, जिसके परिणामस्वरूप सूची में कुल दवाओं की संख्या एक हजार चार सौ उनासी हो गई है।

शिक्षा

- बालक राज्य का भविष्य हैं और शिक्षा द्वारा इस भविष्य को उज्ज्वल बनाना सम्भव है। संस्कार और ज्ञान से शिक्षित और कौशल्य से दीक्षित गुजरात के लिए मेरी सरकार अविरत कार्य कर रही है। सरकारी शालाओं में स्थायी शिक्षकों की भर्ती, आधुनिक ढांचागत सुविधाओं और गुणवत्तापूर्ण शिक्षण के कारण वर्ष 2021-22 से 2025-26 के दौरान तीन लाख, तैंतालिस हजार विद्यार्थियों ने निजी शालाएं छोड़कर सरकारी शालाओं में प्रवेश लिया है।
- शिक्षा व्यवस्था को ज्यादा मजबूत बनाने के लिए वर्ष 2025-26 में राज्य में दस हजार, एक सौ इकतालिस विद्या सहायकों की नियुक्ति की गई है। साथ ही, कच्छ जिले के ग्राम्य और सीमावर्ती क्षेत्रों के लिए विशेष भर्ती द्वारा दो हजार से ज्यादा विद्या सहायकों की नियुक्ति की गई है।
- शाला प्रवेशोत्सव योजना के सकारात्मक परिणाम स्वरूप आज राज्य में नामांकन 100 फीसदी तक पहुंच गया है। ड्रॉप आउट दर 2001-02 में 37.22 से घटकर 2024-25 में 2.42 हुई है। वर्ष 2025-26 में कक्षा 1 में 5,15,648 और बाल वाटिका में 5,78,578 बालक अभ्यास में शामिल हुए हैं।
- राज्य सरकार ने RTE के अंतर्गत कमजोर वर्ग के बालकों की फीस चुकाने के लिए वर्ष 2013-14 से दस हजार की जगह वर्ष 2022-23 से वृद्धि करके तेरह हजार, छह सौ पचहत्तर की सीमा में चुकाने, विद्यार्थियों को शैक्षणिक सामग्री के लिए रुपये तीन हजार देने वाला गुजरात समग्र भारत का प्रथम राज्य बना है।
- RTE अधिनियम के अंतर्गत वर्ष 2013-14 से गैर अनुदानित निजी प्राथमिक शालाओं में कक्षा -एक में पचीस फीसदी सीटें कमजोर वर्ग और वंचित समूह के बालकों के लिए निःशुल्क उपलब्ध करवाई गई है। इसके अंतर्गत वर्ष 2025-26 में कुल पंचानबे हजार, चार सौ चौरानबे विद्यार्थियों को प्रवेश दिया गया है।

- विद्यार्थियों की सलामती राज्य सरकार की प्राथमिकता है। इस उद्देश्य से विद्यादीप योजना के अंतर्गत वर्ष 2025-26 से दुर्घटना बीमा सहायता दो लाख रुपए प्रति विद्यार्थी की गई है। वर्ष 2002-03 से 2024-25 के दौरान छह हजार, छह सौ पचास लाभार्थियों को लगभग उनतीस करोड़ की सहायता प्रदान की गई है।
- बेगलैस दिवस के कार्यक्रम के लिए शालाओं में प्रि-वोकेशनल कौशल्य विकसित करने के लिए प्रवृत्तियां शुरू की गई हैं। जोयफुल, बेगलैस शनिवार, विद्यार्थियों को आनंद मिले ऐसी विभिन्न प्रवृत्तियां जैसे कि योग, सूर्य नमस्कार, खेलकूद, पुस्तक पाठ जैसे प्रयोग शामिल किए गए हैं।
- पांच वर्ष से ज्यादा उमर के बालकों के लिए प्राथमिक शालाओं में बाल वाटिका वर्ग की शुरुआत की गई है। तथा बाल वाटिका रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू की गई है।
- भारतीय ज्ञान प्रणाली को पाठ्यक्रम में शामिल करने के लिए भगवद गीता के सार को कक्षा छह से दस में रुचिप्रद तौर पर प्रस्तुत करने वाला साहित्य शालाओं तक पहुंचाया गया है।
- कक्षा छह से नौ में वैदिक गणित पाठ्य पुस्तकें प्रत्येक शाला में उपलब्ध करवाई गई हैं।
- वर्ष 2025-26 में राज्य में पच्चासी नयी सरकारी माध्यमिक शालाएं और 5 नई सरकारी उच्च माध्यमिक शालाएं शुरू की जा रही हैं। साथ ही, आठ महानगरपालिका क्षेत्रों में अंग्रेजी माध्यम के सरकारी माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों को मंजूरी दी गई है।
- मुख्यमंत्री ज्ञानसेतु मेरिट स्कॉलरशिप योजना के अंतर्गत पिछले तीन वित्तीय वर्ष के दौरान कुल नब्बे हजार विद्यार्थियों को अड़सठ करोड़ से ज्यादा की छात्रवृत्ति प्रदान की गई है।
- मुख्यमंत्री ज्ञानसाधना मेरिट स्कॉलरशिप योजना के अंतर्गत पिछले तीन वित्तीय वर्ष के दौरान कुल पचहत्तर हजार विद्यार्थियों को सत्तावन करोड़ से ज्यादा की छात्रवृत्ति प्रदान की गई है।
- नमो लक्ष्मी योजना के अंतर्गत पिछले 2 वित्तीय वर्ष के दौरान दस लाख, चौरासी हजार से ज्यादा विद्यार्थियों को एक हजार, तीन सौ करोड़ से ज्यादा की सहायता प्रदान की गई है।

- नमो सरस्वती योजना के अंतर्गत पिछले दो वित्तीय वर्ष के दौरान एक लाख, पचास हजार से ज्यादा विद्यार्थियों को दो सौ पांच करोड़ की सहायता प्रदान की गई है।
- वर्ष 2024 की भर्ती के अंतर्गत सरकारी और गैर सरकारी अनुदानित माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शालाओं में कुल नौ हजार, चार सौ शिक्षण सहायक, चार सौ सत्तर आचार्य की भर्ती की गई है।

उच्च एवं तकनीकी शिक्षा :

- राज्य में उच्च शिक्षा में प्रवेश लेने वाले मेधावी एवं आर्थिक रूप से आवश्यकता-ग्रस्त विद्यार्थियों को उच्च अध्ययन हेतु आवश्यक वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री युवा स्वावलंबन योजना (MYSY) के अंतर्गत वर्ष 2025-26 में जनवरी अंत तक कुल बरानवे हजार से ज्यादा विद्यार्थियों को तीन सौ सतासी करोड़ से ज्यादा की सहायता प्रदान की गई है। वहीं, इस योजना के अंतर्गत आज दिन तक कुल छह लाख, तेवीस हजार से ज्यादा विद्यार्थियों को दो हजार, आठ सौ चवालिस करोड़ से ज्यादा की सहायता प्रदान की जा चुकी है।
- राज्य सरकार द्वारा MBBS पाठ्यक्रम में अध्ययनरत छात्राओं को आर्थिक सहायता प्रदान करने हेतु मुख्यमंत्री कन्या केळवणी निधि योजना (MKKN) के अंतर्गत जनवरी-2026 तक MBBS में अध्ययनरत कुल 4,391 छात्राओं को एक सौ सैंतीस करोड़ से ज्यादा की सहायता प्रदान की गई है। इसके साथ ही, योजना के अंतर्गत आज दिन तक कुल 27,997 छात्राओं को आठ सौ पैतीस करोड़ से ज्यादा की सहायता प्रदान की गई है।
- राज्य के युवाओं को संशोधन, नवीनता और उद्योग साहसिकता क्षेत्र में दक्ष बनाने के लिए वर्ष 2027 में आरम्भ स्टुडेंट स्टार्टअप एंड इनोवेशन पॉलिसी (SSIP) के अंतर्गत हुए कामकाज के लिए भारत सरकार द्वारा राज्यों को स्टार्टअप रैंकिंग फ्रेमवर्क के लिए दिए जाने वाले अवार्ड के अंतर्गत गुजरात राज्य लगातार पांच वर्ष से बेस्ट परफॉर्मर स्टेट के रूप में अवार्ड जीत रहा है। जो हम सबके लिए गौरवपूर्ण है।
- देश की सर्वप्रथम स्टुडेंट स्टार्टअप पॉलिसी (2.0) के अंतर्गत सहायता प्राप्त कर रही संस्थाओं द्वारा चार हजार, नौ सौ अड़तालिस प्रूफ ऑफ कंसेप्ट दो हजार, दो सौ बयासी आईपी फाइलिंग, आठ सौ अठाईस स्टार्टअप को सपोर्ट किया गया है।

- राज्य सरकार द्वारा इंटीग्रेटेड मॉड्यूल फॉर प्लेसमेंट एप्रेंटिसशिप कम ट्रेनिंग (IMPACT) योजना के अंतर्गत वर्ष 2025-26 के दौरान सोलह हजार, तीन सौ से ज्यादा विद्यार्थियों सहित आज तक करीब अठावन हजार विद्यार्थियों को तालिम दी गई है।

वंचितों का विकास

विकसित जाति कल्याण

- वंचितों के विकास के लिए वंचितों की सहयोगी बनकर यह सरकार वंचित विकास का उत्तम कार्य कर रही है। दिसम्बर 2025 तक बालवाटिका एवं प्राथमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति एवं गणवेश सहायता तथा माध्यमिक विद्यालय, उच्चतर माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा में अध्ययनरत विकसित जाति के कुल तैंतीस लाख पचहत्तर हजार विद्यार्थियों को विभिन्न शैक्षणिक योजनाओं के अंतर्गत सात सौ साठ करोड़ से ज्यादा की छात्रवृत्ति प्रदान की गई है।
- सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए राज्य सरकार द्वारा सात सौ पचास ग्रंट-इन-एड छात्रावास, अड़सठ सरकारी छात्रावास, एक सौ सतासी आश्रम शालाएं तथा पैंतीस आवासीय विद्यालय संचालित किए जा रहे हैं, जिनमें लगभग बयासी हजार विद्यार्थियों को निःशुल्क आवास, भोजन एवं शिक्षा की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। इस हेतु वर्तमान में दो सौ चौहत्तर करोड़ से ज्यादा रुपए का खर्च किया गया है।
- पंडित दीनदयाल आवास योजना के अंतर्गत आवास निर्माण सहायता को एक लाख बीस हजार से बढ़ाकर एक लाख सत्तर हजार किया गया है। सीमांत अति-पिछड़े, घुमंतू एवं विमुक्त जाति, सामाजिक एवं शैक्षणिक पिछड़ा वर्ग तथा आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के पंद्रह हजार, पांच सौ को मकान निर्माण हेतु दिसम्बर 2025 तक एक सौ तरेपन करोड़ से ज्यादा की सहायता प्रदान की गई है।
- कुंवरबाई का मामेरू योजना तथा सात फेरे सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत दिसम्बर 2025 तक सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग तथा आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग की छप्पन हजार कन्याओं को अड़सठ करोड़ से ज्यादा की सहायता प्रदान की गई है।

अनुसूचित जाति कल्याण

- प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति एवं गणवेश सहायता योजना तथा पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत चार सौ उन्नीस करोड़ से ज्यादा का खर्च कर चार लाख, पचासी हजार विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्रदान की गई है।
- डॉ. सविता अंबेडकर अंतरजातीय विवाह सहायता योजना के अंतर्गत दो लाख, पचास हजार रुपए की सहायता प्रदान की जाती है। दिसम्बर 2025 अंत तक इस योजना में सोलह करोड़ से ज्यादा का खर्च कर पांच सौ सैंतालिस दम्पतियों को लाभ दिया गया है, जिससे सामाजिक समरसता को प्रोत्साहन मिला है।
- डॉ. अंबेडकर आवास योजना के अंतर्गत एक लाख, सत्तर हजार की सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना में दिसम्बर 2025 अंत तक अठावन करोड़ से ज्यादा का खर्च कर चार हजार से ज्यादा लाभार्थियों को मकान निर्माण हेतु सहायता प्रदान की गई है।
- डॉ. अंबेडकर विदेश अध्ययन ऋण योजना के अंतर्गत विदेश में उच्च शिक्षा हेतु पंद्रह लाख तक का ऋण चार फीसदी ब्याज दर पर प्रदान किया जाता है। इस योजना में बासठ करोड़ से ज्यादा का खर्च कर चार सौ अठारह विद्यार्थियों को विदेश में अध्ययन हेतु ऋण प्रदान किया गया है।

सामाजिक सुरक्षा

- संत सूरदास योजना के अंतर्गत साठ प्रतिशत या उससे अधिक दिव्यांगता वाले व्यक्तियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु दिसम्बर 2025 के अंत तक कुल छिहत्तर हजार से ज्यादा लोगों को तिरसठ करोड़ से ज्यादा की सहायता प्रदान की गई है।
- बौद्धिक दिव्यांगता (मानसिक दिव्यांग) से ग्रसित व्यक्तियों को आर्थिक सहायता देने हेतु संचालित पेंशन योजना के अंतर्गत दिसम्बर 2025 के अंत तक कुल सतहत्तर हजार से ज्यादा लाभार्थियों को उनहत्तर करोड़ से ज्यादा की सहायता प्रदान की गई है।

- निराश्रित वृद्धों एवं निराश्रित दिव्यांगजनों के भरण-पोषण हेतु आर्थिक सहायता योजना के अंतर्गत दिसम्बर 2025 तक कुल पांच लाख से ज्यादा लाभार्थियों को पांच सौ छब्बीस करोड़ की सहायता प्रदान की गई है।
- राज्य सरकार की सेवाओं में दिव्यांगजनों के लिए इक्कीस हजार पदों को भरने हेतु विशेष भर्ती अभियान चलाया गया है।
- माता-पिता की छत्रछाया खोने वाले अठारह वर्ष या उससे कम आयु के बच्चों को पालक माता-पिता योजना के अंतर्गत कुल इक्कीस हजार पांच सौ लाभार्थियों को उनसठ करोड़ की सहायता प्रदान की गई है। साथ ही, इस योजना की लाभार्थी बालिकाओं को विवाह के समय सहायता योजना के अंतर्गत कुल दो सौ पचास लाभार्थी बालिकाओं को वर्ष 2025 के अंत तक पांच करोड़ की सहायता प्रदान की गई है।
- अनुसूचित जाति और विकसित जाति के लाभार्थियों के लिए संचालित शैक्षणिक ऋण एवं स्वरोजगार-उन्मुख ऋण योजनाओं हेतु चालू वर्ष में सात सौ पचास करोड़ तथा दिव्यांगजनों के लिए संचालित स्वरोजगार-उन्मुख ऋण योजना हेतु छह करोड़ का प्रावधान किया गया है।

आदिजाति विकास

- वनबंधु कल्याण योजना के अंतर्गत वर्ष 2024-25 में बाईस हजार करोड़ से ज्यादा का प्रावधान किया गया था तथा चालू वर्ष 2025-26 के लिए तीस हजार करोड़ से ज्यादा का प्रावधान किया गया है। इसके अतिरिक्त 'गुजरात पैटर्न' के अंतर्गत वर्ष 2025-26 के लिए एक हजार, उनसठ करोड़ का प्रावधान किया गया है।
- राज्य सरकार तथा भारत सरकार की प्री-मैट्रिक एवं पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं के अंतर्गत अब तक आठ सौ चौवन करोड़ के व्यय से बारह लाख से ज्यादा अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को लाभ प्रदान किया गया है।
- सरकारी एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल, आदर्श आवासीय विद्यालय तथा अनुदानित आश्रम शालाओं में अध्ययनरत लगभग एक लाख साठ हजार अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को अब तक चार सौ छप्पन करोड़ से अधिक के खर्च से निःशुल्क आवास एवं शिक्षा की सुविधा प्रदान की जा रही है।
- एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूलों द्वारा वर्ष 2024-25 में कक्षा दसवीं का 97.18 फीसदी, कक्षा बारहवीं विज्ञान संकाय का 82.17 फीसदी, कक्षा बारहवीं वाणिज्य संकाय का 98.36 फीसदी तथा कक्षा बारहवीं सामान्य संकाय का

99.86 फीसदी औसत बोर्ड परिणाम प्राप्त किया गया है। वहीं आदर्श आवासीय विद्यालयों द्वारा कक्षा दस में 97.23 फीसदी तथा कक्षा बारहवीं विज्ञान संकाय में 83.22 फीसदी परिणाम प्राप्त किया गया है।

- अनुसूचित जनजाति के छात्र-छात्राओं को छात्रावास में रहकर अध्ययन की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु ग्रांट-इन-एड छात्रावासों के लिए चालू वित्तीय वर्ष में अब तक चौहत्तर करोड़ से ज्यादा का खर्च किया गया है, जिससे छप्पन हजार से ज्यादा विद्यार्थी लाभान्वित हो रहे हैं।
- उच्च अध्ययन हेतु अन्य शहरों में रहकर पढ़ाई करने वाले अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए आवास एवं भोजन सुविधा युक्त सरकारी छात्रावासों एवं समरस छात्रावासों पर चालू वर्ष में अब तक पैंसठ करोड़ से अधिक का खर्च किया गया है, जिससे इक्कीस हजार से ज्यादा विद्यार्थी लाभ प्राप्त कर रहे हैं।
- अनुसूचित जनजाति के परिवारों के लिए व्यक्तिगत आवास एवं हलपति आवास योजना के अंतर्गत तेवीस करोड़ से ज्यादा का खर्च कर अनुमानित तीन हजार से ज्यादा लाभार्थियों को लाभ प्रदान किया गया है।
- गंभीर बीमारियों से पीड़ित अनुसूचित जनजाति समाज के रोगियों को चिकित्सा उपचार एवं पौष्टिक आहार हेतु सहायता प्रदान करने के लिए अब तक चौदह करोड़ से ज्यादा का खर्च कर दो हजार से ज्यादा लाभार्थियों को सहायता प्रदान की गई है।
- कृषि विविधीकरण योजना के अंतर्गत आदिवासी किसानों को उन्नत बीज, उर्वरक किट तथा कृषि संबंधी प्रशिक्षण प्रदान किया गया है तथा बयालीस करोड़ के खर्च से कुल छियासी हजार से ज्यादा किसानों को योजना के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है।
- आदिवासी क्षेत्रों में महिलाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से चालू वर्ष में छत्तीस करोड़, अस्सी लाख के खर्च से बारह हजार से ज्यादा दुधारू पशु चार हजार से ज्यादा महिला लाभार्थियों को प्रदान किए गए हैं।
- इंटीग्रेटेड डेयरी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट (आई.डी.डी.पी.) के अंतर्गत राज्य की डेयरियों द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 में अब तक पांच हजार, छह सौ अठाईस लाभार्थियों को सोलह करोड़ बत्तीस लाख के ऋण का लाभ प्रदान किया गया है।

महिला एवं बालकल्याण

- “यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते”, मंत्र के साथ नारी उत्कर्ष और कल्याण के लिए मेरी सरकार प्रतिबद्ध है। राज्य की कुल तरेपन हजार से ज्यादा आंगनवाड़ियों में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु मेरी सरकार प्रतिबद्ध है। राज्य की कुल तिरेपन हजार से ज्यादा आंगनवाड़ियों में शौचालय एवं विद्युत कनेक्शन तथा पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। वर्ष 2025-26 में 1,063 आंगनवाड़ी केंद्रों का लोकार्पण किया गया है, जबकि एक हजार, सतानवे आंगनवाड़ी केंद्रों का भूमिपूजन किया गया है, जिनका निर्माण कार्य प्रगति पर है।
- किसी भी आंगनवाड़ी केंद्र को कार्यकर्ता एवं सहायिका के बिना न रहने देने के उद्देश्य से चालू वर्ष में नौ हजार से अधिक आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं की मानदेय सेवाएं लेने की प्रक्रिया सरकार द्वारा पूर्ण की गई है तथा माननीय मुख्यमंत्रीश्री के करकमलों से नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए हैं।
- राज्य में पोषण स्तर को सुदृढ़ करने हेतु पूरक पोषण योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को ‘बालशक्ति’ एवं ‘मातृशक्ति’ रेडी-टू-कुक पैकेट टेक-होम राशन के रूप में प्रदान किए जा रहे हैं। इस योजना के अंतर्गत वर्ष 2025-26 में नवंबर 2025 तक तीस लाख से अधिक बच्चों, गर्भवती एवं धात्री माताओं को लाभ प्रदान किया गया है।
- बच्चों के साथ-साथ गर्भवती एवं धात्री माताओं के पोषण स्तर में सुधार हेतु राज्य के एक सौ इकतालिस घटकों में दूध संजीवनी योजना लागू की गई है। वर्ष 2025-26 के दौरान अब तक आठ लाख से ज्यादा बच्चों, गर्भवती एवं धात्री माताओं ने इस योजना का लाभ लिया है।
- पोषण सुधा योजना के अंतर्गत आदिवासी जिलों की गर्भवती एवं धात्री माताओं को आंगनवाड़ी केंद्रों में प्रतिदिन एक समय पौष्टिक गर्म भोजन प्रदान किया जाता है। वर्ष 2025-26 में नवंबर 2025 तक नवासी हजार माताओं को इस योजना का लाभ दिया गया है।
- महिलाओं की गर्भावस्था से लेकर बच्चे दो वर्ष के हो जाएं तब तक, 1,000 दिनों में पोषण उपलब्ध करवाने हेतु वर्ष 2022-23 से मुख्यमंत्री मातृशक्ति योजना (MMY) अमल कर राशन किट प्रदान किया जा रहा है। वर्ष 2025-26 के दौरान लाभार्थियों हेतु एक सौ छप्पन करोड़ का व्यय किया गया है।
- पूर्णा योजना के अंतर्गत पंद्रह से अठारह वर्ष की सभी किशोरियों को वर्ष में तीन सौ दिन पूरक पोषण दिया जाता है। वर्ष 2025-26 में राज्य की अनुमानित नौ लाख से ज्यादा किशोरियों को इस योजना के अंतर्गत शामिल किया गया है तथा

दिसंबर 2025 तक कुल दो सौ पचास करोड़ से ज्यादा का खर्च किया गया है।

- राज्य में पोषण के प्रति जागरूकता बढ़ाने हेतु तीन करोड़, सात लाख लोगों की सहभागिता के साथ एक करोड़, पैंतीस लाख प्रवृत्तियां करके पोषण माह मनाया गया है।
- राज्य की गंगा स्वरूपा महिलाएं सम्मान से जी सकें इस उद्देश्य से आर्थिक तौर पर मदद करने हेतु गंगा स्वरूपा आर्थिक सहायता योजना लागू की गई है। राज्य में वर्तमान में लगभग सत्रह लाख लाभार्थी गंगा स्वरूपा बहनों को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से प्रतिमाह एक हजार, दो सौ पचास की दर से वर्ष में कुल दो हजार, पांच सौ करोड़ से ज्यादा की सहायता प्रदान की गई है।
- राज्य में बालिका जन्म दर एवं शिक्षा को प्रोत्साहन देने हेतु व्हाली दीकरी योजना के अंतर्गत तीन लाख से अधिक लाभार्थी बालिकाओं की सहायता स्वीकृत की गई है।
- राज्य की महिलाओं को विपरीत परिस्थितियों में त्वरित सहायता उपलब्ध कराने हेतु अत्याधुनिक तकनीक से सुसज्जित 181 अभयम महिला हेल्पलाइन योजना के अंतर्गत उनसठ रेस्क्यू वैन की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। चालू वर्ष में महिला हेल्पलाइन पर एक लाख, पचास हजार से अधिक महिलाओं द्वारा मार्गदर्शन एवं काउंसलिंग हेतु कॉल किए गए, जिनमें से तीस हजार से अधिक महिलाओं को घटनास्थल पर जाकर सहायता प्रदान की गई।
- पुलिस स्टेशन आधारित सपोर्ट सेंटर योजना के अंतर्गत पारिवारिक अथवा अन्य समस्याओं से प्रभावित महिलाओं को पुलिस स्टेशन में ही काउंसलिंग के माध्यम से मानसिक एवं कानूनी सहयोग प्रदान किया जाता है। राज्य के जिला एवं तहसील मुख्यालयों पर कुल अस्सी सपोर्ट सेंटर कार्यरत हैं, जहां लगभग एक सौ साठ प्रशिक्षित काउंसलरों द्वारा काउंसलिंग एवं कानूनी मार्गदर्शन प्रदान किया जा रहा है। चालू वर्ष में दस हजार से अधिक महिलाओं को इन सेवाओं का लाभ दिया गया है।

शहरी विकास एवं शहरी गृह निर्माण

- देश के यशस्वी प्रधानमंत्री एवं गुजरात राज्य के तत्कालीन माननीय मुख्यमंत्री श्री नरेंद्रभाई मोदी ने वर्ष 2005 में “शहरी विकास वर्ष” की शुरुआत की थी। मेरी सरकार ने वर्ष 2025 को शहरी विकास वर्ष के रूप में मनाकर विकास की गति को दोगुना किया है।
- शहरी विकास वर्ष के अंतर्गत कुल पचपन हजार करोड़ से ज्यादा के तेरह हजार से ज्यादा कार्य मंजूर किए गए हैं। इनमें से करमसद-आणंद, नडियाद, मोरबी, सुरेंद्रनगर, गांधीधाम, पोरबंदर, वापी, नवसारी एवं महेसाणा महानगरों में चार

हजार, नौ सौ पचपन करोड़ से ज्यादा के 2300 जितने कार्यों को मंजूरी दी गई है।

- कलोल, साणंद, सावली, बारडोली और हीरासर सहित कुल पांच सेटेलाइट टाउन घोषित किए गए हैं।
- रेलवे ओवरब्रिज-रेलवे अंडरब्रिज के लिए तीन हजार, एक सौ अस्सी करोड़ के छियानवे कार्यों को मंजूरी प्रदान की गई हैं।
- वडोदरा, जूनागढ़, नवसारी एवं पोरबंदर शहरों में 8.45 कि.मी. लंबे आइकोनिक रोड का निर्माण किया गया है।
- स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत गुजरात के छह शहरों में कुल ग्यारह हजार, पांच सौ सात करोड़ के तीन सौ उनसठ प्रोजेक्ट क्रियान्वित किए गए हैं।
- प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत लगभग बाईस हजार आवासों का आवंटन किया गया है तथा दस हजार से अधिक आवासों का आवंटन प्रक्रियाधीन है।
- PM e-Bus योजना के अंतर्गत राज्य के आठ महानगरों में सात सौ पचास से अधिक बसों हेतु एक सौ तेरह करोड़ का आयोजन है।
- मेट्रो परिवहन सेवा के अंतर्गत कुल अड़सठ किलोमीटर से ज्यादा का कार्य पूर्ण किया गया है, जिसमें से मोटेरा से महात्मा मंदिर तक अठाईस कि.मी.से ज्यादा के मार्ग को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्रभाई मोदी की उपस्थिति में आम जनता के लिए प्रारंभ किया गया है।
- साबरमती रिवरफ्रंट के कुल छह चरणों में से ग्यारह दशमलव दो कि.मी. के एक हजार, दो सौ दो करोड़ के कार्य पूर्ण किए गए हैं, जबकि अठाईस कि.मी. के कार्य वर्तमान में प्रगति पर हैं।
- “PM Street Vendors AtmaNirbhar Nidhi (PM SVANidhi)” योजना के अंतर्गत चार लाख, नब्बे हजार से अधिक शहरी फेरीवालों वालों को बिना बैंक गारंटी एक हजार, एक सौ सत्तर करोड़ से अधिक का ऋण प्रदान किया गया है।
- दस लाख से अधिक जनसंख्या वाले स्वच्छ शहरों की श्रेणी में अहमदाबाद महानगरपालिका ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है।
- राज्य की सभी एक सौ सड़सठ शहरी स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को ODF प्रमाणित किया गया है। अनेक शहरों को Garbage Free City, ODF+/ODF++/Water+ प्रमाणन प्राप्त हुआ है।

**पंचायत एवं
ग्राम विकास**

- टाउन प्लानिंग स्कीम के अंतर्गत Web-GIS के माध्यम से चार सौ टी.पी. स्कीमें उपलब्ध कराई गई हैं तथा छह सौ से अधिक स्कीमें डिजिटलीकरण की प्रक्रिया में हैं।
- ODPS 3.0 को AI, Blockchain जैसी आधुनिक तकनीकों के साथ लागू करने की योजना है।
- बत्तीस मसौदा नगर रचना योजनाएं, अड़तीस प्रारंभिक नगर रचना योजनाएं, तयालिस अंतिम नगर रचना योजनाएं तथा चार विकास योजनाएं स्वीकृत की गई हैं।
- बुलेट ट्रेन परियोजना के अंतर्गत राज्य के आठ स्टेशनों हेतु Gujarat High Speed Railway Station Planning Authority का गठन किया गया है।
- मेरी यह सरकार पूज्य महात्मा गांधीजी के विचारों को समर्पित सरकार है। बापु ने कहा था कि 'भारत की आत्मा गांवों में बसती है', इस मंत्र को साकार करते हुए ग्रामीण विकास क्षेत्र में यह सरकार अभूतपूर्व कार्य कर रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत वर्ष 2025-26 में नवंबर-2025 तक अठहत्तर हजार, सात सौ बावन आवासों का लाभार्थियों द्वारा निर्माण किया गया है, जिसमें नौ सौ अठहत्तर करोड़ से अधिक की सहायता प्रदान की गई है।
- दिनांक 15/11/2025 को माननीय प्रधानमंत्री जी के करकमलों से नर्मदा में आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अंतर्गत संपूर्ण राज्य में एक हजार आठ करोड़ की लागत से कुल इकसठ हजार, एक सौ पचीस लाभार्थियों का ई-गृह प्रवेश संपन्न कराया गया है।
- स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अंतर्गत वर्ष 2025-26 में नवम्बर 2025 तक व्यक्तिगत शौचालय पैतालिस हजार दस, सामुदायिक शौचालय एक सौ बत्तीस ,व्यक्तिगत सोकपिट तीन हजार इकत्तीस तथा बाईस हजार, नौ सौ अड़तीस सामुदायिक सोकपिट का निर्माण पूर्ण किया गया है। साथ ही घन कचरा प्रबंधन के अंतर्गत जैविक कचरे के निपटान हेतु पांच हजार, सात सौ छियानबे सामुदायिक कंपोस्ट पिट तथा तीन हजार, तीन सौ बयासी व्यक्तिगत कंपोस्ट पिट का निर्माण पूर्ण किया गया है। घन कचरा प्रबंधन के कार्यों के अंतर्गत एक हजार, दो सौ तीन सेग्रीगेशन शेड का निर्माण भी पूर्ण किया गया है तथा कुल एक सौ चौहत्तर करोड़ से ज्यादा का खर्च किया गया है।
- गोबरधन परियोजना के अंतर्गत प्रथम चरण की सफलता के पश्चात द्वितीय चरण में चार हजार आठ सौ लाभार्थियों को लाभ प्रदान किया गया है।

- प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना – वाटरशेड डेवलपमेंट कंपोनेंट 2.0 के अंतर्गत वर्ष 2025-26 में भूमि एवं नदी संरक्षण, जल संचयन तथा भू-जल रिचार्ज से संबंधित कुल चार हजार, पांच सौ बयासी कार्य तथा उत्पादन वृद्धि से संबंधित एक हजार, चार सौ तिहत्तर कार्य पूर्ण किए गए हैं, जिनमें अड़तालिस करोड़ से ज्यादा का खर्च किया गया है।
- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत वर्ष 2025-26 में नवम्बर - 2025 अंत तक छह हजार, सात सौ इक्कीस स्वयं सहायता समूहों का गठन किया गया है। रिवॉल्विंग फंड (RF) के अंतर्गत कुल चार हजार, चार सौ एक स्वयं सहायता समूहों को तेरह करोड़ से ज्यादा की सहायता प्रदान की गई है। कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड (CIF) के अंतर्गत पांच हजार, आठ सौ बत्तीस, स्वयं सहायता समूहों को पचहत्तर करोड़ से ज्यादा की सहायता प्रदान की गई है। कुल अड़तालिस हजार, चार सौ चौहत्तर स्वयं सहायता समूहों को कैश क्रेडिट (CC) ऋण के अंतर्गत बैंकों से नौ सौ छिहत्तर करोड़ से ज्यादा का ऋण उपलब्ध कराया गया है।
- मेरी सरकार द्वारा राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक स्तर पर तेरह सरस मेलों का आयोजन किया गया है, जिसमें गुजरात एवं अन्य राज्यों के कुल नौ सौ अस्सी सखी मंडलों ने भाग लिया है तथा लगभग नौ करोड़ से ज्यादा का बिक्री कारोबार हुआ है।
- ई-ग्राम विश्वग्राम योजना के अंतर्गत उपलब्ध सेवाओं की संख्या बढ़कर तीन सौ इक्कीस हो गई है। वर्ष 2025-26 में कुल चार करोड़, तरानवे लाख ट्रांजैक्शन हुए हैं, जिनमें से डिजिटल सेवा सेतु के अंतर्गत वर्ष 2025-26 (नवंबर-2025 तक) बाईस लाख, चौदह हजार ट्रांजैक्शन किए गए हैं।
- 15वें वित्त आयोग के अंतर्गत सड़क, प्राथमिक शिक्षा आदि जैसी मूलभूत सुविधाओं के कार्यों हेतु अब तक तेरह हजार, पंचानवे करोड़ की ग्रांट पंचायतों को आवंटित की गई है। इसके अंतर्गत अब तक दस हजार करोड़ से ज्यादा के खर्च से पांच लाख, बयासी हजार, सात सौ उनहत्तर कार्य पूर्ण किए गए हैं।
- महात्मा गांधी स्वच्छता मिशन के अंतर्गत वर्ष 2016-17 से राज्य की सभी ग्राम पंचायतों में डोर-टू-डोर ठोस कचरा संग्रहण कर एकत्रित कचरे को लैंडफिल साइट तक पहुंचाने हेतु प्रति माह प्रति व्यक्ति चार रुपए की दर से ग्रांट दी जाती थी, जिसे मेरी सरकार ने बढ़ाकर प्रति माह प्रति व्यक्ति आठ रुपए की सहायता स्वीकृत की है। वर्ष 2025-26 में नवंबर-2025 तक एक सौ इकतालिस दशमलव इकानबे करोड़ की प्रोत्साहन ग्रांट प्रदान की गई है।

**श्रम, कौशल्य
विकास एवं
रोजगार**

- उद्योगों को कुशल मानवबल उपलब्ध हो, इस उद्देश्य से सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (I.T.I.) में कारीगर तालिम योजना के अंतर्गत प्रवेश सत्र 2025-26 के अंतर्गत एक लाख, बीस हजार, तीन सौ बत्तीस प्रशिक्षणार्थियों को प्रवेश दिया गया है।
- दिसंबर-2025 तक कुल एक हजार, दो सौ अड़सठ औद्योगिक भर्ती मेलों के आयोजन के माध्यम से कुल बहत्तर हजार, एक सौ अठाईस उम्मीदवारों को तथा रोजगार विनिमय कार्यालयों द्वारा कुल दो लाख, बरानवे हजार, पांच सौ अड़तीस उम्मीदवारों को रोजगार उपलब्ध कराया गया है।
- वर्ष 2025 के दौरान मुख्यमंत्री अप्रेंटिस प्रशिक्षण योजना के अंतर्गत लगभग एक लाख युवाओं को औद्योगिक इकाइयों में उद्योगोन्मुख प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। यह प्रयास राज्य के युवाधन को रोजगारक्षम बनाकर आत्मनिर्भर गुजरात के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं।
- राज्य के युवाधन हेतु वर्तमान समय की आवश्यकता के अनुरूप कौशलवर्धन के उद्देश्य से स्थापित कौशल्या द स्किल यूनिवर्सिटी द्वारा स्किल इंस्टीट्यूट/इंडस्ट्रीज तथा यूनिवर्सिटी/शैक्षणिक संस्थानों के साथ क्रेडिट ट्रांसफर हेतु नौ स्ट्रेटेजिक पार्टनर, सोलह एफिलिएटेड पार्टनर, पैंतीस तथा अंतरराष्ट्रीय शैक्षणिक संस्थानों के साथ ग्यारह एमओयू सहित कुल इकहत्तर एमओयू किए गए हैं। इन विश्वविद्यालयों में एक हजार, तीन सौ पचहत्तर विद्यार्थियों ने दीर्घकालीन पाठ्यक्रमों में तथा पिछले एक वर्ष में एक हजार, पांच सौ उनसठ विद्यार्थियों ने अल्पकालीन पाठ्यक्रमों में प्रवेश प्राप्त किया है।
- श्रम सेतु पोर्टल पर पिछले एक वर्ष में पांच हजार, पांच सौ आवेदनों पर ऑनलाइन कार्रवाई की गई है तथा तेरह हजार, आठ सौ दस ऑनलाइन निरीक्षण किए गए हैं।
- राज्य के श्रमयोगियों को बोनस की राशि दीपावली के समय प्राप्त हो, इस उद्देश्य से वर्ष 2024-25 के दौरान बारह लाख, चवालिस हजार, छह सौ उनसठ श्रमिकों को दो हजार करोड़ से ज्यादा की राशि बोनस के रूप में भुगतान कराई गई है।
- धन्वंतरी आरोग्य रथ योजना के अंतर्गत कुल एक सौ चौवन धन्वंतरी आरोग्य रथों के माध्यम से दिसंबर-2025 तक कुल चालीस लाख, पचीस हजार श्रमिकों को स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं प्रदान की गई हैं।
- शिक्षा सहायता योजना के अंतर्गत पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के दो बच्चों को कक्षा एक से Ph.D. तक की पढ़ाई हेतु एक हजार, आठ सौ से दो लाख तक की सहायता प्रदान की जाती है, जिसके अंतर्गत दिसंबर-2025 तक कुल चवालिस

हजार, चार सौ तिरासी लाभार्थियों को छिहत्तर करोड़ की सहायता प्रदान की गई है।

- श्रमिक अन्नपूर्णा योजना के अंतर्गत पांच रुपए की रियायती दर पर निर्माण श्रमिकों को पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराया जाता है। वर्तमान में दो सौ तरानवे बूथ कार्यरत हैं तथा दिसंबर-2025 तक कुल एक सौ पंद्रह लाख से ज्यादा इकाई भोजन का वितरण किया गया है।

मार्ग एवं मकान विभाग

- उत्तर से दक्षिण तथा पूर्व से पश्चिम के छोरों को जोड़ने और बढ़ते हुए वाहन यातायात को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने नमो शक्ति एक्सप्रेस-वे और सोमनाथ-द्वारका एक्सप्रेस-वे के निर्माण का निर्णय किया है। यह परियोजनाएं राज्य के औद्योगिक केंद्रों, पर्यटन स्थलों और बंदरगाहों को जोड़ेंगी, जिससे आर्थिक गतिविधियों को गति मिलेगी। गुणवत्तायुक्त सड़कों और फ्लाईओवर के निर्माण से ईंधन की बचत होगी तथा यात्रा तेज और सुरक्षित बनेगी। एक हजार, एक सौ कि.मी. लंबाई और लगभग तरानवे हजार, दो सौ चालीस करोड़ की अनुमानित लागत से बनने वाली इन परियोजनाओं से राज्य के पंद्रह जिलों के लगभग ढाई करोड़ से अधिक लोगों को लाभ मिलेगा, सीमावर्ती जिलों का विकास होगा तथा आधारभूत संरचनाओं के लाभ से पूरे राज्य के विकास को गति मिलेगी।
- गरवी गुजरात हाईस्पीड कॉरिडोर के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा बारह कार्यों को सात हजार दो सौ करोड़ से ज्यादा की लागत से विकास हेतु स्वीकृति प्रदान की गई है। इन कार्यों में वर्तमान में निर्माण-पूर्व की प्रक्रियाएं प्रगति पर हैं।
- SER (सूरत आर्थिक क्षेत्र) के अंतर्गत सड़क एवं इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास हेतु नई पहल के रूप में वर्ष 2025-26 में पांच सौ करोड़ का प्रावधान किया गया है तथा एक हजार सात सौ उनचास दशमलव दस करोड़ के कार्य योजना अंतर्गत हैं।
- राज्य सरकार द्वारा सड़कों के निर्माण हेतु जलवायु-स्थिर (क्लाइमेट रेजिलीएंट) एवं नई तकनीक आधारित बीस कार्यों को एक हजार, एक सौ सैंतालीस करोड़ रुपये से अधिक की स्वीकृति प्रदान की गई है।
- राज्य में एक हजार, एक कि.मी. लंबाई की सड़कों का दो हजार, तीन सौ तिहत्तर करोड़ की लागत से चार-लेनीकरण / दस मीटर / सात मीटर चौड़ीकरण का कार्य पूर्ण

किया गया है। वहीं एक हजार, चार सौ सताईस कि.मी. लंबाई की सड़कों का पांच हजार, तयासी करोड़ की अनुमानित लागत से चार मार्गीकरण / दस मीटर / सात मीटर चौड़ीकरण का कार्य प्रगति में है।

- राज्य में पुलों के निर्माण – नये पुलों सहित कुल अठाईस पुलों का कार्य एक सौ सतावन करोड़ की लागत से पूर्ण किया गया है, जबकि एक हजार पांच सौ अठानवे करोड़ की लागत वाले छियासी पुलों के कार्य प्रगति में हैं।
- राज्य में मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत वर्ष 2016-17 से अब तक बयालिस हजार, चार सौ अठत्तर करोड़ की लागत से छियासी हजार, सात सौ सतावन कि.मी. लंबाई के छत्तीस हजार, चार सौ चौहत्तर कार्य स्वीकृत किए गए हैं। इनमें से छयासठ, तीन सौ तीस कि.मी. के सताईस हजार, आठ सौ तीस कार्य पूर्ण हो चुके हैं तथा शेष कार्य प्रगति में हैं। इस योजना के अंतर्गत वर्ष 2025-26 में कुल पांच हजार, चार सौ तीन करोड़ का प्रावधान किया गया है।
- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना – 1 एवं 2 के अंतर्गत स्वीकृत सभी कार्य पूर्ण कर लिए गए हैं। वहीं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना – 3 के अंतर्गत तीन हजार, बारह कि.मी. लंबाई को शामिल किया गया है। वर्तमान स्थिति में दो हजार, आठ सौ कि.मी. लंबाई के दो सौ नवासी सड़क कार्य एवं पैतालिस पुलों के कार्य पूर्ण किए गए हैं।
- सापुतारा से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को जोड़ने वाला, नर्मदा, तापी एवं डांग जिलों से होकर गुजरने वाला सापुतारा-शबरीधाम-सोनगढ़-शेरुला-जरवाणी होते हुए गोरा से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक दो सौ सैंतीस कि.मी. लंबाई के मार्ग के प्रथम चरण में नर्मदा, तापी एवं डांग जिलों के पंचानबे कि.मी. लंबाई के मौजूदा मार्गों को दस मीटर चौड़ा करने का कार्य पूर्ण किया गया है।
- औद्योगिक एवं खनिज क्षेत्रों को जोड़ने वाली सड़कों के सुधार, उन्नयन एवं मजबूतीकरण के तहत आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से दो हजार, तीन सौ तैंतालिस कि.मी. लंबाई के दो सौ इकत्तीस कार्यों को सात हजार, एक सौ अठत्तर करोड़ की स्वीकृति प्रदान की गई है। इनमें से एक हजार, दो सौ बहत्तर कि.मी. लंबाई के एक सौ छत्तीस कार्य दो हजार आठ सौ बीस करोड़ की लागत से पूर्ण किए गए हैं।

- गुजरात देश का सबसे लंबा समुद्र तट रखने वाला राज्य है। गुजरात के समुद्र तट पर स्थित बंदरगाह रणनीतिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण होने के कारण आवश्यक सड़क अधोसंरचना को सुदृढ़ करने हेतु बंदरगाहों को जोड़ने वाले सात सौ सत्तावन कि.मी. लंबाई के छियालिस कार्य एक हजार, एक सौ अठारह करोड़ की लागत से पूर्ण किए गए हैं।
- गुजरात के समुद्र तट पर स्थित मौजूदा सड़कों के मजबूतीकरण, उन्नयन, आवश्यक कड़ियों को जोड़ने के मार्ग तथा छोटे-बड़े पुलों के निर्माण सहित कोस्टल हाईवे विकसित करने हेतु दो हजार, चार सौ चालीस करोड़ की योजना के अंतर्गत प्रथम चरण में दो सौ बहत्तर कि.मी. से अधिक लंबाई के पचीस सड़क कार्यों को छह सौ तरानबे करोड़ से अधिक की स्वीकृति प्रदान की गई है। इनमें से चार सौ उनहत्तर करोड़ के इक्कीस सड़क कार्य पूर्ण किए गए हैं तथा दो सौ चौबीस करोड़ के 4 सड़क कार्य प्रगति में हैं।
- सरखेज-गांधीनगर हाईवे को नौ सौ तेरह करोड़ की लागत से छह-लेन का कार्य पूर्ण किया गया है। साथ ही इस्कॉन से साणंद फ्लाईओवर पर एलिवेटेड कॉरिडोर पांच सौ तीस करोड़, छारोड़ी के पास छह-लेन फ्लाईओवर, साबरमती नदी पर चार-लेन पुल अड़सठ करोड़ की लागत से तथा अडालज चार-लेन नहर के समानांतर नई चार-लेन नहर का कार्य इक्यासी करोड़ की लागत से प्रगति में है।
- वाहन यातायात की सुरक्षा एवं समय की बचत हेतु फाटक-मुक्त अभियान के अंतर्गत राज्य सरकार एवं भारत सरकार के रेलवे मंत्रालय की पचास-पचास प्रतिशत भागीदारी से एक लाख ट्रेन व्हीकल यूनिट से अधिक यातायात वाले रेलवे क्रॉसिंग पर ओवरब्रिज निर्माण के तहत तीन हजार नौ सौ इक्कीस करोड़ की लागत से कुल बयासी रेलवे ओवरब्रिज पूर्ण किए गए हैं।

परिवहन

- फेसलेस सेवाओं के क्रियान्वयन से ड्राइविंग लाइसेंस एवं फेसलेस लर्निंग लाइसेंस से संबंधित सेवाओं का सात लाख, साठ हजार नागरिकों ने लाभ लिया है तथा वाहन संबंधी सेवाओं का कुल अठारह लाख, सड़सठ हजार से ज्यादा नागरिकों ने लाभ प्राप्त किया है।
- Registered Vehicle Scrapping Facility (RVSF) के माध्यम से वाहन स्कैप करने पर परिवहन वाहनों के मोटर वाहन कर में पंद्रह फीसदी तथा गैर-परिवहन वाहनों के मोटर वाहन कर में पचीस फीसदी की राहत प्रदान की जाती है। वर्ष

2025-26 में एक हजार इक्यानवे लाभार्थियों ने कुल एक करोड़ से ज्यादा की कर राहत का लाभ लिया है।

- 8 वर्ष से अधिक आयु वाले वाणिज्यिक वाहनों को सरकार-मान्यता प्राप्त स्क्रेपिंग केंद्र में स्क्रेप कराने पर उनके पुराने बकाया कर, पेनल्टी, ब्याज एवं चालान की दंड राशि माफ करने हेतु वन-टाइम वेवर योजना दिनांक 01-05-2025 से एक वर्ष के लिए लागू की गई है।
- चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में नवंबर 2025 माह के अंत तक ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन के माध्यम से कुल दो लाख, तेईस हजार, तीन सौ इक्कीस फिटनेस प्रमाणपत्र जारी किए गए हैं।
- माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्रभाई मोदीजी की “ग्रीन ग्रोथ” की संकल्पना को साकार करने के तहत पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन के उद्देश्य से वर्तमान में इलेक्ट्रिक वाहनों पर लागू छह फीसदी तक के एकमुश्त (Lumpsum) वाहन कर अमल में है। पूर्णतः इलेक्ट्रिक बैटरी से संचालित वाहनों पर एक वर्ष के लिए पांच फीसदी तक की रिबेट प्रदान कर प्रभावी रूप से एक फीसदी की दर से वाहन कर रखने का जन-हितकारी एवं पर्यावरण-हितकारी निर्णय मेरी सरकार द्वारा किया गया है।
- राज्य में कार्यरत NHA1 तथा राज्य के टोल प्लाजा से गुजरने वाले वाहनों के दस्तावेजों की ऑनलाइन जांच हेतु NIC द्वारा “e-detection” एप्लिकेशन विकसित की गई है, जिसके अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 में नवंबर 2025 तक कुल तीन लाख, तेरह हजार, आठ सौ बयासी चालान जारी किए गए हैं।
- आदिजाति बॉर्डर विलेज योजना के अंतर्गत विद्यार्थियों के लिए एक सौ ग्यारह नई बड़ी बसों को संचालन में लाया गया है।
- राज्य सरकार द्वारा गत वर्ष नौ सौ बासठ सुपर एक्सप्रेस वाहन, एक सौ तिरसठ गुर्जरनगरी वाहन तथा तीन सौ पचास मिडी बसों सहित कुल एक हजार, चार सौ पचहत्तर नई अत्याधुनिक तकनीक वाले वाहनों को यात्री जनता की सेवा में लगाया गया है।
- भगवान बिरसा मुंडाजी की 150वीं जन्म जयंती के अवसर पर लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्रभाई मोदीजी के करकमलों से एक सौ ग्यारह नवीन रेडी-बिल्ट वाहनों का लोकार्पण किया गया है।

- राज्य सरकार ने वर्ष 2025-26 में कंडक्टर वर्ग में दो हजार, तीन सौ बीस, ड्राइवर वर्ग में तीन हजार चौरासी तथा हेल्पर वर्ग में एक हजार, छह सौ अठावन उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रदान किए हैं।

बंदरगाह

- वर्ष 2024-25 में गुजरात मैरीटाइम बोर्ड द्वारा संचालित नॉन-मेजर बंदरगाहों के माध्यम से कुल कार्गो परिवहन चार सौ सतासी मिलियन मीट्रिक टन हुआ है, जो गत वित्तीय वर्ष की तुलना में आठ दशमल छप्पन फीसदी की वृद्धि दर्शाता है। वहीं, इसी अवधि के दौरान भारत के कुल बंदरगाहों से लगभग एक हजार, पांच सौ तरानवे मिलियन मीट्रिक टन कार्गो परिवहन हुआ है, जिसमें गुजरात राज्य के नॉन-मेजर बंदरगाहों का कुल राष्ट्रीय परिवहन में इकतीस फीसदी तथा देश के नॉन-मेजर बंदरगाहों पर होने वाले परिवहन में लगभग छियासठ फीसदी का योगदान रहा है।
- भावनगर जिले के अलंग-सोसीया में विश्व का सबसे बड़ा शिप रीसाइक्लिंग यार्ड विकसित किया गया है। इस शिप रीसाइक्लिंग यार्ड में वर्तमान में एक सौ पचास प्लॉट उपलब्ध हैं, जिनमें से एक सौ अठाईस प्लॉट कार्यरत हैं। इस यार्ड में वर्ष 1983 से अब तक इकहत्तर मिलियन मीट्रिक टन एल.डी.टी. (लाइट डिस्प्लेसमेंट टन) के आठ हजार नौ सौ चौबीस जहाजों को तोड़ा गया है। शिप रीसाइक्लिंग उद्योग में व्याप्त मंदी के कारण सरकार द्वारा शिप ब्रेकर्स को वर्ष 2021 से 2025 के दौरान प्लॉट चार्जेस में कुल एक सौ पैतालिस करोड़ की छूट प्रदान की गई है।

राजस्व

व्यवस्थापन

- मेरी सरकार ने किसान-केंद्रित दृष्टिकोण अपनाते हुए खेती की जमीन के बिक्री संबंधी मामलों में जांच हेतु आवेदक की आवेदन तिथि से पचीस वर्ष पूर्व का रिकॉर्ड ध्यान में नहीं लिया जाएगा, ऐसा नीतिगत निर्णय लेकर एक ऐतिहासिक कदम उठाया है।
- राज्य की सभी महानगर पालिकाओं एवं विकास प्राधिकरणों को छोड़कर राज्य के शेष सभी क्षेत्रों में खेती उद्देश्य की नई और अविभाज्य शर्त, प्रतिबंधित सत्ता प्रकार या नियंत्रित सत्ता प्रकार की सभी जमीनों को पुरानी शर्त की जमीन मानते हुए, अर्थात् इन क्षेत्रों में प्रीमियम भुगतान से मुक्ति प्रदान की गई है।
- जन-केंद्रित दृष्टिकोण के श्रेष्ठ उद्देश्य से मेरी सरकार ने हाउसिंग सोसायटी/एन.टी.सी./एसोसिएशन द्वारा अलॉटमेंट लेटर तथा शेयर सर्टिफिकेट के आधार पर की गई तब्दीलियों पर स्टाम्प ड्यूटी भुगतान हेतु अमनेस्टी योजना में वसूल योग्य बकाया स्टाम्प ड्यूटी की राशि में अस्सी प्रतिशत की कटौती कर जन-हितकारी निर्णय लिया है।

- राज्य में महिलाओं की सामाजिक स्थिति सुदृढ़ हो, इस उद्देश्य से केवल महिलाओं के नाम पर खरीदी जाने वाली स्थावर संपत्ति के दस्तावेजों में संपत्ति क्रेता महिलाओं को 1 फीसदी पंजीकरण शुल्क से छूट दी जाती है। सन् 2022 से नवंबर 2025 तक पंजीकृत कुल लगभग चार लाख से ज्यादा दस्तावेजों में नौ लाख से ज्यादा महिलाओं को पंद्रह सौ करोड़ रुपये से अधिक की पंजीकरण शुल्क की छूट प्रदान की गई है।
- राज्य में स्वामित्व योजना के अंतर्गत राज्य के चौदह हजार, सात सौ से अधिक गांवों में ड्रोन के माध्यम से संपत्तियों को मापने का कार्य पूर्ण किया गया है। नौ हजार, सात सौ बासठ गांवों में प्रमोलगेशन तथा सोलह लाख से अधिक प्रॉपर्टी कार्ड तैयार किए गए हैं।
- राजस्व प्रशासन में पारदर्शिता बढ़े, आधुनिक भूमि प्रशासन प्रणाली और अधिक सुदृढ़ बने तथा भूमि विवादों में कमी आए, इस उद्देश्य से आधुनिक तकनीक के समन्वय हेतु स्पेस एप्लिकेशन सेंटर (SAC) इसरो, अहमदाबाद तथा राजस्व विभाग के बीच MOU किया गया है, जिसके माध्यम से तीस से.मी. हाई-रिजोल्यूशन वाली सैटेलाइट इमेज प्राप्त कर सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण की पहचान तथा शर्तभंग खोजने की पहचान में सहायता मिली है।
- राज्य में अतिक्रमण हटाओ अभियान के रूप में मूल्यवान सरकारी जमीनों पर किए गए अतिक्रमण हटाए गए हैं। अप्रैल-2025 से दिसंबर-2025 की अवधि के दौरान अनुमानित चार हजार, एक सौ पैंतीस हेक्टेयर भूमि से कुल एक हजार, छह सौ छत्तीस सर्वे नंबरों के अतिक्रमण हटाए गए हैं, जिनकी जंत्री आधारित अनुमानित कीमत लगभग तीन हजार, सात सौ पैंसठ करोड़ रुपये है।
- भारत सरकार के गृह मंत्रालय की गाइडलाइन के अनुसार राज्यव्यापी एकीकृत डायल 112 ERSS (Emergency Response Support System) प्रणाली लागू की गई है। जिसके अंतर्गत पुलिस, एम्बुलेंस, फायर, अभयम, चाइल्ड हेल्पलाइन, डिजास्टर मैनेजमेंट जैसी आपातकालीन सेवाओं को एकीकृत किया गया है तथा कुल नौ सौ बासठ PCR वाहन कार्यरत हैं। इसके चलते जनवरी 2026 की स्थिति के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में response time घटकर 11 मिनट 56 सेकंड तथा शहरी क्षेत्रों में अनुमानित आठ मिनट तक हो गया है।
- राज्य पुलिस बल में स्थायी पुलिस भर्ती बोर्ड द्वारा वर्ष 2025 में लोक रक्षक संवर्ग की कुल ग्यारह हजार, आठ सौ निन्यानबे रिक्त स्थानों की भरा गया है।

कानून एवं व्यवस्था

- गुजरात पूरे भारत में साइबर क्राइम संबंधी हेल्पलाइन-1930 के संचालन में दूसरे स्थान पर रहा है।
- साइबर क्राइम से पीड़ित आवेदक के ब्लॉक/फ्रिज किए गए धन को BNSS धारा-503 (सी.आर.पी.सी.-457) के अनुसार माननीय न्यायालय में आवेदन कर आवेदक को वापस दिलाया जा सकता है। माननीय न्यायालय द्वारा आज दिन तक एक लाख, बत्तीस हजार सात सौ पैसठ आवेदकों को कुल दो सौ दो करोड़ रुपये से अधिक की राशि वापस दिलाने के आदेश दिए गए हैं।
- साइबर क्राइम के संबंध में नागरिकों में जागरूकता लाने हेतु विभिन्न प्रचार-प्रसार माध्यमों जैसे कि समाचार पत्र, रेडियो स्टेशन, टीवी चैनल, GSRTC बस पैनल पर विज्ञापन, सोशल मीडिया के माध्यम से जागरूकता फैलाई जाती है। साथ ही स्कूलों-कॉलेजों में जागरूकता सत्र आयोजित किए गए हैं।
- भारतीय न्याय संहिता, 2023: भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 तथा भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 के क्रियान्वयन हेतु पुलिस, जेल, अभियोजक, फॉरेंसिक तथा न्यायिक विभाग के सभी अधिकारी-कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया गया है।
- एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत श्री सरदार वल्लभभाई पटेल की 150वीं जन्म जयंती के अवसर पर 31 अक्टूबर 2025 को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्रभाई मोदी की उपस्थिति में एकता की थीम पर नई दिल्ली में 26 जनवरी एवं 15 अगस्त को होने वाली परेड की तर्ज पर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, एकतानगर में परेड का आयोजन किया गया। इस अवसर पर श्री सरदार वल्लभभाई पटेल की स्मृति में एक सौ पचास रुपये के सिक्के का अनावरण किया गया।

वित्त

व्यवस्थापन

- गुजरात ने FRBM (फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट) द्वारा निर्धारित तीन फीसदी के राजकोषीय घाटे की सीमा का सख्ती से पालन किया है तथा RBI रिपोर्ट के अनुसार, निरंतर रूप से GSDP के दो फीसदी से कम राजकोषीय घाटा एवं राजस्व अधिशेष बनाए रखा है।
- राज्य ने ऋण के संबंध में भी कड़ी वित्तीय अनुशासन बनाए रखा है, जिसमें वर्ष 2024-25 में सार्वजनिक ऋण GSDP का चौदह दशमलव तेईस फीसदी रहा है, जो FRBM की सताईस दशमलव एक फीसदी की निर्धारित सीमा से काफी कम है।
- राज्य की कर राजस्व आय वर्ष 2020-21 से 2024-25 के दौरान लगभग दोगुनी हो गई है। वर्ष 2024-25 में जी.एस.टी., वैट, विद्युत कर एवं प्रोफेशनल टैक्स के

अंतर्गत कुल एक दशमल उन्नीस लाख करोड़ की प्राप्ति हुई है, जो राज्य के सुदृढ़ राजस्व ढांचे को दर्शाती है।

- वर्ष 2024-25 में GSTR-3B रिटर्न के निन्यानबे दशमलव छह फीसदी फाइलिंग के साथ गुजरात पूरे देश में प्रथम स्थान पर है।
- वर्ष 2025-26 में नवंबर-2025 तक ई-वे बिल के वेरिफिकेशन में गुजरात राज्य पूरे देश में प्रथम स्थान पर है।
- हीरा उद्योग के लिए निर्धारित माइक्रो इकाइयों को एक वर्ष के लिए विद्युत कर में छूट प्रदान कर कठिन समय में उद्योग एवं श्रमिकों को राहत दी गई है।
- गुजरात सामूहिक जूथ (जनता) दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत कुल चार करोड़ से अधिक लाभार्थियों को कवर किया गया है। वर्ष 2025-26 से इस योजना के अंतर्गत बीमा सहायता राशि में वृद्धि कर दो लाख से चार लाख तक की बीमा सहायता प्रदान करने का प्रावधान किया गया है।

खेलकूद, युवा एवं सांस्कृतिक गतिविधियां

- खेल महाकुंभ देश का सबसे बड़ा जन-भागीदारी आधारित खेल आंदोलन बनकर विकसित हुआ है, जिसमें चालू वर्ष में बहतर लाख से अधिक खिलाड़ियों का पंजीकरण हुआ है। इनमें से अब तक अनुमानित अठावन लाख खिलाड़ियों ने भाग लिया है।
- सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कार्यक्रम के अंतर्गत दस जिलों में पंद्रह खेलों के लिए कुल अठारह अकादमियां कार्यरत हैं, जिनमें अनुमानित एक हजार सात सौ नब्बे खिलाड़ियों को आवासीय एवं अनावासीय अकादमी के अंतर्गत प्रशिक्षण दिया जा रहा है। नडियाद स्थित हाई परफॉर्मेंस सेंटर में सात खेलों के 290 दो सौ नब्बे से अधिक एलीट खिलाड़ियों को उच्च स्तरीय सहायता प्रदान की जा रही है।
- गुजरात को कॉमनवेल्थ वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप-2025 तथा 11वीं एशियन एक्वेटिक्स चैंपियनशिप-2025 के आयोजन की मेजबानी प्राप्त हुई है।
- सरकार 'युवा शक्ति' और 'सांस्कृतिक विरासत' के समन्वय के माध्यम से राज्य को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध है। 'हर घर तिरंगा', 'सरदार एट एक सौ पचास पदयात्रा' तथा राष्ट्रीय दिवसों के उत्सव के माध्यम से राष्ट्रप्रेम की ज्योति प्रज्वलित रखी जा रही है।
- हमारी सांस्कृतिक विरासत ही हमारी पहचान है। मोढेरा के सूर्य मंदिर में आयोजित 'उत्तरार्ध उत्सव' हो या गांधीनगर का 'वसंतोत्सव', तथा 'माधवपुर घेड का मेला'

आज गुजरात, पश्चिम भारत और उत्तर-पूर्व भारत की अलग पहचान बन रहा है, जो 'एक भारत श्रेष्ठ भारत' की संकल्पना को साकार करता है।

विज्ञान एवं प्राद्यौगिकी

- पिछले दो शैक्षणिक वर्षों (वर्ष 2023-24 और 2024-25) में स्वर्णिम गुजरात स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों ने West Zone, All India University, Khelo India तथा World University Games (Germany) जैसी प्रतियोगिताओं में विभिन्न खेलों में कुल 35 पदक प्राप्त किए हैं। Athletics में All India Gold Medal तथा Women's Volleyball Team द्वारा West Zone Silver Medal प्राप्त करना राज्य के लिए गौरवपूर्ण उपलब्धि है।
- SPV मॉडल के अंतर्गत, राज्य ने पिछले तीन वर्षों से कार्यरत ग्राम पंचायतों के मामले में सौ फीसदी तथा नेटवर्क अपटाइम के मामले में पंचानबे फीसदी के साथ प्रथम स्थान प्राप्त किया है। भारतनेट के अंतर्गत फेज-2 में डिजिटल सेवा सेतु में शामिल तीन सौ इक्कीस सेवाएं लगभग 100 Mbps की तेज इंटरनेट गति के साथ उपलब्ध कराई जा रही हैं, जिसका लाभ लगभग नौ हजार संस्थाओं को मिल रहा है।
- वर्ष 2022-23 में भारतनेट फेज-2 के अंतर्गत बाईस जिलों की सात हजार छह सौ पच्चासी से अधिक ग्राम पंचायत कार्यालयों में वाई-फाई के माध्यम से इंटरनेट सेवा प्रदान करने हेतु "ग्रामीण वाई-फाई" परियोजना शुरू की गई थी। इस ग्रामीण वाई-फाई परियोजना के माध्यम से गांवों के नागरिकों को प्रतिदिन पहले साठ मिनट (एक घंटा) निःशुल्क इंटरनेट सुविधा का सीधा लाभ मिल रहा है। इसके बाद नाममात्र दर पर रिचार्ज कराकर ग्रामीण नागरिक इंटरनेट सेवा का लाभ ले रहे हैं।
- 200 से अधिक डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) योजनाओं में आधार प्रमाणीकरण सेवाओं का उपयोग किया जा रहा है। गत वित्तीय वर्ष में छप्पन करोड़ से अधिक आधार प्रमाणीकरण ट्रांजैक्शन किए गए हैं।
- गुजरात बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर गुजरात सरकार का एक अत्याधुनिक बायोटेक्नोलॉजी अनुसंधान केंद्र है। गुजरात राज्य ने राष्ट्रीय जैव-सुरक्षा के महत्व को ध्यान में रखते हुए "नेशनल सेंटर फॉर हाई-कंटेनमेंट पैथोजन रिसर्च फैसिलिटी" के रूप में तीन सौ बासठ करोड़ के खर्च से भारत की दूसरी अत्याधुनिक बायो-सेफ्टी लेवल-4 (BSL-4) प्रयोगशाला को विकसित करने का कार्य शुरू किया है। इसके

माध्यम से कोरोना, चांदीपुरा, CCHF जैसे अत्यंत संक्रामक वायरस पर दवा और वैक्सीन के अनुसंधान में सहायता मिलेगी।

- गुजरात में पशुओं की दुग्ध उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए NDDB, बनास, साबर डेयरी तथा GCMMF के साथ मिलकर चालीस हजार पशुओं के जीनोटाइपिंग का कार्यक्रम चलाया जा रहा है और अब तक अठाईस हजार से अधिक पशुओं का जीनोटाइपिंग किया जा चुका है। इससे आने वाले समय में अधिक दुग्ध उत्पादन क्षमता वाले पशुधन का विकास किया जा सकेगा।
- राज्य में हुए चांदीपुरा वायरस आउटब्रेक के दौरान गुजरात बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर ने PCR आधारित टेस्ट विकसित कर निदान का समय चौबीस घंटे से भी कम कर दिया है और अब तक तीन सौ अनासी नमूनों का परीक्षण पूर्ण किया गया है। इसके अतिरिक्त चांदीपुरा वायरस का जीनोम सीक्वेंस भी किया गया है।
- GIFT सिटी में AI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को कार्यरत किया गया है, जहां सार्वजनिक सेवाओं के लिए डिप्लॉय करने योग्य AI सॉल्यूशन्स हेतु AI इनोवेशन चैलेंज शुरू किया गया है। AI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में अठारह स्टार्ट-अप कार्यरत हैं। इसके अलावा सरकारी क्षेत्र के सोलह यूज-केस और निजी क्षेत्र के चौदह यूज-केस के लिए AI इनोवेशन चैलेंज लॉन्च किया गया है।
- देश में AI क्षमता तथा बौद्धिक संपदा (IP) के विकास हेतु राज्य सरकार, केंद्र सरकार और निजी क्षेत्र के संयुक्त सहयोग से तीन सौ करोड़ के खर्च से देश का सर्वप्रथम Indian AI Research Organization (IARIO) स्थापित किया गया है।
- राज्य धोलेरा SIR (भारत का पहला वाणिज्यिक सेमीकंडक्टर फैब) और साणंद (माइक्रोन, CG सेमी तथा केन्स के साथ पैकेजिंग क्लस्टर) में स्थित मार्फी परियोजनाओं के माध्यम से वैश्विक सेमीकंडक्टर वैल्यू चेन में प्रवेश कर रहा है, जिससे उत्पादन नेतृत्व और रणनीतिक सप्लाय चेन मजबूत हो रही है। इन परियोजनाओं में एक दशमलव चौबीस लाख करोड़ से अधिक का निवेश शामिल है तथा पैंतालिस हजार से अधिक प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होने की अपेक्षा है।
- गुजरात स्थानीय उत्पादन और आकाश आधारित एप्लिकेशनों को समर्थन देने वाली समर्पित स्पेस टेक नीति के माध्यम से अंतरिक्ष क्षेत्र में भी नेतृत्व को आगे

बढ़ा रहा है। इसके लिए साणंद के पास खोरज GIDC को विशेष स्पेस टेक्नोलॉजी हेतु विकसित किया जा रहा है। इस पार्क में अजीष्टा कंपनी द्वारा देश के स्वदेशी उपग्रह निर्माण संयंत्र की स्थापना की जा रही है।

वन एवं पर्यावरण

- सामाजिक वनीकरण माध्यम से पूरे राज्य में वर्ष 2025-26 में “एक पेड़ मां के नाम 2.0” अभियान के तहत साढ़े दस करोड़ से अधिक पौधों का रोपण किया गया।
- 05 जून, 2025 विश्व पर्यावरण दिवस पर राज्य में कुल 331 कार्यक्रमों में सड़सठ हजार से अधिक पौधों का रोपण किया गया तथा अड़सठ सिंदूर वन बनाए गए।
- राज्य में चार राष्ट्रीय उद्यान, चौबीस अभयारण्य और एक संरक्षण रिजर्व क्षेत्र सहित कुल उनतीस संरक्षित क्षेत्र हैं। गुजरात वन्यजीव संरक्षण और संवर्धन क्षेत्र में अग्रणी स्थान रखता है।
- मार्च-2025 में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदीजी की अध्यक्षता में राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की 7वीं बैठक सासण में आयोजित की गई। जिसमें प्रधानमंत्रीजी द्वारा राज्य में एशियाई सिंह के संरक्षण और संवर्धन के प्रयासों की सराहना की गई तथा इस संबंध में बृहत् गीर क्षेत्र में देखी गई लोकभागीदारी, सहअस्तित्व और मानव-वन्यजीव सहिष्णुता की भावना जैसी बातें देश के अन्य हिस्सों में भी अनुकरण करने का दिशानिर्देशन दिया गया।
- 16वीं सिंह जनगणना अनुमान का कार्य 10 मई से 13 मई के बीच कुल पैंतीस हजार वर्ग कि.मी. क्षेत्र में किया गया, जिसमें ग्यारह जिलों की अठावन तहसीलें शामिल थीं। सिंह जनसंख्या का अनुमान कुल आठ सौ इकरानबे शेरों के रूप में दर्ज किया गया। वर्ष 2020 की तुलना में वर्ष 2025 में सिंह की संख्या में बत्तीस दशमलव बीस फीसदी की वृद्धि हुई।
- चीते की संख्या स्थापित करने के लिए भारत सरकार और राज्य सरकार के दीर्घ दृष्टिकोण से कच्छ जिले के बन्नी ग्रासलैंड में लगभग छह सौ हेक्टेयर क्षेत्र में चीता ब्रिडिंग सेंटर की स्थापना की गई है।
- पिछले वर्ष से राज्य के रतनमहल अभयारण्य में लगभग तीस वर्षों बाद एक बाघ का आगमन हुआ है और यह उस क्षेत्र में स्थायी रूप से रह रहा है।
- मैं राज्य सरकार को जलप्लावित क्षेत्रों के लिए उल्लेखनीय कार्य करने के लिए अभिनंदन देता हूं। राज्य में अब तक चार जल प्लावित क्षेत्र- नळ सरोवर पक्षी

अभयारण्य, थोळ पक्षी अभयारण्य, खीजड़िया पक्षी अभयारण्य, वढवाणा पक्षी अभयारण्य को रामसर साइट्स के रूप में घोषित किया गया था। दिनांक 30/01/2026 को गुजरात के एक और क्षेत्र: कच्छ में स्थित छारी-ढंढ पक्षी अभयारण्य को भी रामसर साइट के रूप में घोषित किया गया है जो गुजरात राज्य के लिए गर्व की बात है। यह राज्य की पांचवीं रामसर साइट बन गई है।

- उद्योगों की चिमनियों से निकलने वाले रजकण (पार्टिकुलेट मैटर) से होने वाले वायु प्रदूषण के नियंत्रण के लिए मेरी सरकार ने ETS-PM (Emission Trading Scheme Particulate Matter) योजना को सुरत और अहमदाबाद में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लागू किया है। इसके तहत पार्टिकुलेट मैटर (PM) का अधिक उत्सर्जन करने वाले उद्योग द्वारा पैसे देकर कम उत्सर्जन करने वाले उद्योग से परमिट खरीदना पड़ता है, जबकि कम उत्सर्जन करने वाले उद्योग को परमिट बेचने से वित्तीय लाभ होता है, जिससे उद्योग प्रदूषण घटाने के लिए प्रेरित होते हैं। इस स्कीम की 'Clean Our Air' श्रेणी के तहत 05 नवंबर, 2025 को रियो-डी-जानेरो, ब्राजील में आयोजित Earth shot Award - 2025 के लिए फाइनलिस्ट के रूप में चयन किया गया था।

प्रशासनिक सुधार एवं आयोजन

- स्पीपा के सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस द्वारा श्री अटल बिहारी वाजपेयीजी की 100वीं जन्मजयन्ती के अवसर पर अटल व्याख्यानमाला (लेक्चर सीरीज) का आयोजन किया गया।
- गुजरात (सार्वजनिक सेवाओं के संबंध में नागरिकों का अधिकार) अधिनियम, 2013 पूर्ण रूप से लागू होने के साथ इस कानून के तहत गुजरात सरकार के कुल बीस विभागों की कुल चार सौ अड़तालिस नागरिकों को सीधे प्रभावित करने वाली सेवाओं को कानून के तहत शामिल किया गया है।
- नागरिकों की समस्याओं के समाधान के लिए भारत सरकार के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग द्वारा ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने के लिए PG पोर्टल सॉफ्टवेयर के माध्यम से नागरिकों की तीन लाख, अड़तालिस हजार पांच सौ अड़तीस शिकायतों का निपटान किया गया है।
- भारत के अन्य राज्यों में रहने वाले गुजरातियों के अलावा विदेश में रहने वाले, अठारह से चालीस वर्ष के मूल गुजरात निवासी गैर-निवासी गुजरातियों की युवा पीढ़ी गुजरात की यात्रा करें, अपने वतन की खुशबू को जाने, अनुभव करने और समझने के

लिए सुधारित गुजरात परिभ्रमण योजना वित्तीय वर्ष 2025-26 से लागू की गई है। इस योजना में गुजरात में लगातार दस दिन के कार्यक्रम में परिवहन (ट्रांसपोर्टेशन), आवास और भोजन तथा स्थल भ्रमण की सुविधाएं प्रदान की जाती हैं।

- मेरी सरकार द्वारा गठित गुजरात प्रशासनिक सुधार पैनल (GARC) द्वारा अब तक कुल छह रिपोर्टें प्रस्तुत की गई हैं, जिनमें प्रशासनिक प्रक्रियाओं में सुधार, मानव संसाधन प्रबंधन, विशेषकर भर्ती और चयन प्रक्रियाओं में पारदर्शिता, टेक्नोलॉजी आधारित शासन, नागरिकलक्ष्यी सेवा वितरण तथा जिम्मेदारी और पारदर्शिता को मजबूत बनाने वाली अनेक व्यवहारिक और प्रभावी सिफारिशें शामिल हैं। सरकार ने इन सिफारिशों को बड़े पैमाने पर स्वीकार किया है और इनमें से कई सिफारिशें आज कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं, जो गुजरात में सुशासन और प्रभावी प्रशासन की दिशा में एक महत्वपूर्ण और दृढ़ कदम साबित हो रही हैं।
- मेरी सरकार ने आधुनिक मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली (Human Resource Management System) अपनाते हुए सभी सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों की सेवा पुस्तिका तथा सेवा और वित्तीय मामलों को इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी (ICT) आधारित “कर्मयोगी पोर्टल” और “कर्मयोगी मोबाइल एप्लिकेशन” पर उपलब्ध कराया है।
- विकसित भारत एट 2047 के राष्ट्रीय दृष्टिकोण को प्रभावी रणनीति में रूपांतरित करने के उद्देश्य से मेरी सरकार ने दीर्घकालिक विकास एजेंडा का समर्थन करने हेतु सामरिक और प्रमाण-आधारित इनपुट प्रदान करने के लिए सितंबर-2024 में गुजरात राज्य इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन (GRIT) की स्थापना की है। GRIT को राज्य का विकास थिंक टैंक के रूप में स्थान दिया गया है।
- नीति आयोग द्वारा विकसित सुरत आर्थिक मास्टर प्लान के आधार पर GRIT ने राज्य के पांच और प्रमुख आर्थिक क्षेत्रों के लिए आर्थिक मास्टर प्लान तैयार किए हैं। जिसका लक्ष्य वर्ष 2047 तक गुजरात के लिए USD 4 ट्रिलियन से अधिक की अर्थव्यवस्था और अठ्ठाईस मिलियन से अधिक नये रोजगार का सृजन करना है। यह आर्थिक मास्टर प्लान लगभग बीस प्राथमिकता वाले क्षेत्रों और उनतीस मेगा प्रोजेक्ट्स द्वारा संचालित तेज और टिकाऊ विकास पर ध्यान केंद्रित करता है, जिसमें लगभग साठ ट्रिलियन की कुल निवेश क्षमता शामिल है।

- नीति आयोग द्वारा आकांक्षित ब्लॉक कार्यक्रम (ABP) के तहत जोन 4 (पश्चिमी जोन) की रैंकिंग में सितंबर-2025 तक नर्मदा जिले की नांदोद तहसील तथा दिसंबर – 2024 तक डांग जिले की सुबीरा तहसील अग्रणी रहे हैं। इन दोनों तहसीलों को नीति आयोग द्वारा पुरस्कार के रूप में एक करोड़ की राशि घोषित की गई है।

सूचना एवं प्रसारण

- राज्य सरकार की लोककल्याणकारी और लाभदायी योजनाओं तथा कार्यक्रमों की जानकारी सामान्य नागरिक और लाभार्थियों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी प्रभावी ढंग से निभाई जा रही है।
- राज्य के प्रत्येक जिला कलेक्टर कार्यालय, जिला विकास अधिकारी कार्यालय और महानगरपालिका कार्यालय में डिजिटल डिस्प्ले कम एग्जिबिशन लगाई गई है, जिसमें राज्य सरकार की योजनाओं को डिजिटल रूप में कार्यालय के समय दौरान प्रस्तुत किया जाता है। इससे सामान्य नागरिक स्वयं को मिलने वाले लाभ या योजना की जानकारी प्राप्त कर सकता है।

न्याय तंत्र

- सुदृढ़ न्याय तंत्र लोकतंत्र का मजबूत स्तम्भ है। कालोल (पंचमहाल), प्रांतीज (साबरकांठा), साणंद (अहमदाबाद) तथा उच्छल (तापी-व्यारा) में नवनिर्मित तहसील स्तर की कोर्ट बिल्डिंग का लोकार्पण किया गया है।
- मोरबी में दो करोड़ अड़तालिस लाख के खर्च से बने नवनिर्मित चैरिटी भवन का लोकार्पण किया गया है।
- सरकार के महत्वपूर्ण IILMS Project के तहत राज्य सरकार पक्षकार हो, ऐसे कोर्ट मामलों का मैपिंग किया गया है। इस पोर्टल के माध्यम से संबंधित कोर्ट में हुई कार्यवाही की जानकारी विभाग के संबंधित अधिकारियों को समय पर प्राप्त होती है, ताकि राज्य सरकार द्वारा समय पर प्रभावी कार्रवाई करके कोर्ट में अपना पक्ष प्रस्तुत करना आसान हो सके।

क्लायमेट चेंज

- विश्व पर्यावरण दिवस (5-जून) पर गुजरात क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर (GCAT) पोर्टल लॉन्च किया गया है। यह देश में किसी भी राज्य द्वारा क्लाइमेट सूचकांकों से संबंधित जानकारी को जिला स्तर पर प्रदर्शित करने वाला पहला डिजिटल प्लेटफॉर्म है।
- सरकारी इमारतों पर सोलर सिस्टम लगाने की योजना के तहत 100 फीसदी सरकारी सहायता के साथ वर्ष 2025-26 में जनवरी-2026 अंत तक छह सौ सात सरकारी इमारतों पर अंदाजित साठ करोड़ रुपये की लागत से 7.75 मेगावाट सोलर फोटोवोल्टिक रूफटॉप सिस्टम की स्थापना की गई है। तथा अब तक कुल पांच हजार, दो सौ चवालिस सरकारी इमारतों पर चार सौ छह करोड़ रुपये की

लागत से पच्चासी मेगावाट से अधिक की सोलर फोटोवोल्टिक रूफटॉप सिस्टम की स्थापना की जा चुकी है।

- बैटरी संचालित द्विचक्री वाहन के लिए सब्सिडी (सहायता) योजना के तहत विद्यालयों में कक्षा 11 से 12 तथा कॉलेज में अध्ययनरत विद्यार्थियों को वर्ष 2025-26 में जनवरी-2026 अंत तक DBT के माध्यम से एक हजार सात सौ चौसठ विद्यार्थियों को दो करोड़ छियासठ लाख रुपये की सब्सिडी (सहायता) प्रदान की गई है। अब तक DBT के माध्यम से कुल पचपन हजार, पांच सौ चौदह विद्यार्थियों को बासठ करोड़ रुपये से अधिक की सब्सिडी (सहायता) प्रदान की जा चुकी है।

पंद्रहवीं गुजरात विधानसभा के इस सम्माननीय सदन को संबोधित करने का मुझे अवसर मिला है। मुझे यह बताते हुए आनंद हो रहा है कि गुजरात शक्तिशाली, समृद्ध और सुरक्षित भारत का आदर्श राज्य है। गुजरात का सर्वग्राही विकास सूरज की तरह चमक रहा है, तब जनप्रिय एवं यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्रभाई मोदीजी के नेतृत्व में हम गुजरात की विकास यात्रा को अभी बहुत आगे लेकर जाना हैं। आत्मनिर्भर और विकसित गुजरात के निर्माण से आत्मनिर्भर और विकसित भारत के निर्माण में योगदान देना है। गुजरात देश का ग्रोथ इंजन है और इसे और मजबूत बनाने की हम सबकी जिम्मेदारी है।

प्रत्येक गुजराती दुनिया में गुजराती होने का गौरव महसूस कर सके और गुजरात के बारे में स्वाभिमान रख सके, ऐसा गुजरात बनाने का प्रयास करने की जिम्मेदारी जनता ने आप सभी को सौंपी है। आप सभी अपने सार्वजनिक जीवन के अनुभव और जनता की अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए इस सदन में जनता के प्रतिनिधि के रूप में अपना सर्वोत्तम योगदान देंगे, ऐसी अभिलाषा व्यक्त करता हूं। जनता के यह आशीर्वाद जनसेवा के लिए आप सभी को अप्रतिम बल प्रदान करेगा, ऐसी मुझे श्रद्धा है।

भारत माता की जय

जय जय गरवी गुजरात



सत्यमेव जयते

गुजरात सरकार

गुजरातना राज्यपाल
श्री आचार्य देवव्रतनुं
गुजरात विधानसभा समक्ष
प्रवचन

गांधीनगर
सोमवार, १ इमी फ़ेब्रुआरी, २०२६

માનનીય અધ્યક્ષ મહોદય તથા વિધાનસભાના માનનીય સદસ્યશ્રીઓ,

પંદરમી ગુજરાત વિધાનસભાના આઠમા સત્રનાં મંગલ પ્રારંભે આપ સૌનું હૃદયપૂર્વક સ્વાગત કરું છું. વિશ્વને સત્ય અને અહિંસાનો માર્ગ બતાવનાર મહાત્મા ગાંધીજી, દેશને એકતાના તાંતણે બાંધનાર સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ, ગુજરાતના મહાન સપૂત, ઋષિતુલ્ય મૂકસેવક પૂજ્યશ્રી રવિશંકર મહારાજ, આર્ય સમાજના સ્થાપક સ્વામી દયાનંદ સરસ્વતી, ગુજરાતની અસ્મિતાના દવજધારક શ્રી ઈન્દુલાલ યાજ્ઞિકની જન્મભૂમિ એવા ગુજરાત રાજ્યની વિધાનસભાને સંબોધન કરવાનો શુભ અવસર મને પ્રાપ્ય થયો, હું તેનો આનંદ અને ગૌરવ અનુભવું છું. “વિકસિત ગુજરાતથી વિકસિત ભારત”ના મંત્રને સાર્થક કરવા તેમજ ગુજરાતની પ્રજાનો સર્વસમાવેશી, સર્વસ્પર્શી, સર્વાંગી વિકાસ કરવા માટે આ વિધાનસભા ગૃહમાં અનેક ઐતિહાસિક અને નાગરિકલક્ષી નિર્ણયો થયા છે.

દેશનાં કોઈ પણ ખૂણે ‘કેમ છો?’નો ઉચ્ચાર થાય છે, ત્યારે પ્રત્યુત્તરમાં ‘મજામાં!’ સાંભળવા મળે છે. ગુજરાત માટેનો આ આદરભાવ એ ગુજરાતની પ્રગતિશીલ વિચારસરણી અને વિકાસને રાષ્ટ્રીય આંદોલન બનાવનાર વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીના લોકપ્રિય નેતૃત્વનું પ્રતિબિંબ છે. ગુજરાત માટે વિકાસની પરિભાષા એટલે એવો વિકાસ જેમાં “સર્વજન હિતાય, સર્વજન સુખાય”ની ભાવના હોય. ગુજરાતની આ વિકાસયાત્રા એવી છે કે...

જ્યાં **યુવાશક્તિ** ના સપનાઓને મળે છે નવી ‘**ઉડાન**’, જ્યાં ખેડૂતના પરસેવાને મળે છે પૂરતું ‘**સન્માન**’.

જ્યાં **નારીશક્તિ**ના ગૌરવનું અમે કરીએ છીએ ‘**જતન**’, અને **ગરીબ** કલ્યાણ માટે કરીએ છીએ ‘**ચિંતન**’.

એક તરફ **ઉદ્યોગો** માટે છે પ્રગતિના ખુલ્લા ‘**દ્વાર**’, તો બીજી તરફ જન-જનના **આરોગ્ય** ની લેવાય છે સંપૂર્ણ ‘**દરકાર**’.. આવા સર્વસ્પર્શી અને સર્વગ્રાહી વિકાસની આ ગુજરાતની જનતા સાક્ષી રહી છે.

સનાતન સંસ્કૃતિના ધામ સોમનાથ મંદિર પર થયેલા આક્રમણને **એક હજાર વર્ષ** પૂર્ણ થયા છે. સોમનાથ મંદિર માત્ર એક શિવાલય નથી, પણ કાળના કપાળે અંકિત થયેલી આપણી ‘**અસ્મિતા**’ અને ‘**અસ્તિત્વ**’ ની વિજયગાથા છે! ઇતિહાસ સાક્ષી છે કે આ પવિત્ર ધામ પર આક્રમણો થયા, વિનાશના પ્રયાસો થયા... પણ આક્રમણના એ **એક હજાર વર્ષ** પછી પણ આપણી સંસ્કૃતિનો દવજ એટલી જ શાનથી લહેરાઈ રહ્યો છે. તેથી જ આ વર્ષ કોઈ સામાન્ય વર્ષ નથી, આ તો ઇતિહાસના ‘**સંઘર્ષ**’ ને ‘**સ્વાભિમાન**’ માં પલટાવવાનું ઐતિહાસિક પર્વ છે. આજની મારી **યુવા પેઢી**... જે આવતીકાલનું ભારત છે, તેમના રંગરંગમાં રાષ્ટ્રભક્તિ અને આપણી ભવ્ય વિરાસતનું ગૌરવ ઘબઘટું રહે, એ માટે જ આપણે ‘**સોમનાથ સ્વાભિમાન પર્વ**’નું આયોજન કર્યું હતું. જાન્યુઆરીની ૮ થી ૧૫ તારીખ સુધી, ભગવાન સોમનાથના ચરણોમાં, આપણા યશસ્વી પ્રધાનમંત્રીશ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીજીનાં પ્રેરક સાન્નિધ્યમાં આપણે સૌએ સાથે મળીને સંસ્કૃતિની આરાધના કરી છે. આ ઉજવણી એ માત્ર ઉત્સવ નથી, પણ રાષ્ટ્રના ગૌરવને પુનઃપ્રસ્થાપિત કરવાનો એક સુંદર અવસર છે!"

દેશની એકતા અને અખંડિતતાના શિલ્પી લોહપુરુષ **સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ** તથા **ભગવાન બિરસા મુંડાજીની ૧૫૦મી જન્મજયંતિ**ની ઉજવણીનું વર્ષ એક ઐતિહાસિક વર્ષ બની રહ્યું છે. રાષ્ટ્ર ગૌરવને ઉજાગર કરવાનું આ પાવન પર્વ છે. આ વર્ષ રાષ્ટ્રગાન **વંદે માતરમ** તથા સરદાર સાહેબની રાષ્ટ્રીય વિચારધારાના વૈશ્વિક પ્રચાર-પ્રસારનું પ્રેરણાસ્ત્રોત બની રહ્યું છે. અખંડ ભારતના શિલ્પી, લોહપુરુષ સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલની જન્મજયંતિનાં સુઅવસરે કરમસદથી કેવડીયા યુનિટી માર્ચ સરદાર @૧૫૦નું આયોજન થયું. કરમસદની પાવન ‘**૨૪**’ માંથી પ્રગટેલી રાષ્ટ્રભક્તિની જ્યોત, આ ૧૧ દિવસની પદયાત્રા જ્યારે વિશ્વની સૌથી વિરાટ પ્રતિમા ‘સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી’ના ચરણોમાં વંદન કરવા પહોંચી, ત્યારે ગુજરાતના ઇતિહાસમાં એક સોનેરી પૃષ્ઠ ઉમેરાયું. આ ‘સરદાર@150’ પદયાત્રા કોઈ સામાન્ય યાત્રા નહોતી, પરંતુ ભારતીયોના ‘**જન**’ અને ‘**મન**’ ને એકતાના અદ્રશ્ય તાંતણે ગૂંથતી એક અવિસ્મરણીય ‘**એકતાયાત્રા**’ બની રહી.

ઘરતી આબા ભગવાન બિરસા મુંડાજીની ૧૫૦મી જન્મજયંતિને યાદગાર બનાવવા અને જનજાતિય નાયકોના શૌર્ય તથા અમૂલ્ય યોગદાનને સન્માનિત કરવા માટે સમગ્ર દેશમાં ૨૦૨૫નું વર્ષ જનજાતીય ગૌરવ વર્ષ તરીકે ઉજવીને ભગવાન બિરસા મુંડાજીને સાચા અર્થમાં સન્માન આપવામાં આવ્યું છે. આ ઉજવણીના ભાગરૂપે જનજાતીય ગૌરવ દિવસની રાષ્ટ્રીય કક્ષાની ભવ્ય -દિવ્ય ઉજવણી શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીની ઉપસ્થિતિમાં નર્મદા જિલ્લાનાં ડેડિયાપાડા ખાતે કરવામાં આવી, જે ગુજરાત માટે ખરેખર ગૌરવની વાત છે. ભગવાન બિરસા મુંડાજીના અને જનજાતીય સમાજના યોગદાનને લોકો સુધી પહોંચાડવા રાજ્યમાં ૭ થી ૧૩ નવેમ્બર, ૨૦૨૫ દરમિયાન જનજાતીય ગૌરવ રથયાત્રાનું સફળ આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. 'સૌનો સાથ, સૌનો વિકાસ'ના મંત્રને ચરિતાર્થ કરવા તેમજ 'વિકાસમાં કોઈ પાછળ ન રહે અને વિકાસથી કોઈ વંચિત પણ ન રહે'ની ભાવના સાથે સરકારે જનજાતિઓના ઉત્કર્ષનો માર્ગ કંડાર્યો છે. જનજાતિ સમુદાયોની આરોગ્ય સુખાકારી વધુ સુનિશ્ચિત કરવા માટે પ્રધાનમંત્રીશ્રીની પ્રેરણાથી ગુજરાત એ જીનોમ સિક્વન્સીંગ પ્રોજેક્ટ શરૂ કરનારું દેશનું પ્રથમ રાજ્ય બન્યું છે. ખાસ નબળા આદિમ જૂથોને પ્રધાનમંત્રી આવાસ યોજના ગ્રામીણ અંતર્ગત આવાસ ફાળવણીમાં ગુજરાતે દેશમાં બેસ્ટ પરફોર્મિંગ સ્ટેટ તરીકે પુરસ્કાર મેળવવાનું ગૌરવ પ્રાપ્ત કર્યું છે.

અમદાવાદ ખાતે આયોજિત **આંતરરાષ્ટ્રીય પતંગ મહોત્સવ ૨૦૨૬** માં દેશના માનનીય વડાપ્રધાનશ્રી તેમજ જર્મનીના માનનીય ચાન્સેલરશ્રીની પ્રેરક ઉપસ્થિતિએ રાજ્યના ઉત્સવને વૈશ્વિક ફલક પર મૂકી એક નવી ઓળખ આપી છે. જેમાં પતંગબાજીની સાથે સાથે ગ્રાન્ડ સિમ્ફની, ફ્લોટિંગ આર્ટ કાઈટ મ્યુઝિયમ અને પોળ સંસ્કૃતિનાં પ્રદર્શન દ્વારા રાજ્યના ભવ્ય વારસાને રજૂ કરાયો હતો.

મારી સરકાર **સરળ, સહજ પરંતુ મક્કમ અને લોકાભિમુખ વહીવટ** માટે સતત પ્રયત્નશીલ રહી છે, જેના ભાગરૂપે પૂર્વ વડાપ્રધાન શ્રી અટલ બિહારી વાજપેયજીની જન્મ જયંતી નિમિત્તે **‘સુશાસન દિવસ’**ની ભવ્ય રીતે ઉજવણી કરવામાં આવી રહી છે. રાજ્યના નાગરિકોના ‘ઇઝ ઓફ લિવિંગ’ વધારવા માટે યોજનાઓ, સેવાઓ અને વિકાસલક્ષી કામો તથા ફરિયાદ નિવારણની કામગીરી સરકાર અસરકારક રીતે કરી રહી છે. રાજ્યના યશસ્વી મુખ્યમંત્રીશ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલના દિશાદર્શનમાં વિવિધ વિભાગોની જુદા જુદા પ્રકારની કામગીરીઓના મહત્વપૂર્ણ પેરામીટર્સને સી.એમ. ડેશબોર્ડ પર એક જ ઇન્ટીગ્રેટેડ પ્લેટફોર્મ પર લાવવામાં આવ્યા છે. ગુડ ગવર્નન્સની એ ઉજ્જવળ પરંપરાને ગતિપૂર્વક આગળ ધપાવતાં સી.એમ. ડેશબોર્ડ દ્વારા સમગ્રલક્ષી **ગવર્નન્સ પર્ફોર્મન્સ ઇન્ડેક્સ (GPI)** તૈયાર કરવામાં આવ્યા છે.

કોમનવેલ્થ ગેમ્સને ૧૦૦ વર્ષ પૂર્ણ થઈ રહ્યા છે, ત્યારે રાજ્યના તત્કાલિન મુખ્યમંત્રીશ્રી અને હાલમાં દેશના યશસ્વી વડાપ્રધાનશ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીની ૨૪ વર્ષની અથાગ મહેનતથી રમતગમત ક્ષેત્રે જે ઇકોસિસ્ટમ ઉભી કરી છે તેના ફળસ્વરૂપે **કોમનવેલ્થ ગેમ્સના** નેતૃત્વનો અવસર આપણને પ્રાપ્ત થયો છે, તે આપણા સૌ માટે ગૌરવવંતી ક્ષણ છે. આ કોમનવેલ્થ ગેમ્સથી વિશ્વને ભારતને આંગણે આવકારવા અને રાજ્યને સ્પોર્ટ્સ હબ બનાવવા ગુજરાત સજ્જ છે, પ્રતિબદ્ધ છે.

કુદરતી આફતના પ્રસંગે મારી સરકાર હંમેશા ગુજરાતની જનતાની પડખે ખભે ખભો મિલાવીને ઊભી રહી છે. રાજ્યમાં આવેલા પૂર અને કમોસમી વરસાદને પરિણામે ખેડૂતોને થયેલા નુકસાનમાંથી તેમને ફરી બેઠા કરવા માટે મુખ્યમંત્રીશ્રીએ સંવેદનશીલ અભિગમ દાખવીને રૂપિયા **અગિયાર હજાર કરોડથી** વધુનું સહાય પેકેજ જાહેર કર્યું છે. આ ઐતિહાસિક પેકેજ એ માત્ર એક સહાય નથી, પણ ઘરતીપુત્રોના પરિશ્રમનું **‘સન્માન’** છે અને કૃષિ અર્થતંત્રને બેઠું કરવાનું **‘અભિયાન’** છે. રાજ્ય સરકાર દ્વારા જાહેર કરાયેલું રાહત પેકેજ માત્ર નીતિગત પગલું નથી, તે એક માનવીય સંવેદનાનું પ્રતિબિંબ છે કે ‘રાજ્ય સરકાર ઘરતીપુત્રો સાથે છે.’ આ પગલાં ખેડૂતના પરિશ્રમને પારખવા સાથે રાજ્યના કૃષિ આધારિત અર્થતંત્રને ઊભું કરવાની દિશામાં એક મજબૂત પગથિયું સાબિત થશે.

મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલનાં નેતૃત્વમાં અત્યાધુનિક ગુજરાતના વિકાસપથ પર એક મજબૂત પગલાં તરીકે રાજ્યના ચાર ઝોનમાં **"વાઈબ્રન્ટ ગુજરાત રિજનલ કોન્ફરન્સ"** નું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે, જેમાં મહેસાણા તથા રાજકોટ ખાતે વાઈબ્રન્ટ ગુજરાત રિજનલ કોન્ફરન્સ સંપન્ન થયેલ છે. 'રિજનલ એસ્પિરેશન્સ, ગ્લોબલ એમ્બિશન્સ'ની થીમ અને 'હર ઘર સ્વદેશી, ઘર ઘર સ્વદેશી'ની ભાવના સાથે યોજાયેલી આ રિજનલ કોન્ફરન્સ માત્ર એક કાર્યક્રમ નહીં, પરંતુ 'આત્મનિર્ભર ગુજરાતથી આત્મનિર્ભર ભારત'ના વિઝનને સાકાર કરવા માટેનો એક વ્યુહાત્મક મંચ બની રહ્યો છે. વાઈબ્રન્ટ ગુજરાત રિજિયોનલ કોન્ફરન્સની આ નવતર પહેલ રાજ્યના ઉદ્યોગોને વડાપ્રધાનશ્રીના વિકસિત ભારત ૨૦૪૭ના વિઝનને આત્મનિર્ભર ભારત અને વોકલ ફોર લોકલ તથા લોકલ ફોર ગ્લોબલનું દિશાદર્શન કરવા માટેનું મહત્વનું પ્લેટફોર્મ બનશે.

મહેસૂલની જટિલ અને ગૂંચવણભરી પ્રક્રિયાઓને લોકાભિમુખ અને સરળ બનાવવા ગુજરાતે પારદર્શી અને વિશ્વસનીય પ્રશાસન માટે **I-ORA (આઈ-ઓરા) પોર્ટલ**ની પહેલ કરી છે. આ એક એવી પહેલ છે જેના પરિણામે લેન્ડ રેકૉર્ડ્સ સંબંધિત ૩૫ થી વધુ સેવાઓ એન્ડ ટુ એન્ડ ઓનલાઈન ઉપલબ્ધ થઈ છે. વધુમાં, નાગરિકોને ઘેર બેઠાં ઇન્ડેક્સ-૨(બે) અને જમીન સંબંધિત દસ્તાવેજો પહોંચાડવા માટે GARVI-2.0 (ગરવી ૨.૦) જેવા ડિજિટલ પ્લેટફોર્મની સુવિધા પણ સરાહનીય છે.

ગુજરાત દેશમાં સૌથી વિશાળ સાગરકાંઠો ધરાવે છે. મુખ્યમંત્રીશ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલના નેતૃત્વમાં **‘સમુદ્ર સે સમૃદ્ધિ’**ના વિઝનને સાકાર કરવા ગુજરાતમાં બંદરોના આધુનિક આંતરમાળખાકીય વિકાસનું એક મહત્વપૂર્ણ કદમ સરકારે ભર્યું છે. આ હેતુસર ગુજરાત મેરિટાઈમ બોર્ડ સાથે ગુજરાત પીપાવાવ પોર્ટ લિમિટેડ (APM ટર્મિનલ્સ) દ્વારા ૧૭ હજાર કરોડ રૂપિયાના મૂડી રોકાણના સમજૂતી કરાર (MoU) કરવામાં આવ્યા છે. આ MoU દ્વારા પીપાવાવ પોર્ટ્સના વિસ્તરણને પરિણામે ગુજરાતની ભારતના ‘મેરિટાઈમ ગેટ-વે’ તરીકે પ્રસ્થાપિત થયેલી ઓળખ વધુ સુદૃઢ થશે.

મારી સરકારે રાજ્ય શાસનમાં **વહીવટી વિકેન્દ્રીકરણ**થી લોકોને જિલ્લા- તાલુકા કક્ષાની કચેરીઓ સાથેના કામકાજમાં સુગમતા રહે, નવું તાલુકા મથક નજીકમાં જ મળવાથી સામાજિક, આર્થિક, આરોગ્ય અને શિક્ષણ સહિતની સર્વત્રાહી સુવિધામાં વધારો થાય તેમજ અંતરિયાળ ગામોમાંથી તાલુકા મથકે આવવા-જવામાંથી સમય, શક્તિ અને નાણાંનો પણ બચાવ થાય તેવા પ્રજાહિતલક્ષી ઉદાત્ત અભિગમથી બનાસકાંઠામાંથી **નવો વાવ-થરાદ જિલ્લો** તથા **નવા ૧૭ તાલુકા**ની રચના કરી છે.

વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીની જન્મભૂમિ અનંત અનાદિ વડનગરના ઐતિહાસિક શર્મિષ્ઠા તળાવ પરિસર ખાતે મુખ્યમંત્રીશ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલની ઉપસ્થિતિમાં ૧૧મા આંતરરાષ્ટ્રીય યોગ દિવસની **"Yoga for One Earth One Health"** અને "સ્વસ્થ ગુજરાત મેદસ્વિતા મુક્ત ગુજરાત" થીમ સાથે રાજ્ય કક્ષાની ઉજવણી કરવામાં આવી હતી. આ પ્રસંગે ૨૧૨૧ યોગ સાઘકોના એક સાથે ભુજંગાસન દ્વારા નવો કિર્તીમાન પ્રસ્થાપિત કરીને ગિનિસ બુક ઓફ વર્લ્ડ રેકર્ડમાં સ્થાન મેળવ્યું છે.

માનનીય વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ જેને ડેમોગ્રાફિક ડિવિડન્ડ કહી છે એવી યુવાશક્તિને લોકોની સેવા કરવાની તક પ્રાપ્ત કરાવવા ગત વર્ષમાં ૩૦,૦૦૦ થી વધુ ઉમેદવારોને મારી સરકાર દ્વારા નિમણૂકપત્ર એનાયત કરવામાં આવ્યા છે. જનસેવાની તક મેળવનાર આ યુવા પેઢી ઈમાનદારી અને નિષ્ઠાથી લોકોની સેવા કરવા તથા નવીનતમ અભિગમ સાથે ઉત્તરોત્તર પ્રગતિના શિખરો સર કરવા કટિબદ્ધ છે. આ પ્રક્રિયા અવિરત તેમજ નિયમિત પણે ચાલુ રહે તે હેતુથી રાજ્ય સરકારે મેનપાવર પ્લાનિંગ માટે **૧૦ વર્ષીય ભરતી કેલેન્ડર** તૈયાર કર્યું છે. જે અંતર્ગત વર્ષ ૨૦૨૪ થી ૨૦૩૩ ના સમયગાળામાં **બે લાખથી વધુ** જગ્યાઓ તબક્કાવાર ભરવાનું આયોજન રાજ્ય સરકાર દ્વારા કરવામાં આવ્યું છે.

સરકાર ઇમાનદારી અને નિષ્ઠાથી લોકોની સેવા કરનાર સરકારી કર્મચારીઓ પ્રત્યે પણ સંવેદનશીલ છે. ગુજરાતમાં ફરજ બજાવતા અખિલ ભારતીય સેવાના અધિકારીઓ અને રાજ્ય સરકારના અધિકારી-કર્મચારી, પેન્શનરો તથા તેમના પરિવારોના સ્વાસ્થ્યની દરકાર લઈ, મારી સરકારે એક મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય કર્યો છે. આયુષ્યમાન ભારત યોજના અંતર્ગત 'ગુજરાત કર્મચોગી સ્વાસ્થ્ય સુરક્ષા યોજના (G-કેટેગરી)'નો પ્રારંભ કરવામાં આવ્યો છે. જે અંતર્ગત તમામ સરકારી અધિકારી-કર્મચારી અને તેમના પરિવારને રૂ.૧૦ લાખ સુધીની કેશલેસ તબીબી સારવારનો લાભ મળશે અને તેમની સ્વાસ્થ્ય સુખાકારીમાં પણ વધારો થશે.

ભારતના લોકલાડીલા પ્રધાનમંત્રીશ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ કંડારેલા ગુજરાતના વિકાસપથ પર મુખ્યમંત્રીશ્રી ભુપેન્દ્રભાઈ પટેલના નેતૃત્વમાં મારી સરકાર નવા આત્મવિશ્વાસ સાથે ગુજરાતને નવી ઉંચાઈ પર લઈ જવા પ્રતિબદ્ધ છે. મારી સરકારના મૃદુ અને મક્કમ નેતૃત્વ હેઠળ પારદર્શક અને પ્રગતિશીલ નિર્ણયોથી સામાજિક, આર્થિક, શૈક્ષણિક, આરોગ્ય અને માળખાગત સુવિધાઓના મહત્વના ક્ષેત્રોમાં તેજ રફતારથી વિકાસ થઈ રહ્યો છે.

કૃષિ અને ખેડૂત પ્રાકૃતિક ખેતી

કલ્યાણ

જમીન, પર્યાવરણ અને માનવજાતના સ્વાસ્થ્ય માટે પ્રાકૃતિક કૃષિ આશીર્વાદરૂપ છે. પ્રાકૃતિક કૃષિને માનનીય વડાપ્રધાનશ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ પોતાના હૃદયની સૌથી નજીક ગણાવી છે અને આ દેશનો દરેક ખેડૂત પ્રાકૃતિક કૃષિ અપનાવે તેવું તેમનું સ્વપ્ન છે. આ સ્વપ્નને સાકાર કરવા માટે ગુજરાત રાજ્યમાં પ્રાકૃતિક કૃષિનો વ્યાપ વધે તે માટે માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રી ભુપેન્દ્રભાઈ પટેલના માર્ગદર્શન હેઠળ સરકાર દ્વારા સુઆયોજિત ઝુંબેશના રૂપમાં કામગીરી થઈ રહી છે.

- રાજ્યમાં પ્રાકૃતિક કૃષિનો વ્યાપ વધારવા માટે ગુજરાત પ્રાકૃતિક કૃષિ વિકાસ બોર્ડ અને વિશ્વની પહેલી પ્રાકૃતિક કૃષિ યુનિવર્સિટીની સ્થાપના કરવામાં આવી છે. જેમાં પ્રાકૃતિક કૃષિ અંગે તાલીમ, પ્રેરણા પ્રવાસ, સંશોધન, કૉંકલેવ, મેગા શિબિર, પરિસંવાદ, પ્રદર્શનનું આયોજન કરવામાં આવે છે.
- અત્યાર સુધીમાં ૧૯ લાખ જેટલા ખેડૂતોને પ્રાકૃતિક ખેતીની તાલીમ આપવામાં આવી છે.
- ચાલુ વર્ષે પ્રાકૃતિક કૃષિ કરતા એક લાખથી વધુ ખેડૂતોને દેશી ગાય નિભાવ ખર્ચ માટે રૂ.૫૮.૭૭ કરોડની સહાય આપવામાં આવી છે.
- ખેડૂતોને પ્રાકૃતિક કૃષિની પ્રત્યક્ષ જાણકારી મળે તે હેતુથી રાજ્યમાં અત્યાર સુધીમાં ખેડૂતોના ખેતર ઉપર આશરે ૭૧૦૦ મોડેલ ફાર્મનું નિર્માણ કરવામાં આવ્યું છે.
- રાજ્યમાં અંદાજીત ૮ લાખથી વધુ ખેડૂતોએ પ્રાકૃતિક ખેતી અપનાવી છે.
- રાજ્યના ડાંગ જિલ્લાને સંપૂર્ણ રસાયણમુક્ત ખેતી કરતો જિલ્લો જાહેર કરવામાં આવ્યો છે. જે અંતર્ગત ૧૦,૦૦૦ જેટલા ખેડૂતોને પ્રાકૃતિક ખેતી હેઠળ આવરી લઈ રૂપિયા પચીસ કરોડથી વધુની સહાય આપવામાં આવી છે.
- આ વખતે પૂરમાં ચોમાસું ખેડૂતોનાં આંસુ બનીને વરસ્યું હતું. આ અતિવર્ષાનાં અતિકપરા સમયમાં આ સરકાર ખેડૂતોનાં અડગ સાથીદાર તરીકે ઉભી રહી છે. મારી સરકારે કમોસમી વરસાદ સામે ખેડૂતોને સહાય માટે ચાલુ વર્ષે માતબર રકમના કૃષિ રાહત પેકેજની જાહેરાત કરી છે. અત્યાર સુધી ૩૩ લાખથી વધુ ખેડૂતોને રૂ. ૯૬૧૦ કરોડની સહાય અસરગ્રસ્ત ખેડૂતોના બેંક ખાતામાં જમા કરવામાં આવી છે. આ સરકારે ખેડૂતોને થયેલ નુકશાનીની ગણતરી અને ચૂકવણી તાત્કાલિક ધોરણે શરુ કરી અને ગણતરીના સમયમાં પૂર્ણ કરી.

ગુજરાતના ઇતિહાસમાં આટલા ઓછા સમયમાં આટલા મોટા પ્રમાણમાં કોઈ સહાય સીધી ખેડૂતોનાં ખાતામાં પહોંચી હોય તેનો આ ઉજ્જવળ અને પહેલો દાખલો છે. આ દર્શાવે છે કે ઈશદા મજબૂત હોય તો આફતો પણ ઝૂકી જાય છે. આ કામગીરી મારી સરકારની ખેડૂતો પ્રત્યેની સંવેદનશીલતા અને પ્રતિબદ્ધતા દર્શાવે છે.

- **વર્ષ ૨૦૨૫-૨૬ માં રાજ્યમાં ખરીફ સીઝનમાં મગફળી, મગ, અડદ અને સોયાબીન જેવી ખેત પેદાશોની અત્યાર સુધી ૮.૩૨ લાખથી વધુ ખેડૂતો પાસેથી ૩.૧૩,૧૦૦ કરોડના મૂલ્યની ૧૮.૨૪ લાખ મે.ટન થી વધુ જથ્થાની ટેકાના ભાવે ખરીદી કરવામાં આવી છે.** ભારત સરકારના સહયોગથી ટેકાના ભાવે મગફળી, મગ, અડદ અને સોયાબીનની ત્વરિત ખરીદી અને બીજી બાજુ કમોસમી વરસાદના કારણે થયેલ સહાયની ચૂકવણીથી “**ડબલ એન્જિન**” સરકારનો કલ્યાણકારી અભિગમ સાર્થક થાય છે.
- **પ્રધાનમંત્રી કિસાન સમ્માન નિધિ યોજના** હેઠળ રાજ્યમાં, આજદિન સુધીમાં **એક થી એકવીસ હસામાં આશરે ૩.૨૨ હજાર કરોડની સહાય ૬૯ લાખ થી વધુ ખેડૂત કુટુંબોને** તેમના **બેંક એકાઉન્ટમાં સીધી જમા કરવામાં આવી છે.**
- ચાલુ વર્ષ ૨૦૨૫-૨૬ માં **ટ્રેક્ટર તેમજ ટ્રેક્ટર સંચાલિત ખેત ઓખર/સાધનની ખરીદી** માટે બહોળી સંખ્યામાં લાભાર્થીઓને આવરી લેવા માટે રૂ. ૧૪૦૦ કરોડથી વધુની બજેટ જોગવાઈ કરવામાં આવેલ છે. ટ્રેક્ટર ખરીદી માટે સહાય વધારીને વર્ષ ૨૦૨૫-૨૬ થી **એક લાખ રૂપિયા કરવામાં આવેલ છે.**
- રાજ્ય કક્ષાએથી તમામ જિલ્લાઓ અને તાલુકાઓમાં પાક સ્થિતિ, હવામાન આધારિત જોખમો અને રોગ-જીવાતનું રિયલ-ટાઈમ મોનીટરીંગ તેમજ તે અંગે ખેડૂતોને સમયસર અને યોગ્ય માર્ગદર્શન મળી રહે તે હેતુસર “**કૃષિ પ્રગતિ**” **વેબ પોર્ટલ** અને “**કૃષિ પ્રગતિ**” **મોબાઈલ એપ** વિકસાવવામાં આવેલ છે. જેમાં લાખોની સંખ્યામાં ખેડૂતો સીધા જોડાયા છે અને આ એપ્લીકેશનનો લાભ લઈ રહ્યા છે.
- ખેડૂતો વિવિધ સહાયકારી યોજનાઓમાં “Online” અરજી કરી શકે તે માટે ચાલુ વર્ષ ૨૦૨૫-૨૬ થી નવું **આઈ ખેડૂત પોર્ટલ ૨.૦** વિકસાવવામાં આવ્યું છે.
- ભારત સરકારશ્રીની એગ્રીસ્ટેક યોજના હેઠળ ગુજરાત રાજ્ય દ્વારા ફાર્મર રજીસ્ટ્રી હેઠળ અત્યાર સુધીમાં ૫૯ લાખથી વધુ ખેડૂતોનું રજીસ્ટ્રેશન પૂર્ણ કરવામાં આવેલ છે તથા ડીજીટલ ક્રોપ સર્વેની કામગીરી પણ હાથ ધરવામાં આવી છે. જેમાં સારી કામગીરી બદલ ભારત સરકાર દ્વારા રૂપિયા ૪૧૩ કરોડ પ્રોત્સાહક ગ્રાન્ટ તરીકે આપવામાં આવ્યા છે.

બાગાયત

- ગુજરાત પાસે પોતાની આગવી ઓળખ કહી શકાય તેમજ વૈશ્વિક સ્તરે આગવું સ્થાન ધરાવતા બાગાયતી ઉત્પાદનોમાં “**ગીરની કેસર કેરી**”, “**વલસાડી હાકુસ કેરી**” “**કચ્છી ખારેક**” અને “**અમલસાડી ચીકુ**” નો સમાવેશ થાય છે.
- બાગાયતી યોજનાઓના અમલીકરણ થકી વર્ષ ૨૦૨૪-૨૫ માં ફળપાકોમાં ૪.૪૪ લાખ હેક્ટર વિસ્તાર તથા ૮૫.૮૧ લાખ મે.ટન ઉત્પાદન, શાકભાજી પાકોમાં ૮.૭૫ લાખ હેક્ટર વિસ્તાર તથા ૧૮૫ લાખ મે. ટન ઉત્પાદન, મસાલા પાકોમાં ૮.૧૮ લાખ હેક્ટર વિસ્તાર તથા ૧૨.૯૧ લાખ મે.ટન ઉત્પાદન થયેલ છે.

- ચાલુ વર્ષ ૨૦૨૫-૨૬ માં અત્યાર સુધી સંકલિત બાગાયત વિકાસની પ્રવૃત્તિઓ માટે રૂ. ૩૪૧.૪૭ કરોડની સહાય થકી ૧.૭૨ લાખ જેટલા બાગાયતદારોને વિવિધ યોજનાઓ અંતર્ગત લાભાન્વિત કરવામાં આવેલ છે.
- બાગાયત ખાતા દ્વારા બાગાયતી પાકોના કાપણી પછીના વ્યવસ્થાપન માટે રાજ્યમાં વિવિધ માળખાકીય સુવિધાઓ ઉભી કરવામાં આવેલ છે. જેમાં ૫૪૮ કોલ્ડ સ્ટોરેજ તેમજ ૨૭૬૨ પેક હાઉસ, ૮૩ - રાયપર્નીંગ ચેમ્બર, ૪૧૩- સોર્ટીંગ ગ્રેડીંગ એકમ તેમજ ૧૯- રીફરવાન તથા અન્ય માળખાકીય સુવિધાઓનો સમાવેશ થયેલ છે.
- રાજ્યના ખેડૂતોને બાગાયત પાક માટે અદ્યતન ટેકનોલોજી પ્રદાન કરવાના હેતુથી રાજ્યમાં આઠ (૮) સેન્ટર ઓફ એક્સેલેન્સ કાર્યરત છે તથા બીજા નવા ૯ (નવ) સેન્ટર ઓફ એક્સેલેન્સ નિર્માણ પામી રહેલ છે. આ કેન્દ્રો દ્વારા અત્યાર સુધીમાં અંદાજે ૧.૦૦ લાખ જેટલા ખેડૂત, યુવાનોને કૌશલ્યવર્ધન અંગેની તાલીમ આપવામાં આવેલ છે.

પશુપાલન

- ગુજરાત રાજ્યના આર્થિક અને સામાજિક વિકાસમાં પશુપાલન અને ડેરી ક્ષેત્રનું આગવું યોગદાન છે.
- પશુઆરોગ્ય ક્ષેત્રે રાજ્યમાં જાન્યુઆરી, ૨૦૨૬ અંતિત ૬૦ લાખથી વધુ પશુઓને સારવાર તેમજ ૪૦૦૦ થી વધુ પશુ આરોગ્ય મેળાની કામગીરી કરવામાં આવેલ છે.
- રાજ્યના પશુપાલકો પોતાના પશુઓમાં જાતીય સીમેનની સંવર્ધનની અદ્યતન ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ કરવા માટે પ્રોત્સાહિત થાય તે માટે સરકારી સંસ્થાઓ ખાતે માત્ર રૂ. ૫૦/- ફી ચૂકવી જાતીય સીમેનથી કૃત્રિમ બીજદાનની સુવિધા કરવામાં આવી છે. આ વર્ષમાં જાન્યુઆરી, ૨૦૨૬ સુધીમાં ૨.૭૪ લાખ પશુઓમાં જાતીય સીમેનથી કૃત્રિમ બીજદાન થયેલ છે.
- કૃત્રિમ બીજદાન કવરેજની દ્રષ્ટિએ સો લાખથી વધુ સંવર્ધિત પશુધન ધરાવતા રાજ્યોમાં ગુજરાત પ્રથમ ક્રમે છે.
- જાન્યુઆરી, ૨૦૨૬ અંતિત ૧૫,૩૧૫ જેટલા ફર્ટીલીટી ઇમ્પ્રુવમેન્ટ કેમ્પ/જાતીય આરોગ્ય કેમ્પનું આયોજન કરી ૮ લાખથી વધુ પશુઓને સારવાર પૂરી પાડવામાં આવેલ છે.
- ભારતીય સંસ્કૃતિ ગૌ, ગંગા, ગીતા અને ગાયત્રીની સંસ્કૃતિ છે. પબ્લિક ટ્રસ્ટ એક્ટ હેઠળ નોંધાયેલ ગૌશાળા-પાંજરાપોળ ખાતે રાખવામાં આવતા ગાય અને ભેંસ વર્ગના પશુઓના નિભાવ માટે “મુખ્યમંત્રી ગૌમાતા પોષણ યોજના” અંતર્ગત પશુદીઠ પ્રતિદિન રૂ.૩૦/- લેખે સહાય રાજ્ય સરકાર દ્વારા આપવામાં આવે છે. વર્ષ ૨૦૨૫-૨૬ દરમિયાન કુલ ૧,૬૦૦ થી વધુ સંસ્થાઓના ૪.૫૦ લાખથી વધુ પશુઓ માટે રૂ. ૨૪૧.૩૫ કરોડની સહાય ચૂકવવામાં આવી છે.

મત્સ્યોદ્યોગ

- રાજ્યનું વર્ષ ૨૦૨૫-૨૬નું ડિસેમ્બર-૨૦૨૫ અંતિત અંદાજિત મત્સ્ય ઉત્પાદન ૭.૯૧ લાખ મે.ટન થયેલ છે, જેની અંદાજિત કિંમત રૂપિયા ૧૯,૦૦૦/- કરોડ થાય છે.
- મત્સ્ય ઉત્પાદન કેન્દ્રોના વિકાસ માટે અંદાજે રૂ.૧૭૦૦ કરોડના વિવિધ કામો પ્રગતિમાં છે.

- ગુજરાત મત્સ્યોદ્યોગ (સુધારા) કાયદો, ૨૦૨૫ હેઠળ Gujarat State Fisheries Harbour and Aquaculture Authority ની સ્થાપના કરેલ છે, જે આંતરદેશીય એકવાકલ્ચરનાં વિકાસ અને મત્સ્ય ઉત્પાદન કેન્દ્રોની જાળવણી માટેની કામગીરી કરશે.
- **ઝીંગા ફાર્મ ઉછેર ક્ષેત્ર** માટે રૂ.૮૫ કરોડનું Comprehensive Package ચાલુ વર્ષે મંજૂર થયેલ છે જે હેઠળ ભાંભરાપાણી મત્સ્યોદ્યોગ ક્ષેત્રે ફાર્મ ધારકોને ઇલેક્ટ્રીસીટી ડ્યુટી ઉપર સંપૂર્ણ રાહત અને વીજ વપરાશના યુનિટ ઉપર સહાય આપવામાં આવે છે. જાન્યુઆરી – ૨૦૨૬ અંતિત કુલ રૂ ૬૦.૦૦ કરોડનો ખર્ચ કરવામાં આવેલ છે.
- ગુજરાતના માછીમારો નવી ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ કરી મત્સ્ય/ઝીંગા ઉત્પાદન કરી પોતાની આવક બમણી કરી શકે તે માટે વિકસિત ગુજરાત ફંડ હેઠળ ઇન્ટેસીવ એકવાકલ્ચર ફાર્મિંગ માટે તથા મેરીકલ્ચર ઝોનેશન માટે રૂ.૧૨.૫૦ કરોડ ફાળવવામાં આવ્યા છે.
- **પ્રધાનમંત્રી મત્સ્ય સંપદા યોજના** અંતર્ગત માછીમાર જૂથ અકસ્માત વીમા યોજના દ્વારા રાજ્યના ૧,૧૦,૦૦૦ માછીમારોને વીમા કવચ આપવામાં આવ્યું છે.

સહકાર

- ભારત સરકાર દ્વારા બનાવેલ સહકાર મંત્રાલય દ્વારા ‘સહકારથી સમૃદ્ધિ’ના મંત્રને ચરિતાર્થ કરવા માટે અને સહકારી મંડળીઓને આર્થિક રીતે વધુ સક્ષમ તેમજ પારદર્શક બનાવવા માટે રાજ્ય સરકાર દ્વારા અનેકવિધ ક્રાંતિકારી પહેલો અમલમાં મૂકવામાં આવી છે.
- રાજ્યના સહકારી માળખામાં નાણાકીય સમાવેશને વેગ આપવા માટે મારી સરકારે ઐતિહાસિક પગલું ભરીને ૧૨,૫૮૦ થી વધુ માઇક્રો એટીએમ (Micro ATM) કાર્યરત કર્યા છે, જેણે ગ્રામીણ વિસ્તારોમાં અત્યાર સુધીમાં રૂ. ૧૩,૦૦૦ કરોડથી વધુના મૂલ્યના રૂ.૧૬ કરોડ ટ્રાન્ઝેક્શન સફળતાપૂર્વક પૂર્ણ કર્યા છે. આ પહેલ અંતર્ગત ૧૮ લાખથી વધુ પશુપાલકોને બેંકિંગ સેવાઓ સાથે સીધા જોડવામાં આવ્યા છે. તેમજ રાજ્યના મોટા ભાગના ગામો બેંકિંગ સુવિધાનો લાભ મેળવી રહ્યા છે.
- **બનાસ ડેરી** દ્વારા દામા ખાતે દૈનિક ૪૦ મે.ટન ગોબરનું એકત્રીકરણ અને વૈજ્ઞાનિક પ્રોસેસિંગ કરીને **બાયો સી.એન.જી.** નું ઉત્પાદન કરતો પ્લાન્ટ સ્થાપવામાં આવ્યો છે, જેનાથી પશુપાલકોને ગોબરના વેચાણ થકી વધારાની આવક પ્રાપ્ત થઈ રહી છે. આ પ્રોસેસિંગ દરમિયાન તૈયાર થતા ઉચ્ચ ગુણવત્તાયુક્ત ભૂમિ- **જૈવિક ખાતર (“ભૂમિ અમૃત”)** ના ઉપયોગથી ખેડૂતોના ખેતીખર્ચમાં ઘટાડો થયો છે.
- ૧૦૦ મે.ટન ના એક પ્લાન્ટ દ્વારા પ્રતિ દીન આશરે ૧,૮૦૦ કિલો બાયો-સીએનજી (Bio-CNG) અને ૧૦૦ મે.ટન જેટલા જૈવિક ખાતરનું ઉત્પાદન કરવામાં આવે છે. આ જૈવિક ખાતરનું બનાસ ડેરી દ્વારા “ભૂમિ અમૃત” બ્રાન્ડ નામે વેચાણ કરવામાં આવે છે. આ પ્રોજેક્ટ્સ માત્ર પશુપાલકોની આવકમાં વધારો જ નહીં, પરંતુ વાર્ષિક અંદાજે ૬,૭૫૦ ટન જેટલા કાર્બન ઉત્સર્જનમાં ઘટાડો કરીને પર્યાવરણ સંરક્ષણમાં પણ પાયારૂપ ભૂમિકા ભજવશે.

જળ

વ્યવસ્થાપન

- એક સમયે ગુજરાતને પાણીની અછતવાળા વિસ્તાર તરીકે ઓળખવામાં આવતું હતું. મારી સરકારના ઉત્તમ જળ વ્યવસ્થાપનથી આજે ગુજરાત **પાણીદાર** રાજ્ય બન્યું છે. વર્ષ ૨૦૨૫-૨૬માં ડિસેમ્બર – ૨૦૨૫ સુધીમાં નાના અને મોટા મળી કુલ ૨૦૨ ચેકડેમોના કામો પૂર્ણ થયા છે. ઉપરાંત ૧૮૬ નાના અને ૨૦૪ મોટા ચેકડેમો પ્રગતિ હેઠળ છે,

જે પૂર્ણ થતા ૭૮૦૦ હેક્ટર વિસ્તારને સિંચાઈ લાભ મળશે. ડિસેમ્બર-૨૦૨૫ સુધી રાજ્યમાં કુલ ૧,૮૭,૭૯૧ ચેકડેમો થકી અંદાજે ૪.૬૧ લાખ હેક્ટરથી વધુ વિસ્તારમાં સીધો અથવા આડકતરો સિંચાઈ લાભ પ્રાપ્ત થયો છે.

- ચોમાસા દરમિયાન સાબરમતી નદીમાં ઘરોઈ બંધથી હેઠવાસમાં નદીમાં વહી જતા પાણીનો સંગ્રહ કરવા માટે સાબરમતી નદી ઉપર રૂ.૨૦૦૦ કરોડથી વધુના ખર્ચે જુદા જુદા ૧૪ સ્થળોએ સીરીઝ ઓફ બેરેજ બનાવીને નદીને જીવંત રાખવાનું આયોજન સરકારશ્રી દ્વારા કરવામાં આવેલ છે. જે પૈકી ૦૫ બેરેજની કામગીરી પૂર્ણ થયેલ છે. જેનાથી અમદાવાદ, ગાંધીનગર, મહેસાણા અને સાબરકાંઠા જિલ્લાના ૫૦,૦૦૦ હેક્ટરથી વધુ વિસ્તારને સિંચાઈનો પ્રત્યક્ષ અથવા પરોક્ષ લાભ થાય છે.
- આ ઉપરાંત ઘરોઈ બંધને રૂ.૧૦૫૯ કરોડના ખર્ચે વિશ્વ કક્ષાના પ્રવાસન સ્થળ તરીકે વિકસાવવાની કામગીરી પણ પ્રગતિ હેઠળ છે.
- **સૌની યોજના** અંતર્ગત નર્મદાના પૂરનાં વધારાના પાણીથી ડિસેમ્બર-૨૦૨૫ સુધીમાં ૧૦૫ જળાશયો જોડવામાં આવેલ છે. જે પૈકી ૯૯ જળાશયો, ૨૩૪ ગામ તળાવો અને ૧૬૧૬ ચેકડેમોમાં ૧,૨૯,૦૩૮ મિલિયન ઘન ફૂટ પાણી આપવામાં આવેલ છે. જેના થકી આશરે ૨.૬૩ લાખથી વધુ હેક્ટરમાં સિંચાઈ સુવિધા અને અનેક શહેરોમાં પીવાના પાણીની સુવિધા સુઢ્ઢ બની છે.
- કડાણા, પાનમ, કરજણ, ઉકાઈ જળાશય તેમજ નર્મદા નહેર આધારિત કુલ ૧૧ ઉદવહન સિંચાઈ યોજનાઓ દ્વારા દાહોદ, પંચમહાલ, મહિસાગર, સુરત, ભરૂચ અને નર્મદા જિલ્લાઓના ૭૬૯ ગામોના આશરે ૯૨,૦૦૦ હેક્ટર વિસ્તારમાં સિંચાઈનો લાભ આપવામાં આવી રહ્યો છે.
- સુજલામ સુફલામ જળ અભિયાન- **“કેચ ધ રેઈન ૨.૦”** અંતર્ગત વર્ષ ૨૦૨૫ દરમિયાન જુદા-જુદા વિભાગો દ્વારા ૧૪,૫૦૦ થી વધુ કામો થયેલ છે. આ કામો થકી જળ સંગ્રહશક્તિમાં કુલ ૨૦,૮૧૫ લાખ ઘન ફૂટ જેટલો વધારો થયેલ છે તથા ૧૦.૩૯ લાખ માનવદિનની રોજગારી ઉત્પન્ન થયેલ છે

પાણી પુરવઠા

- રાજ્ય સરકારે પાણી પુરવઠા યોજનાઓ માટે ભૂગર્ભ જળ ઉપર અવલંબન ન રાખતા તેને નદી, જળાશય, કેનાલ, તળાવ જેવા સર્ફેસ સોર્સ આધારિત યોજનામાં તબદીલ કરવાની અનેરી સિદ્ધિ મેળવી છે.
- પાણી પુરવઠા યોજનાઓ માટે ૩૨૯૦ કિલોમીટરની બલ્ક પાઈપલાઈનનું વિશાળ નેટવર્ક ઉભું કરી દેશમાં સૌપ્રથમ એવી રાજ્યવ્યાપી પાણી પુરવઠા ગ્રીડ દ્વારા રાજ્યના ૧૫,૮૦૨ ગામોને અને ૨૫૧ શહેરી વિસ્તારોને સર્ફેસ સ્રોત આધારિત પીવાના પાણીની સુવિધા પૂરી પાડવામાં રાજ્ય સરકારને સફળતા મળી છે અને તેનાથી ગુજરાતનાં ૫.૪૫ કરોડ નાગરિકોને પીવાના પાણીનો લાભ મળતો થયો છે.
- મારી સરકાર દ્વારા પાણી પુરવઠા માટે ચાલુ વર્ષે રૂ. ૪૪૩ કરોડની ૧૨ યોજનાઓનું લોકાર્પણ તથા રૂ.૬૦/-કરોડની ૧ યોજનાનું ખાતમુહૂર્ત કરવામાં આવેલ છે.

- રાજ્યની પ્રજાને યોગ્ય ગુણવત્તાવાળું અને પૂરતી માત્રામાં પાણી વિતરણ સુનિશ્ચિત બને તે ઉદ્દેશથી તેમજ લીકેજ, ચોરી, વેડફાટ ઉપર નિયંત્રણ રહે તે હેતુથી સ્માર્ટ મીટરીંગ તેમજ વોટર ટ્રીટમેન્ટ પ્લાન્ટમાં ક્વોલિટી એનલાઇઝરનો ઉપયોગ કરવામાં આવેલ છે. જેનું ગાંધીનગર સેન્ટ્રલ મોનીટરીંગ સ્ટેશન દ્વારા રીયલટાઇમ મોનીટરીંગ કરવામાં આવે છે.
- પાણીની ગુણવત્તાની યોગ્ય ચકાસણી માટે રાજ્યમાં ચાલુ વર્ષે નવીન ૦૩ લેબોરેટરી શરૂ થતા કુલ ૮૩ લેબોરેટરીઓ કાર્યરત થઈ છે.

અન્ન, નાગરિક પુરવઠા અને ગ્રાહકોની બાબતો

- **પ્રધાનમંત્રી ગરીબ કલ્યાણ અન્ન યોજના** હેઠળ મારી સરકાર દ્વારા ૭૫ લાખ કુટુંબોની ૩.૧૮ કરોડ જનસંખ્યાને અન્ન સુરક્ષા પૂરી પાડવામાં આવી રહી છે, જેમાં અંત્યોદય કુટુંબોને માસિક કુટુંબ દીઠ ૩૫ કિલોગ્રામ તથા અગ્રતા ધરાવતા કુટુંબોને માસિક વ્યક્તિદીઠ ૫ કિલો અનાજનું વિનામૂલ્યે વિતરણ કરવામાં આવે છે.
- **વન નેશન વન રેશનકાર્ડ યોજના** હેઠળ રાજ્યના જુદા જુદા જિલ્લાઓમાં નોંધાયેલ કાર્ડધારકો રાજ્યમાં કોઈ પણ વાજબી ભાવની દુકાનેથી “સ્ટેટ પોર્ટેબીલીટી” હેઠળ અનાજ મેળવી શકે છે. જે હેઠળ રાજ્યમાંથી ગત વર્ષની સરખામણીએ ચાલુ વર્ષે આશરે ૫.૨૯ લાખ જેટલા વધુ એટલે કે, કુલ ૩૭.૯૧ લાખ જેટલા કાર્ડધારકોએ આ યોજનાનો લાભ લીધેલ છે.
- વર્ષ ૨૦૨૫-૨૬ માં જાન્યુઆરી-૨૦૨૬ સુધી વર્ષ ૨૦૨૪-૨૫ની સરખામણીમાં **કઠોળ વિતરણ યોજના** હેઠળ, તુવેરદાળ અને ચણાનું કુલ ૧૭,૧૩૮ મે.ટન વધુ વિતરણ થવા પામેલ છે તથા **મીઠાનાં વિતરણ યોજના** હેઠળ ડબલ ફોર્ટીફાઈડ મીઠાનું ૪,૩૦૩ મે.ટન વધુ વિતરણ થવા પામેલ છે અને **ખાદતેલ વિતરણ યોજના** હેઠળ ૭૭,૯૬૭ પાઉચનું વધુ વિતરણ થવા પામેલ છે.
- **“પ્રધાનમંત્રી ઉજ્જવલા યોજના”** અંતર્ગત વર્ષ ૨૦૨૫-૨૬ના પ્રથમ તબક્કામાં ગત વર્ષની સરખામણીએ ૮.૩૯ લાખ જેટલા વધુ લાભાર્થીઓ એટલે કે, કુલ ૩૮.૩૯ લાખ લાભાર્થીઓને લાભ આપવામાં આવેલ છે.
- **જનવિશ્વાસ ૨.૦** પહેલ અંતર્ગત લીગલ મેટ્રોલોજી એક્ટ હેઠળ નાના વેપારીઓ અને ઉદ્યોગોને વ્યવસાય કરવાની સરળતા વધે તે હેતુથી અનાવશ્યક અનુમતિઓ અને દંડાત્મક જોગવાઈઓમાંથી રાહત આપવામાં આવેલ છે.
- રાજ્ય ગ્રાહક સુરક્ષા હેલ્પલાઇન પર ચાલુ નાણાકીય વર્ષમાં અત્યાર સુધીમાં દસ હજાર કરતાં વધારે ગ્રાહકોને ફરિયાદ પરત્વે માર્ગદર્શન આપવાની કામગીરી કરવામાં આવેલ છે.

ઊર્જા અને પેટ્રોકેમિકલ્સ

આ ઊર્જાવાન ગુજરાત છે. રાજ્યના નાગરિકોના જીવનમાંથી અંધારા ઉતેચવા અને અજવાળા પાથરવા આ સરકાર પ્રતિબદ્ધ છે. ગુજરાત રાજ્યના વર્ષ ૨૦૦૨ થી વર્ષ ૨૦૨૫ દરમિયાન થયેલા નોંધપાત્ર અને ઐતિહાસિક વિકાસમાં વીજ ક્ષમતા વૃદ્ધિનું મહત્વપૂર્ણ યોગદાન રહેલ છે. રાજ્યની મહત્તમ વીજ માંગ વર્ષ ૨૦૦૨ માં ૭.૭ ગીગાવોટ હતી, જે વર્ષ ૨૦૨૫ સુધીમાં વધીને ૨૬.૪ ગીગાવોટ થઈ છે — જે લગભગ ત્રણ ગણી વૃદ્ધિ દર્શાવે છે. આ ગુજરાતના ઝડપી ઔદ્યોગિક વિકાસ અને આર્થિક પ્રગતિનું પ્રતિબિંબ છે.

- ગુજરાતમાં વર્ષ ૨૦૦૨ માં સબ-સ્ટેશનોની સંખ્યા ૭૩૬ હતી, જે વર્ષ ૨૦૨૫માં ત્રણ ગણા વધારા સાથે ૨,૪૭૪ થઈ છે. ટ્રાન્સમિશન લાઈનો ૩૧ હજાર કિમીમાંથી વધીને ૭૮ હજાર કિમી થઈ છે. તથા ડિસ્ટ્રિબ્યુશન લાઈનો (HT + LT) ૩.૬૧ લાખ કિલોમીટરથી વધીને ૨.૨૫ ગણા વધારા સાથે ૮.૨૬ લાખ કિલોમીટર થઈ છે, જેના કારણે ગ્રામ્ય અને શહેરી વિસ્તારોમાં વીજળીની પહોંચ વધુ મજબૂત બની છે. ટ્રાન્સફોર્મર સેન્ટરો ૨.૨૮ લાખમાંથી દસ ગણા વધારા સાથે ૨૧.૨૫ લાખ થયા છે.
- ગુજરાત સ્ટેટ ઇલેક્ટ્રિસિટી કોર્પોરેશન લિમિટેડ (GSECL) ને ભારત ઇલેક્ટ્રિસિટી – પાવરિંગ ઇન્ડિયા એવોર્ડ્સ 2025માં **"બેસ્ટ જનરેશન કંપની ઓફ ધ ચર – સ્ટેટ જેન્કો"** ના પ્રતિષ્ઠિત એવોર્ડથી સન્માનિત કરવામાં આવી છે.
- ગુજરાત રાજ્યને ઇન્ડિયન વિન્ડ ટર્બાઇન મેન્યુફેક્ચરર્સ એસોસિએશન (IWTMA) દ્વારા સૌથી વધુ પવન ક્ષમતા સ્થાપિત કરવા માટે **વિન્ડ ઇન્ડિયા એવોર્ડ 2025 જેવા પ્રતિષ્ઠિત એવોર્ડ**થી સન્માનિત કરવામાં આવેલ છે.
- રાજ્યની ચારેય સરકારી વીજ વિતરણ કંપનીઓ UGVCL, MGVCL, DGVCL & PGVCL ને મીનીસ્ટ્રી ઓફ પાવર, ભારત સરકાર, નવી દિલ્હી દ્વારા A+ રેટિંગ સાથે દેશની શ્રેષ્ઠ ચાર કંપનીમાં સ્થાન આપવામાં આવ્યું છે.
- ગુજરાતનો ઇતિહાસ સૂર્ય અને પ્રકૃતિપૂજાનો ઇતિહાસ છે. આ પુરાતન ઇતિહાસને નૂતન ટેકનોલોજી સાથે જોડતા ગુજરાત આજે સમગ્ર દેશમાં ૪૨.૫ ગીગાવોટ સ્થાપિત રીન્યુએબલ એનર્જી ક્ષમતા સાથે **સમગ્ર દેશમાં પ્રથમ ક્રમકે** છે. જેમાં ૧૪.૮ ગીગાવોટ સ્થાપિત પવનઊર્જા ક્ષમતા સાથે સમગ્ર દેશમાં પ્રથમ ક્રમકે છે. તથા ૨૫.૫ ગીગાવોટ સ્થાપિત સોલાર ઊર્જા ક્ષમતા સાથે સમગ્ર દેશમાં પ્રથમ ક્રમકે છે.
- ગુજરાત રાજ્યમાં કચ્છમાં ખાવડા ખાતે ૩૭ ગીગાવોટ રીન્યુએબલ એનર્જીની ક્ષમતા ધરાવતો **વિશ્વનો સૌથી મોટો રીન્યુએબલ એનર્જી પાર્ક** બની રહ્યો છે. જેમાં હાલમાં ૧૧ ગીગાવોટથી વધુ રીન્યુએબલ એનર્જી ઉત્પાદન ક્ષમતા હાંસિલ કરેલ છે.
- રીન્યુએબલ એનર્જી પ્રોજેક્ટ નોંધણીથી લઈને પ્રોજેક્ટ કમિશનિંગ સુધીના વન-સ્ટોપ સોલ્યુશન માટે સિંગલ વિન્ડો કિલચરન્સ પોર્ટલ **"અક્ષય ઊર્જા સેતુ પોર્ટલ"** શરૂ કર્યું છે.
- રાજ્યના ખેડૂતોને વિશ્વસનીય વીજ પુરવઠો, ઉદ્યોગોને સતત ઊર્જા અને સામાન્ય નાગરિકોને ગુણવત્તાયુક્ત સેવા ઉપલબ્ધ થાય તે માટે વિજ વિતરણ કંપનીઓ દ્વારા ૨૦,૭૦૦ kmથી વધુના MVCC કેબલ નાખવામાં આવેલ છે.
- દરિયાકાંઠાના વિસ્તારો અને સીમા ચૌકી (Border Outpost) વિસ્તારોમાં સુરક્ષા સુનિશ્ચિત કરવા અને અતિપ્રતિકૂળ પરિસ્થિતિઓને ધ્યાનમાં રાખીને Elevated 11KV XLPE Cable Network પાયલોટ પ્રોજેક્ટ તરીકે અમલમાં મૂકાયો છે.
- ભારત સરકારની RDSS યોજના મારફત વીજ વિતરણ ક્ષેત્રમાં નુકસાન ઘટાડવા, વિતરણ નેટવર્ક મજબૂત કરવા અને ગ્રાહકોને ગુણવત્તાયુક્ત, સતત વીજ પુરવઠો ઉપલબ્ધ કરાવવામાં આવે છે. આ યોજના હેઠળ રાજ્યમાં વીજ વિતરણ આંતરમાળખાનાં મજબૂતીકરણ અને આધુનિકીકરણ માટે ભારત સરકાર દ્વારા ૬૦ ટકા નાણાકીય સહાય પૂરી પાડવામાં આવે છે. જેનો મારી સરકારે મહત્તમ ઉપયોગ કરીને ડિસેમ્બર-૨૦૨૫ સુધીમાં રૂ. ૩૭૮૪ કરોડનાં કામો પૂર્ણ કરેલ છે.

- મારી સરકાર દ્વારા ડિસેમ્બર ૨૦૨૫માં **ત્રણ અત્યંત મહત્વપૂર્ણ નવી નીતિઓ** – (૧) ગુજરાત ઇન્ટીગ્રેટેડ રિન્યુએબલ એનર્જી પોલિસી ૨૦૨૫, (૨) ગુજરાત પમ્પડ સ્ટોરેજ પ્રોજેક્ટ (PSP) પોલિસી, ૨૦૨૫ અને (૩) ગુજરાત ગ્રીન હાઇડ્રોજન પોલિસી, ૨૦૨૫ જાહેર કરવામાં આવી છે. જે દર્શાવે છે કે આ રાજ્યનો વિકાસ પોલીસી ડ્રીવન વિકાસ છે.
- ઉક્ત નીતિઓ દ્વારા રાજ્યમાં ૧૦૦ GW થી વધુ રિન્યુએબલ ક્ષમતાના વિકાસનું લક્ષ્ય રાખવામાં આવેલ છે. વધુમાં ગ્રીન હાઇડ્રોજન માટે ૩૦ GW ઇલેક્ટ્રોલાઇઝર ક્ષમતાને ટેકો આપવા માટે ૭૫ GW રિન્યુએબલ એનર્જીનો લક્ષ્યાંક રાખવામાં આવેલ છે અને જે લગભગ ૫ MMTPA CO₂ ઉત્સર્જન ઘટાડવામાં મહત્વપૂર્ણ યોગદાન આપશે. રાજ્યમાં ૨૦૩૫ સુધીમાં લગભગ ૭૫,૦૦૦ કરોડના રોકાણ સાથે ૭૫ GWh પમ્પડ સ્ટોરેજ ક્ષમતા બનાવવાનું પણ લક્ષ્યાંક રાખવામાં આવેલ છે. જે ગુજરાત રાજ્યને સ્વચ્છ ઊર્જા, ઊર્જા સંગ્રહ અને ગ્રીન હાઇડ્રોજન માટે અગ્રણી હબ તરીકે સ્થાપિત કરવામાં મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા નિભાવશે.
- શિયાળાની કડકડતી ઠંડીમાં ખેડૂતોને રાત્રે ખેતરમાં પાણી વાળવામાં પડતી મુશ્કેલી અને જંગલી પશુપ્રાણીઓના ભયની ચિંતાને દૂર કરવા સરકારે દિવસે વીજળી આપવા **કિસાન સૂર્યોદય યોજના** અમલમાં મૂકી છે. આ યોજના હેઠળ રાજ્યના ૯૯% ગામડાઓમાં ખેડૂતોને દિવસે વીજળી પ્રદાન કરવામાં આવી રહી છે.
- રાજ્યમાં **પીએમ સૂર્ય ઘર મફત વીજળી યોજના** હેઠળ ૫ લાખથી વધુ રૂફટોપ સોલાર સિસ્ટમ્સ સ્થાપિત કરી દેશમાં પ્રથમ ક્રમાંકે છે.
- GSECL દ્વારા ભાવનગર (પડવા) ખાતે ૭૫૦ કિલોવોટનો **રાજ્યનો પ્રથમ ફ્લોટિંગ સોલર પ્રોજેક્ટ** શરૂ કરાયો છે અને બીજા આશરે ૨૫૦૦ મેગાવોટ થી વધુ કેપેસિટીના ફ્લોટિંગ સોલાર પ્રોજેક્ટ્સ આયોજન હેઠળ છે.
- રાજ્યના ગુજરાત સ્ટેટ પેટ્રોનેટ લિમિટેડ (GSPL) એ ગેસના પરિવહન માટે ઓક્ટોબર ૨૦૨૫ સુધીમાં કુલ ૨૭૯૫ કિમી લાંબી કુદરતી ગેસ ટ્રાન્સમીશન પાઇપ લાઇન નેટવર્ક વિકસાવેલ છે.

ઉદ્યોગ

- ઉદ્યોગ અને વ્યાપાર એ ગુજરાતીઓના લોહીમાં છે. વાઇબ્રન્ટ ગુજરાતના સફળ મોડેલને વધુ વિસ્તૃત કરવા યોજાયેલ **વાઇબ્રન્ટ ગુજરાત પ્રાદેશિક પરિષદ (VGRC) ૨૦૨૫-૨૬**માં મહેસાણા ખાતે કુલ રૂ. ૩.૨૫ લાખ કરોડના અને રાજકોટ ખાતે રૂ.૫.૭૮ લાખ કરોડના એમ.ઓ.યુ થયેલ છે.
- રાજ્યમાં ટેક્સટાઇલ ઉદ્યોગોને વૈશ્વિક સ્તરે સ્પર્ધાત્મક બનાવવા માટે વિવિધ ટેક્સટાઇલ નીતિઓ હેઠળ ૮,૦૦૦ થી વધુ એકમોને રૂ.૧૮૦૦ કરોડથી વધુની સહાય ચૂકવવામાં આવી છે અને અંદાજિત ૬૫,૦૦૦થી વધુને રોજગારી મળેલ છે.
- રાજ્યમાં સંશોધન અને વિકાસ પ્રવૃત્તિને વેગ મળે તથા રાજ્યના યુવા સાહસિકોને તેમના ઇનોવેટીવ વિચારને પ્રોત્સાહન આપવા માટે **સ્ટાર્ટઅપ અને ઇનોવેશન યોજના** હેઠળ રૂ.૬૮.૧૪ કરોડથી વધારેની સહાયનું ચૂકવણું કરવામાં આવેલ છે. આ યોજના માટે વર્ષ : ૨૦૧૮, ૨૦૧૯, ૨૦૨૧, ૨૦૨૨ અને વર્ષ : ૨૦૨૩-૨૪ એમ સતત પાંચ ટર્મમાં નેશનલ સ્ટાર્ટઅપ રેન્ડીંગ ફ્રેમવર્ક અંતર્ગત સમગ્ર દેશમાં ગુજરાત પ્રથમ ક્રમે **“બેસ્ટ પરફોર્મર”** તરીકે જાહેર થયેલ છે.

- મોટા કદના ઉદ્યોગોને સહાય યોજના હેઠળ કુલ રૂ. ૨૨૩ એકમોને અપાયેલ રજિસ્ટ્રેશનથી કુલ રૂ. ૬૩ હજાર કરોડથી વધુનું સૂચિત મૂડીરોકાણ અને અંદાજિત ૭૧,૫૦૦ ની પ્રત્યક્ષ રોજગારી તેમજ અંદાજિત ૧.૭૮ લાખ જેટલી પરોક્ષ રોજગારી ઉદભવશે.
- રાજ્યએ ઈઝ ઓફ ડુઈંગ બિઝનેસ તથા ઈઝ ઓફ લિવિંગને અપનાવીને તેને વધુ સશક્ત બનાવવા માટે વિશ્વાસ આધારિત ગવર્નન્સ (ટ્રસ્ટ બેઝડ ગવર્નન્સ) ના અભિગમ અને રિડ્યુસિંગ કોમ્પ્લાયન્સ બર્ડન અભ્યાસ હેઠળ મારી સરકારે ગુજરાત જન વિશ્વાસ (જોગવાઈઓમાં સુધારા) અધિનિયમ ૨૦૨૫ અમલમાં મૂક્યો છે. આ અધિનિયમ અંતર્ગત ૧૧ રાજ્ય અધિનિયમો તથા નિયમોની કુલ ૫૧૬ જોગવાઈઓને ગુનારહિત કરવામાં આવી છે. આ એકરૂપ કાયદાકીય સુધારાઓ હેઠળ નાની તથા ટેકનિકલ ભૂલો માટે કેદની જોગવાઈને નિરીક્ષણાત્મક દંડમાં બદલી દેવામાં આવી છે. જેના પરિણામે ઉત્પાદક, દુકાનદાર તથા ઔદ્યોગિક કામદારોને સીધો લાભ પ્રાપ્ત થયો છે તેમજ સરકાર પ્રત્યેનો વિશ્વાસ વધુ મજબૂત બન્યો છે.
- MSME ઉદ્યોગોને સહાય આપવા વિવિધ યોજનાઓ માટે કુલ રૂ. ૧૫૫૦ કરોડની જોગવાઈ કરવામાં આવેલ છે. આ યોજનાઓ આત્મનિર્ભર ગુજરાત સ્કીમ ફોર આસિસ્ટન્સ ટુ MSME યોજના હેઠળ કુલ રૂ. ૭૩૦ કલેઈમ અરજીઓને આશરે રૂ. ૧૩૧૯ કરોડની સહાય ચુકવવામાં આવેલ છે તથા અંદાજે રૂ. ૨૭,૪૬૭ કરોડનું મુડી રોકાણ આવેલ છે અને ૧ લાખથી વધુ રોજગારીનું સર્જન થયેલ છે.
- માર્કેટ ડેવલપમેન્ટ આસિસ્ટન્સ યોજના હેઠળ પ્રદર્શનમાં ભાગ લેનાર એકમોને તથા આયોજનકર્તાને લાભ આપવામાં આવે છે. આ યોજના અંતર્ગત કુલ ૧૦૦૨ એકમોને રૂ. ૧૮૮૪.૨૯ લાખની સહાયની ચૂકવણી કરવામાં આવેલ છે.
- ગુજરાત ઔદ્યોગિક વિકાસ નિગમ દ્વારા નાણાકીય વર્ષ ૨૦૨૫-૨૬માં આશરે ૩૪૨.૬૨ હેક્ટર જમીન નવી વસાહતો માટે મેળવવામાં આવી છે. વર્ષ ૧૯૬૨ થી ડિસેમ્બર-૨૦૨૫ દરમિયાન કુલ ૪૬,૮૧૯ હેક્ટર જમીન ઔદ્યોગિક વિકાસ માટે સંપાદિત કરવામાં આવી છે.
- ગુજરાત ઔદ્યોગિક વિકાસ નિગમ દ્વારા આજદિન સુધી રાજ્યમાં ૨૩૯ થી વધુ ઔદ્યોગિક વસાહતો સ્થાપવામાં આવેલ છે.
- વર્ષ ૨૦૨૫ દરમિયાન ૪૪૭ ઉદ્યોગકારો માટે ૨૭૪ હેક્ટર જમીનમાં ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર સુવિધાઓ વિકસાવવામાં આવેલ છે.
- સાણંદ એક આંતરરાષ્ટ્રીય ઇન્ડસ્ટ્રીઅલ હબ તરીકે વિકસી રહ્યું છે. સાણંદ ઔદ્યોગિક વસાહતમાં Micron, Kaynes Technology, CG Power, Taiyo Nippon Sanso India, BASF જેવી વિશ્વકક્ષાની મલ્ટીનેશનલ કંપનીઓ માટે ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર વિકસાવવામાં આવી રહેલ છે.
- એક સમયે જેને ખારા પાટની ખારી જમીન તરીકે ઓળખવામાં આવતું હતું તે ધોલેરા આજે વિકાસની નવી ઉંચાઈઓ સાથે નવી ઓળખ મેળવી રહ્યું છે. ધોલેરા સ્પેશીયલ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ રીગ્યુલેશન ડેવલોપમેન્ટ ઓથોરીટી ખાતે ભારત સરકારના "ઇન્ડિયા સેમિકન્ડક્ટર મિશન" હેઠળના ૫ પૈકીના ૪ સેમિકન્ડક્ટર પ્રોજેક્ટ ગુજરાતમાં સ્થાપવામાં આવી રહ્યા છે. જેમાં દેશનું પ્રથમ સેમિકન્ડક્ટર ફેબ્રિકેશન યુનિટ ધોલેરામાં ટાટા ઇલેક્ટ્રોનિક્સ દ્વારા રૂ. ૯૧,૦૦૦ કરોડના રોકાણ સાથે કામ પ્રગતિમાં છે.

- **ગુજરાત રેલ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ડેવલપમેન્ટ કોર્પોરેશન લી.** દ્વારા બેડી પોર્ટ થી વિન્ડમિલ સ્ટેશન (૨.૫૭ કિમી) સુધી રેલ તથા ગતિશક્તિ ટર્મિનલ પ્રોજેક્ટ પૂર્ણ કરી કમીશનિંગ કરેલ છે. તેમજ પી.એમ. ગતિશક્તિ પ્રોજેક્ટ અન્વયે મોરબી નજીક રફાલેશ્વર ખાતે ગતિશક્તિ કાર્ગો ટર્મિનલનું કાર્ય પૂર્ણ થયેલ છે.
- ભૂસ્તર વિજ્ઞાન અને ખનીજ ખાતા મારફત ચાલુ વર્ષ: ૨૦૨૫-૨૬ દરમિયાન કુલ રૂ.૨૦૬૭ કરોડની મહેસૂલી આવક થયેલ છે.
- જાહેર હરાજીથી મુખ્ય ખનીજનાં કુલ-૯ બ્લોકમાં તથા ગૌણ ખનીજના કુલ-૪૫૭ બ્લોકમાં ખનીજ ઉત્પાદન કરવાની કાર્યવાહી શરૂ થયેલ છે જે આવનારા સમય માટે મહેસૂલી આવકનો વધારો સૂચવે છે.
- ચાલુ નાણાકીય વર્ષ દરમિયાન ગુજરાત ખનીજ વિકાસ નિગમ લિ. દ્વારા ૨૦,૦૦૦ કરોડ ની માર્કેટ કેપનો લક્ષ્યાંક પ્રાપ્ત કરેલ છે.
- પાછલા નાણાકીય વર્ષમાં ગુજરાત વિકાસ નિગમ મારફત રાજ્ય સરકારને રૂ.૨૩૭ કરોડ જેટલી ડિવિડન્ડની આવક પ્રાપ્ત થયેલ છે.

પ્રવાસન

- ગરબો એ ગુજરાતની સાંસ્કૃતિક ઓળખ છે. યુનેસ્કો દ્વારા ગુજરાતના ગરબાને અમૂર્ત સાંસ્કૃતિક વારસા (Intangible Cultural Heritage) તરીકે જાહેર કરેલ છે. આપણો ગરવો ગરબો હવે ગ્લોબલ બન્યો છે ત્યારે ગુજરાત ટુરીઝમ દ્વારા પ્રથમ વાર પ્રિ-નવરાત્રિનું આયોજન રાજ્ય બહાર ઉદયપુર, રાજસ્થાન ખાતે અને પોસ્ટ-નવરાત્રિનું આયોજન દિલ્લી ખાતે કરવામાં આવેલ હતું.
- રાષ્ટ્રીય એકતા દિવસની સાથે-સાથે દિલ્લી બહાર પ્રથમવાર **“ભારત પર્વ”**નું આયોજન સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી, એકતાનગર ખાતે તા.૦૧ થી ૧૫ નવેમ્બર, ૨૦૨૫ દરમિયાન કરવામાં આવેલ હતું. ભારત પર્વમાં વિવિધ રાજ્યો તેમજ કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશો દ્વારા ભાગ લઈને પોતાની લોકસંસ્કૃતિ, ખાણી-પીણી, હસ્તકલાનું પ્રદર્શન કરીને **“ભારતની વિવિધતામાં એકતા”**ના દર્શન કરાવેલ હતાં.
- કૃષ્ણ-રૂક્મણી યાત્રાધામ માધવપુર-પોરબંદરના સર્વગ્રાહી વિકાસ માટે પ્રથમ તબક્કામાં રૂ. ૪૭.૯૯ કરોડના કામો પૂર્ણ થયેલ છે.
- આદ્યશક્તિ ધામ અંબાજી ખાતે **આદિ શક્તિ રાષ્ટ્રીય મહિલા તીરંદાજી સ્પર્ધાનું** તારીખ ૮ થી ૧૦ એપ્રિલ ૨૦૨૫ દરમિયાન આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. આ ત્રણ દિવસીય સ્પર્ધા દરમિયાન, દેશભરના અલગ-અલગ રાજ્યોમાંથી ૭૦૦ થી વધુ યુવા મહિલા તીરંદાજોએ ભાગ લીધો હતો. આ વર્ષે તા.૨૧-૨૩ જાન્યુઆરી ૨૦૨૬ દરમિયાન રાષ્ટ્રીય મહિલા તીરંદાજી સ્પર્ધાનું આયોજન કરવામાં આવેલ.
- એડવેન્ચર પ્રવાસનના વિકાસ અર્થે મે-જૂન ૨૦૨૫માં ઘરોઈ ખાતેના એડવેન્ચર ફેસ્ટમાં તેમજ ડીસેમ્બર ૨૦૨૫માં માંડવી ખાતેના બીચ ફેસ્ટીવલમાં સ્પોર્ટ્સ એક્ટીવીટીનું સફળ આયોજન કરવામાં આવેલ છે.
- મોઢરસાગર-પોરબંદર અને ઘોળાવીરા-કરછ ખાતે રૂ.૨૦૦ કરોડના ખર્ચે હાલમાં પ્રવાસન સવલતો વિકસાવવાની કામગીરી પ્રગતિ હેઠળ છે.

- ગુજરાતમાં પ્રવાસન ક્ષેત્રમાં થયેલ વિકાસને કારણે રાજ્યમાં આવતા પ્રવાસીઓની સંખ્યા વર્ષ ૨૦૨૪માં ૧૬.૭૭ કરોડ હતી, જે વધીને વર્ષ ૨૦૨૫માં ૨૨.૨૮ કરોડ થયેલ છે.
- અંબાજી યાત્રાધામ ખાતે **“અંબાજી કોરીડોર”** પ્રોજેક્ટ અંતર્ગત રૂ. ૧૬૩૨ કરોડના ખર્ચે બે તબક્કામાં વિવિધ વિકાસકાર્યો પ્રગતિ હેઠળ છે.
- શ્રી માતાનો મઢ, જિ.કચ્છ ખાતે શ્રી આશાપુરા માતાજી મંદિરના દર્શને આવતા યાત્રાળુઓને પુરતી સગવડો ઉપલબ્ધ થાય તે માટે તેનો સર્વગ્રાહી વિકાસ કરવા અંગે રૂ. ૩૨.૭૦ કરોડના ખર્ચે વિકાસકામો કરવામાં આવેલ છે.
- હૈદરાબાદ ખાતે આયોજિત રાષ્ટ્રીય કક્ષાની ‘વિંગ્સ ઇન્ડિયા-૨૦૨૬’ ઇવેન્ટમાં કેન્દ્રીય ઉદ્ધયન મંત્રીશ્રીના હસ્તે ગુજરાતને **‘બેસ્ટ સ્ટેટ ફોર પ્રમોશન ઓફ એવિએશન ઇકોસિસ્ટમ’**નો પુરસ્કાર એનાયત કરવામાં આવેલ.

કુટીર અને ગ્રામોદ્યોગ

- મારી સરકાર દ્વારા ‘વોકલ ફોર લોકલ’ અને ‘હર ઘર સ્વદેશી, ઘર ઘર સ્વદેશી’ના મંત્રને સાકાર કરવા સ્વદેશી ખાદીના ઉત્પાદન પર સહાય તેમજ વેચાણ માટે મેળાઓ થકી પ્રોત્સાહન પૂરું પાડવામાં આવે છે. માનનીય પ્રધાનમંત્રીશ્રીએ આપેલ ‘ખાદી ફોર નેશન, ખાદી ફોર ફેશનના સૂત્રને સાકાર કરતા, રાજ્ય સરકારશ્રીના વિવિધ પ્રયત્નો થકી છેલ્લા ચાર વર્ષમાં ખાદીનું કુલ વેચાણ રૂ. ૩૬૭ કરોડ થી વધીને રૂ. ૬૮૩ કરોડ થયેલ છે. આમ, ખાદીના વેચાણમાં છેલ્લા ચાર વર્ષમાં ૮૬ ટકાનો વધારો જોવા મળેલ છે. શ્રી વાજપેયી બેન્કેબલ યોજના અંતર્ગત લોન મર્યાદા રૂ. ૮ લાખથી વધારીને રૂ. ૨૫ લાખ અને સહાયની મહત્તમ મર્યાદા રૂ. ૧.૨૫ લાખથી વધારીને રૂ. ૩.૭૫ લાખ કરવામાં આવેલ છે. આ યોજના થકી વર્ષ ૨૦૨૫-૨૬માં જાન્યુઆરી-૨૦૨૬ અંતિત ૪૭,૫૫૧ લાભાર્થીઓને અંદાજિત રૂ. ૩૬૭ કરોડનો લાભ આપવામાં આવેલ છે.
- ગુજરાત રાજ્ય હસ્તકલા અને હાથસાળ નિગમ દ્વારા વર્ષ ૨૦૨૫-૨૬માં જાન્યુઆરી-૨૦૨૬ સુધીમાં રૂ. ૩૩.૫૯ કરોડની હાથસાળ અને હસ્તકલાની ચીજવસ્તુઓનું વિક્રમજનક વેચાણ કરવામાં આવેલ છે.

આરોગ્ય અને પરિવાર કલ્યાણ

- મારી સરકાર ‘સર્વે સન્તુ નિરામય’નાં મંત્રને સાચા અર્થમાં સાકાર કરી રહી છે. ઉત્કૃષ્ટ આરોગ્ય સેવાઓ જન-જન સુધી પહોંચાડવા આ સરકાર પ્રતિબદ્ધ છે. ડિસેમ્બર ૨૦૨૫ સુધીમાં, ઓ. પી. ડી અને આઈ. પી. ડી મારફતે આશરે ૯.૫૦ કરોડ કેસોમાં આરોગ્ય સેવાઓ પૂરી પાડવામાં આવી છે. ૧૩ લાખથી વધુ મોટી અને નાની સર્જરીઓ, ૬.૨૫ કરોડથી વધુ લેબોરેટરી પરીક્ષણો અને ૨.૯૬ કરોડથી વધુ લોકોનું બિનચેપી રોગો માટે સ્ક્રીનિંગ કરવામાં આવ્યું છે. વધુમાં, લગભગ ૯.૬૩ લાખ ગર્ભવતી મહિલાઓ અને ૯.૪૧ લાખ બાળકોનું રસીકરણ કરવામાં આવ્યું છે.
- કિડની અને કેન્સરના દર્દીઓને વિકેન્દ્રિત સેવાઓ ઉપલબ્ધ કરાવવા માટે ૨૮૧ ડાયાલિસિસ કેન્દ્રો અને ૩૫ ડે-કેર કીમોથેરાપી કેન્દ્રો સ્થાપવામાં આવ્યા છે.
- અંતરિયાળ વિસ્તારોમાં આરોગ્ય સેવાઓ મજબૂત બનાવવા માટે ડિસેમ્બર ૨૦૨૫ સુધીમાં ૨૨ ટેલિમેડિસિન હબ મારફતે ૧.૨૪ કરોડથી વધુ કન્સલ્ટેશન કરવામાં આવ્યા છે.

- **આયુષ્માન ભારત પ્રધાનમંત્રી જન આરોગ્ય યોજના** અંતર્ગત, ડિસેમ્બર ૨૦૨૫ સુધીમાં ૨.૭૦ કરોડથી વધુ લાભાર્થીઓને આયુષ્માન કાર્ડ આપવામાં આવ્યા છે. તેમજ રૂપિયા ૩૨૭૩.૭૦ કરોડના દાવાઓને મંજૂર કરવામાં આવ્યા છે.
- **નમોશ્રી યોજના** અંતર્ગત માતા મૃત્યુદર અને શિશુ મૃત્યુદર ઘટાડવાના હેતુથી DBT મારફતે પાત્રતા ધરાવતી ૭.૫ લાખથી વધુ મહિલાઓને રૂપિયા ૪૫૦ કરોડ જેટલી નાણાકીય સહાય પૂરી પાડવામાં આવી છે.
- મલ્ટી-સ્પેશિયાલિટી તથા સુપર-સ્પેશિયાલિટી સેવાઓ ઉપલબ્ધ કરાવવા ગાંધીનગર, અમદાવાદ-સોલા, વડોદરા, સુરત, રાજકોટ, ભાવનગર અને જામનગર ખાતેની સરકારી હોસ્પિટલોની ક્ષમતા અને કાર્યક્ષમતામાં વધારો કરવામાં આવી રહ્યો છે.
- ડૉક્ટરોની ઉપલબ્ધતા સુનિશ્ચિત કરવા માટે સતત પ્રયાસો કરવામાં આવી રહ્યા છે. MBBS ડૉક્ટરોની ૯૫ ટકા કરતાં વધુ જગ્યાઓ ભરવામાં આવી છે. MBBS તથા તજજ્ઞ ડૉક્ટરોની પૂરતી ઉપલબ્ધતા માટે રાજ્યમાં સ્નાતક અને અનુસ્નાતક બેઠકોની સંખ્યા અનુક્રમે ૭૫૭૫ અને ૩૫૪૫ થઈ છે.
- જાહેર આરોગ્ય વ્યવસ્થામાં દવાઓની ઉપલબ્ધતા સુનિશ્ચિત કરવા માટે આવશ્યક દવાઓની યાદી (Essential Drug List)માં ૧૫૦ નવી દવાઓનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે, જેના પરિણામે યાદીમાં કુલ દવાઓની સંખ્યા ૧૪૭૯ થઈ છે.

શિક્ષણ

- બાળકો એ રાજ્યનું ભાવિ છે અને શિક્ષણ દ્વારા આ ભાવિને ઉજ્જવળ બનાવી શકાય છે. સંસ્કાર અને જ્ઞાનથી શિક્ષિત અને કૌશલ્યોથી દીક્ષિત ગુજરાત માટે મારી સરકાર અવિરત કાર્ય કરી રહી છે. સરકારી શાળાઓમાં કાયમી શિક્ષકોની ભરતી, આધુનિક માળખાકીય સુવિધાઓ અને ગુણવત્તાસભર શિક્ષણના કારણે વર્ષ ૨૦૨૧-૨૨થી ૨૦૨૫-૨૬ દરમિયાન ૩,૪૩,૦૦૦ વિદ્યાર્થીઓએ ખાનગી શાળાઓ છોડીને સરકારી શાળાઓમાં પ્રવેશ લીધો છે.
- શિક્ષણ વ્યવસ્થાને વધુ મજબૂત બનાવવા માટે વર્ષ ૨૦૨૫-૨૬માં રાજ્યમાં **૧૦,૧૪૧ વિદ્યાસહાયકોની નિમણૂક** કરવામાં આવી છે ઉપરાંત, **૬૨૪ જિદાના** ગ્રામ્ય અને સીમાવર્તી વિસ્તારો માટે ખાસ ભરતી દ્વારા ૨,૦૭૩ વિદ્યાસહાયકોની નિમણૂક કરવામાં આવી છે.
- **શાળા પ્રવેશોત્સવ યોજના**ના સકારાત્મક પરિણામે આજે રાજ્યમાં **નામાંકન ૧૦૦ ટકા** સુધી પહોંચવામાં છે અને **ડ્રોપઆઉટ દર** ૨૦૦૧-૦૨ માં ૩૭.૨૨થી ઘટીને ૨૦૨૪-૨૫ માં ૨.૪૨ થયો છે. વર્ષ ૨૦૨૫-૨૬માં ધોરણ-૧માં ૫,૧૫,૬૪૮ અને બાલવાટિકામાં ૫,૭૮,૫૭૮ બાળકો અભ્યાસમાં જોડાયા છે.
- રાજ્ય સરકારે R.T.E અંતર્ગત નબળા વર્ગના બાળકો માટેની ફી પરત ચુકવણી પેટે વર્ષ ૨૦૧૩-૧૪ થી રૂ. ૧૦,૦૦૦ ને બદલે વર્ષ ૨૦૨૨-૨૩ થી વધારો કરી રૂ. ૧૩,૬૭૫ ની મર્યાદામાં ચૂકવવા, તેમજ વિદ્યાર્થીઓને શૈક્ષણિક સામગ્રી માટે રૂ. ૩,૦૦૦ ની સહાય આપનાર **ગુજરાત સમગ્ર દેશમાં પ્રથમ રાજ્ય** બન્યું છે.

- R.T.E. અધિનિયમ અંતર્ગત વર્ષ ૨૦૧૩-૧૪થી બિન અનુદાનિત ખાનગી પ્રાથમિક શાળાઓમાં ધોરણ-૧માં ૨૫ ટકા બેઠકો નબળા વર્ગ અને વંચિત જૂથના બાળકો માટે વિનામૂલ્યે ઉપલબ્ધ કરાવવામાં આવી છે. જે અંતર્ગત વર્ષ ૨૦૨૫-૨૬માં કુલ ૮૫,૪૮૪ વિદ્યાર્થીઓને પ્રવેશ ફાળવવામાં આવેલ છે.
- વિદ્યાર્થીઓની સલામતી રાજ્ય સરકારની પ્રાથમિકતા છે, આ હેતુસર **વિદ્યાદીપ યોજના** અંતર્ગત વર્ષ ૨૦૨૫-૨૬થી અકસ્માત વીમા સહાય રૂ. ૨,૦૦,૦૦૦ વિદ્યાર્થીદીઠ કરવામાં આવી છે. વર્ષ ૨૦૦૨-૦૩થી ૨૦૨૪-૨૫ દરમિયાન ૬,૬૫૦ લાભાર્થીઓને અંદાજે રૂ. ૨૮ કરોડની સહાય આપવામાં આવી છે.
- બેગલેસ દિવસના કાર્યક્રમ માટે શાળાઓમાં પ્રિ-વોકેશનલ કૌશલ્યો વિકસાવવા માટેની પ્રવૃત્તિઓ શરૂ કરવામાં આવી છે. જોયકુલ-બેગલેસ શનિવાર- વિદ્યાર્થીઓને મજા આવે તે માટે વિવિધ પ્રવૃત્તિઓ જેવી કે, યોગ, સૂર્યનમસ્કાર, રમત, પુસ્તક વાંચન, પ્રયોગો વગેરેનું આયોજન કરેલ છે.
- ૫ વર્ષથી વધુ ઉંમરના બાળકો માટે પ્રાથમિક શાળાઓમાં બાલવાટિકા વર્ગની શરૂઆત કરવામાં આવી છે તથા બાલવાટિકા નોંધણીની પ્રક્રિયા હાથ ધરવામાં આવી છે.
- ભારતીય જ્ઞાન પ્રણાલીને અભ્યાસક્રમમાં સમાવવા માટે ભગવદ્ ગીતાના સારને ધોરણ ૬ થી ૧૦માં રસપ્રદ રીતે રજૂ કરતું સાહિત્ય શાળાઓ સુધી પહોંચાડવામાં આવેલ છે.
- ધોરણ ૬ થી ૮ માં વૈદિક ગણિત પાઠ્યપુસ્તકો દરેક શાળામાં ઉપલબ્ધ કરાવ્યા છે.
- વર્ષ-૨૦૨૫-૨૬ માં રાજ્યમાં ૮૫ નવી સરકારી માધ્યમિક શાળાઓ અને ૦૫ નવી સરકારી ઉચ્ચતર માધ્યમિક શાળાઓ શરૂ કરવામાં આવી છે, ઉપરાંત ૦૮ મહાનગરપાલિકા વિસ્તારમાં અંગ્રેજી માધ્યમની સરકારી માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શાળાઓની મંજૂરી આપવામાં આવી છે.
- **મુખ્યમંત્રી જ્ઞાનસેતુ મેરીટ સ્કોલરશીપ યોજના** અંતર્ગત છેલ્લા ત્રણ નાણાંકીય વર્ષ દરમિયાન કુલ ૮૦,૦૦૦ વિદ્યાર્થીઓને કુલ રૂ. ૬૮.૮૦ કરોડની શિષ્યવૃત્તિ ચુકવવામાં આવી છે.
- **મુખ્યમંત્રી જ્ઞાનસાધના મેરીટ સ્કોલરશીપ યોજના** અંતર્ગત છેલ્લા ત્રણ નાણાંકીય વર્ષ દરમિયાન કુલ ૭૫,૦૦૦ વિદ્યાર્થીઓને કુલ રૂ. ૮૭.૫૩ કરોડની શિષ્યવૃત્તિ ચુકવવામાં આવી છે.
- **નમો લક્ષ્મી યોજના** અંતર્ગત છેલ્લા બે નાણાંકીય વર્ષ દરમિયાન ૧૦,૮૪,૮૮૨ વિદ્યાર્થીનીઓને રૂ. ૧૩૩૮ કરોડની સહાય ચુકવવામાં આવી છે.
- **નમો સરસ્વતી યોજના** અંતર્ગત છેલ્લા બે નાણાંકીય વર્ષ દરમિયાન ૧,૫૦,૭૬૨ વિદ્યાર્થીઓને કુલ રૂ. ૨૦૫ કરોડની સહાય ચુકવવામાં આવી છે.
- વર્ષ ૨૦૨૪ની ભરતી અંતર્ગત સરકારી અને બિનસરકારી અનુદાનિત માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શાળાઓમાં કુલ ૮૪૦૦ શિક્ષણ સહાયક, ૪૭૦ આચાર્યની ભરતી કરવામાં આવી છે.

ઉચ્ચ અને ટેકનિકલ શિક્ષણ

- રાજ્યના ઉચ્ચ અભ્યાસક્રમમાં પ્રવેશ મેળવતા તેજસ્વી અને જરૂરીયાતમંદ વિદ્યાર્થીઓને ઉચ્ચ શિક્ષણ માટે જરૂરી આર્થિક સહાય મળી રહે તે હેતુથી મુખ્યમંત્રી યુવા સ્વાવલંબન યોજના(MYSY) હેઠળ વર્ષ ૨૦૨૫-૨૬ અંતર્ગત જાન્યુઆરી અંતિત કુલ ૯૨,૦૩૪ વિદ્યાર્થીઓને રૂ.૩૮૭.૦૩ કરોડની સહાય ચૂકવેલ છે તથા આ યોજના અંતર્ગત આજદિન સુધીમાં કુલ ૬,૨૩,૮૯૧ વિદ્યાર્થીઓને કુલ રૂ.૨૮૪૪.૬૮ કરોડની સહાય ચુકવવામાં આવી છે.
- રાજ્ય સરકારે MBBS માં અભ્યાસ કરતી વિદ્યાર્થીનીઓને આર્થિક સહાય પૂરી પાડવા મુખ્યમંત્રી કન્યા કેળવણી નિધિ યોજના (MKKN) હેઠળ જાન્યુઆરી-૨૦૨૬ સુધીમાં કુલ ૪૩૯૧ વિદ્યાર્થીનીઓને રૂ.૧૩૭.૨૫ કરોડની સહાય ચુકવવામાં આવી છે તથા આ યોજના અંતર્ગત આજદિન સુધીમાં કુલ ૨૭,૯૯૭ વિદ્યાર્થીનીઓને કુલ રૂ.૮૩૫.૧૯ કરોડની સહાય ચુકવવામાં આવી છે.
- રાજ્યના યુવાનો સંશોધન, નવીનતા અને ઉદ્યોગસાહસિકતા ક્ષેત્રે સજ્જ થાય તે હેતુથી વર્ષ ૨૦૧૭માં શરૂ કરવામાં આવેલ સ્ટુડન્ટ સ્ટાર્ટઅપ એન્ડ ઇનોવેશન પોલીસી (SSIP) હેઠળ થયેલ કામગીરી માટે ભારત સરકાર દ્વારા રાજ્યોને સ્ટાર્ટઅપ રેન્કિંગ ફ્રેમવર્ક માટે આપવામાં આવતા એવોર્ડ અંતર્ગત ગુજરાત રાજ્ય **સતત પાંચ વર્ષથી બેસ્ટ પર્ફોમર રાજ્ય** તરીકેનો એવોર્ડ મેળવી રહ્યું છે, જે આપણા સૌ માટે ગૌરવપૂર્ણ છે.
- દેશની સૌપ્રથમ સ્ટુડન્ટ સ્ટાર્ટઅપ એન્ડ ઇનોવેશન પોલીસી(2.0) અંતર્ગત સહાય મેળવી રહેલ સંસ્થાઓ દ્વારા ૪,૯૪૮ પ્રૂફ ઓફ કન્સેપ્ટ, ૨,૨૮૨ IP ફાઇલિંગ, ૮૨૮ સ્ટાર્ટઅપને સપોર્ટ આપવામાં આવેલ છે.
- રાજ્ય સરકાર દ્વારા ઇન્ટીગ્રેટેડ મોડ્યુલ ફોર પ્લેસમેન્ટ એપ્રેન્ટિસશીપ કમ ટ્રેઈનીંગ (IMPACT) યોજના હેઠળ વર્ષ ૨૦૨૫-૨૬ દરમિયાન ૧૬,૩૦૦ થી વધુ વિદ્યાર્થીઓ સહિત આજ દિન સુધીમાં અંદાજિત ૫૮ હજાર વિદ્યાર્થીઓને તાલીમ આપવામાં આવેલ છે.

વંચિતોનો

વિકાસ

વિકસતી જાતિ કલ્યાણ

- વંચિતોના વિકાસ માટે વંચિતોના વાણીજ્ય બની આ સરકાર વંચિત વિકાસનું ઉત્તમ કાર્ય કરી રહી છે. બાલવાટિકા તથા પ્રાથમિક શાળાના વિદ્યાર્થીઓને શિષ્યવૃત્તિ અને ગણવેશ સહાય તેમજ માધ્યમિક શાળા, ઉચ્ચતર માધ્યમિક તથા ઉચ્ચ શિક્ષણમાં અભ્યાસ કરતા વિકસતી જાતિના ૩૩.૭૫ લાખ વિદ્યાર્થીઓને વિવિધ શૈક્ષણિક યોજનાઓ હેઠળ ડિસેમ્બર,૨૦૨૫ અંતિત રૂ.૭૬૦.૨૫ કરોડની શિષ્યવૃત્તિ આપવામાં આવી છે.
- સામાજિક અને શૈક્ષણિક રીતે પછાતવર્ગો માટે રાજ્યમાં ૭૫૦ ગ્રાન્ટ ઇન એઈડ છાત્રાલયો, ૬૮ સરકારી છાત્રાલયો અને ૧૮૭ આશ્રમશાળાઓ તેમજ ૩૫ નિવાસી શાળાઓ કાર્યરત છે, જેમાં અંદાજે ૮૨,૦૦૦ **વિદ્યાર્થીઓને વિનામૂલ્યે રહેવા, જમવા અને ભણવાની સુવિધાઓ** પુરી પાડવામાં આવી રહી છે, જેમા અત્યાર સુધીમાં રૂ.૨૭૪.૭૧ કરોડનો ખર્ચ કરવામાં આવેલ છે.

- **પંડિત દિનદયાળ આવાસ યોજના** અંતર્ગત મકાન બાંધકામ સહાય રૂ.૧.૨૦ લાખથી વધારીને રૂ.૧.૭૦ લાખ કરવામાં આવી છે. છેવાડાના અતિપછાત, વિચરતી વિમુક્ત જાતિ, સામાજિક અને શૈક્ષણિક પછાતવર્ગ અને આર્થિક પછાતવર્ગના ૧૫,૫૦૦ થી વધુ નાગરિકોને મકાન બાંધવા માટે ડિસેમ્બર,૨૦૨૫ અંતિત રૂ.૧૫૩ કરોડ જેટલી સહાય ચૂકવવામાં આવી છે.
- **કુંવરબાઈનું મામેરું યોજના** અને **સાત ફેરા સમૂહ લગ્ન યોજના** અંતર્ગત સામાજિક અને શૈક્ષણિક રીતે પછાતવર્ગ તથા આર્થિક રીતે પછાત વર્ગની ૫૬,૦૦૦ થી વધુ કન્યાઓને ડિસેમ્બર,૨૦૨૫ અંતિત અંદાજિત રૂ. ૬૮.૫૦ કરોડની સહાય આપવામાં આવી છે.

અનુસૂચિત જાતિ કલ્યાણ

- **પ્રિ-મેટ્રિક શિષ્યવૃત્તિ તથા ગણવેશ સહાય યોજના** અને **પોસ્ટ મેટ્રિક શિષ્યવૃત્તિ યોજના**માં ડિસેમ્બર,૨૦૨૫ અંતિત રૂ.૪૧૯ કરોડનો ખર્ચ કરી ૪.૮૫ લાખ જેટલા વિદ્યાર્થીઓને શિષ્યવૃત્તિ આપવામાં આવી છે.
- **ડૉ. સવિતા આંબેડકર આંતરજ્ઞાતિય લગ્ન સહાય યોજના**માં રૂ.૨.૫૦ લાખ સહાય આપવામાં આવે છે. ડિસેમ્બર,૨૦૨૫ અંતિત રૂ.૧૬.૦૩ કરોડનો ખર્ચ કરી ૫૪૭ યુગલોને આ યોજનાનો લાભ આપવામાં આવ્યો છે, જે સામાજિક સમરસતાને પ્રેરણા આપે છે.
- **ડૉ.આંબેડકર આવાસ યોજના** હેઠળ રૂ.૧,૭૦,૦૦૦ ની સહાય આપવામાં આવે છે. આ યોજનામાં ડિસેમ્બર,૨૦૨૫ અંતિત રૂ.૫૮.૧૨ કરોડનો ખર્ચ કરી ૪,૭૯૯ લાભાર્થીઓને મકાન બાંધવા માટે સહાય આપવામાં આવી છે.
- **ડૉ.આંબેડકર વિદેશ અભ્યાસ લોન યોજના** અંતર્ગત વિદેશમાં ચાલતા ઉચ્ચ કક્ષાના અભ્યાસ અર્થે રૂ.૧૫ લાખની લોન ૪%ના દરે આપવામાં આવે છે. જેમાં ડિસેમ્બર,૨૦૨૫ અંતિત રૂ.૬૨.૮૦ કરોડનો ખર્ચ કરી ૪૧૮ વિદ્યાર્થીઓને વિદેશમાં ભણવા માટે લોન આપવામાં આવી છે.

સમાજ સુરક્ષા

- **સંત સૂરદાસ યોજના** હેઠળ ૬૦% કે તેથી વધુ દિવ્યાંગતા ધરાવતા કુલ-૭૬,૫૨૫ વ્યક્તિઓને ડિસેમ્બર,૨૦૨૫ અંતિત કુલ રૂ.૬૩.૧૦ કરોડની નાણાકીય સહાય આપવામાં આવેલ છે.
- બૌદ્ધિક અસમર્થતા ધરાવતી (મનોદિવ્યાંગ) વ્યક્તિઓને આર્થિક સહાય આપવાની પેન્શન યોજના હેઠળ ડિસેમ્બર,૨૦૨૫ અંતિત ૭૭,૯૦૦ જેટલા લાભાર્થીઓને આશરે રૂ.૬૯ કરોડની સહાય ચૂકવવામાં આવેલ છે.
- નિરાધાર વૃદ્ધો અને નિરાધાર દિવ્યાંગોના નિભાવ માટે આર્થિક સહાય યોજના હેઠળ ડિસેમ્બર,૨૦૨૫ અંતિત અંદાજિત ૫.૪૨ લાખ લાભાર્થીઓને રૂ.૫૨૬ કરોડ જેટલી સહાય ચૂકવી છે.
- રાજ્ય સરકારની સેવાઓમાં દિવ્યાંગજનો માટે રૂ.૧,૦૦૦ થી વધુ જગ્યાઓ ભરવા માટે ખાસ ભરતી ઝુંબેશ હાથ ધરવામાં આવેલ છે.

- માતા-પિતાની છત્રછાયા ગુમાવનાર ૧૮ વર્ષ કે તેથી ઓછી ઉંમરના બાળકોને **પાલક માતા-પિતા યોજના** હેઠળ અંદાજિત રૂ.૫૦૦ લાભાર્થીઓને ડિસેમ્બર, ૨૦૨૫ અંતિત રૂ.૫૯ કરોડ જેટલી સહાય ચૂકવેલ છે. આ યોજનાની લાભાર્થી દિકરીને લગ્ન સમયે સહાય યોજના હેઠળ ડિસેમ્બર, ૨૦૨૫ અંતિત રૂ.૫૦ લાભાર્થી દિકરીઓને રૂ.૫ કરોડની સહાય ચૂકવેલ છે.
- અનુસૂચિત જાતિ અને વિકસતિ જાતિના લાભાર્થીઓ માટે ચાલતી શૈક્ષણિક લોન તથા સ્વરોજગારલક્ષી લોન યોજના માટે વિવિધ નિગમોને ચાલુ વર્ષે રૂ. ૭૫૦ કરોડ તેમજ દિવ્યાંગજનો માટે ચાલતી સ્વરોજગારલક્ષી લોન યોજના માટે રૂ. ૬ કરોડની ફાળવણી કરવામાં આવી છે.

આદિજાતિ વિકાસ

- **વનબંધુ કલ્યાણ યોજના** અંતર્ગત વર્ષ ૨૦૨૪-૨૫ માં રૂ.૨૨,૦૨૫.૮૧ કરોડની જોગવાઈ કરવામાં આવેલ તેમજ ચાલુ વર્ષ ૨૦૨૫-૨૬ માટે રૂ.૩૦૧૨૦.૯૬ કરોડની જોગવાઈ કરવામાં આવી છે. ‘ગુજરાત પેટર્ન’ હેઠળ ચાલુ વર્ષ ૨૦૨૫-૨૬ માટે રૂ.૧૦૫૯ કરોડની જોગવાઈ કરવામાં આવી છે.
- **રાજ્ય સરકારની તથા ભારત સરકારની પ્રિ-મેટ્રીક અને પોસ્ટ મેટ્રીક શિષ્યવૃત્તિની** યોજનાઓ અંતર્ગત અત્યાર સુધી રૂ.૮૫૪ કરોડના ખર્ચે ૧૨.૨૨ લાખ અનુસૂચિત જનજાતિના વિદ્યાર્થીઓને લાભ આપવામાં આવેલો છે.
- સરકારી એકલવ્ય મોડેલ રેસિડેન્શિયલ શાળાઓ, આદર્શ નિવાસી શાળાઓ તથા અનુદાનિત આશ્રમશાળાઓ ખાતે અનુસૂચિત જનજાતિના આશરે ૧.૬૦ લાખ વિદ્યાર્થીઓએ અત્યાર સુધી રૂ.૪૫૬.૪૭ કરોડના ખર્ચે વિનામુલ્યે નિવાસ સહ અભ્યાસની સુવિધાનો લાભ લઈ રહેલ છે.
- એકલવ્ય મોડેલ રેસિડેન્શિયલ શાળાઓએ વર્ષ-૨૦૨૪-૨૫માં ધોરણ ૧૦નું ૯૭.૧૮%, ધોરણ ૧૨ વિજ્ઞાન પ્રવાહનું ૮૨.૧૭%, ધોરણ ૧૨ વાણિજ્ય પ્રવાહનું ૯૮.૩૬% અને ધોરણ ૧૨ સામાન્ય પ્રવાહનું ૯૯.૮૬% સરેરાશ બોર્ડ પરિણામ મેળવેલ છે. જ્યારે આદર્શ નિવાસી શાળાઓએ ધોરણ ૧૦માં ૯૭.૨૩% તથા ધોરણ ૧૨ વિજ્ઞાનપ્રવાહમાં ૮૩.૨૨% પરિણામ મેળવેલ છે.
- અનુસૂચિત જનજાતિના કુમાર-કન્યા છાત્રાલયમાં રહી અભ્યાસ કરી શકે તે માટે **ગ્રાન્ટ ઈન એઈડ છાત્રાલય** માટે ચાલુ નાણાંકીય વર્ષમાં અત્યાર સુધી ૭૪.૭૮ કરોડ નો ખર્ચ કરવામાં આવેલ છે. આ છાત્રાલયોમાં ૫૬,૪૮૨ વિદ્યાર્થીઓ લાભ લઈ રહ્યા છે.
- ઉચ્ચ અભ્યાસ માટે બહાર ગામ રહીને અભ્યાસ કરતા અનુ. જનજાતિના વિદ્યાર્થીઓ માટે રહેવા-જમવાની સુવિધા સાથેના **સરકારી છાત્રાલયો અને સમરસ છાત્રાલયો** માટે ચાલુ વર્ષે અત્યાર સુધી રૂ.૬૫.૩૮ કરોડનો ખર્ચ કરવામાં આવેલ છે. જેનો લાભ રૂ.૧,૩૦૦ વિદ્યાર્થીઓ લઈ રહ્યા છે.
- અનુ. જનજાતિના પરિવારો માટેની **વ્યક્તિગત અને હળપતિ આવાસ યોજના** અંતર્ગત રૂ.૨૩.૫૮ કરોડનો ખર્ચ કરી અંદાજિત ૩૧૧૭ લાભાર્થીઓને લાભ આપવામાં આવેલો છે.

- અનુસૂચિત જનજાતિ સમાજના ગંભીર રોગથી પીડિત દર્દીઓને તબીબી સારવાર તથા પૌષ્ટિક આહારના ખર્ચમાં મદદરૂપ થવા માટે આપવામાં આવતી સહાય પેટે અત્યાર સુધી રૂ.૧૪.૩૨ કરોડનો ખર્ચ કરી **૨૩૪૭** લાભાર્થીઓને લાભ આપવામાં આવેલો છે.
- **કૃષિ વૈવિધ્યકરણ** યોજના અંતર્ગત આદિજાતિ ખેડૂતોને સુધારેલા બિયારણ, ખાતર કીટ અને કૃષિ અંગેની તાલીમ આપવામાં આવે છે તથા રૂ. ૪૨ કરોડના ખર્ચે કુલ ૮૬,૧૩૧ ખેડૂતોને યોજના હેઠળ આવરી લેવામાં આવેલા છે.
- આદિજાતિ વિસ્તારોમાં આદિજાતિ મહિલાઓને રોજગારી પુરી પાડવાના હેતુસર ચાલુ વર્ષે કુલ રૂ.૩૬.૮૦ કરોડના ખર્ચે ૧૨,૪૬૫ દુધાળા પશુઓ **૪૦૮૬** મહિલા લાભાર્થીઓને આપવામાં આવેલા છે.
- **ઇન્ટીગ્રેટેડ ડેરી ડેવલપમેન્ટ પ્રોજેક્ટ (આઇ.ડી.ડી.પી)** અંતર્ગત રાજ્યની ડેરીઓ દ્વારા ગ્રામ્ય આદિજાતિ વિસ્તારમાં નાણાંકીય વર્ષ ૨૦૨૫-૨૬માં અત્યાર સુધી **કુલ- ૫૬૨૮ લાભાર્થીઓ**ને રૂ.૧૬.૩૨ કરોડના ધિરાણનો લાભ આપવામાં આવેલો છે.

મહિલા અને બાળ કલ્યાણ

- યત્ર નાર્યસ્તુ પૂજ્યન્તેનાં મંત્ર સાથે નારી ઉત્કર્ષ અને કલ્યાણ માટે મારી સરકાર પ્રતિબદ્ધ છે. રાજ્યની તમામ આંગણવાડીઓમાં પાયાની સુવિધાઓ ઉપલબ્ધ કરાવવા મારી સરકાર કટિબદ્ધ છે. રાજ્યની કુલ ૫૩,૦૬૫ આંગણવાડીઓમાં શૌચાલય, વીજ કનેક્શન તેમજ પીવાના પાણીની સુવિધા પુરી પાડવામાં આવેલ છે. વર્ષ ૨૦૨૫-૨૬ માં ૧૦૬૩ આંગણવાડી કેન્દ્રોનું લોકાર્પણ કરવામાં આવેલ છે જ્યારે ૧૦૮૭ આંગણવાડી કેન્દ્રોના ખાતમુહૂર્ત કરવામાં આવેલ છે જેનું બાંધકામ પ્રગતિમાં છે.
- આંગણવાડી કાર્યકર અને તેડાગર વગર કોઈ આંગણવાડી ન રહે તે માટે ચાલુ વર્ષે **૬૦૦૦ થી વધુ** આંગણવાડી કાર્યકર અને તેડાગરને માનદસેવાઓથી લેવા માન. મુખ્યમંત્રીશ્રીના વરદહસ્તે નિમણૂકપત્રો એનાયત કરવામાં આવેલ છે.
- રાજ્યમાં પોષણ સ્તરને સુદૃઢ કરવા **“પૂરક પોષણ યોજના”** હેઠળના લાભાર્થીઓને બાલશક્તિ અને માતૃશક્તિના **રેડી ટૂ ફૂડના** પેકેટ **ટેક હોમ રેશન** તરીકે આપવામાં આવે છે. આ યોજના હેઠળ વર્ષ ૨૦૨૫-૨૬ માં નવેમ્બર, ૨૦૨૫ અંતિત **૩૦ લાખથી વધુ** બાળકો, સગર્ભા અને ધાત્રી માતાઓને લાભ **આપવામાં આવ્યો** છે.
- બાળકો, સગર્ભા અને ધાત્રી માતાઓના પોષણ સ્તરમાં સુધારો લાવવા કુલ ૧૪૧ ઘટકોમાં **દૂધ સંત્રપની યોજના** અમલી છે. વર્ષ ૨૦૨૫-૨૬ દરમિયાન અત્યાર સુધીમાં ૮.૬૪ લાખ બાળકો, સગર્ભા અને ધાત્રી માતાઓએ આનો લાભ લીધેલ છે.
- **પોષણ સુધા યોજના** અંતર્ગત આદિજાતિ જિલ્લાઓની સગર્ભા અને ધાત્રી માતાઓને આંગણવાડી કેન્દ્રમાં જ દરરોજ એક વખત પૌષ્ટિક ગરમ ભોજન આપવામાં આવે છે. વર્ષ ૨૦૨૫-૨૬ માં નવેમ્બર ૨૦૨૫ સુધીમાં ૮૮ હજાર માતાઓને લાભ આપ્યો છે.
- મહિલાઓની સગર્ભાવસ્થાથી બાળક ૨ વર્ષનું થાય ત્યાં સુધીના **૧૦૦૦ દિવસ** સુધી પોષણ પૂરૂ પાડવા વર્ષ ૨૦૨૨-૨૦૨૩ થી **“મુખ્યમંત્રી માતૃશક્તિ યોજના (MMY)”**નો અમલ કરી **રો-શશન કીટ** આપવામાં આવે છે. વર્ષ ૨૦૨૫-૨૬ દરમિયાન લાભાર્થીઓ માટે ૧૫૬ કરોડ ખર્ચ થયેલ છે.

- **પૂર્ણા યોજના અંતર્ગત** ૧૫ થી ૧૮ વર્ષની તમામ કિશોરીઓને વાર્ષિક ૩૦૦ દિવસ માટે પૂરક પોષણ આપવામાં આવે છે. વર્ષ ૨૦૨૫-૨૬ માં રાજ્યની અંદાજિત ૮.૫૦ લાખ કિશોરીઓને આવરી લીધેલ છે. જે અંતર્ગત ડિસેમ્બર-૨૦૨૫ અંતિત કુલ રૂ.૨૫૦.૩૫ કરોડ ખર્ચ થયેલ છે.
- રાજ્યમાં પોષણ અંગે જાગૃકતા લાવવા ૩.૭ કરોડ લોકોની સહભાગીતા સાથે ૧.૩૫ કરોડ પ્રવૃત્તિઓ હાથ ધરીને **પોષણ માસ**ની ઉજવણી રાજ્યમાં કરવામાં આવેલ છે.
- રાજ્યની ગંગાસ્વરૂપા બહેનો સન્માનપૂર્વક જીવી શકે તે હેતુથી આર્થિક રીતે મદદરૂપ થવા મારી સરકાર દ્વારા **ગંગા સ્વરૂપા આર્થિક સહાય યોજના** અમલમાં મૂકવામાં આવી છે. રાજ્યમાં હાલ અંદાજિત ૧૭ લાખ લાભાર્થી ગંગા સ્વરૂપા બહેનોને ડાયરેક્ટ બેનીફીટ ટ્રાન્સફર (DBT) મારફતે દર માસે રૂ.૧૨૫૦ લેખે આ વર્ષે રૂ.૨૫૬૨ કરોડની સહાય ચૂકવવામાં આવેલ છે.
- રાજ્યમાં દિકરીના જન્મદર અને શિક્ષણને પ્રોત્સાહિત કરવા **“વ્હાલી દીકરી યોજના”** અંતર્ગત ૩ લાખથી વધુ લાભાર્થી દીકરીઓની સહાય મંજૂર કરવામાં આવેલ છે.
- રાજ્યની મહિલાઓને વિપરીત સ્થિતિમાં ત્વરિત મદદ મળી રહે તે માટે અદ્યતન ટેકનોલોજીથી સજ્જ **૧૮૧ અભયમ મહિલા હેલ્પલાઇન** યોજના હેઠળ ૫૯ રેસ્ક્યુ વાનની સુવિધા પુરી પાડી છે. આ વર્ષે મહિલા હેલ્પલાઇન માં ૧.૫૦ લાખથી વધુ મહિલાઓએ માર્ગદર્શન અને કાઉન્સેલીંગ માટે કોલ કરતાં ૩૦ હજારથી વધુ બહેનોને ઘટનાસ્થળે જઈને મદદ પહોંચાડવામાં આવી છે.
- **પોલીસ સ્ટેશન બેઇઝડ સપોર્ટ સેન્ટર યોજના** હેઠળ કૌટુંબિક કે અન્ય સમસ્યાથી અસરગ્રસ્ત મહિલાઓને પોલીસ સ્ટેશનમાં જ કાઉન્સેલિંગ દ્વારા માનસિક અને કાનૂની પીઠબળ પૂરું પાડવામાં આવે છે. રાજ્યના જિલ્લા અને તાલુકા મથકોએ કુલ ૮૦ સપોર્ટ સેન્ટર કાર્યરત છે, જેમાં ૧૬૦ જેટલા કુશળ કાઉન્સિલરો દ્વારા કાઉન્સેલીંગ તેમજ કાનૂની માર્ગદર્શન આપવામાં આવે છે. આ વર્ષે ૧૦ હજારથી વધુ મહિલાઓને આ સેવાઓ પુરી પાડવામાં આવેલ છે.

શહેરી વિકાસ અને શહેરી ગૃહ નિર્માણ

દેશના યશસ્વી વડાપ્રધાન અને ગુજરાત રાજ્યના તત્કાલિન માન. મુખ્ય મંત્રીશ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ વર્ષ ૨૦૦૫ માં “શહેરી વિકાસ વર્ષ”ની શરૂઆત કરી હતી. મારી સરકારે વર્ષ ૨૦૨૫ ને શહેરી વિકાસ વર્ષ તરીકે ઉજવી વિકાસની ગતિ બમણી કરી છે.

- શહેરી વિકાસ વર્ષ અન્વયે કુલ ૫૫,૦૭૩ કરોડનાં ૧૩,૩૧૪ કામો મંજૂર કર્યા છે, જે પૈકી નવરચિત કરમસદ –આણંદ, નડીયાદ, મોરબી, સુરેન્દ્રનગર, ગાંધીધામ, પોરબંદર વાપી, નવસારી, મહેસાણા મહાનગરોમાં કુલ ૪૮૫૫ કરોડથી વધુના ૨૩૦૦ જેટલા કામો મંજૂર કર્યા છે.
- કલોલ, સાણંદ, સાવલી, બારડોલી અને હિરાસર એમ કુલ ૫ સેટેલાઈટ ટાઉન જાહેર કરવામાં આવ્યા છે.

- Railway Over Bridge/Railway Under Bridge હેઠળ ૩૧૮૦ કરોડના ૯૬ કામો મંજૂર કરવામાં આવ્યા છે.
- વડોદરા, જૂનાગઢ, નવસારી અને પોરબંદર શહેરોમાં ૮.૪૫ કિ.મી. આઈકોનિક રોડ બનાવવામાં આવ્યા છે.
- **સ્માર્ટ સીટી મિશન** અંતર્ગત ગુજરાતના ૬ શહેરોમાં કુલ રૂ.૧૧૫૦૭ કરોડના ૩૫૯ પ્રોજેક્ટ હાથ ધરવામાં આવ્યા છે.
- **પ્રધાનમંત્રી આવાસ યોજના(શહેરી)** અંતર્ગત ૨૨,૦૦૦ જેટલા આવાસોની ફાળવણી કરવામાં આવી છે અને વધુ ૧૦૦૦૦ આવાસો ફાળવણી હેઠળ છે.
- **PM e Bus સેવા યોજના હેઠળ રાજ્યના ૮ મહાનગરોમાં ૭૫૦ થી વધુ બસ માટે ૧૧૩ કરોડનું આયોજન હાથ ધરેલ છે.**
- મેટ્રો પરિવહન સેવા હેઠળ કુલ ૬૮.૨૫૭ કિ.મી. કામગીરી પૂર્ણ કરેલ છે. જે પૈકી મોટેરાથી મહાત્મા મંદિર સુધીના કુલ ૨૮.૨૫ કિમીના રૂટને માન. વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીની ઉપસ્થિતિમાં જાહેર જનતા માટે ખુલ્લો મુકાયો છે.
- સાબરમતી રિવરફ્રન્ટના કુલ ૬ ફેઝમાંથી ૧૧.૨ કિમીના રૂ.૧૨૦૨ કરોડના કામો પૂર્ણ કરેલ છે. જ્યારે ૨૮ કિમીના કામો હાલ પ્રગતિ હેઠળ છે
- “PM Street Vendors AtmaNirbhar Nidhi” (PM SVANidhi) થી ૪.૯૦ લાખથી વધુ શેરી ફેરીયાઓને રૂ. ૧૧૭૦/- કરોડની લોન બેંક ગેરંટી વગર આપવામાં આવી છે.
- **૧૦ લાખથી વધારે વસ્તી** ધરાવતા સ્વચ્છ શહેરોની કેટેગરીમાં **અમદાવાદ મહાનગરપાલિકાને પ્રથમ ક્રમાંક** પ્રાપ્ત થયેલ છે.
- રાજ્યની તમામ ૧૬૭ શહેરી સ્થાનિક સ્વરાજ્યની સંસ્થાઓ ODF પ્રમાણિત થઈ છે. અનેક શહેરોને Garbage Free City , ODF+/ODF++/Water+ સર્ટિફિકેશન મળ્યું છે.
- **ટાઉન પ્લાનિંગ સ્કીમ** હેઠળ વેબ-GIS દ્વારા ૪૦૦ ટી.પી. સ્કીમ ઉપલબ્ધ કરવામાં આવી છે અને વધુ ૬૦૦ સ્કીમનું ડિજિટલાઇઝેશન પ્રક્રિયા હેઠળ છે.
- ODPS 3.0 ને AI, Blockchain જેવી આધુનિક ટેકનોલોજી સાથે અમલમાં મૂકવા આયોજન છે.
- ૩૨ મુસદ્દારૂપ નગર રચના યોજના, ૩૮ પ્રારંભિક નગર રચના યોજના, ૪૩ આખરી નગર રચના યોજના તેમજ ૦૪ વિકાસ યોજનાઓ મંજૂર કરવામાં આવી છે.
- Bullet Train ના રાજ્યના ૮ સ્ટેશનો માટે Gujarat High Speed Railway Station Planning Authority ની રચના કરવામાં આવી છે.

પંચાયત અને
ગ્રામ વિકાસ

- **મારી આ સરકાર પૂજ્ય મહાત્મા ગાંધીજીના વિચારોને વરેલી સરકાર છે. બાપુએ કહ્યું હતું કે, 'ભારતનો આત્મા ગામડાઓમાં વસે છે.'** આ મંત્રને ચરિતાર્થ કરતા ગ્રામીણ વિકાસ ક્ષેત્રે આ સરકાર અભૂતપૂર્વ કાર્ય કરી રહી છે. પ્રધાનમંત્રી આવાસ યોજના (ગ્રામીણ) અંતર્ગત વર્ષ ૨૦૨૫-૨૬માં નવેમ્બર-૨૦૨૫ સુધીમાં ૭૮,૭૫૨ આવાસોનું લાભાર્થીઓ દ્વારા નિર્માણ કરવામાં આવેલ જેમાં રૂ. ૯૭૮ કરોડથી વધુની સહાય આપવામાં આવેલ છે.
- તા.૧૫/૧૧/૨૦૨૫ના રોજ માનનીય વડાપ્રધાનશ્રીના વરદહસ્તે નર્મદા ખાતે યોજાયેલ કાર્યક્રમમાં પ્રધાનમંત્રી આવાસ યોજના-ગ્રામીણ અંતર્ગત સમગ્ર રાજ્યમાં રૂ.૧૦૦૮.૧૯ કરોડના ખર્ચે કુલ ૬૧,૧૨૫ લાભાર્થીઓનો ઈ-ગૃહ પ્રવેશ કરવામાં આવેલ છે.
- **સ્વચ્છ ભારત મિશન (ગ્રામીણ)** અંતર્ગત વર્ષ ૨૦૨૫-૨૬ માં નવેમ્બર-૨૦૨૫ અંતિત વ્યક્તિગત શૌચાલય ૪૫૦૧૦, સામૂહિક શૌચાલય ૧૩૨, વ્યક્તિગત સોકપીટ ૩૦૩૧ અને સામૂહિક સોકપીટ ૨૨૯૩૮ બાંધકામ પૂર્ણ થયેલ છે તેમજ ઘન કચરાના વ્યવસ્થાપન અંતર્ગત જૈવિક કચરાના નિકાલ માટે ૫૭૯૬ સામૂહિક કમ્પોસ્ટ પીટ અને ૩૩૮૨ વ્યક્તિગત કમ્પોસ્ટ પીટ બાંધકામ પૂર્ણ કરવામાં આવેલ છે. ઘન કચરાના વ્યવસ્થાપનની કામગીરીના ભાગરૂપે ૧૨૦૩ સેગ્રીગેશન શેડનું બાંધકામ પૂર્ણ કરવામાં આવેલ છે અને કુલ રૂ. ૧૭૪.૯૨ કરોડનો ખર્ચ કરવામાં આવેલ છે.
- **ગોબરઘન પ્રોજેક્ટ** અંતર્ગત પ્રથમ ચરણની સફળતા બાદ બીજા ચરણમાં ૪૮૦૦ લાભાર્થીઓને લાભ આપવામાં આવ્યો છે.
- **પ્રધાનમંત્રી કૃષિ સિંચાઈ યોજના-વોટરશેડ ડેવલપમેન્ટ કમ્પોનન્ટ ૨.૦** અંતર્ગત વર્ષ ૨૦૨૫-૨૬માં નવેમ્બર-૨૦૨૫ અંતિત ભૂમિ અને ભેજ સંરક્ષણના, જળસંગ્રહના અને ભૂ-જળ રિચાર્જના કુલ ૪૫૮૨ કામો તેમજ ઉત્પાદન પૃદ્ધિને લગત ૧૪૭૩ કામો પૂર્ણ થયેલ છે. જે પૈકી રૂ. ૪૮.૨૪ કરોડનો ખર્ચ થયેલ છે.
- **રાષ્ટ્રીય ગ્રામીણ આજીવિકા મિશન** અંતર્ગત વર્ષ ૨૦૨૫-૨૬ માં નવેમ્બર-૨૦૨૫ અંતિત ૬૭૩૧ સ્વસહાય જૂથોની રચના કરવામાં આવેલ છે. રીવોલ્વીંગ ફંડ (RF) પેટે કુલ ૪૪૦૧ સ્વસહાય જૂથોને કુલ રૂ. ૧૩.૧૬ કરોડ સહાય આપવામાં આવેલ છે, કૉમ્યુનિટી ઈન્વેસ્ટમેન્ટ ફંડ (CIF) પેટે ૫૮૩૨ સ્વસહાય જૂથોને રૂ.૭૫.૪૫ કરોડ પેટે સહાય આપવામાં આવેલ છે. કુલ ૪૮૪૭૪ સ્વસહાય જૂથોને કેશ કેડિટ (CC) લોન પેટે બેન્ક માથી રૂ. ૯૭૬.૬૧ કરોડનું ધિરાણ આપવામાં આવેલ છે.
- મારી સરકારે રાષ્ટ્રીય અને પ્રાદેશિક કક્ષાના ૧૩ **સરસ મેળા**નું આયોજન કર્યું છે. જેમાં ગુજરાત અને અન્ય રાજ્યના એમ કુલ ૯૮૦ સખી મંડળ દ્વારા ભાગ લીધેલ અને રૂ. ૯.૫૦ કરોડ જેટલું વેચાણ થયેલ છે.
- **ઈ-ગ્રામ વિશ્વગ્રામ** યોજના અંતર્ગત મળનાર સેવાઓની સંખ્યા વધીને ૩૨૧ થયેલ છે. જેમાં વર્ષ ૨૦૨૫-૨૬ માં ૪.૯૩ કરોડ ટ્રાન્ઝેક્શન થયેલ છે. જે પૈકી ડીજીટલ સેવા સેતુ હેઠળ વર્ષ ૨૦૨૫-૨૬ (નવેમ્બર-૨૫) અંતિત ૨૨.૧૪ લાખ ટ્રાન્ઝેક્શન થયેલ છે.

- **૧૫મા નાણાપંચ** અંતર્ગત રસ્તા, પ્રાથમિક શિક્ષણ વગેરે જેવી પ્રાથમિક સુવિધાઓ હેઠળના કામો માટે અત્યાર સુધીમાં ૧૩,૦૯૫ કરોડની ગ્રાંટ પંચાયતોને ફાળવવામાં આવેલ છે, જે અંતર્ગત અત્યાર સુધીમાં રૂ.૧૦,૧૬૨.૬૦ કરોડના ખર્ચે ૫,૮૨,૭૬૯ કામો પૂર્ણ કરવામાં આવેલ છે.
- **મહાત્મા ગાંધી સ્વચ્છતા મિશન અંતર્ગત** વર્ષ ૨૦૧૬-૧૭ થી રાજ્યની તમામ ગ્રામ પંચાયતોમાં ડોર ટુ ડોર ઘન કચરાનું કલેક્શન કરી એકત્રિત કરવામાં આવેલો કચરો લેન્ડ ફિલ્ડ સાઈટ સુધી લઈ જવા માટે પ્રતિ માસ વ્યક્તિ દીઠ રૂ.૪.૦૦ લેખે ગ્રાંટ આપવામાં આવતી હતી, જે મારી સરકારે વધારીને પ્રતિ માસ વ્યક્તિ દીઠ રૂ.૮.૦૦ લેખે સહાય આપવાનો નિર્ણય કરેલ છે. વર્ષ ૨૦૨૫-૨૬માં નવેમ્બર-૨૦૨૫ અંતિત રૂ.૧૪૧.૯૧ કરોડની પ્રોત્સાહક ગ્રાંટ આપવામાં આવી છે.

શ્રમ, કૌશલ્ય વિકાસ અને રોજગાર

- ઉદ્યોગોને કુશળ માનવબળ મળી રહે તે હેતુથી સરકારી ઔદ્યોગિક તાલીમ સંસ્થાઓ (I.T.I.) ખાતે કારીગર તાલીમ યોજના હેઠળ પ્રવેશસત્ર ૨૦૨૫-૨૬ અંતર્ગત ૧,૨૦,૩૩૨ તાલીમાર્થીઓને પ્રવેશ આપેલ છે.
- ડિસેમ્બર-૨૦૨૫ અંતિત કુલ ૧૨૬૮ ઔદ્યોગિક ભરતી મેળાના આયોજનથી કુલ ૭૨,૧૨૮ ઉમેદવારોને તથા રોજગાર વિનિમય કચેરીઓ દ્વારા કુલ ૨,૯૨,૫૩૮ ઉમેદવારોને રોજગારી પૂરી પાડવામાં આવેલ છે.
- વર્ષ ૨૦૨૫ દરમિયાન મુખ્યમંત્રી એપ્રેન્ટિસ તાલીમ યોજના અંતર્ગત આશરે **એક લાખ** યુવાઓને ઔદ્યોગિક એકમોમાં ઉદ્યોગલક્ષી તાલીમ આપવામાં આવી છે. આ પ્રયાસો રાજ્યના યુવાઘનને રોજગારક્ષમ બનાવી આત્મનિર્ભર ગુજરાતના નિર્માણમાં મહત્વપૂર્ણ યોગદાન આપી રહ્યા છે.
- રાજ્યના યુવાઘન માટે સાંપ્રત સમયની જરૂરિયાતને અનુલક્ષીને કૌશલ્યવર્ધન હેતુથી સ્થપાયેલ ‘કૌશલ્ય ધી સ્કીલ યુનિવર્સિટી’ દ્વારા સ્કીલ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ/ઇન્ડસ્ટ્રીઝ તથા યુનિવર્સિટીઓ/શૈક્ષણિક સંસ્થાઓ સાથે કેડિટ ટ્રાન્સફર માટે ૯, સ્ટ્રેટેજિક પાર્ટનર તરીકે ૧૬, એફીલીયેટેડ પાર્ટનર તરીકે ૩૫ તથા આંતરરાષ્ટ્રીય શૈક્ષણિક સંસ્થાઓ સાથે ૧૧ એમઓયુ સહિત કુલ ૭૧ એમઓયુ કરેલ છે. આ યુનિવર્સિટી ખાતે ૧૩૭૫ વિદ્યાર્થીઓએ લાંબા ગાળાના અભ્યાસક્રમમાં તથા છેલ્લા ૧ વર્ષમાં ૧૫૫૯ વિદ્યાર્થીઓએ ટૂંકા ગાળાના અભ્યાસક્રમમાં પ્રવેશ મેળવેલ છે.
- શ્રમ સેતુ પોર્ટલમાં છેલ્લા ૧ વર્ષમાં ૫૫૦૦ અરજીઓ પર ઓનલાઈન કાર્યવાહી કરેલ છે તથા ૧૩,૮૧૦ ઓનલાઈન ઇન્સ્પેક્શન કરવામાં આવેલ છે.
- રાજ્યના શ્રમયોગીઓને દિવાળીના સમયે બોનસની રકમ મળી રહે તે માટે વર્ષ ૨૦૨૪-૨૫ દરમિયાન ૧૨,૪૪,૬૫૯ શ્રમિકોને **રૂ.૨૦૨૯ કરોડ** રકમ બોનસ તરીકે ચૂકવણી કરાવવામાં આવેલ છે.
- ઘનવંતરી આરોગ્ય રથ યોજના હેઠળ કુલ ૧૫૪ ઘનવંતરી આરોગ્ય રથ મારફતે ડિસેમ્બર-૨૦૨૫ અંતિત કુલ ૪૦.૨૫ લાખ શ્રમિકોને આરોગ્યલક્ષી સેવા આપેલ છે.

- શિક્ષણ સહાય યોજના હેઠળ નોંધાયેલ બાંધકામ શ્રમિકોના બે બાળકોને ધોરણ ૧ થી Ph.D. સુધીના અભ્યાસ માટે રૂ.૧,૮૦૦ થી રૂ. ૨ લાખ સુધીની સહાય આપવામાં આવે છે, જેમાં ડિસેમ્બર-૨૦૨૫ સુધી કુલ ૪૪,૪૮૩ લાભાર્થીઓને **રૂ.૭૬ કરોડ**ની સહાય આપવામાં આવી છે.
- શ્રમિક અન્નપૂર્ણા યોજના હેઠળ રૂ.૫ ના રાહત દરે બાંધકામ શ્રમિકોને પોષ્ટિક ભોજન પૂરું પાડવામાં આવે છે. હાલ ૨૯૩ બુથ કાર્યરત છે અને ડિસેમ્બર-૨૦૨૫ સુધી કુલ ૧૧૫.૩૦ લાખ ભોજન વિતરણ થયેલ છે.

**માર્ગ અને
મકાન વિભાગ**

- ઉત્તરથી દક્ષિણ અને પૂર્વથી પશ્ચિમના છેડાઓને જોડવા તેમજ વધતા જતા વાહન વ્યવહારને પહોંચી વળવા રાજ્ય સરકારે **નમો શક્તિ એક્સપ્રેસ-વે** અને **સોમનાથ-દ્વારકા એક્સપ્રેસ-વે** બનાવવાનો નિર્ધાર કર્યો છે. આ પ્રોજેક્ટ્સ રાજ્યના ઔદ્યોગિક કેન્દ્રો, પ્રવાસન ધામો અને બંદરોને જોડશે, જેનાથી આર્થિક ગતિવિધિઓને વેગ મળશે અને ગુણવત્તાયુક્ત રસ્તાઓ અને ફ્લાય ઓવરના નિર્માણથી ઇંધણની બચત થશે અને મુસાફરી ઝડપી તથા સુરક્ષિત બનશે. ૧૧૦૦ કિ.મી. લંબાઈના અને રૂ. ૯૩૨૪૦ કરોડના અંદાજીત ખર્ચે હાથ ધરાનારા આ પ્રોજેક્ટથી રાજ્યના ૧૫ જિલ્લાના અંદાજીત ૨.૫ કરોડથી વધુ લોકોને લાભ મળશે અને છેવાડાના જિલ્લાઓનો વિકાસ થશે તથા આંતરમાળખાકીય સુવિધાઓના લાભ થકી સમગ્ર રાજ્યના વિકાસને વેગ મળશે.
- **ગરવી ગુજરાત હાઈસ્પીડ કોરીડોર** અંતર્ગત રાજ્ય સરકાર દ્વારા ૧૨ કામોને રૂ.૭૨૦૬.૧૮ કરોડના ખર્ચે વિકસાવવા મંજૂરી આપેલ છે. જે કામગીરી પ્રગતિ હેઠળ છે.
- **SER (સુરત આર્થિક ક્ષેત્ર) અંતર્ગત રોડ અને ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરના ડેવલપમેન્ટ** અંગે નવી બાબત તરીકે સમાવેશ કરી વર્ષ ૨૦૨૫-૨૬માં રૂ.૫૦૦ કરોડની જોગવાઈ રાખેલ છે, રૂ.૧૭૪૯.૧૦ કરોડના કામો આયોજન હેઠળ છે.
- રાજ્ય સરકાર દ્વારા રસ્તાઓના નિર્માણ માટે **આબોહવા સ્થિતિસ્થાપક (કલાઈમેટ રેઝીલીયન્ટ) અને નવી ટેકનોલોજી** વાળા ૨૦ કામોની રૂ.૧૧૪૭.૦૮ કરોડની મંજૂરી આપેલ છે.
- રાજ્યમાં ૧૦૦૧ કિ.મી. લંબાઈના રસ્તાઓનું રૂ.૨૩૭૩ કરોડના ખર્ચે ચારમાર્ગીયકરણ / ૧૦ મીટર/ ૭ મી. પહોળા કરવાની કામગીરી પૂર્ણ કરી છે. જ્યારે ૧૪૨૭ કિ.મી. લંબાઈના રસ્તાઓનું રૂ.૫૦૮૩ કરોડની અંદાજીત રકમથી ચારમાર્ગીયકરણ / ૧૦ મીટર / ૭ મીટર પહોળા કરવાની કામગીરી પ્રગતિમાં છે.
- રાજ્યમાં પુલનાં બાંધકામ/નવા પુલો સહિત ૨૮ પુલોની કામગીરી રૂ.૧૫૭ કરોડના ખર્ચે પૂર્ણ થયેલ છે, જ્યારે રૂ.૧૫૯૮ કરોડના ૮૬ પુલોની કામગીરી પ્રગતિમાં છે.
- રાજ્યમાં **મુખ્યમંત્રી ગ્રામ સડક યોજના** હેઠળ વર્ષ ૨૦૧૬-૧૭ થી અત્યાર સુધી રૂ.૪૨૪૭૮ કરોડ ના ૮૬૭૫૭ કિ.મી.ના ૩૬૪૭૪ કામો મંજૂર કરવામાં આવેલ છે. તે પૈકી ૬૬૩૩૦ કિ.મી. ના ૨૭૮૩૦ કામો પૂર્ણ થયેલ છે તથા બાકીના કામો પ્રગતિમાં છે. આ યોજના હેઠળ વર્ષ ૨૦૨૫-૨૬ માં કુલ રૂ.૫૪૦૩ કરોડની જોગવાઈ કરવામાં આવેલ છે.

- **પ્રધાનમંત્રી ગ્રામ સડક યોજના – ૧ અને ૨** હેઠળ મંજૂર થયેલ તમામ કામો પૂર્ણ કરવામાં આવેલ છે. તથા **પ્રધાનમંત્રી ગ્રામ સડક યોજના– ૩** હેઠળ ૩૦૧૨ કિ.મી. લંબાઈને આવરી લેવામાં આવેલ છે. હાલની સ્થિતિએ ૨૮૦૦ કિ.મી. લંબાઈનાં ૨૮૯ રસ્તાના કામો તથા ૪૫ બ્રિજના કામો પૂર્ણ કરવામાં આવેલ છે.
 - સાપુતારાથી સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી ને જોડતા નર્મદા, તાપી અને ડાંગ જિલ્લામાંથી પસાર થતો સાપુતારા-શબરીધામ-સોનગઢ-શેરુલા-ઝરવણી થઈને ગોરાથી સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટીના ૨૩૭ કિ.મી. લંબાઈના પ્રથમ તબક્કામાં નર્મદા, તાપી અને ડાંગ જિલ્લાના ૯૫ કિ.મી. લંબાઈના હયાત રસ્તાઓને ૧૦ મી. પહોળા કરવાની કામગીરી પૂર્ણ થયેલ છે.
 - ઔદ્યોગિક અને ખાણ ખનીજ વિસ્તારોને જોડતા રસ્તાઓની સુધારણા, અપગ્રેડેશન અને મજબૂતીકરણની કામગીરી હાથ ધરી અદ્યતન સવલતો પૂરી પાડવાના અભિગમરૂપે ૨૩૪૩ કિ.મી. લંબાઈના ૨૩૧ કામોને ૩.૭૧૭૮ કરોડની મંજૂરી આપવામાં આવેલ છે. જે પૈકી ૧૨૭૨ કિ.મી. લંબાઈના ૧૩૬ કામો ૩.૨૮૨૦ કરોડના ખર્ચે પૂર્ણ થયેલ છે.
 - ગુજરાત દેશનો સૌથી લાંબો દરિયાકિનારો ધરાવતું રાજ્ય છે. ગુજરાતના દરિયાકિનારે આવેલા બંદરો વ્યુહાત્મક દ્રષ્ટિએ ઘણા મહત્વના હોઈ, જરૂરી માર્ગવ્યવસ્થાનું આંતરમાળખું અદ્યતન કરવા માટે બંદરોને જોડતા ૭૫૭ કિ.મી. લંબાઈના ૪૬ કામો ૩.૧૧૧૮ કરોડના ખર્ચે પૂર્ણ થયેલ છે.
 - ગુજરાતના દરિયા કાંઠે આવેલ હયાત રસ્તાઓનું મજબૂતીકરણ, અપગ્રેડેશન, ખુટતી કડીના રસ્તાઓ અને નાના મોટા પુલોના બાંધકામ સહિત **કોસ્ટલ હાઈવે** વિકસાવવા માટે ૩.૨૪૪૦ કરોડનાં આયોજન અન્વયે પ્રથમ તબક્કામાં કુલ ૨૭૨.૮૦ કિ.મી. લંબાઈના ૨૫ રસ્તાઓના કામોને ૩.૬૯૩.૫૩ કરોડની મંજૂરી મળેલ છે. જે પૈકી ૩.૪૬૯ કરોડના ૨૧ રસ્તાઓની કામગીરી પૂર્ણ થઈ છે તથા ૩.૨૨૪.૫૦ કરોડના ૪ રસ્તાઓના કામો હાથ ધરેલ છે.
 - **સરખેજ-ગાંધીનગર હાઈવે**ને ૩.૯૧૩ કરોડના ખર્ચે છ-માર્ગીય કરવાની કામગીરી પૂર્ણ થયેલ છે તેમજ ઈસ્કોનથી સાણંદ ફ્લાય ઓવરમાં એલીવેટેડ કોરીડોર ૩.૫૩૦ કરોડ, છારોડી પાસે ૬ માર્ગીય ફ્લાયઓવર, સાબરમતી નદી પર ચારમાર્ગીય બ્રીજ ૩.૬૮ કરોડના ખર્ચે તથા અડાલજ ચાર માર્ગીય કેનાલની બાજુમાં નવીન ચારમાર્ગીય કેનાલની કામગીરી ૩.૮૧ કરોડના ખર્ચે પ્રગતિ હેઠળ છે.
 - વાહનવ્યવહારની સલામતી માટે તેમજ સમયની બચત માટે **ફાટકમુક્ત અભિયાન** હેઠળ રાજ્ય સરકાર તથા રેલ્વે મંત્રાલય, ભારત સરકારના ૫૦-૫૦ ટકા ભાગીદારી હેઠળ એક લાખ ટ્રેન વ્હીકલ યુનિટથી વધુ ટ્રાફિક હોય તેવા રેલ્વે કોર્સીંગ પર ઓવરબ્રીજ બાંધવાની કામગીરી અન્વયે વિવિધ યોજના અંતર્ગત ૩.૩૯૩૧ કરોડના ખર્ચે કુલ ૮૨ રેલ્વે ઓવરબ્રીજ પૂર્ણ થયેલ છે.
- વાહન વ્યવહાર** • ફેસલેસ સેવાનું અમલીકરણ થવાથી ડ્રાઈવિંગ લાયસન્સ અને લર્નિંગ લાયસન્સ સંબંધિત સેવાનો ૭.૬૦ લાખ નાગરિકો તેમજ વાહન સંબંધિત સેવાઓનો કુલ ૧૮.૬૭ લાખથી વધુ નાગરિકોએ લાભ લીધેલ છે.

- Registered Vehicle Scrapping Facility (RVSF) મારફતે વાહન સ્કેપ કરવાથી ટ્રાન્સપોર્ટ વાહનના મોટરવાહન ટેક્ષમાં ૧૫% અને નોન-ટ્રાન્સપોર્ટ વાહનના મોટરવાહન ટેક્ષમાં ૨૫% મુજબની રાહત આપવામાં આવે છે. આ યોજના હેઠળ વર્ષ ૨૦૨૫-૨૬માં ૧,૦૯૧ લાભાર્થીઓએ કુલ રૂ.૧.૦૬ કરોડની ટેક્ષ રાહતનો લાભ લીધેલ છે.
- ૮ વર્ષથી વધુ આયુ ધરાવતા કમર્શિયલ વાહનો સરકાર માન્ય સ્કેપીંગ સેન્ટરમાં સ્કેપ કર્યેથી તેઓનો જૂનો ભરપાઈ કરવાનો બાકી ટેક્ષ, પેનલ્ટી, વ્યાજ તથા ચલણના દંડની રકમ માફ કરવા માટે વન ટાઈમ વેવર યોજના તા.૦૧.૦૫.૨૦૨૫ થી એક વર્ષ માટે અમલી કરવામાં આવેલ છે.
- ચાલુ નાણાકીય વર્ષ ૨૦૨૫-૨૬માં નવેમ્બર ૨૦૨૫ માસના અંતે ઓટોમેટેડ ટેસ્ટીંગ સ્ટેશન દ્વારા કુલ ૨,૨૩,૩૨૧ ફિટનેસ સર્ટિફિકેટ ઇસ્યુ કરવામાં આવેલ છે.
- માન. વડાપ્રધાનશ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીની “ગ્રીન ગ્રોથ”ની સંકલ્પનાને સાકાર કરવાના ભાગરૂપે પર્યાવરણની જાળવણી અને સંવર્ધન માટે જે ઇલેક્ટ્રીક વાહનો પર હાલમાં ૬% સુધી ઉચ્ચક(Lumpsum) વાહન વેરો અમલમાં છે, તેવા સંપૂર્ણપણે ઇલેક્ટ્રીક બેટરીથી સંચાલિત વાહનો પર ૧ વર્ષ માટે ૫% સુધી રીબેટ આપી અસરકારક ૧% લેખે વેરાનો દર રાખવાનો પ્રજાલક્ષી અને પર્યાવરણલક્ષી નિર્ણય મારી સરકારે કર્યો છે.
- રાજ્યમાં કાર્યરત NHAI અને રાજ્યના ટોલ પ્લાઝા પરથી પસાર થતા વાહનોના દસ્તાવેજો ઓનલાઈન ચકાસવા માટે NIC દ્વારા “e-detection” એપ્લીકેશન વિકસાવવામાં આવેલ છે. જેમાં નાણાકીય વર્ષ ૨૦૨૫-૨૬માં નવેમ્બર ૨૦૨૫ અંતિત કુલ ૩,૧૩,૮૮૨ ચલણ ઇસ્યુ કરવામાં આવેલ છે.
- આદિજાતિ બોર્ડર વિલેજ યોજના અંતર્ગત નવીન ૧૧૧ મોટી બસો વિદ્યાર્થીઓ માટે સંચાલનમાં મુકેલ છે.
- રાજ્ય સરકારે ગત વર્ષે ૯૬૨ સુપર એક્સપ્રેસ વાહનો, ૧૬૩ ગુર્જરનગરી વાહનો અને ૩૫૦ મીડી બસો મળી કુલ ૧૪૭૫ નવીન અદ્યતન ટેકનોલોજી વાળા વાહનો મુસાફર જનતાની સેવામાં મુકેલ છે.
- ભગવાન બિરસા મુન્ડાજીની ૧૫૦મી જન્મ જયંતિ નિમિત્તે લોકલાડીલા માન.વડાપ્રધાનશ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીના હસ્તે ૧૧૧ નવીન રેડી બિલ્ટ વાહનોનું લોકાર્પણ કરવામાં આવ્યું છે.
- રાજ્ય સરકારે વર્ષ ૨૦૨૫-૨૬ માં કંડક્ટર કક્ષામાં ૨૩૨૦, ડ્રાયવર કક્ષામાં ૩૦૮૪ તથા હેલ્પર કક્ષામાં ૧૬૫૮ ઉમેદવારોને નિમણૂક આપેલ છે.

બંદરો

- વર્ષ ૨૦૨૪-૨૫ માં **ગુજરાત મેરીટાઇમ બોર્ડ** દ્વારા સંચાલિત નોન-મેજર બંદરો દ્વારા કુલ કાર્ગો પરિવહન ૪૮૭.૭૩ મિલિયન મેટ્રિક ટન થયું છે. જે ગત નાણાકીય વર્ષ કરતા ૮.૫૬%નો વધારો દર્શાવે છે. જ્યારે આ જ સમયગાળા દરમિયાન ભારતના કુલ બંદરો પરથી આશરે ૧૫૯૩ મિલિયન મેટ્રિક ટન કાર્ગો પરિવહન થયેલ. જેમાં ગુજરાત રાજ્યના નોન-મેજર બંદરો કુલ રાષ્ટ્રીય પરિવહનના ૩૧% તથા દેશના નોન-મેજર બંદરો પરના પરિવહનમાં આશરે ૬૬% સિંહફાળો દર્શાવે છે.

- ભાવનગર જિલ્લાના **અલંગ-સોસીયા** ખાતે વિશ્વનો સૌથી મોટો **શીપ રીસાયક્લીંગ ચાર્ડ** વિકસાવવામાં આવેલ છે. આ શીપ રીસાયક્લીંગ ચાર્ડ ખાતે હાલમાં ૧૫૦ પ્લોટો આવેલા છે, તે પૈકી ૧૨૮ પ્લોટ કાર્યરત છે. આ ચાર્ડ ખાતે વર્ષ ૧૯૮૩ થી અત્યાર સુધી ૭૧.૦૫ મીલીયન મેટ્રીક ટન એલ.ડી.ટી (લાઇટ ડીસપ્લેસમેન્ટ ટન)ના ૮૯૨૪ જહાજો ભાંગવામાં આવેલ છે. શીપ રીસાયક્લીંગ ઉદ્યોગમાં પ્રવર્તતી મંદીના કારણે સરકારશ્રી દ્વારા શીપ બ્રેકરોને વર્ષ ૨૦૨૧ થી ૨૦૨૫ સુધીમાં પ્લોટ ચાર્જીસમાં કુલ રૂ.૧૪૫ કરોડની છૂટછાટ આપવામાં આવેલ છે

મહેસૂલી વ્યવસ્થાપન

- મારી સરકારે ખેડૂતલક્ષી અભિગમ કેળવીને ખેતીની જમીનના વેચાણ અંગે **ખેડૂત ખરાઈ**ની ચકાસણીમાં અરજદારની અરજીની તારીખથી ૨૫ વર્ષ અગાઉનો રેકર્ડ ધ્યાને લેવાનો રહેશે નહીં તે મુજબનો નીતિવિષયક નિર્ણય લઈને એક ઐતિહાસિક પગલું ભર્યું છે.
- રાજ્યની તમામ મહાનગરપાલિકાઓ તથા વિકાસ સત્તા મંડળો સિવાયના રાજ્યના તમામ વિસ્તારની ખેતી હેતુસરની નવી અને અવિભાજ્ય શરત, પ્રતિબંધિત સત્તા પ્રકાર અથવા નિયંત્રિત સત્તા પ્રકારની તમામ જમીનો જુની શરતની ગણવા એટલે કે આ વિસ્તારમાં **પ્રિમિયમ ભરવામાંથી મુક્તિ** આપવામાં આવેલ છે.
- પ્રજાલક્ષી અભિગમના ઉમદા હેતુથી મારી સરકારે હાઉસીંગ સોસાયટી/ એન.ટી.સી./ એસોસીએશન દ્વારા એલોટમેન્ટ લેટર તેમજ શેર સર્ટીફિકેટથી કરવામાં આવેલ તબદીલીઓ ઉપર સ્ટેમ્પ ડ્યુટી ભરપાઈ કરવા અંગેની **એમ્નેસ્ટી યોજના**માં વસુલવાપાત્ર ખુટતી સ્ટેમ્પ ડ્યુટીની રકમમાં **૮૦ ટકા ઘટાડો** કરીને પ્રજાલક્ષી નિર્ણય કરેલ છે.
- રાજ્યમાં મહિલાઓનો સામાજિક દરજ્જો ઉંચો આવે તે હેતુથી માત્ર મહિલાઓના નામે ખરીદ થતી સ્થાયર મિલકતના દસ્તાવેજોમાં **મિલકત ખરીદનાર મહિલાઓને ૧% નોંધણી ફી માફ** કરવામાં આવે છે. વર્ષ ૨૦૨૨ થી નવેમ્બર ૨૦૨૫ અંતીત નોંધણી થયેલ કુલ ૪.૫ લાખ જેટલા દસ્તાવેજોમા ૯.૭૩ લાખ જેટલી મહિલાઓને રૂપિયા **પંદરસો કરોડ** કરતા વધુની નોંધણી ફી ની માફી આપવામાં આવી છે.
- રાજ્યમાં **સ્વામિત્વ યોજના** અંતર્ગત રાજ્યના ૧૪,૭૦૦ કરતાં વધુ ગામોમાં ડ્રોન દ્વારા મિલકતોની માપણીની કામગીરી પૂર્ણ કરવામાં આવેલ છે. ૯૭૬૨ ગામોમાં પ્રમોલગેશન અને ૧૬ લાખથી વધુ પ્રોપર્ટીકાર્ડ તૈયાર કરવામાં આવેલ છે.
- મહેસૂલી વહીવટમાં પારદર્શિતા વધે, આધુનિક જમીન વહીવટ પ્રણાલી વધુ મજબૂત બને તથા જમીન વિવાદોમાં ઘટાડો થાય તે હેતુસર આધુનિક તકનિકીનું સંયોજન કરવા **સ્પેસ એપ્લીકેશન સેન્ટર (SAC) ઇસરો, અમદાવાદ તથા મહેસૂલ વિભાગ** વચ્ચે MOU કરવામાં આવેલ છે જેના થકી ૩૦ સે.મી. હાઈ રીઝોલ્યુશન ધરાવતી સેટેલાઈટ ઇમેજ પ્રોક્યોર કરીને સરકારી જમીનો પરના દબાણો શોધવામાં તેમજ શરતભંગ શોધવામાં મદદ મળેલ છે.
- રાજ્યમાં **દબાણ હટાવો ઝુંબેશ** સ્વરૂપે કિંમતી સરકારી જમીનો પરના દબાણો દૂર કરવામાં આવેલ છે. જેની વિગતે એપ્રિલ-૨૦૨૫ થી ડિસેમ્બર-૨૦૨૫ સુધીના સમયગાળામાં અંદાજે ૪૧૩૫ હેક્ટર જમીન પરથી કુલ ૧૬૩૬ સર્વે નંબરોના દબાણ દૂર કરેલ છે. જેની જંત્રી આધારિત કિંમત અંદાજે ૩૭૬૫ કરોડ થાય છે.

**કાયદો અને
વ્યવસ્થાપન**

- ભારત સરકારના ગૃહ મંત્રાલયની ગાઈડલાઈન મુજબ રાજ્યવ્યાપી એકીકૃત ડાયલ – ૧૧૨ **ERSS (Emergency Response Support system)** સીસ્ટમ લાગુ કરવામાં આવી છે. જે અંતર્ગત પોલીસ, એમ્બ્યુલન્સ, ફાયર, અભયમ, ચાઈલ્ડ હેલ્પલાઈન, ડીઝાસ્ટર મેનેજમેન્ટ જેવી ઇમરજન્સી સેવાઓ સંકલિત કરવામાં આવેલ છે અને કુલ ૯૬૨ PCR વાહનો કાર્યરત છે. જેનાં ફળ સ્વરૂપે જાન્યુઆરી ૨૦૨૬ ની સ્થિતિએ ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં response time ઘટીને ૧૧ મિનિટ ૫૬ સેકન્ડ અને શહેરી વિસ્તારોમાં અંદાજિત ૦૮ મિનિટ જેટલો થઈ ગયેલ છે.
- રાજ્ય પોલીસ દળમાં કાયમી પોલીસ ભરતી બોર્ડ દ્વારા વર્ષ ૨૦૨૫માં લોકરક્ષક સંવર્ગોની ૧૧,૮૯૯ જેટલી જગ્યાઓ ભરવામાં આવેલ છે.
- સમગ્ર ભારતમાં **સાયબર ક્રાઈમ** અંગેની હેલ્પલાઈન-૧૯૩૦ ની કામગીરીમાં ગુજરાત બીજા ક્રમાંક પર રહેલ છે.
- સાયબર ક્રાઈમનો ભોગ બનેલ અરજદારના બ્લોક/ફ્રિઝ થયેલ નાણાં B.N.S.S. કલમ-503 (Cr.P.C.-૪૫૭) મુજબ નામદાર કોર્ટમાં અરજી કરી અરજદારને પરત અપાવી શકાય છે. નામદાર કોર્ટ દ્વારા આજદિન સુધીમાં ૧,૩૨,૭૬૫ જેટલા અરજદારોને કુલ રૂ.૨૦૨ કરોડથી વધુ નાણાં પરત અપાવવાનો હુકમ કરેલ છે.
- સાયબર ક્રાઈમ અંગે નાગરીકોમાં અખબારો, રેડીયો સ્ટેશનો, ટી.વી.ચેનલો, GSRTC બસ પેનલ પર જાહેરાતો, સોશીયલ મીડીયા જેવા વિવિધ પ્રચાર પ્રસારનાં માધ્યમો દ્વારા જાગરુકતા લાવવામાં આવે છે. તેમજ શાળા-કોલેજોમાં જાગૃતિ સત્ર યોજવામાં આવેલ છે.
- ભારતીય ન્યાય સંહિતા, ૨૦૨૩, ભારતીય નાગરિક સુરક્ષા સંહિતા, ૨૦૨૩ અને ભારતીય સાક્ષ્ય અધિનિયમ, ૨૦૨૩**ના અમલીકરણ માટે પોલીસ, જેલ, પ્રોસીક્યુટર, ફોરેન્સિક તેમજ જ્યુડીશીયલના તમામ અધિકારી-કર્મચારીઓને તાલીમ આપવામાં આવેલ છે.
- એક ભારત શ્રેષ્ઠ ભારતના ભાગરૂપે **શ્રી સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલની ૧૫૦મી જન્મ જયંતી** નિમિત્તે ૩૧ ઓક્ટોબર ૨૦૨૫ના રોજ માન. વડાપ્રધાનશ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીની ઉપસ્થિતિમાં એકત્વની થીમ પર નવી દિલ્હી ખાતે ૨૬મી જાન્યુઆરી અને ૧૫મી ઓગસ્ટના રોજ થતી પેરેડ જેવી પેરેડનું સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી, એકતાનગર ખાતે આયોજન કરવામાં આવેલ. આ પ્રસંગે શ્રી સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલની ચાદમાં રૂપિયા ૧૫૦ના સિક્કાનું અનાવરણ કરવામાં આવેલ હતું.

**નાણા
વ્યવસ્થાપન**

- ગુજરાતે FRBM (ફિસ્કલ રિસ્પોન્સિબિલિટી એન્ડ બજેટ મેનેજમેન્ટ) દ્વારા નિર્ધારિત ૩%ની રાજકોષીય ખાધની મર્યાદાનું ચુસ્તપણે પાલન કર્યું છે અને RBI રિપોર્ટ મુજબ, સાતત્યપૂર્ણ રીતે GSDPના ૨%થી ઓછી રાજકોષીય ખાધ અને મહેસૂલી પુરાંત જાળવી રાખી છે.
- રાજ્યએ દેવા બાબતે પણ ચુસ્ત શિસ્ત જાળવેલું છે, જેમાં વર્ષ ૨૦૨૪-૨૫ માં જાહેર દેવું GSDPના ૧૪.૨૩% રહ્યું છે – જે FRBMની ૨૭.૧%ની મર્યાદા કરતા ઘણું ઓછું છે.

- રાજ્યની પોતાની કરવેરાની આવક ૨૦૨૦-૨૧ થી ૨૦૨૪-૨૫ વચ્ચે લગભગ બમણી થઈ છે. વર્ષ ૨૦૨૪-૨૫ માં જી.એસ.ટી., વેટ, વીજકર અને પ્રોફેશનલ ટેક્સ હેઠળ રૂ.૧.૧૮ લાખ કરોડ મેળવ્યા છે, જે રાજ્યના મહેસૂલી માળખાની સુઢઢતા દર્શાવે છે.
- વર્ષ ૨૦૨૪-૨૫ માં GSTR-3B પત્રકના ૯૯.૬ % ફાઈલિંગ સાથે ગુજરાત સમગ્ર દેશમાં પ્રથમ ક્રમાંક પર છે.
- સને ૨૦૨૫-૨૬માં નવેમ્બર-૨૦૨૫ અંતિત ઈ-વે બિલના વેરીફિકેશનમાં **ગુજરાત રાજ્ય સમગ્ર દેશમાં પ્રથમ ક્રમાંકે** છે.
- હીરા ઉઘોગના નિયત કરાયેલા માઈક્રો એકમોને એક વર્ષ માટે વીજકરમાં છૂટ આપી મુશ્કેલ સમયમાં ઉઘોગ અને શ્રમિકોને રાહત પૂરી પાડવામાં આવેલ છે.
- **ગુજરાત સામુહિક જુથ (જનતા)અકસ્માત વીમા યોજના** હેઠળ કુલ રૂ.૧૨ કરોડથી વઘારે લાભાર્થીઓને આવરી લેવાયેલ છે. વર્ષ ૨૦૨૫-૨૬ થી આ યોજના હેઠળ વીમા સહાય રકમમાં વઘારો કરીને રૂ. ૨ લાખ થી રૂ. ૪ લાખ સુધીની વીમા સહાય આપવાની જોગવાઈ કરવામાં આવેલ છે.

**રમતગમત,
યુવા અને
સાંસ્કૃતિક
પ્રવૃત્તિઓનો**

- **ખેલ મહાકુંભ** દેશનો સૌથી મોટો જન-ભાગીદારી આધારિત રમતગમત આંદોલન બનીને વિકસ્યો છે, જેમાં ચાલુ વર્ષે ૭૨ લાખથી વધુ ખેલાડીઓનું રજીસ્ટ્રેશન થયેલ છે. જેમાં અત્યાર સુધી અંદાજિત ૫૮ લાખ જેટલા ખેલાડીઓએ ભાગ લીધેલ છે.
- **સેન્ટર ઓફ એક્સેલેન્સ કાર્યક્રમ** અંતર્ગત ૧૦ જિલ્લાઓમાં ૧૫ રમતો માટે કુલ ૨૮ એકેડમી કાર્યરત છે, જેમાં અંદાજિત ૧૭૯૦ ખેલાડીઓને નિવાસી તથા બિન-નિવાસી એકેડમી હેઠળ તાલીમ આપવામાં આવે છે. નડિયાદ સ્થિત હાઈ પરફોર્મન્સ સેન્ટરમાં સાત રમતોના ૨૯૦થી વધુ એલિટ ખેલાડીઓને ઉચ્ચ સ્તરની સહાય પૂરી પાડવામાં આવે છે.
- **ગુજરાતને કોમનવેલ્થ વેઈટલિફ્ટિંગ ચેમ્પિયનશિપ ૨૦૨૫**, ૧૧મી એશિયન એક્વેટિક્સ ચેમ્પિયનશિપ ૨૦૨૫ના આયોજનની યજમાની મળેલ છે.
- સરકાર 'યુવા શક્તિ' અને 'સાંસ્કૃતિક વારસા'ના સમન્વય દ્વારા રાજ્યને નવી ઊંચાઈઓ પર લઈ જવા કટિબદ્ધ છે. 'હર ઘર તિરંગા', 'સરદાર@૧૫૦પદયાત્રા' અને રાષ્ટ્રીય દિવસની ઉજવણી દ્વારા રાષ્ટ્રપ્રેમની જ્યોત પ્રજ્વલિત રાખવામાં આવે છે.
- આપણો સાંસ્કૃતિક વારસો એ આપણી ઓળખ છે. મોઢેરાના સૂર્યમંદિર ખાતે યોજાતો 'ઉત્તરાર્ધ ઉત્સવ' હોય કે ગાંધીનગરનો 'વસંતોત્સવ', તેમજ “માઘવપુર ઘેડનો મેળો” આજે ગુજરાત, પશ્ચિમ ભારત અને ઈશાન ભારતની અલગ ઓળખ બની રહ્યો છે, જે 'એક ભારત શ્રેષ્ઠ ભારત'ની સંકલ્પનાને ચરિતાર્થ કરે છે.
- છેલ્લા બે શૈક્ષણિક વર્ષ(વર્ષ ૨૦૨૩-૨૪ અને ૨૦૨૪-૨૫) માં સ્પર્ધિમ ગુજરાત સ્પોર્ટ્સ યુનિવર્સિટીના વિઢાર્થીઓએ West Zone, All India University, Khelo India તથા World University Games (Germany)જેવી સ્પર્ધાઓમાં જુદી જુદી રમતોમા કુલ ૩૫ મેડલ પ્રાપ્ત કર્યા છે, Athleticsમાં All India Gold Medal તથા Women's Volleyball Team દ્વારા West Zone Silver Medal પ્રાપ્ત કરવું રાજ્ય માટે ગૌરવપૂર્ણ સિદ્ધિ છે.

વિજ્ઞાન અને પ્રોઘોગિકી

- SPV મોડેલ અંતર્ગત, રાજ્યએ છેલ્લા ત્રણ વર્ષથી કાર્યરત ગ્રામપંચાયત બાબતે ૧૦૦ % અને નેટવર્ક અપડાઈમ બાબતે ૮૫% સાથે પ્રથમ સ્થાન પ્રાપ્ત કરેલ છે. **ભારતનેટ અંતર્ગત ફેઝ-૨** માં ડિજિટલ સેવા સેતુમાં આવરી લેવાતી ૩૨૧ જેટલી સેવાઓ ૧૦૦ Mbps જેટલા ઝડપી ઈન્ટરનેટ સાથે પહોંચાડવામાં આવી રહી છે. જેનો લાભ ૮૦૦૦ જેટલી સંસ્થાઓને મળે છે.
- વર્ષ ૨૦૨૨-૨૩માં ભારતનેટ ફેઝ-૨ હેઠળનાં ૨૨ જિલ્લાઓના ૭૬૮૫ થી વધુ ગ્રામ પંચાયત કચેરીમાં વાઈ-ફાઈ દ્વારા ઈન્ટરનેટ સેવા પુરી પાડવાનો **“ગ્રામ્ય વાઈ-ફાઈ”** પ્રોજેક્ટ હાથ ધરવામાં આવ્યો હતો. આ ગ્રામ્ય વાઈ-ફાઈ પ્રોજેક્ટ દ્વારા ગામડાનાં નાગરિકો હાલમાં દરરોજ પ્રથમ ૬૦ મિનિટ (એક કલાક) માટે નિઃશુલ્ક ઈન્ટરનેટ સુવિધાનો સીધો જ લાભ મેળવી રહ્યા છે. ત્યારબાદ નજીવા દરે રીચાર્જ કરાવીને ગ્રામ્ય નાગરિકો ઈન્ટરનેટ સેવાનો લાભ લઈ રહ્યા છે.
- ૨૦૦ થી વધુ **ડાયરેક્ટ બેનિફિટ ટ્રાન્સફર (DBT)** યોજનાઓમાં આધાર પ્રમાણીકરણ સેવાઓનો ઉપયોગ થઈ રહ્યો છે. ગત નાણાકીય વર્ષમાં ૫૬ કરોડ થી વધુ આધાર પ્રમાણીકરણ ટ્રાન્ઝેક્શન થયેલ છે.
- **ગુજરાત બાયોટેકનોલોજી રિસર્ચ સેન્ટર** એ ગુજરાત સરકારનું એક અત્યાધુનિક બાયોટેકનોલોજી સંશોધન કેન્દ્ર છે. ગુજરાત રાજ્યએ રાષ્ટ્રીય જૈવ સુરક્ષાનાં મહત્વને ધ્યાને લઈ “નેશનલ સેન્ટર ફોર હાઈ-કન્ટેનમેન્ટ પેથોજન રિસર્ચ ફેસિલીટી” તરીકે રૂ.૩૬૨ કરોડનાં ખર્ચે ભારતની બીજી અત્યાધુનિક બાયોસેફ્ટી લેવલ-૪ (BSL-4) લેબોરેટરી બનાવવાની કામગીરી ચાલુ કરેલ છે. જેના દ્વારા અત્યંત ચેપી વાયરસ જેવા કે કોરોના, ચાંદીપૂરા, CCHF પર દવા અને રસી ના સંશોધનમાં મદદ મળશે.
- ગુજરાતના પશુઓમાં દૂધ ઉત્પાદન ક્ષમતા વધારવા માટે NDDDB, બનાસ, સાબર કેરી તથા GCMMF સાથે મળીને ૪૦૦૦૦ પશુઓનો જીનોટાઈપિંગનો પ્રોગ્રામ ચલાવે છે અને અત્યાર સુધીમાં ૨૮,૦૦૦ થી વધુ પશુઓનું જીનોટાઈપિંગ કરવામાં આવેલ છે. જેના થકી આવનાર દિવસોમાં વધારે દૂધ ઉત્પાદનની ક્ષમતા ધરાવનાર પશુધન ઊભું કરી શકાશે.
- રાજ્યમાં થયેલા ચાંદીપૂરા વાયરસ આઉટ બ્રેકમાં **ગુજરાત બાયોટેકનોલોજી રિસર્ચ સેન્ટર**એ પી.સી.આર. બેઝલ ટેસ્ટ વિકસાવી નિદાનનો સમય ૨૪ કલાકથી પણ ઓછો કરી આજ દિન સુધી ૩૭૮ જેટલા સેમ્પલનું નિદાન પૂરું પાડેલ છે. આ ઉપરાંત ચાંદીપૂરા વાયરસનું જીનોમ સીક્વન્સી કરેલ છે.
- ગીફ્ટ સિટી ખાતે AI સેન્ટર ઓફ એક્સેલન્સને કાર્યરત કરવામાં આવેલ છે. જેમાં જાહેર સેવાઓ માટે ડીપ્લોયેબલ AI સોલ્યુશન્સ માટે AI ઈનોવેશન ચેલેન્જ શરૂ કરવામાં આવેલ છે. AI સેન્ટર ઓફ એક્સેલન્સ ખાતે ૧૮ સ્ટાર્ટ-અપ કાર્યરત છે. આ ઉપરાંત સરકારી ક્ષેત્રના ૧૬ યુઝ કેસો અને ખાનગી ક્ષેત્રના ૧૪ યુઝ કેસો માટે AI ઈનોવેશન ચેલેન્જ લોન્ચ કરવામાં આવેલ છે.
- દેશમાં AI ક્ષમતા તથા બૌદ્ધિક સંપદા(IP)નો વિકાસ કરવા રાજ્ય સરકાર, કેન્દ્ર સરકાર તથા ખાનગી ક્ષેત્રનાં સંયુક્ત સહકારથી રૂ.૩૦૦ કરોડના ખર્ચે દેશમાં સર્વપ્રથમ Indian AI Research Organization (IARIO)ની સ્થાપના કરવામાં આવી છે.

- ગુજરાત ઘોલેરા SIR (ભારતનું પ્રથમ વાણિજ્યિક સેમિકન્ડક્ટર ફેબ) અને સાણંદ (માઈક્રોન, CG સેમી અને કેન્સ સાથે પેકેજિંગ કલસ્ટર) ખાતે marquee પ્રોજેક્ટ્સ દ્વારા વૈશ્વિક સેમિકન્ડક્ટર મૂલ્ય શૃંખલામાં પ્રવેશ કરી રહ્યું છે - જે ઉત્પાદન નેતૃત્વ અને વ્યૂહાત્મક સપ્લાય ચેઇનને મજબૂત બનાવે છે. આ પ્રોજેક્ટ્સમાં રૂ. ૧.૨૪ લાખ કરોડથી વધુનું રોકાણ સામેલ છે અને ૪૫,૦૦૦ થી વધુ પ્રત્યક્ષ અને પરોક્ષ રોજગારીનું સર્જન થવાની અપેક્ષા છે.
- ગુજરાત સ્થાનિક ઉત્પાદન અને અવકાશ-આધારિત એપ્લિકેશનોને ટેકો આપતી સમર્પિત સ્પેસ ટેક નીતિ દ્વારા અવકાશ ક્ષેત્રમાં નેતૃત્વને પણ આગળ ધપાવી રહ્યું છે. જે માટે સાણંદ પાસે ખોરજ GIDCને ખાસ સ્પેસ ટેકનોલોજી માટે વિકસાવવામાં આવી રહેલ છે. આ પાર્કમાં અઝીષ્ટા કંપની દ્વારા દેશના સ્પેસેશી સેટેલાઈટ બનાવવાના પ્લાન્ટની સ્થાપના થઈ રહી છે.

વન અને પર્યાવરણ

- **સામાજિક વનીકરણ માધ્યમથી** સમગ્ર રાજ્યમાં વર્ષ ૨૦૨૫-૨૬ માં **“એક પેડ માં કે નામ 2.0”** અભિયાન હેઠળ ૧૦.૫૯ કરોડ રોપાઓનું વાવેતર કરવામાં આવેલ છે.
- તા.૦૫ મી જુન, ૨૦૨૫ વિશ્વ પર્યાવરણ દિવસે રાજ્યમાં કુલ ૩૩૧ કાર્યક્રમમાં ૬૭,૦૦૦ કરતાં વધારે રોપાઓનું વાવેતર કરેલ તેમજ **૬૮ સિંદુર વન** બનાવવામાં આવેલ છે.
- રાજ્યમાં ૪-રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાન, ૨૪ અભયારણ્ય અને ૧ કન્ઝર્વેશન રીઝર્વ વિસ્તાર મળી કુલ ૨૯ રક્ષિત વિસ્તારો આવેલા છે. ગુજરાત વન્યપ્રાણી સંરક્ષણ અને સંવર્ધન ક્ષેત્રે મોખરાનું સ્થાન ધરાવે છે.
- માર્ચ-૨૦૨૫માં માનનીય પ્રધાનમંત્રીશ્રી નરેન્દ્ર મોદીજીની અધ્યક્ષતામાં રાષ્ટ્રીય વન્યજીવ બોર્ડની ૭ મી બેઠક સાસણ ખાતે યોજવામાં આવેલ. જેમાં પ્રધાનમંત્રીજી દ્વારા રાજ્યમાં એશિયાઈ સિંહના સંરક્ષણ અને સંવર્ધનના પ્રયાસોની સરાહના કરવામાં આવેલ તેમજ આ બાબતે બૃહદ ગીર વિસ્તારમાં જોવા મળતી લોકભાગીદારી, સહઅસ્તિત્વ અને માનવ વન્યજીવ સહિષ્ણુતાની ભાવના જેવી બાબતોનું દેશના અન્ય વિસ્તારોમાં પણ અનુકરણ કરવા દિશાસૂચન કરવામાં આવેલ છે.
- **૧૬મી સિંહ** વસ્તી અંદાજની કામગીરી ૧૦મે થી ૧૩મે દરમિયાન કુલ ૩૫,૦૦૦ ચો.કિ.મી. વિસ્તારમાં હાથ ધરવામાં આવેલ જેમાં ૧૧ જિલ્લાના ૫૮ તાલુકાનો સમાવેશ કરવામાં આવેલ. સિંહ વસ્તીનાં અંદાજ મુજબ કુલ-૮૯૧ સિંહોની સંખ્યા નોંધાયેલ છે. વર્ષ ૨૦૨૦ ની સરખામણીએ વર્ષ ૨૦૨૫ માં સિંહ વસ્તીમાં **૩૨.૨૦ ટકાનો વધારો** થયેલ છે.
- ચિત્તાની વસ્તી સ્થાપિત કરવા ભારત સરકારશ્રી અને રાજ્ય સરકારશ્રીના દીર્ઘ દ્રષ્ટિકોણથી કચ્છ જિલ્લાના બત્રી ગ્રાસલેન્ડ ખાતે અંદાજીત ૬૦૦ હેક્ટર વિસ્તારમાં ચિત્તા બ્રિડિંગ સેન્ટરની સ્થાપના કરેલી છે.
- ગત વર્ષથી રાજ્યના રતનમહાલ અભયારણ્યમાં આશરે ત્રીસ વર્ષ બાદ એક વાઘનું પણ આગમન થયેલ છે અને તે આ વિસ્તારમાં સ્થાયી થયેલ છે.

- હું રાજ્ય સરકારને જળપ્લાવિત વિસ્તારો માટે ઉદ્દેશનીય કામગીરી કરવા બદલ અભિનંદન પાઠવું છું. રાજ્યમાં અત્યાર સુધીમાં ચાર જળપ્લાવિત વિસ્તારો: નળ સરોવર પક્ષી અભયારણ્ય, થોળ પક્ષી અભયારણ્ય, ખીજડીયા પક્ષી અભયારણ્ય, વઢવાણા પક્ષી અભયારણ્ય ને રામસર સાઈટ્સ તરીકે જાહેર કરવામાં આવેલ હતા. તા.૩૦/૦૧/૨૦૨૬ ના રોજ ગુજરાતના વધુ એક વિસ્તાર: કચ્છમાં આવેલ છારી-ઢંઢ પક્ષી અભયારણ્યને પણ રામસર સાઈટ તરીકે જાહેર કરવામાં આવેલ છે જે ગુજરાત રાજ્ય માટે ગર્વની બાબત છે. જે રાજ્યની પાંચમી રામસર સાઈટ બનેલ છે.
- ઉદ્યોગોની ચીમનીઓમાંથી નીકળતા રજકણો (પાર્ટિક્યુલેટ મેટર)થી થતા હવા પ્રદૂષણના નિયંત્રણ માટે મારી સરકારે ETS-PM(Emission Trading Scheme Particulate Matter) યોજનાને સુરત અને અમદાવાદ ખાતે **પાયલોટ પ્રોજેક્ટ** તરીકે અમલમાં મુકી છે. જે અંતર્ગત પાર્ટિક્યુલેટ મેટર (PM) નું વધુ ઉત્સર્જન કરનાર ઉદ્યોગ દ્વારા નાણાં ચૂકવી ઓછું ઉત્સર્જન કરનાર ઉદ્યોગ પાસેથી પરમીટ ખરીદવી પડે છે જ્યારે ઓછું ઉત્સર્જન કરનાર ઉદ્યોગને પરમીટ વેચવાથી નાણાંકીય ફાયદો થાય છે જેના કારણે ઉદ્યોગો પ્રદૂષણ ઘટાડવા માટે પ્રેરાય છે. આ સ્કીમની 'Clean Our Air' કેટેગરી હેઠળ તા. ૦૫મી નવેમ્બર, ૨૦૨૫ ના રોજ રીયો-ડી-જાનેરો, બ્રાઝીલ ખાતે યોજાયેલ Earth shot Award - 2025 માટે ફાયનલીસ્ટ તરીકે પસંદગી પામેલ.

વહીવટી સુધારણા અને આયોજન

- સ્પીપાના સેન્ટર ફોર ગવર્નન્સ દ્વારા શ્રી અટલબિહારી વાજપેયીજીની ૧૦૦ મી જન્મજયંતિ ઉજવણી નિમિત્તે અટલ વ્યાખ્યાનમાળા (લેક્ચર સીરીઝ)નું આયોજન કરવામાં આવેલ હતું.
- ગુજરાત (જાહેર સેવાઓ અંગેનો નાગરિકોનો અધિકાર) અધિનિયમ, ૨૦૧૩ પૂર્ણ રીતે અમલમાં આવતાં આ કાયદા અંતર્ગત ગુજરાત સરકારના કુલ-૨૦ વિભાગોની કુલ ૪૪૮ જેટલી નાગરિકોને સીધી સ્પર્શતી સેવાઓને કાયદા હેઠળ આવરી લેવામાં આવેલ છે.
- નાગરિકોના પ્રશ્નોના નિરાકરણ માટે ભારત સરકારના વહીવટી સુધારણા અને લોક ફરિયાદ વિભાગ દ્વારા ઓનલાઈન ફરિયાદ નોંધાવી શકાય તે માટે PG Portal સોફ્ટવેર દ્વારા નાગરિકોની ૩,૪૮,૫૩૮ જેટલી ફરિયાદોનો નિકાલ થયેલ છે.
- ભારતના અન્ય રાજ્યોમાં વસતા ગુજરાતીઓ ઉપરાંત ભારત બહાર વિદેશમાં વસતાં, ૧૮ થી ૪૦ વર્ષના મૂળ ગુજરાતના વતની હોય તેવા બિન-નિવાસી ગુજરાતીઓની યુવા પેઢી ગુજરાતની મુલાકાત લેતી થાય, પોતાના વતનની સુવાસને જાણે, માણે અને સમજે તે માટે સુધારેલ ગુજરાત પરિભ્રમણ યોજના નાણાકીય વર્ષ ૨૦૨૫-૨૬થી અમલમાં મુકવામાં આવેલ છે. આ યોજનામાં ગુજરાતમાં સતત ૧૦ દિવસના કાર્યક્રમમાં પરિવહન(ટ્રાન્સપોર્ટેશન), રહેવા -જમવાની તથા સ્થળ મુલાકાત અંગેની સુવિધા પુરી પાડવામાં આવે છે.
- મારી સરકાર દ્વારા રચાયેલ **ગુજરાત વહીવટી સુધારણા પંચ (GARC)** દ્વારા અત્યાર સુધીમાં કુલ છ અહેવાલો રજૂ કરવામાં આવ્યા છે, જેમાં વહીવટી પ્રક્રિયાઓમાં સુધારા, માનવ સંસાધન વ્યવસ્થાપન — ખાસ કરીને ભરતી અને પસંદગી પ્રક્રિયામાં પારદર્શિતા,

ટેક્નોલોજી આધારિત શાસન, નાગરિક-કેન્દ્રિત સેવા વિતરણ તેમજ જવાબદારી અને પારદર્શિતાને મજબૂત બનાવતી અનેક વ્યવહાર અને અસરકારક ભલામણો સમાવિષ્ટ છે. સરકારે આ ભલામણોને મોટા પાયે સ્વીકારી છે, અને તેમાંથી ઘણી ભલામણો આજે અમલીકરણના વિવિધ તબક્કામાં છે, જે ગુજરાતમાં સુશાસન અને કાર્યક્ષમ વહીવટની દિશામાં એક મહત્વપૂર્ણ અને દ્રઢ પગલું સાબિત થઈ રહી છે.

- મારી સરકારે આધુનિક માનવસંસાધન વ્યવસ્થાપન પદ્ધતિ(Human Resource Management System) અપનાવતા તમામ સરકારી અધિકારીઓ/કર્મચારીઓની સેવાપોથી તથા સેવાકીય અને નાણાકીય બાબતોને ઈન્ફોર્મેશન એન્ડ કમ્યુનિકેશન ટેક્નોલોજી(ICT) આધારિત “કર્મચોગી પોર્ટલ” અને “કર્મચોગી મોબાઇલ એપ્લિકેશન” પર ઉપલબ્ધ કરાવી છે.
- **વિકસિત ભારત @2047** ના રાષ્ટ્રીય વિઝનને કાર્યક્ષમ વ્યૂહરચનામાં રૂપાંતરિત કરવાના હેતુથી મારી સરકારે લાંબા ગાળાના વિકાસ એજન્ડાને ટેકો આપવા માટે વ્યૂહાત્મક અને પુરાવા-આધારિત ઈનપુટ્સ પ્રદાન કરવા સપ્ટેમ્બર-૨૦૨૪ માં ગુજરાત રાજ્ય ઈન્સ્ટિટ્યુશન ફોર ટ્રાન્સફોર્મેશન (GRIT) ની સ્થાપના કરી છે. GRIT ને રાજ્યના વિકાસ થિંક ટેન્ક તરીકે સ્થાન આપવામાં આવ્યું છે.
- નીતિ આયોગ દ્વારા વિકસાવવામાં આવેલ સુરત આર્થિક માસ્ટર પ્લાનને આધારે GRIT એ રાજ્યના વધુ પાંચ મુખ્ય આર્થિક ક્ષેત્રો માટે આર્થિક માસ્ટર પ્લાન તૈયાર કર્યા છે. જે વર્ષ ૨૦૪૭ સુધીમાં ગુજરાત માટે USD 4 ટ્રિલિયનથી વધુની અર્થવ્યવસ્થા અને ૨૮ મિલિયનથી વધુ નવી રોજગારીનું સર્જન કરવાનો ધ્યેય રાખે છે. આ આર્થિક માસ્ટર પ્લાન લગભગ ૨૦ પ્રાથમિકતા ધરાવતાં ક્ષેત્રો અને ૨૮ મેગા પ્રોજેક્ટ્સ દ્વારા સંચાલિત ઝડપી અને ટકાઉ વિકાસ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરે છે, જેમાં લગભગ રૂ. ૬૦ ટ્રિલિયનની કુલ રોકાણ ક્ષમતા છે.
- નીતિ આયોગ દ્વારા આકાંક્ષિત બ્લોક કાર્યક્રમ (ABP) અંતર્ગત ઝોન ૪ (પશ્ચિમ ઝોન) અંતર્ગત રેન્કીંગમાં સપ્ટેમ્બર-૨૦૨૫ અંતિત નર્મદા જિલ્લાનો નાંદોદ તાલુકો, તેમજ ડિસેમ્બર – ૨૦૨૪ અંતિત ડાંગ જિલ્લાનો સુબીર તાલુકો અગ્રેસર રહેલ છે. આ બન્ને તાલુકાને નીતિ આયોગ દ્વારા એવોર્ડ પેટે એક કરોડ રૂપિયાની રકમ જાહેર કરેલ છે

માહિતી અને પ્રસારણ

- રાજ્ય સરકારની લોકકલ્યાણકારી અને લાભદાયી યોજનાઓ અને કાર્યક્રમોની માહિતી સામાન્ય નાગરિક તથા લાભાર્થીઓ સુધી પહોંચાડવાની જવાબદારી અસરકારક રીતે નિભાવવામાં આવી રહી છે.
- રાજ્યની દરેક જિલ્લા કલેક્ટર કચેરી, જિલ્લા વિકાસ અધિકારીની કચેરી અને મહાનગરપાલિકાની કચેરીમાં ડિજિટલ ડિસ્પ્લે કમ એક્ઝિબિશન મૂકી રાજ્ય સરકારની યોજનાઓને ડિજિટલ સ્વરૂપે કચેરીના સમય દરમિયાન રજૂ કરવામાં આવે છે. જેનાથી સામાન્ય નાગરિક પોતાને મળતા લાભો અથવા યોજનાની વિગતો મેળવી શકે છે.

ન્યાયતંત્ર

- સુદૃઢ ન્યાયતંત્ર એ લોકશાહીનો મજબૂત સ્તંભ છે. કાલોલ(પંચમહાલ), પ્રાંતિજ(સાબરકાંઠા), સાણંદ(અમદાવાદ) તથા ઉચ્છલ(તાપી-વ્યારા) ખાતે નવનિર્મિત તાલુકા કક્ષાની કોર્ટ બિલ્ડિંગના લોકાર્પણ કરવામાં આવેલ છે.
- મોરબી ખાતે રૂ.૨ કરોડ ૪૮ લાખના ખર્ચે બનેલ નવનિર્મિત ચેરીટી ભવનનું લોકાર્પણ કરવામાં આવેલ છે.
- સરકારશ્રીના મહત્વના IILMS Project અંતર્ગત રાજ્ય સરકાર પક્ષકાર હોય તેવા કોર્ટ કેસોનું મેપિંગ કરવામાં આવેલ છે. આ પોર્ટલ દ્વારા કેસને સંબંધિત નામ, કોર્ટમાં થયેલ કાર્યવાહીની વિભાગના સંબંધિત અધિકારીઓને સમયસર જાણ થાય છે જેથી રાજ્ય સરકાર દ્વારા સમયસર અસરકારક કાર્યવાહી કરીને નામ. કોર્ટ સમક્ષ પોતાનો પક્ષ રજૂ કરવામાં સરળતા રહે છે.

કલાયમેટ ચેન્જ

- વિશ્વ પર્યાવરણ દિવસ, ૫ મી જુનના રોજ **ગુજરાત કલાયમેટ એક્શન ટ્રેકર (GCAT) પોર્ટલ** લોન્ચ કરેલ છે. જે દેશમાં કોઈપણ રાજ્ય દ્વારા કલાયમેટ સૂચકાંકો સંબંધિત માહિતી જિલ્લા સ્તરે પ્રદર્શિત કરતું પ્રથમ ડિજિટલ પ્લેટફોર્મ છે.
- **સરકારી ઇમારતો ઉપર સોલાર સિસ્ટમ લગાવવાની યોજના** અંતર્ગત ૧૦૦% સંપૂર્ણ સરકારી સહાય સાથે વર્ષ ૨૦૨૫-૨૬ માં જાન્યુઆરી-૨૦૨૬ અંતિત ૬૦૭ સરકારી ઇમારતો પર અંદાજિત રૂ.૬૦ કરોડના ખર્ચે ૭.૭૫ મેગાવૉટ સોલાર ફોટોવોલ્ટેક રૂફટોપ સિસ્ટમની સ્થાપના કરવામાં આવેલ છે. તેમજ અત્યાર સુધીમાં કુલ-૫૨૪૪ સરકારી ઇમારતો પર અંદાજિત રૂ.૪૦૬ કરોડનાં ખર્ચે ૮૫.૭૩ મેગાવૉટ સોલાર ફોટોવોલ્ટેક રૂફટોપ સિસ્ટમની સ્થાપના કરવામાં આવેલ છે.
- બેટરી સંચાલિત ડ્વિચક્રી વાહન માટે સબસિડી (સહાય) યોજના અંતર્ગત શાળાઓમાં ધોરણ-૧૧ થી ૧૨ તથા કોલેજમાં અભ્યાસ કરતાં વિદ્યાર્થીઓને બેટરી સંચાલિત ડ્વિચક્રી વાહન માટે વર્ષ ૨૦૨૫-૨૬ માં જાન્યુઆરી-૨૦૨૬ અંતિત DBT મારફતે ૧૭૬૪ વિદ્યાર્થીઓને રૂ.૨.૬૬ કરોડની સબસિડી (સહાય) આપવામાં આવેલ છે. તેમજ અત્યાર સુધી DBT મારફતે કુલ ૫૫,૫૧૪ વિદ્યાર્થીઓને રૂ.૬૨.૭૧ કરોડની સબસિડી (સહાય) આપવામાં આવેલ છે.

પંદરમી ગુજરાત વિધાનસભાના આ સન્માનીય ગૃહને સંબોધવાનો મને અવસર મળ્યો છે ત્યારે મને જણાવતા આનંદ થાય છે કે, ગુજરાત શક્તિશાળી, સમૃદ્ધ અને સુરક્ષિત એવું ભારતનું આદર્શ રાજ્ય છે. ગુજરાતનો સર્વત્રાહી વિકાસ સૂરજની જેમ ઝળહળી રહ્યો છે ત્યારે લોકલાડીલા અને યશસ્વી વડાપ્રધાનશ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીના નેતૃત્વમાં આપણે ગુજરાતની વિકાસયાત્રા હજુ ખૂબ આગળ લઈ જવાની છે. આત્મનિર્ભર અને વિકસિત ગુજરાતના નિર્માણથી આત્મનિર્ભર અને વિકસિત ભારતના નિર્માણમાં યોગદાન આપવાનું છે. ગુજરાત દેશનું ગ્રોથ એન્જિન છે અને તેને વધુ મજબૂત બનાવવાની આપણા સૌની જવાબદારી છે.

પ્રત્યેક ગુજરાતી વિશ્વમાં ગુજરાતી હોવાનું ગૌરવ લઈ શકે અને ગુજરાત વિશે સ્વાભિમાન ધરાવી શકે તેવા ગુજરાતનું જતન કરવાની જવાબદારી જનતાએ આપ સૌને સોંપી છે. આપ સૌ આપના જાહેર જીવનના અનુભવો અને પ્રજાની અપેક્ષાઓ નજર સમક્ષ રાખીને આ સભાગૃહમાં જનતાના પ્રતિનિધિ તરીકે આપનું શ્રેષ્ઠતમ યોગદાન આપશો તેવી અભિલાષા રાખું છું. જનતાના આ આશીર્વાદ જનસેવા માટે આપ સૌને અપ્રતિમ બળ આપશે એવી મને શ્રદ્ધા છે.

ભારત માતા કી જય

જય જય ગરવી ગુજરાત



सत्यमेव जयते

Government of Gujarat

Address
by
Shri Acharya Devvrat
Governor of Gujarat
to the
Gujarat Legislative Assembly

Gandhinagar

Monday, 16th February, 2026

Hon'ble Speaker and Hon'ble Members of the Legislative Assembly,

I wholeheartedly welcome you all on the auspicious beginning of the Eighth session of the Fifteenth Gujarat Legislative Assembly. I am delighted and proud to have the auspicious opportunity to address the Legislative Assembly of the State of Gujarat- the birthplace of Mahatma Gandhiji, who showed to the world path of truth and non-violence; Sardar Vallabhbhai Patel, who united the country; the great son of Gujarat the Rishi-like silent worker Pujiyashree Ravi Shankar Maharaj; the founder of Arya Samaj Swami Dayanand Saraswati and the flag bearer of Gujarat's pride, Shri Indulal Yagnik. To make the mantra of "Viksit Gujarat to Viksit Bharat" a reality and to ensure all-inclusive, all-affecting and all-round development of the people of Gujarat, many historic and citizen-oriented decisions have been taken in this Legislative Assembly.

Whenever 'Kem Chho?' is uttered in any corner of the country, the reply received is 'Majama'. This respect for Gujarat is a reflection of Gujarat's progressive thinking and the popular leadership of Prime Minister Shri Narendrabhai Modi, who has made development a national movement. The definition of development for Gujarat is such development that has the spirit of "**Sarvajan Hitaya, Sarvajan Sukhaya**". This development journey of Gujarat is such...

Where the dreams of **Yuvashakti** get new '**wings**', where the sweat of farmers gets due '**respect**'.

Where we '**protect**' the dignity of **Narishakti**, and '**think**' for the welfare of the **poor**.

On one hand, there is an open '**door**' of progress for **industries** and on the other hand,

Complete '**care**' is taken for the **health** of the people.

The people of Gujarat have been witnesses to such all-encompassing and comprehensive development.

It has been **a thousand year** since the attack on the Somnath Temple, the sacred place of Sanatan Sanskruti. Somnath Temple is not just a Shiva temple, but a victory tale of our '**Identity**' and '**existence**' imprinted on the forehead of time. History is a witness that this sacred place was attacked and attempts were made to destroy it but even after a thousand years of attack, the flag of our Sanskruti is fluttering with the same pride and glory. Therefore, this year is not an ordinary year but it is a historical occasion to turn the '**struggle**' of history into '**self-respect**'. We had organized '**Somnath Swabhiman Parva**' so that my **young generation** of today which is the India of tomorrow, may keep patriotism and the pride of our

glorious heritage in their mind. From January 9th to 15th, at the threshold of Lord Somnath, we all came together to worship culture in the inspiring presence of our renowned Prime Minister Shri Narendrabhai Modiji. This celebration is not just a festival, but a beautiful opportunity to restore the pride of the nation.

This year is a historic year of celebrating the 150th birth anniversary of the architect of the unity and integrity of the country, the Iron Man, Sardar Vallabhbhai Patel and Bhagwan Birsa Mundaji. This is a sacred occasion to highlight the pride of the nation. This year is also becoming a source of inspiration for the global promotion of the national anthem Vande Mataram and the national ideology of Sardar Saheb. On the occasion of the birth anniversary of the architect of united India, Iron Man Sardar Vallabhbhai Patel, Unity March Sardar@150 was organized from Karamsad to Kevadiya. When the flame of patriotism, which shone from the sacred land of Karamsad, reached the feet of the world's largest statue 'Statue of Unity' to pay homage, a golden page was added to the history of Gujarat. This 'Sardar@150' Padyatra was not an ordinary journey, but an unforgettable 'Ekta yatra' that tied the 'people' and 'minds' of Indians with an invisible thread of unity.

To commemorate **the 150th birth anniversary of Dharti Aaba Lord Birsa Mundaji** and to honour the valour and invaluable contribution of tribal heroes, the year 2025 has been celebrated as the Janjatiya Gaurav Varsh across the country, thus honouring Lord Birsa Mundaji in the true sense. As part of this celebration, a grand and divine celebration of the National Level Janjatiya Gaurav Divas was held at Dediapada in Narmada district in the presence of Shri Narendrabhai Modiji, which truly is a matter of pride for Gujarat. To communicate the contribution of Lord Birsa Mundaji and the tribal community to the people, the Janjatiya Gaurav Rath Yatra was successfully organized in the State from 7th to 13th November, 2025. In order to fulfill the mantra of '*Sauno Saath, Sauno Vikas*' and with the spirit of 'no one should be left behind in development and no one should be deprived of development', the Government has paved the way for the upliftment of tribals. With the inspiration of the Prime Minister, Gujarat is also the first State in the country to start the genome sequencing project to further ensure health and well-being of tribal communities. Gujarat has earned the honour of being awarded as the best performing State in the country in allocating houses to Particularly Vulnerable Tribal Groups under Pradhan Mantri Awas Yojana-Gramin.

The inspiring presence of the Hon'ble Prime Minister and the Hon'ble Chancellor of Germany at **the International Kite Festival 2026** organized in Ahmedabad has given a new identity to the State's festival globally. In which, along with kite flying, the grand heritage of the State was presented through a grand symphony, floating art kite museum and an exhibition of *Pol culture*.

As a part of My Government's continuous effort for **simple, easy but firm and people-oriented administration**, '**Sushasan Divas**' is celebrated grandly on the birth anniversary of former Prime Minister Shri Atal Bihari Vajpayeeji. The Government is effectively implementing schemes, services and development works and grievance redressal to increase the 'Ease of Living' of the State citizens. Under the guidance of the renowned Chief Minister of the State Shri Bhupendrabhai Patel, important parameters of different types of operations of various departments have been brought on a single integrated platform on the CM Dashboard. The CM Dashboard has prepared a comprehensive **Governance Performance Index (GPI)** by taking forward that promising tradition of good governance.

As **the Commonwealth Games** is completing 100 years, it is a proud moment for all of us that we have got an opportunity to host **the Commonwealth Games** as a result of 24 years constant efforts towards building sports ecosystem by the then Chief Minister of the State and the current renowned Prime Minister of the nation, Shri Narendrabhai Modiji. Through the Commonwealth Games, Gujarat is ready and committed to welcome the world to India and make the State a sports hub.

My Government has always stood by the people of Gujarat during natural calamities. The Chief Minister, showing a sympathetic approach, has announced a relief package of more than **Eleven thousand crores** to help farmers recover from the losses caused by the floods and unseasonal rains in the State. This historic package is not just an aid, but an '**honour**' of the hard work of the sons of the soil and a '**Mission**' to revive the agricultural economy. The relief package announced by the State Government is not just a policy measure, it is a reflection of a sentiment that 'the State Government is with the farmers.' These steps will serve as a strong platform towards recognizing the hard work of the farmers and boosting an agriculture-based economy in the State.

Under the leadership of Chief Minister Shri Bhupendrabhai Patel, as a strong initiative on the development path of a modern Gujarat, "**Vibrant Gujarat Regional Conference**" is being organized in four zones of the State. Out of these, Vibrant Gujarat Regional Conference in Mehsana and Rajkot have been held. Organized with the theme of 'Regional Aspirations, Global Ambitions' and the spirit of 'Har Ghar Swadeshi, Ghar Ghar Swadeshi', these Regional Conferences are becoming not just a program, but a strategic platform to realize the vision of 'Atmanirbhar Gujarat to Atmanirbhar Bharat'. This innovative initiative of Vibrant Gujarat Regional Conference will become an important platform for the State industries to guide the Prime Minister's vision of Viksit Bharat@2047 to become Atmanirbhar Bharat and Vocal for Local and Local for Global.

Gujarat has initiated the **I-ORA portal** for transparent and reliable administration to make the complex Revenue processes, people-oriented and simple. As a result, more than 35 services related to land records are available end-to-end online. In addition, the facility of digital platforms like GARVI-2.0 to deliver Index-2(two) and land related documents to the citizens at home is also commendable.

Gujarat has the longest coastline in the country. Under the leadership of Chief Minister Shri Bhupendrabhai Patel, the Government has taken an important step towards modern infrastructure development of ports in Gujarat to realize the vision of '**Samudra se Samriddhi**'. Accordingly, a Memorandum of Understanding (MoU) has been signed between Gujarat Maritime Board and Gujarat Pipavav Port Limited (APM Terminals) for a capital investment of Seventeen Thousand crores. Gujarat's established identity as the 'Maritime Gateway' of India will be further strengthened due to expansion of Pipavav Ports through this MoU.

With a noble and people-centric approach aimed at administrative decentralisation and enhancing ease of access to district and taluka-level offices, my Government has undertaken significant reforms. In the spirit of ensuring greater convenience in public dealings, improving access to social, economic, health, and educational services through the establishment of nearby taluka headquarters, and reduce the time, effort, and financial burden for citizens travelling from remote villages, a new Vav–Tharad district has been carved out from Banaskantha, along with the creation of 17 new talukas.

With the theme "**Yoga for One Earth One Health**" and "*Swasth Gujarat Medasvita Mukh Gujarat*", the 11th International Yoga Day was celebrated at the historic Sharmistha Lake precinct in Vadnagar, the birthplace of Prime Minister Shri Narendrabhai Modiji, in the presence of Chief Minister Bhupendrabhai Patel. On this occasion, 2121 yoga practitioners registered a new record by performing Bhujangasana together and secured a place in the Guinness Book of World Records.

In order to provide an opportunity to the youth to serve the people, the youth whom Hon'ble Prime Minister Shri Narendrabhai Modiji has called the "demographic dividend", more than 30,000 candidates have been awarded appointment letters by My Government in the last year. This young generation getting opportunity to serve the people, is determined to serve the people with honesty and dedication and innovative approach, striving to scale ever-greater heights of progress. In order to ensure that this process continues uninterruptedly and regularly, the State Government has prepared a **10-year recruitment calendar** for manpower planning under which, the State Government has planned to fill **more than two lakh** posts in phased manner during the period from 2024 to 2033.

The Government is also compassionate towards Government employees serving the people with honesty and devotion. My Government has taken an important decision for taking care of the health of All India Service officers, State Government officers and employees, pensioners serving in Gujarat and their families. Under Ayushman Bharat Yojana, '**Gujarat Karmayogi Swasthya Suraksha Yojana (G-Category)**' has been launched. Under this all Government officers-employees and their families will avail the benefit of cashless medical treatment up to Rs.10 lakh which will improve their health and well-being too.

My Government, headed by the Chief Minister Shri Bhupendrabhai Patel, is committed to soar Gujarat to new heights with renewed confidence on the development path of Gujarat carved by India's beloved Prime Minister Shri Narendrabhai Modiji. Under my Government's sensible and steadfast leadership, transparent and progressive decisions are leading to rapid development in the key sectors including social welfare, economic growth, education, health and infrastructure.

**Agriculture
and
Farmer
Welfare**

Natural Farming

Natural Farming is a blessing for the soil, environment and health of mankind. Hon'ble Prime Minister Shri Narendrabhai Modiji has considered Natural Farming as the closest to his heart and has dreamt that every farmer of this country should adopt natural farming. To realize this dream, a well-planned campaign is being carried out by the Government under the guidance of Hon'ble Chief Minister Shri Bhupendrabhai Patel to increase the scope of natural farming in the State.

- To increase the scope of Natural Farming in the State, Gujarat Prakrutik Krushi Vikas Board and the world's first Natural Farming Science University have been established in which training, inspirational tours, research, mega camps, seminars, exhibitions are organized on Natural Farming.
- So far, about 19 lakh farmers have been trained in Natural Farming.
- This year, more than one lakh farmers practicing Natural Farming have been given assistance of Rs.58.77 crore for maintaining indigenous cows.
- So far, about 7100 **model farms** have been built in the State so that farmers can get first-hand knowledge of Natural Farming.

- More than 8 lakh farmers have adopted natural farming in the State.
- Dang district of the State has been declared a district practicing completely “**chemical-free farming**”. About 10,000 farmers of the district have been covered under Natural Farming and more than Rs.25 crore have been given assistance to them.
- This time, the monsoon rains turned into tears for the farmers. In this difficult time of excessive rains, this Government has stood as a steadfast ally of the farmers. My Government has announced a huge agricultural relief package this year to help farmers against unseasonal rains. So far, **more than 33 lakh farmers have been given Rs.9610 crores of assistance** which has been deposited in affected farmers’ bank accounts. The Government started the calculation and payment of the losses incurred by the farmers on an immediate basis and completed it within the stipulated time. This is a first example in the history of Gujarat that such a large amount of assistance has reached the accounts of the farmers directly in such a short time. This shows that if the intention is strong, even disasters can be overcome. This work shows the sensitivity and commitment of my Government towards the farmers.
- In the year 2025-26, in the State, in the Kharif season, **more than 18.24 lakh metric tons of agricultural produce like groundnut, moong, urad and soybean have been purchased from more than 8.32 lakh farmers worth Rs.13,100 crores at the Minimum Support Price.** The speedy purchase of groundnut, moong, urad and soybean at Minimum Support Prices with the support of the Government of India and the payment of assistance due to unseasonal rains has proved the welfare approach of the “**double engine**” Government.
- Under the **Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi Yojana**, assistance of about **Rs.22 thousand crores** has been **directly deposited in the bank accounts of more than 69 lakh farmer families** in the State in one to twenty-one installments till date.

- In the current year 2025-26, a budget provision of more than Rs.1400 crores has been made to cover a larger number of beneficiaries **for the purchase of tractors and tractor-powered farm tools/equipments**. Assistance for tractor purchase has been increased to **Rs.1 lakh** from the year 2025-26.
- For the purpose of real-time monitoring of crop condition, weather-related risks and diseases and pests in all districts and talukas from the State level and for the farmers to get timely and appropriate guidance regarding the same, the “**Krishi Pragati**” web portal and the “**Krishi Pragati**” mobile app have been developed in which lakhs of farmers have directly joined and are getting benefitted.
- A new **iKhedut Portal 2.0** has been developed from the current year 2025-26 so that farmers can apply online for various assistance schemes.
- Under the AgriStack scheme of the Government of India, the state of Gujarat has so far completed the registration of more than 59 lakh farmers under the Farmer Registry and the work of Digital Crop Survey has also been carried out. In which Rs.413 crore has been given as incentive grant by the Government of India for good performance.

Horticulture

- Gujarat has its own unique identity and horticultural products that have a prominent position at the global level like “**Kesar Keri of Gir**”, “**Valsadi Hafus Keri**”, “**Kutchi Kharek**” and “**Amalsadi Chiku**”.
- Through the implementation of horticultural schemes, in the year 2024-25, 4.44 lakh hectares of area and 85.81 lakh metric tons of production have been achieved in fruit crops, 8.75 lakh hectares of area and 185.02 lakh metric tons of production have been achieved in vegetable crops, 8.18 lakh hectares of area and 12.91 lakh metric tons of production have been achieved in spice crops.
- In the current year 2025-26, **Rs.341.47** crore has been provided so far as an assistance to **1.72 lakh** horticulturalists under various schemes for integrated horticulture development activities.

- Various infrastructure facilities have been set up in the state for the post-harvest management of horticultural crops by the Horticulture Department. These include 548 cold storages and 2762 pack houses, 83 - ripening chambers, 413 - sorting grading units and 19 - reefers and other infrastructure facilities.
- Eight **Centres of Excellence** are functioning in the State with the aim of providing advanced technology for horticultural crops to the farmers of the State and another nine new Centres of Excellence are being constructed. So far, approximately 1 lakh farmers and youth have been trained in skill development through these centres.

Animal Husbandry

- Animal husbandry and dairy sector has a prominent contribution in the economic and social development of Gujarat state.
- More than 60 lakh animals have been treated and more than 4000 animal health fairs have been organized in the State by the end of January 2026.
- In order to encourage use of the latest technology of breeding of sexual semen in the animals, artificial insemination with sexual semen has been facilitated at Government institutions by paying a fee of only Rs.50. This year, 2.74 lakh animals have been artificially inseminated with sex sorted semen by the end of January, 2026.
- **Gujarat ranks first** among the states with more than one hundred lakh bred livestock in terms of artificial insemination coverage.
- By the end of January, 2026, 15,315 fertility improvement camps/sexual health camps have been organized and more than 8 lakh animals have been treated.
- Indian culture is the culture of cow, Ganga, Gita and Gayatri. Under the “Chief Minister Gaumata Poshan Yojana”, assistance of Rs.30 per animal per day is provided by the State Government for the maintenance of cows and buffaloes kept in Gaushala-Panjarapol registered under the Public Trust Act. During the year 2025-26, assistance of Rs.241.35 crore has been paid for more than 4.50 lakh animals of more than 1,600 institutions.

Fisheries

- The fish production of the state for the year 2025-26 is 7.91 lakh MT as on December-2025 is estimated to be worth Rs.19,000/- crore.
- Various works worth Rs.1700 crore are in progress for the development of fish landing centres.
- Gujarat State Fisheries Harbour and Aquaculture Authority has been established under the Gujarat Fisheries (Amendment) Act, 2025, which will work for the development of inland aquaculture and maintenance of fish landing centres.
- A comprehensive package of Rs.95 crore has been approved this year for Shrimp farming, under which farm holders in the Brackish water Aquaculture sector are given complete exemption on electricity duty and assistance on power consumption units. A total expenditure of Rs.60 crore has been made as on January-2026.
- To enable fishermen of Gujarat to double their income by using new technology in fish/shrimp production, Rs.12.50 crore has been allocated for intensive aquaculture farming and Mari culture zoning under the Viksit Gujarat Fund.
- Under the Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana, insurance cover has been provided to 1,10,000 fishermen of the State through the Fishermen Group Accident Insurance Scheme.

Cooperation

- The Ministry of Cooperation created by the Government of India has implemented several revolutionary initiatives by the State Government to embody the mantra of “*Sahkar se Samriddhi*” (Prosperity through Cooperation) and to make the cooperative societies more financially viable and transparent.
- To boost financial inclusion in the cooperative structure of the State, My Government has taken a historic step and made more than 12,580 Micro ATMs operational, which have so far successfully completed 2.16 crore transactions worth more than Rs.13,000 crore in rural areas. Under this initiative, more than 19 lakh cattle farmers have been directly connected to banking services. Most of the villages of the State are getting the benefit of banking facilities.

- **Banas Dairy** has set up a plant at Dama to collect and scientifically process 40 MT of cow dung daily and produce **Bio CNG**, due to which cattle farmers are getting additional income from the sale of cow dung. The use of high-quality **soil-organic fertilizer (“Bhoomi Amrut”)** prepared during this processing has reduced the farming costs of farmers.
- A 100 MT plant produces about 1,800 kg of Bio-CNG and 100 MT of organic fertilizer per day. This organic fertilizer is sold by Banas Dairy under the brand name “Bhoomi Amrut”. These projects will not only increase the income of the livestock farmers, but will also play a fundamental role in environmental protection by reducing carbon emissions by about 6,750 tonnes annually.

Water Management

- Once upon a time, Gujarat was known as a water-scarce region. Today, Gujarat has become a water-rich state due to the excellent water management of My Government. In the year 2025-26, a total of 202 check dams, both small and large, have been completed by December 2025. In addition, 186 small and 204 large check dams are under progress, which will provide irrigation benefits to an area of 7800 hectares. As of December 2025, a total of 1,87,791 check dams in the State have provided direct or indirect irrigation benefits to an area of more than 4.61 lakh hectares.
- During the monsoon, the Government has planned to build a series of barrages at 14 different places on the Sabarmati River at a cost of more than Rs.2000 crores to store the water flowing into the river downstream from the Dharoi Dam. Out of these, the work of 5 barrages has been completed. This will directly or indirectly benefit more than 50,000 hectares of area in Ahmedabad, Gandhinagar, Mahesana and Sabarkantha districts.
- In addition, the work of developing **Dharoi Dam** as a world-class tourist destination at a cost of Rs.1059 crore is also in progress.

- Under the **SAUNI Yojana**, 105 reservoirs have been connected by December-2025 with the excess flood water of Narmada. Out of these 1,29,038 million cubic feet of water has been provided in 99 reservoirs, 234 village ponds and 1616 check dams. Due to this irrigation facilities in more than 2.63 lakh hectares and drinking water facilities in many cities have been strengthened.
- A total of 11 lift irrigation schemes based on Kadana, Panam, Karjan, Ukai reservoirs and Narmada canal are providing irrigation benefits to about 92,000 hectares of 769 villages in Dahod, Panchmahal, Mahisagar, Surat, Bharuch and Narmada districts.
- Under Sujalam Sufalam Jal Abhiyan- **“Catch the Rain 2.0”**, more than 14,500 works have been done by different departments during the year 2025. Through these works, a total of 20,815 lakh cubic feet of water storage capacity has been increased and 10.39 lakh man-days of employment have been generated.

Water Supply

- The State Government has achieved the significant achievement of transitioning from reliance on groundwater for water supply systems to utilizing surface sources such as rivers, reservoirs, canals, and lakes.
- Through the establishment of an extensive network of 3290 km. of bulk pipelines for water supply schemes, the State Government has effectively delivered surface source-based drinking water supply to 15802 villages and 251 urban regions within the State, marking the first comprehensive state-wide water supply grid in the nation, thereby providing drinking water to 5.45 crore citizens of Gujarat.
- My Government has launched 12 schemes valued at Rs.443 crores and has laid the foundation stone for a scheme worth Rs.60 crores aimed at enhancing water supply, this year.
- With the aim of ensuring proper quality and sufficient quantity of water supply to the people of the State and to control leakage, theft and wastage, quality analyzers have been used in smart metering and water treatment plants. This is monitored in real time by Gandhinagar Central Monitoring Station.

**Food, Civil
Supplies and
Consumer
Affairs**

- With the establishment of 3 new laboratories this year dedicated to the accurate testing of water quality, the total number of operational laboratories in the state has now reached to 83.
- My Government has been providing food security to 3.18 crore individuals across 75 lakh families through the **Pradhan Mantri Garib Kalyan Anna Yojana**. Under this scheme, 35 kilograms of food grains are provided at no cost to each Antyodaya family every month, while 5 kilograms of food grains are provided per person per month to priority families.
- Under the **One Nation One Ration Card Scheme**, cardholders registered in various districts of the state are permitted to obtain food grains from any fair price shop within the state under “State Portability”. This year, approximately 5.29 lakh additional cardholders from the state have benefited from this scheme compared to the previous year, i.e. total 37.91 lakh cardholders have availed the benefit of this scheme.
- Till January 2026 in the year 2025-26, there has been an increase of 17,138 MT in the distribution of tur dal and gram under the **Pulses Distribution Scheme** compared to the year 2024-25. Additionally, 4,303 MT more double fortified salt has been distributed under the **Salt Distribution Scheme**, and additional 77,967 pouches have been distributed under the **Edible Oil Distribution Scheme**.
- Under the “**Pradhan Mantri Ujjwala Yojana**” in the first phase of the year 2025-26, additional 8.39 lakh beneficiaries have availed benefits compared to the previous year, i.e. a total of 38.39 lakh beneficiaries have availed benefit under this scheme.
- The **Jan Vishwas 2.0** initiative has offered relief to small traders and industries in accordance with the Legal Metrology Act, thereby enhancing the ease of doing business.
- During the current financial year, the State Consumer Protection Helpline has been actively assisting over ten thousand consumers with their complaints.

Energy and Petrochemicals

The Government is dedicated to eliminating darkness from the lives of its citizens and illuminating their futures. The expansion of power capacity has played a crucial role in the remarkable and historic growth of Gujarat from 2002 to 2025. The peak power demand in the State was 7.7 GW in 2002, which has increased to 26.4 GW by 2025 nearly a three-fold increase. This growth reflects Gujarat's swift industrial advancement and economic development.

- The number of sub-stations in Gujarat was 736 in the year 2002, which has increased threefold to 2,474 in the year 2025. The length of transmission lines has expanded from 31 thousand km to 79 thousand km. Additionally, distribution lines (HT + LT) have increased from 3.61 lakh km to 8.26 lakh km, reflecting a 2.25-fold increase, which has significantly enhanced electricity access in rural and urban regions. The number of transformer centres has surged from 2.28 lakh to 21.25 lakh, marking a ten-fold increase.
- Gujarat State Electricity Corporation Limited (GSECL) has received the prestigious award of "**Best Generation Company of the Year - State Genco**" at the Bharat Electricity – Powering India Awards 2025.
- Gujarat State has been honoured with the prestigious award of the **Wind India Award 2025** by the Indian Wind Turbine Manufacturers Association (IWTMA) for the highest wind capacity installation.
- The four government power distribution companies in the State, namely UGVCL, MGVCL, DGVCL, and PGVCL, have received an A+ rating from the Ministry of Power, Government of India, New Delhi, placing them among the top four companies in the country.
- The historical narrative of Gujarat reflects a deep reverence for the sun and nature. By merging this rich heritage with contemporary technology, Gujarat currently holds **the first rank in the country** with an impressive 42.5 Gigawatts of installed renewable energy capacity. It also holds first ranks in the country with the 14.8 Gigawatts of installed wind energy capacity and 25.5 Gigawatts of installed solar energy capacity.

- **The world's largest renewable energy park**, with a capacity of 37 GW, is currently under construction at Khawda, Kutch, Gujarat. In which, over 11 GW of renewable energy generation capacity has been realized till date.
- The "**Akshay Urja Setu Portal**" with a single-window clearance system, has been introduced to provide a one stop solution for everything from the registration of renewable energy projects to their commissioning.
- More than 20,700 km of MVCC cables have been installed by the power distribution companies to ensure reliable power supply to the state's farmers, uninterrupted energy to industries and quality service to the common citizens.
- The Elevated 11KV XLPE Cable Network has been implemented as a pilot project to enhance security in coastal regions and border outpost areas while also considering extremely adverse conditions.
- The RDSS scheme of the Government of India aims to reduce losses within the power distribution sector, enhance the distribution network, and ensure a reliable and quality power supply for consumers. Under this scheme, the Government of India provides 60 percent financial assistance to strengthen and modernize the power distribution infrastructure within the state. My Government has fully utilized this fund and accomplished projects valued at Rs.3784 crore by December 2025.
- My Government has announced **three very important new policies** in December 2025 – (1) Gujarat Integrated Renewable Energy Policy 2025, (2) Gujarat Pumped Storage Project (PSP) Policy, 2025 and (3) Gujarat Green Hydrogen Policy, 2025. This indicates that the development of this state is policy driven development.
- The aforementioned policies aim to foster the development of more than 100 GW of renewable energy capacity within the state. Furthermore, a target of 75 GW RE has been set to support 30 GW of electrolyser capacity for green hydrogen, which will make a substantial impact on reducing CO₂ emissions by approximately 5 MMTPA. The state has set a target to construct 75 GWh of pumped storage capacity by 2035 with an investment of about Rs.75,000 crore.

This will play a significant role in establishing the state of Gujarat as a leading hub for clean energy, energy storage and green hydrogen.

- In order to ease the challenges faced by farmers during watering their fields at night amidst the harsh winter cold and to mitigate their concerns regarding wild animals, the Government has implemented the **Kisan Suryoday Yojana** to supply electricity during the day. Under this scheme, farmers are receiving electricity during the day in 99% of the villages across the state.
- Under the **PM Surya Ghar Free Electricity Scheme**, the state has secured the first rank in the country in installing more than 5 lakh rooftop solar systems.
- GSECL has introduced the **Floating Solar Project, the first of its kind in the State**, with the capacity of 750 KW, located in Bhavnagar (Padwa). Other floating solar projects with a capacity of more than 2500 MW are under planning.
- Gujarat State Petronet Limited (GSPL) has established a natural gas transmission pipeline network, extending 2795 km, aimed at facilitating gas transportation by October 2025.

Industry

- The essence of industry and commerce is deeply integrated with the people of Gujarat. MoUs amounting to Rs.3.25 lakh crore in Mehsana and Rs.5.78 lakh crore in Rajkot have been signed during the **Vibrant Gujarat Regional Conference (VGRC) 2025-26**, organized to further expand the successful model of Vibrant Gujarat.
- In order to enhance the global competitiveness of the textile industries within the State, assistance of more than Rs.1800 crore has been allocated to more than 8,000 units under various textile policies, resulting in employment generation for an estimated 65,000 individuals.
- In order to enhance research and development activities within the state and to motivate young entrepreneurs to cultivate their innovative concepts, more than Rs.68.14 crore has been allocated under the **Startup and Innovation Scheme**. Under this scheme, Gujarat has been declared as the **"Best Performer"** nationwide according to the National Startup Ranking Framework for five consecutive years, namely 2018, 2019, 2021, 2022, and 2023-24.

- A total of 223 units have been registered under the Large Scale Industries Support Scheme, which is expected to result in a proposed investment exceeding Rs.63,000 crore. Furthermore, this will generate approximately 71,500 direct employment jobs and an estimated 1.78 lakh indirect employments.
- My Government has implemented the Gujarat Jan Vishwas (Amendment in Provisions) Act, 2025, following the approach of Trust Based Governance and Reducing Compliance Burden Study to further strengthen Ease of Doing Business and Ease of Living. Under this Act, a total of 516 provisions of 11 state acts and rules have been decriminalized. Under these uniform legal amendments, the penalties for minor and technical infractions have been modified from imprisonment to observational penalties. As a result, manufacturers, shopkeepers and industrial workers have received direct benefits and trust in the government has been strengthened.
- A total provision of Rs.1550 crore has been made to provide assistance under various schemes to MSME industries. Under the Atmanirbhar Gujarat Scheme for Assistance to MSME, total 22,730 claim applications have received assistance of approximately Rs.1319 crore. Furthermore, a capital investment of around Rs.27,467 crore has been attracted and more than 1 lakh employment has been generated.
- Under the Market Development Assistance Scheme, benefits are provided to the units participating in the exhibition as well as the organizers. Under this scheme, assistance of Rs.1884.29 lakhs has been provided to total 1002 units.
- Gujarat Industrial Development Corporation has acquired approximately 342.62 hectares of land for new settlements in the financial year 2025-26. A total of 46,819 hectares of land has been acquired for industrial development from the year 1962 to December-2025.
- The Gujarat Industrial Development Corporation has established more than 239 industrial estates within the State till date.

- In the year 2025, infrastructure facilities have been developed across 274 hectares of land for 447 industrialists.
- Sanand is evolving into a global industrial center. Infrastructure is being developed in the Sanand Industrial Estate for world-class multinational companies such as Micron, Kaynes Technology, CG Power, Taiyo Nippon Sanso India, and BASF.
- Dholera, previously referred to as the saline region of barren land, is gaining new identity with significant advancements in development. Four out of five semiconductor projects under the "India Semiconductor Mission" by the Government of India are being established in Gujarat at **the Dholera Special Investment Regional Development Authority**. In which, the first semiconductor fabrication unit of the country, with an investment of Rs.91,000 crores by Tata Electronics is being developed in Dholera.
- **The Gujarat Rail Infrastructure Development Corporation Ltd.** has completed and commissioned the rail and Gatishakti Terminal project extending from Bedi Port to Windmill Station (2.57 km). Additionally, the construction of the Gatishakti Cargo Terminal at Rafaleswar, located near Morbi, under the PM Gatishakti Project has also been finalized.
- The Geology and Mining Department has generated a total revenue of Rs.2067 crore in the current year 2025-26.
- Mineral production has commenced in 9 major mining blocks and 457 minor mining blocks through public auction, indicating an anticipated increase in revenue for the upcoming period.
- Gujarat Mineral Development Corporation Ltd. has achieved the target of a market cap of Rs.20,000 crore during the current financial year.
- The State Government has received dividend income of Rs.237 crore through Gujarat Mineral Development Corporation in the previous financial year.

Tourism

- Garba is the cultural identity of Gujarat. UNESCO has declared Garba of Gujarat as an Intangible Cultural Heritage. With the globalization of our Garba festival, Gujarat Tourism hosted the first Pre-Navratri event outside the State in Udaipur, Rajasthan and the Post-Navratri event in Delhi.
- **“Bharat Parv”** was organized for the first time outside Delhi at the Statue of Unity, Ektanagar from November 01 to 15, 2025, along with National Unity Day. Various states and union territories participated in Bharat Parv and showcased their folk culture, cuisine, and handicrafts, thereby demonstrating **“India’s unity in diversity”**.
- Works amounting to Rs.47.99 crore have been completed in the first phase for the comprehensive development of Krishna-Rukmini pilgrimage site Madhavpur - Porbandar.
- **The Adi Shakti National Women's Archery Competition** was organized at Adyashakti Dham Ambaji from 8 to 10 April 2025. More than 700 young women archers from various states across the country participated during this three-day competition. This year, the National Women's Archery Competition was organized from 21-23 January 2026.
- Sports activities have been successfully organized at the Adventure Fest at Dharoi in May-June 2025 and the Beach Festival at Mandvi in December 2025 for the development of adventure tourism.
- The development of tourism infrastructure at Mokarsagar-Porbandar and Dholavira-Kutch, at a cost of Rs.200 crore, is under progress.
- As a result of advancements in the tourism industry in Gujarat, the number of tourists visiting the State has increased to 22.28 crore in 2025 from 16.77 crore in 2024.
- Various development works are under progress in two phases at the Ambaji Yatra Dham under the **“Ambaji Corridor”** project, at a cost of Rs.1632 crore.
- Development works have been carried out at an expenditure of Rs.32.70 crore for the comprehensive development of Shri Ashapura Mataji Temple located at Shri Matano Madh, district Kutch, aimed at offering sufficient amenities to the visiting pilgrims.

**Cottage and
Village
Industry**

- Gujarat was awarded the '**Best State for Promotion of Aviation Ecosystem**' award by the Union Aviation Minister at the national level 'Wings India-2026' event organized in Hyderabad.
- In order to realize the mantra of 'Vocal for Local' and 'Har Ghar Swadeshi, Ghar Ghar Swadeshi', My Government is offering support for the production of local Khadi and promoting its sale through various fairs. Realizing the slogan 'Khadi for Nation, Khadi for Fashion' given by Hon'ble Prime Minister, the total sale of Khadi has increased from Rs.367 crore to Rs.683 crore in the last four years due to various efforts of the State Government. Consequently, there has been an 86 percent growth in Khadi sales during this period. Under Shri Vajpayee Bankable Yojana, the loan ceiling has been increased to Rs.25 lakh from Rs.8 lakh, while the maximum limit of assistance has been increased to Rs.3.75 lakh from Rs.1.25 lakh. Benefit of approximately Rs.367 crore has been availed to 47,551 beneficiaries in the year 2025-26 by the end of January-2026 under this scheme.
- Gujarat State Handloom and Handicraft Corporation has achieved a record sale of handloom and handicraft products worth Rs.33.59 crore during the year 2025-26 till January-2026.

**Health and
Family
Welfare**

- My Government is truly realizing the mantra of "**Sarve Santu Niramaya**" (May all be healthy). This government is committed to providing excellent health services to the people. As of December 2025, health services have been provided in approximately 9.50 crore cases through O.P.D and I.P.D. More than 13 lakh major and minor surgeries performed, over 6.25 crore laboratory tests conducted and more than 2.96 crore people were screened for non-communicable diseases. Furthermore, around 9.63 lakh pregnant women and 9.41 lakh children have been vaccinated.
- A total of 281 dialysis centres and 35 day-care chemotherapy centres have been established to provide decentralized services to patients suffering from kidney diseases and cancer conditions.
- By December 2025, more than 1.24 crore consultations have been carried out through 22 telemedicine hubs to enhance healthcare services in remote areas.

- More than 2.70 crore beneficiaries have received Ayushman cards under the **Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana** as of December 2025. Additionally, claims amounting to Rs.3273.70 crore have been approved.
- Under the **Namoshree Yojana**, financial support totalling Rs 450 crore has been extended to more than 7.5 lakh eligible women via Direct Benefit Transfer (DBT) to decrease maternal and infant mortality rates.
- The capacity and efficiency of government hospitals in Gandhinagar, Ahmedabad-Sola, Vadodara, Surat, Rajkot, Bhavnagar, and Jamnagar are being enhanced to provide multi-specialty and super-specialty services.
- Consistent efforts are being made to ensure the availability of doctors. More than 95% of the posts of MBBS doctors have been filled. The total number of graduate and postgraduate seats in the State has increased to 7575 and 3545 respectively, to ensure sufficient availability of both MBBS and specialist doctors.
- In order to ensure the availability of medications within the public health system, 150 additional medicines have been added to the Essential Drug List, bringing the total count of medicines on the list to 1479.

Education

- The children are the future of the State and this future can be illuminated through education. My Government is diligently striving for a Gujarat enriched with culture and knowledge and equipped with essential skills. As a result of recruitment of permanent teachers in Government schools, modern infrastructure facilities and providing quality education, 343,000 students have left private schools and enrolled in government schools from the years 2021-22 to 2025-26.
- In order to enhance the education system, a total of **10,141 Vidya Sahayak** have been appointed in the State in the year 2025-26. Furthermore, an additional 2,073 *Vidya Sahayak* have been recruited specifically for the rural and border regions of **Kutch district**.
- A favorable outcome of the **School Enrollment Scheme** is that the enrollment rate in the State has now achieved **100 percent**, while the **dropout rate** has significantly decreased from 37.22 in 2001-02 to 2.42 in 2024-25. In the year 2025-26, a total of 5,15,648 children have enrolled in Standard-1, and 5,78,578 have enrolled in Balvatika.

- The State Government has increased the fee reimbursement for underprivileged children under R.T.E. from Rs.10,000 in the year 2013-14 to Rs.13,675 in the year 2022-23. Additionally, Gujarat has emerged as **the first State in the country**, providing assistance of Rs.3,000 to the students for educational materials.
- Under the R.T.E. Act, 25% of the seats in Standard-1 at non-granted private primary schools have been allocated at no cost to children from underprivileged sections and deprived groups from year 2013-14. As a result, a total of 95,494 students have been granted admission for the year 2025-26.
- The State Government prioritizes the safety of students; for this purpose, a provision of accident insurance assistance amounting to Rs.2,00,000 per student has been made under the **Vidyadeep Yojana** from the year 2025-26. During the years 2002-03 to 2024-25, assistance of approximately Rs.29 crore has been provided to 6,650 beneficiaries.
- Activities aimed at developing pre-vocational skills have commenced in schools as a part of the “Bag less Day” Program. Joyful-Bagless Saturday – activities like yoga, Surya Namaskar, games, book reading, and experiments have been arranged for students to enjoy.
- The Balvatika class has been started in primary schools for children aged over 5 years and the registration process for Balvatika has been undertaken.
- Literature that conveys the core principles of the Bhagavad Gita in an interesting manner has been provided to schools for students in standards 6 to 10, aiming to incorporate the Indian knowledge system into the curriculum.
- Vedic Mathematics textbooks are made available in all schools from standard 6 to 9.
- 85 new government secondary schools and 5 new government higher secondary schools have been started in the State in the year 2025-26. Furthermore, approvals have been granted to English medium government secondary and higher secondary schools in 8 municipal areas.

- Under **Mukhya Mantri Gyan Setu Merit Scholarship Yojana**, scholarships amounting to Rs.68.90 crores have been disbursed to 90,000 students during the last three financial years.
- Under **Mukhya Mantri Gyan Sadhana Merit Scholarship Yojana**, scholarships amounting to Rs.97.53 crores have been disbursed to 75,000 students during the last three financial years.
- Under **Namo Lakshmi Yojana**, assistance of Rs.1338 crore has been disbursed to 10,84,892 girl students during the last two financial years.
- Under **Namo Saraswati Yojana**, assistance of Rs.205 crore has been disbursed to 1,50,762 students during the last two financial years.
- A total of 9,400 Assistant Teachers and 470 Principals have been recruited in government and non-government grant-in-aid secondary and higher secondary schools under the recruitment process of the year 2024.

Higher and Technical Education

- In order to provide financial assistance to the talented and needy students enrolling in the higher educational courses in the State, assistance of Rs.387.03 crore has been disbursed to 92,034 students under Mukhya Mantri Yuva Svavalamban Yojana(MYSY) by January for the year 2025-26. Assistance of total Rs.2844.68 crore has been disbursed to 6,23,891 students till date under this scheme.
- The State Government has disbursed assistance of Rs.137.25 crore to 4391 girl students by January 2026, under Mukhya Mantri Kanya Kelvani Nidhi Yojana (MKKN) to provide financial support to the girl students studying in MBBS. The total amount disbursed under this scheme till date is Rs.835.19 crore, benefiting 27,997 girl students.
- It is a matter of pride for all of us that Gujarat has been honoured with the **Best Performer State for five consecutive years** under the Startup Ranking Framework, which is awarded by the Government of India to states for their efforts under the Student Startup and Innovation Policy (SSIP), launched in 2017, aiming to equip the youth of the State in the sectors like research, innovation, and entrepreneurship.

- Support has been provided to 4,948 proofs of concept, 2282 IP filings, and 828 startups by the institutions which are receiving assistance under the Student Startup and Innovation Policy (2.0), the first of its kind in the country.
- The State Government has provided training to approximately 58,000 students till date, which includes more than 16,300 students during the year 2025-26 under the Integrated Module for Placement Apprenticeship cum Training (IMPACT) Scheme.

Development of the Deprived

Developing Caste Welfare

- This government is doing an excellent job for development of the deprived by supporting the deprived people. Scholarships and uniform assistance have been provided to the students of kindergarten and primary schools as well as scholarships worth Rs.760.25 crores to 33.75 lakh students of the developing castes studying in secondary schools, higher secondary and higher education under various educational schemes by the end of December 2025.
- There are 750 Grant-in-Aid hostels, 68 government hostels and 187 ashram schools as well as 35 residential schools functioning in the State for the socially and educationally backward classes, in which approximately 82,000 students are being provided **free accommodation, food and study facilities**, in which Rs.274.71 crore has been spent so far.
- The house construction assistance under the **Pandit Deendayal Awas Yojana** has been increased from Rs.1.20 lakh to Rs.1.70 lakh. An assistance of Rs.153 crore has been paid to more than 15,500 citizens belonging to the most backward classes, nomadic and de-notified tribe, socially and educationally backward classes and economically backward classes for the construction of houses by the end of December 2025.
- More than 56,000 girls from socially and educationally backward classes and economically backward classes have been provided assistance of an estimated Rs.68.50 crore under the **Kunwar Bai Nu Mameru Yojana** and the **Saat Phera Samuh Lagna Yojana**, by the end of December 2025.

Scheduled Caste Welfare

- About 4.85 lakh students have been provided scholarships by spending Rs.419 crore under the **Pre-Matric Scholarship and Uniform Assistance Scheme and the Post-Matric Scholarship Scheme** by the end of December 2025.
- Assistance of Rs.2.50 lakh is provided under **Dr. Savita Ambedkar Inter Caste Marriage Assistance Scheme**. 547 couples have been benefited under this scheme by spending Rs.16.03 crore by the end of December 2025, which inspires social harmony.
- Assistance of Rs.1,70,000 is provided under **Dr. Ambedkar Awas Yojana**. Assistance has been provided to 4,799 beneficiaries for the construction of houses under this scheme by spending Rs.58.12 crore by the end of December 2025.
- A loan of Rs.15 lakh is provided at the rate of 4% for higher education abroad under the scheme of **Dr. Ambedkar Loan Scheme for higher study in foreign countries** in which, Rs.62.80 crore has been spent and **418 students have been given loans to study in foreign countries** by the end of December 2025.

Social Security

- A total of 76,525 persons with 60% or more disability have been provided financial assistance of Rs.63.10 crore under the **Sant Surdas Yojana** by the end of December 2025.
- Assistance of approximately Rs.69 crore has been paid to about 77,900 beneficiaries under the Pension Scheme for providing financial assistance to the persons with intellectual disabilities (psycho-disabled) by the end of December 2025.
- About 5.42 lakh beneficiaries have been paid assistance of Rs.526 crore under the Economic Assistance Scheme for the maintenance of destitute older persons and destitute disabled persons by the end of December 2025.
- A Special Recruitment Drive has been launched to fill more than 21,000 vacancies for the differently-abled persons in the State Government Services.

**Tribal
Development**

- By the end of December 2025, an estimated 21,500 beneficiaries have been paid Rs.59 crore under the **Palak Mata-Pita Yojana** for the children aged 18 years or below who have lost their parents' protection . An assistance of Rs.5 crore has been paid to 250 beneficiary daughters at the time of their marriage under this scheme by the end of December 2025.
- Rs.750 crore has been allocated to various corporations this year for the educational loan and self-employment loan scheme stands for beneficiaries of Scheduled Castes and Developing Castes and Rs.6 crore has been allocated for the self-employment loan scheme stands for the differently-abled persons.
- A provision of Rs.22,025.81 crore has been made in the year 2024-25 and a provision of Rs.30120.96 crore has been made for the current year 2025-26 under the **Vanbandhu Kalyan Yojana**. A provision of Rs.1059 crore has been made under the '**Gujarat Pattern**' for the current year 2025-26.
- Benefits have been provided to 12.22 lakh students of Scheduled Tribe at a cost of Rs.854 crore so far under the **pre-matric and post-matric scholarship schemes of the State Government and the Government of India**.
- About 1.60 lakh students of Scheduled Tribes are availing free residential co-educational facilities at **Government Eklavya Model Residential Schools, Adarsh Nivasi Schools** and **Grant in aid Ashram Schools** till now at a cost of Rs.456.47 crore.
- Eklavya Model Residential Schools have achieved an average board result of 97.18% in Standard 10, 82.17% in Standard 12 Science stream, 98.36% in Standard 12 Commerce stream and 99.86% in Standard 12 General stream in the year 2024-25. While Adarsh Nivasi Schools have achieved 97.23% in Standard 10 and 83.22% in Standard 12 Science stream.
- Rs.74.78 crore has been spent so far for the **Grant-in-Aid Hostels** in the current financial year so that boys and girls of

Scheduled Tribe can study in hostels. 56,482 students are taking benefit of these hostels.

- Rs.65.38 crore has been spent so far for the **Government Hostels and Samaras Hostels** with boarding and lodging facilities for the students of Scheduled Tribe studying outside the village for higher studies. 21,300 students are taking the benefit of this.
- About 3117 beneficiaries have been provided benefits by spending Rs.23.58 crore under the **Vyaktigat and Halpati Awas Yojana** for the families of Scheduled Tribe.
- About **2347** beneficiaries have been benefited by spending Rs.14.32 crore for medical treatment and nutritious food to the patients of the Scheduled Tribe community suffering from serious diseases.
- Improved seeds, fertilizers and training on agriculture are provided to tribal farmers under the **Agricultural Diversification Scheme** and a total of 86,131 farmers have been covered under the scheme at a cost of Rs.42 crore.
- With a view to providing employment to tribal women in tribal areas, 12,465 milch cattle have been provided to 4086 women beneficiaries at a total cost of Rs.36.80 crore this year.
- A total of **5628 beneficiaries** have been provided loan benefits worth Rs.16.32 crore so far in the financial year 2025-26 by the dairies of the State in rural tribal areas under the **Integrated Dairy Development Project (IDDP)**.

Women and Child Development

- With the mantra of “*Yatra Naryastu Pujayante*” (Where women are worshipped) my Government is committed to the upliftment and welfare of women. My Government is committed to provide basic facilities in all the Anganwadis of the State. Toilets, electricity connections and drinking water facilities are provided in a total of 53,065 Anganwadis of the State. In the year 2025-26, 1063 Anganwadi centers have been inaugurated while the foundation stone of 1097 Anganwadi centers has been laid, the construction of which is in progress.

- In order to ensure that no Anganwadi remains without Anganwadi workers and Tedagars, **more than 9000** Anganwadi workers and Tedagars have been awarded appoint letters on honorary services at the behest of the Hon'ble Chief Minister this year.
- To strengthen the nutritional level in the State, **ready-to-cook packets** of Balshakti and Matrushakti are provided as **take-home ration** to the beneficiaries under the "**Purak Poshan Yojana**". Under this scheme, more than **30 lakh children**, pregnant and lactating mothers have been provided benefit by the end of November, 2025 in the year 2025-26.
- The **Dudh Sanjeevani Yojana** is implemented in a total of 141 components to improve the nutritional level of children, pregnant and lactating mothers. So far, 8.64 lakh children, pregnant and lactating mothers have taken benefit of this during the year 2025-26.
- Nutritious hot meal is provided to pregnant and lactating mothers of tribal districts once a day at the Anganwadi Center under the **Poshan Sudha Yojana**. Total 89 thousand mothers have been benefited by the end of November, 2025 in the year 2025-26.
- To provide nutrition to women for **1000 days** starting from pregnancy till her child attains the age of 2 years, **raw-ration kits** are being provided by implementing the "**Mukhyamantri Matrushakti Yojana (MMY)**" from the year 2022-2023. Total Rs.156 crores have been spent for beneficiaries during the year 2025-26.
- Supplementary nutrition is provided to all adolescent girls aged 15 to 18 years for 300 days annually under the **Purna Yojana**. About 9.50 lakh adolescent girls of the State have been covered in the year 2025-26. Under which, a total of Rs.250.35 crores have been spent by the end of December-2025.
- **Poshan Month** has been celebrated in the State by undertaking 1.35 crore activities with the participation of 3.7 crore people to create awareness about nutrition in the State.

- My Government has implemented the **Ganga Swarupa Economic Assistance Scheme** to provide financial assistance to the Gangaswarupa sisters of the State so that they can live with dignity. Currently, about 17 lakh beneficiary Ganga Swarupa sisters in the State have been paid an assistance of Rs.1250 per month through Direct Benefit Transfer (DBT) and an assistance of Rs.2562 crore has been paid for the same in this year.
- Assistance has been approved for more than 3 lakh beneficiary daughters under the “**Vahali Dikari Yojana**” to encourage the birth rate and education of girls in the state.
- Facility of 59 rescue vans equipped with latest technology has been provided under the **181 Abhayam Mahila Helpline Scheme** to ensure that women of the State get immediate help in adverse situations. This year, more than 1.50 lakh women called the Mahila Helpline for guidance and counselling and more than 30 thousand sisters have been helped on the spot.
- The women affected by family or other problems are provided mental and legal support through counselling in the police station itself under the **Police Station Based Support Center Scheme**. Total of 80 support centers are functioning at the District and Taluka headquarters of the State, in which counselling and legal guidance is provided by about 160 skilled counsellors. More than 10 thousand women have been provided these services during this year.

Urban Development and Urban Housing

- The honorable Prime Minister of the country and the then Chief Minister of Gujarat State Shri Narendrabhai Modi launched the “Urban Development Year” in the year 2005. My Government has celebrated the year 2025 as the Urban Development Year and doubled the pace of development.
- Under the Urban Development Year, 13,314 works worth a total of Rs.55,073 crores have been approved, out of which 2300 works worth a total of more than Rs.4955 crores have been approved in the newly formed Karamsad-Anand, Nadiad, Morbi, Surendranagar, Gandhidham, Porbandar, Vapi, Navsari, Mehsana metropolitan cities.

- A total of 5 satellite towns have been declared namely Kalol, Sanand, Savli, Bardoli and Hirasar.
- Total 96 works worth Rs.3180 crores have been approved under Railway Over Bridge/Railway under Bridge.
- 8.45 km. iconic roads have been built in Vadodara, Junagadh, Navsari and Porbandar cities.
- Under the **Smart City Mission**, 359 projects worth a total of Rs.11507 crore have been taken up in 6 cities of Gujarat.
- About 22,000 houses have been allotted and another 10000 houses are under allocation under **the Pradhan Mantri Awas Yojana (Urban)**.
- A plan of Rs.113 crore has been taken up for more than 750 buses in 8 metropolitan cities of the State under the PM e-Bus Seva Yojana.
- A total of 68.257 km. works have been completed under the Metro Transport Service. Out of which, a total of 28.25 km route from Motera to Mahatma Mandir has been opened for the public in the presence of Hon. Prime Minister Shri Narendrabhai Modi.
- Out of the total 6 phases of Sabarmati Riverfront, works of 11.2 km worth Rs.1202 crore have been completed. While the work of 28 km is currently in progress.
- “PM Street Vendors Atmanirbhar Nidhi” (PM SVANidhi) has provided loans worth Rs.1170/- crore to more than 4.90 lakh street vendors without bank guarantee.
- Ahmedabad Municipal Corporation has received the first rank in the category of clean cities with a population of more **than 10 lakh**.
- All 167 urban local bodies of the State have been ODF certified. Many cities have received Garbage Free City, ODF+/ODF++/Water+ certification.
- Under the **Town Planning Scheme**, 400 TP schemes have been made available through Web-GIS and digitalization of another 600 schemes is under process.

- ODPS 3.0 is planned to be implemented with modern technologies like AI, Block chain.
- 32 draft town planning plans, 38 preliminary town planning plans, 43 final town planning plans and 04 development plans have been approved.
- Gujarat High Speed Railway Station Planning Authority has been formed for 8 stations of the State for Bullet Train.

Panchayat and Rural Development

- My Government is dedicated to the principles of Mahatma Gandhi. Bapu had said, 'The soul of India resides in its villages.' Fulfilling this mantra, this government is doing unprecedented work in the field of rural development. Under the **Pradhan Mantri Awas Yojana (Gramin)** 78,752 houses have been constructed by the beneficiaries by the end of November-2025 in the year 2025-26, in which more than Rs.978 crores of assistance has been provided.
- A program organized in Narmada on date 15/11/2025 in the presence of the Hon'ble Prime Minister, a total of 61,125 beneficiaries have been given e-house entry at a cost of Rs.1008.19 crores under the **Pradhan Mantri Awas Yojana - Gramin** in the entire state.
- Under the **Swachh Bharat Mission (Gramin)**, by the end of November-2025 in the year 2025-26, 45010 individual toilets, 132 collective toilets, 3031 individual soak pits and 22938 collective soak pits have been completed and under solid waste management, 5796 collective compost pits and 3382 individual compost pits have been constructed for disposal of organic waste. As part of the solid waste management work, 1203 segregation sheds have been constructed and a total expenditure of Rs.174.92 crore has been incurred.
- After the success of the first phase, 4800 beneficiaries have been provided benefits in the second phase under the **Gobardhan Project**.
- Under the **Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojana-Watershed Development Component 2.0**, a total of 4582 works of soil and moisture conservation, water harvesting and groundwater recharge as well as 1473 works related to production enhancement have been completed by the end of

November-2025 in the year 2025-26. Out of which Rs.48.24 crore has been incurred.

- Total 6731 Self Help Groups have been formed **under the National Rural Livelihood Mission**. A total of 4401 Self Help Groups have been provided with a total assistance of Rs.13.16 crore under Revolving Fund (RF), 5832 Self Help Groups have been provided with assistance of Rs.75.45 crore under Community Investment Fund (CIF). A total of 48474 Self Help Groups have been provided with a loan of Rs.976.61/- crore from banks as Cash Credit (CC) loans.
- My Government has organized 13 **Saras Melas** at national and regional level. In which a total of 980 Sakhi Mandals from Gujarat and other states participated and sales worth Rs.9.50 crore was made.
- The number of services available under **e-Gram Vishwagram Yojana** has increased to 321. In which 4.93 crore transactions have been made in the year 2025-26. Out of these 22.14 lakh transactions have been made under Digital Seva Setu by the end of the year 2025-26 (November-25).
- A grant of Rs.13,095 crore has been allocated to the Panchayats so far for works under primary facilities like roads, primary education etc. under the **15th Finance Commission**, under which 5,82,769 works have been completed so far at a cost of Rs.10,162.60 crore.
- Under the **Mahatma Gandhi Swachhta Mission**, from the year 2016-17, a grant of Rs.4.00 per person per month was given for door-to-door collection of solid waste in all the Gram Panchayats of the State and the collected waste was taken to the landfill site, which My Government has decided to increase to Rs.8.00 per person per month. An incentive grant of Rs.141.91 crore has been provided by the end of November-2025 in the year 2025-26.
- In order to provide skilled manpower to the industries, 1,20,332 trainees have been admitted under the Craftsmen Training Scheme at the Government Industrial Training Institutes (I.T.I.) under the admission session 2025-26.

**Labour, Skill
Development
and
Employment**

- A total of 72,128 candidates have been provided employment by organizing a total of 1268 industrial recruitment fairs and a total of 2,92,538 candidates have been provided employment through employment exchange offices by the end of December-2025.
- About one lakh youth have been provided industry-oriented training in industrial units under the Chief Minister's Apprentice Training Scheme during the year 2025. These efforts are making the youth of the State employable and contributing significantly to the creation of a self-reliant Gujarat.
- Kaushalya -The Skill University, established for the purpose of skill development in line with the current needs of the youth of the State, has signed a total of 71 MoUs, including 9 for credit transfer, 16 as strategic partners, 35 as affiliated partners and 11 MoUs with international educational institutions. 1375 students have taken admission in long-term courses and 1559 students have taken admission in short-term courses at this university in the last 1 year.
- In the Shram Setu portal, 5500 applications have been processed online over the last 1 year and 13,810 online inspections have been carried out.
- In order to ensure that the workers of the State get the bonus amount during Diwali, an amount of Rs.**2029 crore** has been paid as bonus to 12,44,659 workers during the year 2024-25.
- Under the Dhanvantari Arogya Rath Yojana, a total of 40.25 lakh workers have been provided health services through a total of 154 Dhanvantari Arogya Raths by the end of December-2025.
- Under the Education Assistance Scheme, two children of construction workers registered for studies from Standard 1 to Ph.D. are provided with assistance ranging from Rs.1,800/- to Rs.2 lakh, in which a total of 44,483 beneficiaries have been provided assistance of **Rs.76 crore** by December-2025.

**Road and
Building
Department**

- Nutritious food is provided to construction workers at a concessional rate of Rs.5/- under the Shramik Annapurna Yojana. Currently, 293 booths are operational and a total of 115.30 lakh meals have been distributed by December 2025.
- The State Government has decided to build **Namo Shakti Expressway** and **Somnath-Dwarka Expressway** to connect the ends of the State from north to south and east to west and to meet the increasing traffic. These projects will connect the industrial centers, tourist destinations and ports of the State, which will give a boost to economic activities and the construction of quality roads and flyovers will save fuel and make travel faster and safer. This project with 1100 km. length to be undertaken at an estimated cost of Rs.93,240 crores will benefit more than 2.5 crores people in 15 districts of the State and the development of the remote districts will be enhanced and the development of the entire State will be accelerated by the benefit of infrastructure facilities.
- The State Government has approved 12 works to be developed at a cost of Rs.7206.18 crores under the **Garvi Gujarat High Speed Corridor**. The work is in progress.
- A provision of Rs.500 crore has been made for the development of roads and infrastructure under **SER (Surat Economic Region)** as a new item in the year 2025-26, works worth Rs.1749.10 crore are under planning.
- The State Government has approved 20 works worth Rs.1147.08 crore for the construction of roads with **climate resilience and new technology**.
- The work of four-lane/10 meters/7 meters widening of 1001 km long roads at a cost of Rs.2373 crore has been completed in the State. While the work of four-lane / 10 meters / 7 meters widening of 1427 km long roads at an estimated cost of Rs.5083 crore is in progress.
- The work of 28 bridges including construction/new bridges in the State has been completed at a cost of Rs.157 crore, while the work of 86 bridges worth Rs.1598 crore is in progress.

- Under the **Mukhya Mantri Gram Sadak Yojana**, 36474 works of 86757 km worth Rs.42478 crore have been approved in the State since the year 2016-17. Out of these, 27830 works of 66330 km have been completed and the remaining works are in progress. A total provision of Rs.5403 crore has been made under this scheme in the year 2025-26.
- All the works approved under **Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana - 1 and 2** have been completed. And a length of 3012 km has been covered under **Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana - 3**. At present, works of 289 roads with 2800 km. and works of 45 bridges have been completed.
- In the first phase of 237 km road connecting Saputara to Statue of Unity, passing through Narmada, Tapi and Dang districts from Saputara- Shabridham- Songadh- Sherula- Zarwani to Gora to Statue of Unity, the work of widening the existing roads of 95 km length of Narmada, Tapi and Dang districts by 10 m has been completed.
- In order to provide modern facilities by undertaking the work of improvement, upgradation and strengthening of roads connecting industrial and mining areas, 231 works of 2343 km length have been sanctioned at a cost of Rs.7178 crore. Out of these 136 works with 1272 km. of length have been completed at a cost of Rs.2820 crore.
- Gujarat is the state with the longest coastline in the country. Since the ports of Gujarat are strategically important, to upgrade the necessary road infrastructure connecting the ports, 46 works of length 757 km have been completed at a cost of Rs.1118 crore.
- In the first phase, works of 25 roads with the length 272.80 km including the strengthening and upgrading of existing roads, connecting missing links, and the construction of small and large bridges have been sanctioned at a cost of Rs.693.53 crore under the plan of ₹2,440 crore to develop a **Coastal Highway** along the Gujarat coastline. Out of these, work of 21 roads worth Rs.469 crore has been completed and work of 4 roads worth Rs.224.50 crore has been taken up.

- The work of making the **Sarkhej - Gandhinagar highway** six-lane at a cost of Rs.913 crore has been completed and the elevated corridor from Iscon to Sanand flyover at a cost of Rs.530 crore, a 6-lane flyover near Chharodi, a four-lane bridge over the Sabarmati river at a cost of Rs.68 crore and the work of a new four-lane canal next to the Adalaj four-lane canal at a cost of Rs.81 crore is in progress.
- For the safety of traffic and to save time, under the **Railway Crossing Free Campaign**, a total of 82 railway over bridges have been completed under various schemes at a cost of Rs.3931 crore under the work of constructing over bridges at railway crossings with traffic exceeding one lakh train vehicle units under the 50% sharing of the State Government and the Ministry of Railways, Government of India.

Transport

- With the implementation of the faceless service, 7.60 lakh citizens have availed the benefit of services related to driving license and learning license and a total of 18.67 lakh citizens have taken benefit of vehicle-related services.
- A relief of 15% in motor vehicle tax for transport vehicles and 25% in motor vehicle tax for non-transport vehicles is provided for scrapping a vehicle through the Registered Vehicle Scrapping Facility (RVSF). Under this scheme, 1,091 beneficiaries have availed a total tax relief of Rs.1.06 crore in the year 2025-26.
- A one-time waiver scheme has been implemented for one year from 01.05.2025 to waive the outstanding tax, penalty, interest and challan fine for scrapping commercial vehicles that are more than 8 years old at a government-approved scrapping center.
- A total of 2,23,321 fitness certificates have been issued by the Automated Testing Station by the end of November 2025 in the current financial year 2025-26.
- As a part of realizing the vision of “Green Growth” of Hon’ble Prime Minister Shri Narendrabhai Modi and for the preservation and enhancement of the environment, My Government has taken a public-oriented and environment-friendly decision to set an effective tax rate at 1% by providing a rebate of up to 5% for 1 year on electric vehicles powered by fully electric batteries, on which a lump sum vehicle tax of up to 6% is currently in force.

- NIC has developed 'e-detection' application for online verification of documents of vehicles passing through the State toll plazas and NHAI operating in the State in which, a total of 3,13,882 challans have been issued by the end of November 2025 in the financial year 2025-26.
- Under the Tribal Border Village Scheme, 111 new big buses have been deployed into operation for students.
- Last year, the State Government has deployed 1475 new vehicles with advanced technology including 962 super express vehicles, 163 Gurjarnagari vehicles and 350 midi buses in the service of the traveling for public.
- Hon'ble Prime Minister Shri Narendrabhai Modi flagged-off 111 new ready-built vehicles in the service of people on the occasion of the 150th birth anniversary of Bhagwan Birsa Mundaji.
- The State Government has appointed 2320 candidates in the conductor category, 3084 in the driver category and 1658 in the helper category in the year 2025-26.

Ports

- The total volume of cargo transported through non-major ports operated by the **Gujarat Maritime Board** in the fiscal year 2024-25 has been 487.73 million metric tons. This indicates an increase of 8.56% over the last financial year. In the same period, approximately 1593 million metric tons of cargo were moved from all ports of India in which Gujarat represents 31% of the overall national cargo movement and holds a significant 66% share of the cargo transported through non-major ports in the nation.
- The world's largest **Ship Recycling Yard** has been developed at **Alang-Sosia** in the Bhavnagar district. Currently, there are 150 plots at this ship recycling yard, out of which 128 plots are operational. Since 1983, a total of 8924 ships, amounting to 71.05 million metric tons LDT (Light Displacement Ton) have been dismantled at this yard. In response to the ongoing downturn in the ship recycling sector, the Government has provided given a total relaxation of Rs.145 crore in plot charges to ship breakers from the year 2021 to 2025.

Revenue Administration

- My Government has taken a historic step by adopting a farmer-oriented approach and deciding that records of the applicant prior to 25 years from the date of application will not be considered while doing the **farmer verification** for the sale of agricultural land.
- All areas of the state, except all municipalities and development authorities, for agricultural purposes, are **exempted from paying premiums** in this area, as per the New and inseparable tenure, all land of restricted tenure type or controlled tenure type are considered as old tenure.
- With the noble intention of a citizen-centric approach, My Government has taken a pro-people decision by reducing the missing amount of recoverable stamp duty by **80 percent** in the **Amnesty Scheme** for reimbursement of stamp duty on transfers made by housing societies/NTCs/associations through allotment letters and share certificates.
- With an aim to enhance the social status of women in the state, **1% registration fee is waived for women who purchase property** in immovable property documents purchased only in the name of women. Out of a total of 4.5 lakh documents registered from 2022 to the end of November 2025, 9.73 lakh women have been given a waiver of registration fee of more than rupees **Fifteen hundred** crore.
- Under the **Swamitva Yojana** in the state, the measurement of properties using drones has been completed in more than 14,700 villages. The process has been officially promulgated in 9,762 villages, and more than 1.6 million property cards have been generated.
- In order to enhance transparency in revenue administration, strengthen modern land administration system and reduce land disputes, an MOU has been signed between **Space Application Centre(SAC) ISRO, Ahmedabad and Revenue Department** to integrate modern technology, which has helped in procuring 30 cm high resolution satellite images and detecting encroachments on government lands and the detection of violations.

- Encroachments on valuable government lands have been removed in the state as part of the **Encroachment Removal Campaign**. These include the removal of encumbrances on a total of 1636 survey numbers from approximately 4135 hectares of land during the period from April-2025 to December-2025, the value of which is estimated at 3765 crores based on Jantri.

Law and order

- A state-wide unified dial-112 ERSS(**Emergency Response Support System**) system has been implemented as per the guidelines of the Home Ministry, Government of India. Under which emergency services like Police, Ambulance, Fire, Abhayam, Child helpline, and Disaster Management have been integrated and a total of 962 PCR vehicles are operational. As a result, the response time in rural areas has reduced to 11 minutes 56 seconds and in urban areas to approximately 08 minutes as of January 2026.
- The Police Recruitment Board has filled 11,899 vacancies of Lok Rakshak cadre in the state police force in the year 2025.
- Gujarat ranks second in the operation of **Cyber Crime Helpline- 1930** in the entire India.
- The blocked/frozen money of the applicant who is a victim of cybercrime can be returned to the applicant by filing an application in the Hon'ble Court under Section-503 (C.R.P.C.-457) of the B.N.S.S. Act. The Hon'ble Court has ordered the return of a total of more than Rs.202 crores to 1,32,765 applicants till date.
- Awareness is being created among the citizens about cybercrime through various media like newspapers, radio stations, TV channels, advertisements on GSRTC bus panels, and Social media. As well as awareness sessions have been organized in schools and colleges.
- All police staff, jail, prosecutor, forensic and judicial officers and employees have been trained for the implementation of the **Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023**, the **Bharatiya Nagrik Suraksha Sanhita, 2023** and the **Bharatiya Sakshya Adhiniyam, 2023**.

Fiscal Management

- As a part of Ek Bharat Shreshtha Bharat initiative, on the occasion of the **150th birth anniversary of Shri Sardar Vallabhbhai Patel**, on 31 October 2025, in the presence of Hon. Prime Minister Shri Narendrabhai Modi, a parade similar to the parades held on 26th January and 15th August in New Delhi on the theme of unity was organized at the Statue of Unity, Ektanagar. On this occasion, a commemorative coin of Rs.150 was unveiled in the memory of Shri Sardar Vallabhbhai Patel.
- Gujarat has strictly adhered to the fiscal deficit limit of 3% set by FRBM (Fiscal Responsibility and Budget Management) and has consistently maintained a fiscal deficit and revenue surplus of less than 2% of GSDP, according to the RBI report.
- The State has also maintained strict debt discipline, with public debt at 14.23% of GSDP in 2024-25 - much lower than the FRBM limit of 27.1%.
- The tax revenue of the State has almost doubled between 2020-21 and 2024-25. In the year 2024-25, Rs.1.19 lakh crore has been collected under GST, VAT, electricity tax and professional tax, which shows the robustness of the revenue structure of the state.
- Gujarat ranks first in the country with 99.6% filing of GSTR - 3B form in the year 2024-25.
- **Gujarat state ranks first in the country** in the verification of e-way bills at the end of November 2025 in the year 2025-26.
- The electricity tax exemption has been given to the specified micro units of the diamond industry for one year, providing relief to the industry and workers in difficult period.
- A total of more than 4.12 crore beneficiaries have been covered under **the Gujarat Samuhik Juth (Janata) Accident Insurance Scheme**. From the year 2025-26, the insurance assistance amount under this scheme has been increased from Rs.2 lakh to Rs.4 lakh to provide insurance assistance.

Sports, Youth and Cultural Activities department

- The **Khel Mahakumbh** has evolved into the largest people participation-based sports movement of the country, with more than 72 lakh players registered this year. An estimated 58 lakh players have participated so far.
- Under the **Centre of Excellence** initiative, there are currently 28 academies operating across 10 districts, catering to 15 different sports, with around 1790 players receiving training in both resident and non-resident academies. The High Performance Centre at Nadiad provides high-level support to more than 290 elite players across seven sports categories.
- Gujarat has received an opportunity to host the **Commonwealth Weightlifting Championships in 2025**, as well as the 11th Asian Aquatics Championships in the same year.
- The Government is dedicated to elevating the State to new levels through the synergy of 'Youth Power' and 'Cultural Heritage'. The spirit of patriotism is sustained through initiatives such as 'Har Ghar Tiranga', 'Sardar@150 Padayatra', and the observance of National Day.
- Our cultural heritage defines our identity. Whether it is the 'Uttarardha Utsav' celebrated at the Sun Temple in Modhera, the 'Vasantotsav' of Gandhinagar, or the 'Madhavpur Ghed Fair', these events are increasingly becoming a unique representation of Gujarat, Western India, and North-East India, reflecting the idea of 'Ek Bharat Shreshtha Bharat'.
- In the last two academic years (years 2023-24 and 2024-25), the students of Swarnim Gujarat Sports University have won a total of 35 medals in various sports in competitions like West Zone, All India University, Khelo India and World University Games (Germany). The All India Gold Medal in Athletics and the West Zone Silver Medal by the Women's Volleyball Team are a proud achievement for the State.

Science and Technology

- Under the SPV model, the state has achieved the top position regarding the functioning of Gram Panchayats, maintaining a 100% success rate and a network uptime of 95% over the past three years. Under **BharatNet, in Phase-2**, 321 services covered by Digital Seva Setu are being delivered with 100 Mbps fast internet. About 9000 institutions are getting the benefit of the same.

- The “**Rural Wi-Fi**” project was undertaken to provide internet service through Wi-Fi in more than 7685 Gram Panchayat offices of 22 districts under BharatNet Phase-2 in the year 2022-23. Through this Rural Wi-Fi project, the villagers are currently get direct benefit of the complimentary internet service for the first 60 minutes (one hour) every day. After that, the villagers are availing the internet service by recharging at a nominal rate.
- Aadhar authentication services are being used in more than 200 **Direct Benefit Transfer (DBT)** schemes. More than 56 crore Aadhar authenticated transactions were done in the last financial year.
- **Gujarat Biotechnology Research Centre** is a state-of-art biotechnology research centre of the Government of Gujarat. Recognizing the significance of national biosecurity, the state of Gujarat has initiated the establishment of India's second advanced Biosafety Level-4 (BSL-4) laboratory, with an investment of Rs.362 crore, designated as the "National Centre for High-Containment Pathogen Research Facility." This facility will help in the research on drugs and vaccines targeting highly infectious viruses such as Corona, Chandipura, and CCHF.
- In order to enhance the milk production capacity of cattle in Gujarat, the NDDB, Banas, Sabar Dairy, and GCMMF are implementing a genotyping program involving 40,000 cattle, of which over 28,000 have already been genotyped. This initiative aims to develop livestock with higher milk production capabilities in the future.
- In the Chandipura virus outbreak in the state, **Gujarat Biotechnology Research Centre** has developed a PCR-based test, reducing the diagnosis time to less than 24 hours, and has provided diagnosis of 379 samples till today. In addition, the genome sequence of Chandipura virus has been done.
- AI Centre of Excellence has been launched at GIFT City. In which AI Innovation Challenge has been launched for deployable AI solutions for public services. 18 start-ups are working at AI Centre of Excellence. In addition, AI Innovation Challenge has been launched for 16 use cases in the government sector and 14 use cases in the private sector.

- To develop AI capabilities and intellectual property (IP) in the country, the first **Indian AI Research Organization (IARIO)** of the country has been established at an expenditure of Rs.300 crore with the joint co-operation of the State Government, central government and the private sector.
- Gujarat is entering into the global semiconductor value chain through marquee projects at Dholera SIR (India's first commercial semiconductor fab) and Sanand (Packaging Cluster with Micron, CG Semi and CANS) - strengthening manufacturing leadership and strategic supply chain. These projects involve an investment of over Rs.1.24 lakh crore and are expected to create over 45,000 direct and indirect jobs.
- Gujarat is also pursuing leadership in the space sector through a dedicated space tech policy supporting local manufacturing and space-based applications. To achieve this goal, the Khoraj GIDC located near Sanand is being developed specifically for space technology initiatives. This park is being established by the Azishta Company with the aim of producing indigenous satellites for the country.

Forest and Environment

- In the year 2025-26, a total of 10.59 crore saplings have been planted throughout the state as part of the "**Ek Ped Maa Ke Naam 2.0**" initiative through **Social Forestry**.
- On World Environment Day on 05th June, 2025, more than 67,000 saplings have been planted in a total of 331 programs in the state and **68 Sindoor Van** have been created.
- There are a total of 29 protected areas in the State, including 4 national parks, 24 sanctuaries and 1 conservation reserve area. Gujarat is at the forefront in the field of wildlife conservation and breeding.
- The 7th meeting of the National Wildlife Board was held at Sasan under the chairmanship of Hon'ble Prime Minister Shri Narendra Modi in March-2025 in which the Prime Minister appreciated the efforts made for the conservation and breeding of the Asiatic lion in the State. He also directed that the spirit of public participation, coexistence and human-wildlife tolerance observed in the Greater Gir region should be replicated in other areas of the nation.

- From May 10 to May 13, the **16th lion population** census was conducted in a total area of 35,000 sq. km., which included 58 talukas of 11 districts. According to the lion population census, a total of 891 lions have been recorded. There has been **an increase of 32.20 percent** in the lion population in the year 2025 compared to the year 2020.
- Due to the farsightedness of the Government of India and the State Government to create a sustainable leopard population, a leopard breeding centre has been set up over an area of approximately 600 hectares within the Banni grasslands of Kutch district.
- Last year, a tiger also arrived in Ratanmahal Sanctuary of the state after about thirty years and has settled in the area.
- I congratulate the State Government for doing remarkable work for wetlands. So far, four wetlands in the state: Nal Sarovar Bird Sanctuary, Thol Bird Sanctuary, Khijdia Bird Sanctuary, Wadhwan Bird Sanctuary have been declared as Ramsar Sites. On 30/01/2026, one more area of Gujarat: Chhari-Dhandh Bird Sanctuary in Kutch has also been declared as a Ramsar Site, which is a matter of pride for the state of Gujarat. Which has become the fifth Ramsar Site of the state.
- My Government has implemented the ETS-PM (Emission Trading Scheme Particulate Matter) scheme to control air pollution caused by particulate matter (Particulate Matter) emitted from industrial chimneys, **as a pilot project** in Surat and Ahmedabad. Under this scheme, industries that emit higher levels of particulate matter (PM) are required to purchase permits from those with lower emissions, while the latter benefit financially from selling these permits, thereby incentivizing a reduction in pollution. This initiative, categorized under 'Clean Our Air', was recognized as a finalist for the Earth shot Award - 2025, which took place in Rio de Janeiro, Brazil, on November 5, 2025

Administrative Reforms and Planning

- SPIPA's Centre for Good Governance organized the Atal Lecture Series to commemorate the 100th birth anniversary of Shri Atal Bihari Vajpayiji.
- With the complete implementation of the Gujarat (Right of Citizens to Public Services) Act, 2013, a total of 448 services directly affecting citizens of a total of 20 departments of the Gujarat Government have been covered under the Act.
- In order to resolve the concerns of citizens, 3,48,538 complaints of citizens have been disposed of through the PG Portal software for online complaint registration by the Department of Administrative Reforms and Public Grievances, Government of India.
- The Reformed Gujarat Paribhraman Yojana has been implemented from the financial year 2025-06, to ensure that the Gujaratis, besides living in other states of India and the younger generation of non-resident Gujaratis, who are originally from Gujarat between the ages of 18 and 40, visit Gujarat and know, enjoy and understand the essence of their homeland. In this scheme, transportation, accommodation, food, and site visit facilities are provided in a continuous 10-day program in Gujarat.
- The **Gujarat Administrative Reforms Commission (GARC)** constituted by my Government has so far submitted a total of six reports, which contain several practical and effective recommendations on reforms in administrative processes, human resource management—especially transparency in recruitment and selection processes, technology-enabled governance, citizen-centric service delivery, and strengthening accountability and transparency. The Government has largely accepted these recommendations and many of them are in various stages of implementation today, which is proven to be a significant and decisive step toward good governance and proficient administration in Gujarat.
- My Government has implemented a modern Human Resource Management System, which has made accessible the service books and financial matters of all government officers and employees through the Information and Communication Technology (ICT) based "**Karmayogi Portal**" and "**Karmayogi Mobile Application**".

- My Government has founded the Gujarat State Institution for Transformation (GRIT) with an aim to transform the national vision of **Viksit Bharat@2047** into an actionable strategy in September-2024. This institution aims to deliver strategic and evidence-based insights to bolster the long-term development agenda. GRIT is designated as the development think tank of the state
- GRIT has prepared Economic Master Plans for five more key economic sectors of the state based on the Surat Economic Master Plan developed by NITI Aayog. It aims to create an economy of over USD 4 trillion and over 28 million new jobs for Gujarat by 2047. These Economic Master Plans focus on rapid and sustainable growth driven by around 20 priority sectors and 29 mega projects, with a total investment potential of around Rs.60 trillion.
- Nandod taluka in Narmada district and Subir taluka in Dang district are at the forefront of the rankings within Zone 4 (Western Zone) as part of the Aspirational Block Program (ABP) initiated by NITI Aayog, at the end of September 2025 and December 2024, respectively. NITI Aayog has declared a prize of Rs 1 crore for each of these talukas.

Information and Broadcasting

- The responsibility of disseminating information regarding the public welfare and advantageous schemes and programs of the State Government to the common citizens and beneficiaries is being effectively carried out.
- Digital displays-cum-exhibitions are being installed in every Office of the District Collector, Offices of the District Development Officer, and Office of the Municipal Corporation throughout the state to showcase the schemes of the State Government in a digital format during office hours. This allows the common citizen to access the benefits or details of the schemes available to them.

Judiciary

- A strong judiciary is a strong pillar of democracy. Newly constructed taluka level court buildings have been inaugurated at Kalol (Panchmahal), Prantij (Sabarkantha), Sanand (Ahmedabad) and Uchchal (Tapi-Vyara).

- A newly constructed Charity Bhavan built at a cost of Rs.02 crore 48 lakhs has been inaugurated at Morbi.
- As part of the important IILMS Project of the government, mapping of court cases in which the State Government is a petitioner has been conducted. Through this portal, the concerned officers of the department are informed about the proceedings in the court related to the case in a timely manner so that it becomes easy for the State Government to take effective action in a timely manner and present its arguments before the court.

Climate Change

- The **Gujarat Climate Action Tracker (GCAT) Portal** has been launched on World Environment Day, June 5. It is the first digital platform in the country to display information related to climate indicators at the district level by any state.
- As part of the initiative **to install solar systems on government properties**, by January 2026, 7.75 MW of solar photovoltaic rooftop systems have been installed across 607 government buildings, with an estimated expenditure of Rs.60 crores for the fiscal year 2025-26, fully supported by the government. As well as, till now, a total of 85.73 MW of solar photovoltaic rooftop systems have been installed on 5244 government buildings, incurring an estimated cost of Rs.406 crores.
- A total subsidy of Rs.2.66 crore has been allocated to 1,764 students via Direct Benefit Transfer (DBT) under the Subsidy (Assistance) Scheme for Battery-Powered Two-Wheelers intended for students enrolled in grades 11 and 12 in schools and colleges for the academic year 2025-26, up until January 2026. Additionally, a total of Rs.62.71 crore has been disbursed to 55,514 students through DBT so far.

I am pleased to address this august house of the 15th Gujarat Legislative Assembly and assert that the strong, prosperous and secure Gujarat is an exemplary State of India. As the comprehensive development of Gujarat radiates like the sun, under the guidance of the beloved and dignified Prime Minister Shri Narendrabhai Modi, we must advance the developmental journey of Gujarat even further. By building Atmanirbhar and Viksit Gujarat, we have to contribute to build a self-reliant and Viksit Bharat. Gujarat is the growth engine of the country and it is our collective duty to enhance its strength.

The public has entrusted you with the responsibility of safeguarding Gujarat so that every Gujarati can be proud to be a Gujarati anywhere in the world and have self-respect for Gujarat. I hope that each of you will make your best contribution as a public representative in this assembly, considering your experiences in public life and the expectations of the people. I am assured that the blessing of the public will give you unmatched strength for your service to the people.

**Bharat Mata Ki Jay.
Jay Jay Garvi Gujarat**
